



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37]
No. 37]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 12, 1998/भाद्र 21, 1920
NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 12, 1998/BHADRA 21, 1920

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह धलण संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II) PART II—Section 3—Sub-Section (II)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
आदेश

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1998

स्टाम्प

के रूप में वर्णित अधिनियम एस० बी० आई० बॉन्ड्स 1998
पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभाव है।

[सं. 29/98-स्टाम्प-फा. 15/21/98-बि. क.]

अवर्णा शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 25th August, 1998

STAMPS

का.आ. 1781—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899
(1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड
(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार
एतद्वारा मै. साउथ इंडियन बैंक लि., नई दिल्ली को
मात्र तेरह लाख छहत्तर हजार पचास रुपए का समेकित
स्टाम्प शुल्क अर्था करने की अनुमति प्रदान करती है जो
उक्त कम्पनी द्वारा जारी किए जाने वाले तेरह करोड़
छहत्तर लाख पांच हजार रुपए के समग्र मूल्य के
00001 से 27521 तक की विशिष्ट संख्या वाले पांच-
वांश हजार रु० के अमुरक्षित, विमोक्ष्य प्रोमिसरी नोटों

S.O. 1781.—In exercise of the powers conferred by clause
(b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act,
1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits
M's. South Indian Bank Limited, New Delhi to pay consoli-
dated stamp duty of rupees thirteen lakhs seventy six
thousand and fifty only chargeable on account of the stamp
duty on bonds in the nature of promissory notes described
as Unsecured, Redemable. Subordinate SIB BONDS 1998
of rupees five thousand each bearing distinctive num-
bers from 00001 to 27521 aggregating to rupees thirteen

crores seventy six lakhs and five thousand only to be issued by the said company.

[No. 29/98-Stamps/F. No. 15/21/98-ST]
APARNA SHARMA, Under Secy.

आर्थिक कार्य विभाग))

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1998

का. आ. 1782— बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की संस्तुति पर घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 1 के उपबंध इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 31 मार्च, 1999 तक उदयपुर मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि., उदयपुर (राजस्थान) पर लागू नहीं होंगे।

[फा. सं. 1(17)/95-ए. सी.]

एम. के. ठाकुर, अवसर सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 25th August, 1998

S.O. 1782.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government on the recommendations of the Reserve Bank of India declares that the provisions of sub-section 1 of Section 11 of the said Act shall not apply to the Udaipur Central Co-operative Bank Ltd., Udaipur (Rajasthan), from the date of publication of this notification in the Official Gazette to 31 March, 1999.

[F. No. 1(17)/95-AC]

S. K. THAKUR, Under Secy.

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1998

कां० आ० 1783.—भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 के उन्नीसवें) के खण्ड 8 के उपखण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, भारत सरकार उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित सार्वजनिक संस्था का नाम एतद्वारा जोड़ती है।

“डिस्काउंट एण्ड फाइनेंस हाउस आफ इण्डिया लिमिटेड”

[सं० 4(1)-ई5/95 (I)]

के० गुर्तु, निदेशक

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 31st August, 1998

S.O. 1783.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby adds to the

Schedule to the said Act the name of the following public institution, namely :—

“Discount and Finance House of India Limited”

[No. 4(1)-EV/95(I)]

K. GURTU, Director

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1998

का.आ. 1784—भविष्य निधि अधिनियम 1925 (1925 के उन्नीसवें) के खण्ड 8 के उपखण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि उपरोक्त अधिनियम के सभी प्रावधान (सिवाय खण्ड 6 के) “डिस्काउंट एण्ड फाइनेंस हाउस आफ इण्डिया लिमिटेड” द्वारा इसके कर्मचारियों के लाभ के लिए स्थापित भविष्य निधि पर लागू होंगे।

[संख्या 4(1)-ई. 5/95(2)]

के० गुर्तु, निदेशक

New Delhi, the 31st August, 1998

S.O. 1784.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 8 of the Provident Fund Act, 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act (except section 6-A) shall apply to the Provident Fund established for the benefit of the employees of the “Discount and Finance House of India Limited”.

[No. 4(1)-EV/95 (II)]

K. GURTU, Director

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1998

का.आ. 1785—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “पेट्रोलियम स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, नई दिल्ली” को 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 तक के कर-निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्—

(1) कर निर्धारिणी उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिये उसका संचयन इस प्रकार के संचयन हेतु उक्त खण्ड (23) द्वारा यथा संशोधित धारा 11 की उपधारा (2) तथा (3) के उपबन्धों के अनुरूप पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;

(2) कर निर्धारिणी उपर-उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों में भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जखर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु, जिसे उपर्युक्त

खण्ड (23) के तीसरे परन्तुक के अधीन बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए, के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्थैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;

(3) कर-निर्धारिती अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपनी आय के किसी भाग का सवितरण अपने से संबद्ध किसी एसोसिएशन अथवा संस्था को अनुदान के अलावा नहीं करेगा. और

(4) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार में प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हों जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हो।

[अधिसूचना सं. 10684/फा.सं. 196/
23/96-आयकर नि.-1)]

समर भद्र, अधर सचिव

(Department of Revenue)

New Delhi, the 3rd September, 1998

(INCOME TAX)

S.O. 1785.—In exercise of the powers conferred by clause (23) of Section 10 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Petroleum Sports Control Board, New Delhi" for the purpose of the said clause for assessment years 1996-97, 1997-98 and 1998-99 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate it for application, in consonance with the provisions of sub-section (2) and (3) of Section 11 as modified by the said clause (23) for such accumulation wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest on deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture or any other article as may be notified by the Board under the third provision to the aforesaid clause (23) for any period during the previous year(s) relevant to the assessment year(s) mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of section 11;
- (iii) the assessee will not distribute any part of its income in any manner to its members except as grants to any association or institution affiliated to it;
- (iv) this notification will not apply in relation to any income, being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 10684/F. No. 196/23/96-ITA-I]

SAMAR BHADRA, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1998

का.आ. 1786—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा डा. विजय एल. केलकर, वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली को श्री मोन्टेक सिंह आहलुवालिया के स्थान पर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में निदेशक नियुक्त करती है।

[संख्या एक. 9/9/98-बी.ओ.-I]

एम. दामोदरन, संयुक्त सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 2nd September, 1998

S.O. 1786.—In pursuance of clause (d) of sub-section (1) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Central Government hereby nominates Dr. Vijay L. Kelkar, Finance Secretary in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi to be a Director on the Central Board of the Reserve Bank of India with immediate effect and until further orders vice Shri Montek Singh Ahluwalia.

[F. No. 9/9/98-B.O.I.]

M. DAMODARAN, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1998

का.आ. 1787.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, संलग्न अनुबंध में निम्नलिखित बैंकों के सूचीबद्ध कार्यालयों/शाखाओं को, जिनके 80% से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

क्रम सं.	बैंक का नाम	कार्यालयों/ शाखाओं की संख्या
1.	यूको बैंक	294
2.	पंजाब नेशनल बैंक	112
3.	ग्रान्धा बैंक	034
4.	कार्पोरेशन बैंक	006
5.	मिडिकेट बैंक	040
6.	पंजाब एंड सिंध बैंक	016
7.	स्टेट बैंक आफ़ बीकानेर एंड जयपुर	006
8.	यूनियन बैंक आफ़ इंडिया तथा	024
9.	बैंक आफ़ महाराष्ट्र	019
योग		551

[फा. सं. 11016/2/98-हिन्दी]

रमेशबाबू अणियेरी, उपनिदेशक (राजभाषा)

1. यूको बैंक
कोरमंगला
146/2-350/1
कोरमंगला
बेंगलूर-560 034
2. यूको बैंक (कम्प्यूटरीकृत)
एम. जी. रोड शाखा
पोस्ट बाक्स 5132
83, महात्मा गांधी रोड,
बेंगलूर-560 001
3. यूको बैंक
राममूर्ति नगर शाखा
साइट नं. 42, मुनिक्लप्पा ले-आउट
बनसवाडी,
राममूर्ति नगर,
बेंगलूर-560 016
4. यूको बैंक
के.एस. आर. रोड,
हम्पन्नकट्टा
मंगलूर-575 001
5. यूको बैंक
गांव-डोडा आलहाली
डाकघर-कनकपुरा
जिला-बेंगलूर
पिन-562 117
6. यूको बैंक
डाकघर-कोडिहाल्लि
कनकपुरा तालुक
बेंगलूर-562 119
7. यूको बैंक
मेन रोड,
डाकघर-भरलवाडी
तालुक-कनकपुरा
बेंगलूर-562 121
वक्षिणी अंचल
8. यूको बैंक (कंप्यूटरीकृत)
बेंगलूर सिटी
पोस्ट बाक्स नं. 9523
13/22, कैम्पे गोडा रोड
बेंगलूर-560 009
9. यूको बैंक
बनशंकरी शाखा,
4010, न्यू के.आर. रोड
बनशंकरी II स्टेज
बेंगलूर-560 070
10. यूको बैंक
इन्दिरा नगर शाखा,
531, बिल्डिंगला II स्टेज
इन्दिरा नगर
बेंगलूर-560 038
11. यूको बैंक
फ्रेजर टाउन शाखा
14/14 ए, मस्जिद रोड
फ्रेजर टाउन,
बेंगलूर-560 005
12. यूको बैंक
जयनगर शाखा
238/35, 9वां मेन रोड
111 ब्लॉक, जयनगर
बेंगलूर-560 011
13. यूको बैंक
जालहल्ली शाखा
एच.एम. टी. डाकघर
जालहल्ली,
बेंगलूर-560 031
14. यूको बैंक
भैसूर रोड, केंगेरी पुलिस स्टेशन
केंगेरी
बेंगलूर-560 060
15. यूको बैंक
2891/92 सद्दनोवर चेम्बर्स
खड्डे बाजार
बेलगांव-590 002
16. यूको बैंक
डाकघर-अमिनभावी
जिला-धारवाड़
पिन-581 201
17. यूको बैंक
नगर-गुलबर्गा
संख्या 32 सुपर मार्केट
पहली मंजिल
डाकघर व जिला-गुलबर्गा (कर्नाटक)
18. यूको बैंक
87/80, देवराज अर्ल रोड
भैसूर-570 001
19. यूको बैंक
विशिष्ट वसूली शाखा
13/22, कैम्पेगोडा रोड
बेंगलूर-560 009

- | | |
|---|---|
| <p>20. यूको बैंक
बल्लारायू भवन
कुनेन रोड
अलेप्पी-688 001</p> <p>21. यूको बैंक
पोस्ट बैग नं. 127
जयस्ती भवन
पालायाम जंक्शन
कोझिकोड-673 001</p> <p>22. यूको बैंक
मल्लापुझसेरी
डाकघर-नेल्लीकला
वाया-एलानथुर
जिला-पाथनमथिट्टा
पिन-689 643</p> <p>23. यूको बैंक
गांव-आरकल
पी.ओ. थाडिकाड
जिला-क्वैलान-691 306</p> <p>24. यूको बैंक
पोस्ट बैग नं. 509
खैसे बिल्डिंग
बीच रोड
क्वैलान-691 001</p> <p>25. यूको बैंक
स्वराज राजुंड
सी-24/955, हाई रोड,
त्रिचूर-680 001</p> <p>26. यूको बैंक
पोस्ट बाक्स 79
13/5, कास जंक्शन,
थीरुवल्ला-689101</p> <p>27. यूको बैंक
वाराकला
एम.जी.ई.
(केरल)</p> <p>28. यूको बैंक
सी सी 29/257 ए
एस.एन. पार्क रोड,
कन्नूर-607001
(केरल)</p> <p>29. यूको बैंक
यूको बैंक भवन,
पोस्ट बैग-161, टी.सी. 25/2286/
ओवर ब्रीज जंक्शन
त्रिवेंद्रम-695001</p> | <p>30. यूको बैंक
10/1229/ए, एस एस पीटर
एंड पाल्स चर्च कम्पाउण्ड,
डाकघर-फोर्ट कोचीन
कोचीन-682001</p> <p>31. यूको बैंक
पोस्ट बाक्स नं. 2564
कावेरी बिल्डिंग,
क्लाथ बाजार स्ट्रीट
एर्णाकुलम-682031</p> <p>32. यूको बैंक
पोस्ट बाक्स 281
मट्टनचेरी
कोचीन-682002</p> <p>33. यूको बैंक
एम.जी. शाखा
1, 35/2361 रविपुरम
एर्णाकुलम-682016</p> <p>34. यूको बैंक
पोस्ट बैग नं. 581
बिलिंगडन आइलैंड
कोचीन-682003</p> <p>35. यूको बैंक
डाकघर-कसकुट्टी
वाय-अंगमाली
एर्णाकुलम-683576</p> <p>36. यूको बैंक
पो. बैग नं. 1/50 ए
न्यू मुनम्बम फेरी
पी सी पल्लिपोट
मुनम्बम
जिला-एर्णाकुलम (केरल)</p> <p>37. यूको बैंक
बिड़लाकूटग्रम
मावूर-673661</p> <p>38. यूको बैंक
पोस्ट बाक्स नं. 325, सं. 20
मार्केट रोड
पालघाट-678014</p> <p>39. यूको बैंक
मदाशिवपेट तालुक,
आत्मकूर,
जिला-मेदक
पिन-502292</p> |
|---|---|

40. यूको बैंक
1-10, बाजार स्ट्रीट
डाकघर-8 राला
जिला-चित्तूर
पिन-517130
41. यूको बैंक
नागलापुरम
जिला-चित्तूर
पिन-517589
42. यूको बैंक
132, टी.पी. एरिया
श्री वेकटेश्वर बस स्टैंड के सामने
तिरुपति,
पिन-517501
43. यूको बैंक
ओंकार काम्पलेक्स (प्रथम तल)
बड़ी मस्जिद के पास
राजामुन्नी, (पूर्व गोदावरी)
पिन-533101
44. यूको बैंक
9/1, अरुन्धेलपेट
गुंटूर-522002
45. यूको बैंक
मैन रोड
डाकघर-दुस्ताबाद
जिला-करीमनगर (आन्ध्र प्रदेश)
पिन-505467
46. यूको बैंक
जी एन टी रोड,
हनुमान जंक्शन
जिला-कृष्णा
पिन-521105
47. यूको बैंक
(पोस्ट बॉक्स सं. 121)
26/15-7/1, मैन रोड,
विशाखापत्तनम-530001
48. यूको बैंक
हिन्दुस्तान शिपयार्ड कालोनी
गांधी ग्राम
विशाखापत्तनम-530005
49. यूको बैंक
हिन्दुस्तान जिक
स्मेल्टर फैक्टरी शाखा
जिक स्मेल्टर डाकघर,
विशाखापत्तनम-530015
50. यूको बैंक
क्वार्टर नं. 18/ए, बी.एस.पी टाउनशी
विशाखापत्तनम-530031
51. यूको बैंक
मारीकल
जिला-महबूबनगर
पिन-509351
52. यूको बैंक
गांव एवं पी.ओ. मगनूर
जिला-महबूबनगर
पिन-509208
53. यूको बैंक
नया बाजार
डाकघर बानापती
जिला-महबूबनगर
पिन-509103
54. यूको बैंक
10-14-1/ए मेड रोड
डाकघर-संगरेडुडी
मेडक-502001
55. यूको बैंक
गांव-पट्टिन्नपुर, बाधा मुथंगी
जिला मेडक,
पिन 502300
56. यूको बैंक
गांव एवं डाकघर पोडिचिनपल्ली
जिला मेडक
पिन 502110
57. यूको बैंक
पोस्ट बॉक्स नं. 10,
सूबेदार पेट, नैल्लोर
जिला-नैल्लोर (आन्ध्र प्रदेश)
पिन-524001
58. यूको बैंक
1/30, मैन रोड,
देवरपल्ली
जिला-विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)
पिन-531030
59. यूको बैंक
गांव व डाकघर-काकरापडू
ब्लाक-कोयूरु,
चिन्तापल्ली तालुका
जिला-विशाखापत्तनम
पिन-531099
60. यूको बैंक
गांव व डाकघर-कोटूरु
बामा-माकावरापत्तनम
जिला-विशाखापत्तनम
पिन-531113

61. यूको बैंक
गांव व डाकघर—लम्मासिंगी
तहसील—चिन्तापल्ली
जिला—विशाखापत्तनम
पिन—531116
62. यूको बैंक
गांव व डाकघर—राधवेन्द्रनगर
गुदेम कोटे
जिला—विशाखापत्तनम
पिन—531133
63. यूको बैंक
पोस्ट बॉक्स नं. 27
रामरत्न मेशन
जी. एन. टी. रोड के निकट
पावरपेट—एलुरु
जिला—पश्चिम गोदावरी
पिन—532001
64. यूको बैंक
गांव एवं डाकघर—माधाराम
तालुक—कलवाकुर्ती
जिला—महबूबनगर
पिन—509357
65. यूको बैंक
प. ब. नं. 328
डी. नं. 27/18/47
कांग्रेस आफिस रोड,
गवर्नर पेट,
विजयवाडा, जिला—कृष्ण (आन्ध्र प्रदेश)
पिन—520002
66. यूको बैंक
पोस्ट बॉक्स नं.—176
रंगन्नाचरी स्ट्रीट, विजयवाडा
जिला—कृष्ण—520001
67. यूको बैंक
थोटवाल्लूर मंदिर,
पोस्ट—थोटवाल्लूर
जिला—कृष्ण
पिन—521163
68. यूको बैंक
गांव—सुरामपल्ली
डाकघर—तून्ना, जिला—कृष्ण,
पिन—521212
69. यूको बैंक
पोस्ट बॉक्स नं.—3
5-1-908 पुष्पांजली काम्प्लेक्स
रीयर ब्लोक, भूम तल,
कोटी, हैदराबाद
पिन—50019 5
70. यूको बैंक
आबिद सकिल
5-8-600 से 604, प्रथम तल,
भुवारक बाजार,
हैदराबाद—500001
71. यूको बैंक
पथ सं. 11, बंजारा हिल्स,
हैदराबाद—500034
72. यूको बैंक, हैदराबाद सिटी,
16-2-705/28, मालकपेट,
मुसताज कालेज पथ,
डाकघर व जिला—हैदराबाद
आंध्र प्रदेश
पिन—500036
73. यूको बैंक
2-2-147/1 महात्मा गांधी रोड,
सिकन्दराबाद—500003
74. यूको बैंक
पोस्ट बॉक्स नं. 26,
9-1-167/168 सरोजनी देवी रोड
सिकन्दराबाद (आन्ध्र प्रदेश)
पिन—500003
75. यूको बैंक
चित्र-बांगरूपालम मेम रोड,
अरागोडा, जिला—चित्रूर
पिन—517129
76. यूको बैंक
वैश्य होस्टल के सामने
कमला नगर,
अनन्तपुर—515001
77. यूको बैंक
वेंकटस्वरपुरम, प्रथम तल
लब्धीपेट,
विजयवाडा, जिला—कृष्णा
पिन—520010
78. यूको बैंक
8-1-21, फ्लैट नं. 12,
सूर्यनगर, टोली चौकी,
हैदराबाद—500008
79. यूको बैंक
10-12-84, अजैमीय स्वासी टेम्पल स्ट्रीट
अट्टिली, जिला—पश्चिम गोदावरी
पिन—534134
80. यूको बैंक
मिरजलगुडा—मल्काजगीरी रोड,
13-1/41, सैरपुरी,
हैदराबाद—500047

पश्चिम अंचल

81. यूको बैंक,
समदानी बिल्डिंग,
गोमतेश मार्केट के सामने,
नई गुलमण्डी मार्ग,
औरंगाबाद-431001
82. यूको बैंक,
79, महात्मा गांधी रोड,
पोस्ट बाक्स सं. 33,
पुणे-1
83. यूको बैंक,
659, सदाशिव पेठ,
अश्वर्या गणपति के सामने,
पुणे-411030
84. यूको बैंक,
हमाम स्ट्रीट शाखा,
राणावहादुर भवन
18/18ए अम्बालाल दोषी रोड,
मुम्बई-400023
85. यूको बैंक,
"गोकुल"
66/ए डा. आत्माराम भर्चेंट रोड,
भुलेश्वर, मुम्बई 400002
86. यूको बैंक,
खार शाखा,
508, लिफिंग रोड,
बांद्रा,
मुम्बई-400050
87. यूको बैंक,
"अलकार"
208, सेम्युल स्ट्रीट,
मांडवी,
मुम्बई-400003
88. यूको बैंक,
गूल एनेक्सी आफ केराबाला लॉज,
स्टेशन रोड,
मांताकृत्र (पश्चिम),
मुम्बई-400054
89. यूको बैंक,
संमगिरि सदन,
171, गिरगांव रोड,
मुम्बई-400004
90. यूको बैंक,
ठाणे सेलापुर शाखा,
इंद्रियानी बिल्डिंग,
कलबा (पूर्व)
जिला-ठाणे
91. यूको बैंक,
मोहन हाउस,
55, बार्डन रोड,
मुम्बई-400026
92. यूको बैंक,
"सेचरी भवन"
डा. ऐनी बेसेन्ट रोड, बरली,
मुम्बई-400016
93. यूको बैंक,
बाईडक्यू सी.ए. बिल्डिंग एनेक्सी
18, मादाम कामा रोड,
मुम्बई-400001
94. यूको बैंक,
पिम्परी पी.एफ.,
पुणे-411018
95. यूको बैंक,
(पोस्ट बाक्स 64),
पहली मंजिल, लक्ष्मी भवन,
माउन्ट रोड, एक्सटेन्शन,
नागपुर-440001
96. यूको बैंक,
खेड-शिवापुर शाखा,
लक्ष्मी निवास,
अप्सरा होटल के पास,
खेड-शिवापुर बाग,
तालुका हवेली,
जिला-पुणे-412205
97. यूको बैंक,
धुलिया शाखा,
'कल्पना' 1196 नगर पार्टी,
धुलिया-424001
98. यूको बैंक,
यशवंत मंडल,
रविहार पेठ,
नामिक मिटी
99. यूको बैंक,
क्वाटर्न. 7151/2 और 3
टाइप II आडिनेन्स फ़ैक्टरी, अम्बाजारी,
पोस्ट-अम्बाजारी डिफेंस प्रोजेक्ट,
जिला-नागपुर
100. यूको बैंक
ग्राम सर्वे सं. 360
डाकघर-कलभ
तालुका-आंबेगांव
जिला-पुणे-410515

101. यूको बैंक,
एस.एस.सी ई. बोर्ड बिल्डिंग,
शिवाजी नगर,
पुणे-411010
102. यूको बैंक,
न्यू रविवार पेठ,
पुणे
103. यूको बैंक,
शिंदसागर अपार्टमेंट्स,
गणेशखिड रोड,
161 ए, मोदी बाग,
पुणे-411016
104. यूको बैंक,
1137-बी घेरवाड़ा,
चित्रा टाकीज के सामने,
पुणे-411006
105. यूको बैंक,
जियोजी मेशन,
225/9ए पुणे शोलापुर रोड,
हडपसर,
पुणे-411028
106. यूको बैंक,
अर्टिलरी सेन्टर शाखा,
डा. थोल्स बिल्डिंग,
प्लॉट नं. 32 बी/सर्वे नं. 38,
जैन भवन के सामने,
अर्टिलरी रोड,
नासिक रोड-422101
107. यूको बैंक,
खडगांव,
तालुका-डिंडोरी,
जिला-नासिक-422205
108. यूको बैंक,
क्लाथ मार्केट,
अकोला,
जिला-अकोला
109. यूको बैंक,
अहमदनगर शाखा,
चितले मार्ग,
अहमदनगर
110. यूको बैंक,
18, निव पेठ,
जलगांव-425001
111. यूको बैंक,
भुसावल शाखा,
पांढुरंग टाकीज,
न्यू एग्रिया के पास,
भुसावल-425201
112. यूको बैंक,
"उमा चित्रा मंदिर",
भागवत चित्रा नगर,
मोगरजी पेठ,
पो.गा. नं. 81,
शोलापुर-413001
113. यूको बैंक,
वरहा शाखा,
ग्राम पंचायत शाखा,
तालुका-दयोसा,
जिला-अमरावती
114. यूको बैंक,
गांव व डाकघर-नागमयान,
तालुका-वैजापुर,
जिला-औरंगाबाद
115. यूको बैंक,
महाकाली,
डाकघर व जिला-चंद्रापुर
116. यूको बैंक,
धुधुस शाखा,
धुधुस ग्राम पंचायत,
जिला-चंद्रापुर
117. यूको बैंक,
बल्लारपुर शाखा,
बल्लारशा,
जिला-चंद्रापुर
118. यूको बैंक,
न्यू माजरी कोलियरी,
डाकघर-शिवाजीनगर,
जिला-चंद्रापुर-442506
119. यूको बैंक,
मार्दोल,
गोवा-403404
120. यूको बैंक,
मुवराया बिल्डिंग,
म्युनिमिपल मार्केट के निकट,
पो.बा. नं. 29
मापुसा-403507
(गोवा)
121. यूको बैंक,
1002, बुधवार पेठ,
पुणे-411002
122. यूको बैंक,
बारामती शाखा,
बारामती कृषि उत्पाद

- बाजार समिति,
प्रिमिपल मार्केट यार्ड,
बारामती-413102
- शुक्रवार पेठ,
तिलक मार्ग,
पुणे-411002
123. यूको बैंक,
शिवाजी विश्वविद्यालय,
विद्यानगर,
कोल्हापुर-4
133. यूको बैंक,
सांगवी शाखा;
सांगवी,
तालुका-बारामती,
जिला-पुणे
124. यूको बैंक,
ग्रोल्ड रेलवे स्टेशन के सामने,
सामंती मिशन मेन रोड,
429/40, खान भाग;
सांगली-416416
134. यूको बैंक,
स्थान एवं डाकघर-वाग्शी,
सिन्दखेड़ा ब्लाक,
जिला-धुले
125. यूको बैंक,
चंदा रायतवाड़ी शाखा
गांव-डाकघर-चंद्रापुर-442040
135. यूको बैंक,
कोंधवा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स शाखा,
नेहा अपार्टमेंट्स,
5ए/1ए, कोंधवा,
पुणे-411022
126. यूको बैंक,
हिन्दुस्तान लालपेठ शाखा,
डाकघर-हिन्दुस्तान लालपेठ,
कोलियारी;
जिला-चंद्रापुर
136. यूको बैंक,
लाखपुरी शाखा,
ग्राम पंचायत कार्यालय;
दरियापुर बानोसा मार्ग,
तालुका-मूर्तिजापुर,
जिला-अकोला-444116
127. यूको बैंक,
नगर परिषद मार्केट कॉम्प्लेक्स,
दूसरा माला,
चंद्रापुर,
जिला-चंद्रापुर
137. यूको बैंक,
त्रिचोली बंदरूक शाखा,
ग्राम पंचायत भवन,
दरियापुर अंजनगांव मुरजी मार्ग,
तालुका-अंजनगांव मुरजी,
जिला-अमरावती-445205
128. यूको बैंक,
कोरपावली शाखा,
तालुका-यावत
जिला-जलगांव-525301
138. यूको बैंक,
गिरनारे शाखा,
माधव राव वामन शेटी हाउस,
स्थान व डाकघर-गिरनारे,
तालुका व जिला-नासिक,
पिन-422203
129. यूको बैंक,
वीरवाडे शाखा
तालुका-वोपड़ा,
जिला-जलगांव-425107
139. यूको बैंक,
स्थान व डाकघर-सिरसी
तहसील-उमरेड,
जिला-नागपुर
130. यूको बैंक,
मुंगी शाखा,
स्थान व डाकघर-मुंगी,
तहसील-शेवगांव
जिला-अहमदनगर-414503
140. यूको बैंक,
मेहदी हाउस,
ग्राम-वैजनाथ,
तालुका-कर्जल,
जिला-रायगड
131. यूको बैंक,
कान्होली बारा शाखा,
तालुका-होंगणा,
जिला-नागपुर-441110
132. यूको बैंक,
यशवन्त अपार्टमेंट्स;
सी.टी.एस. नं. 1032
पेट्रोल पम्प के सामने,

141. यूको बैंक,
गांधी-नगरधन,
डाकघर-रतनलाल जगन्नाथ जयसवाल भवन,
जिला-नागपुर-441106
142. यूको बैंक,
राहु शाखा,
नैन स्थानक संघ,
मकान नं. 337,
स्थान एवं डाकघर-राहु,
तहसील-दौण्ड,
जिला-पुणे-412207
143. यूको बैंक,
सर्वेक्षण सं. 1/1,
कोथरुड डाकघर के निकट,
कोथरुड,
पुणे-411029
144. यूको बैंक,
निम्बा सवा सहकारी सोसायटी,
तहसील-ब.वा.पुर,
जिला-अकोला
145. यूको बैंक,
यशोधन अपार्टमेंट,
जयप्रकाश रोड, चार बंगला,
अंधेरी (पश्चिम)
मुम्बई-400058
146. यूको बैंक,
354, अब्दुल रहमान स्ट्रीट,
मुम्बई-400008
147. यूको बैंक,
पाईपवाला बिल्डिंग,
62, कोलाबा रोड,
मुम्बई-400005
148. यूको बैंक,
पूज शिकारपुर पंचायत,
मर्वोदथ सोसायटी,
(गोल्फ क्लब के पास)
प्लॉट नं. 112 और 113
चैम्बूर कालोनी, चैम्बूर,
मुम्बई-400074
149. यूको बैंक,
गोरेगांव शाखा "शिल्पांजलि"
सर्वे सं. 411-एच.एस.वी. रोड,
गोरेगांव (पश्चिम)
मुम्बई-400082
150. यूको बैंक,
"अलंकार" 187 बलराम स्ट्रीट,
ग्रॉफ ग्रांट रोड,
मुम्बई-400007
151. यूको बैंक,
जय अपार्टमेंट,
डी.पी. रोड एवं एम.जी. रोड जंक्शन,
कान्दीवली (पश्चिम),
मुम्बई-400067
152. यूको बैंक,
कांशी ब्रिज, निचली मंजिल,
एस.जी. रोड, मलाड (पश्चिम)
मुम्बई-400064
153. यूको बैंक,
लक्ष्मी हाउस, फ्लैट सं. 1,
निचली मंजिल,
84, लेडी हार्डिंग रोड,
मादुगा (पश्चिम रेलवे)
मुम्बई-400016
154. यूको बैंक,
मुलुंड शाखा,
आणंदी विला, ए. ब्याक,
गणेश गावडे रोड,
मुलुंड (पश्चिम)
मुम्बई-400080
155. यूको बैंक,
गीतम अपार्टमेंट,
72, पाली हिल,
बान्द्रा, मुम्बई
156. यूको बैंक,
"विमल" 184 खेतवाडी मेन रोड,
मुम्बई-400004
157. यूको बैंक,
मुम्बई फिजिकल कल्चर एसो. स्टेडियम,
भारतीय ग्रीष्म मंदिर,
नायगाव,
मुम्बई-400031
158. यूको बैंक,
विले पार्ले (पूर्व) शाखा,
जसोदा निवास,
विले पार्ले (पूर्व)
मुम्बई-400057
159. यूको बैंक,
बोरीवली (पश्चिम) शाखा,
गणपति अपार्टमेंट, लोकमान्य तिलक रोड,
बोरीवली (पश्चिम)
मुम्बई-400092
160. यूको बैंक,
श्रीरंग हाउसिंग सोसायटी,
गोपिग सेंटर, कासल मिल के पास,
ठाणे पश्चिम (सैन्ट्रल रेलवे)

161. यूको बैंक,
जुहु विले पार्ले शाखा,
अल नेमत भवन,
प्लॉट सं. 3/21,
जुहु विले पार्ले विकास योजना,
जुहु रोड, विले पार्ले (पश्चिम)
मुम्बई-400056

162. यूको बैंक,
अजीम मंजील,
308, कोटना गेट,
भिवंडी, जिला-ठाणे

163. यूको बैंक,
मैसर्स मेघना कारपोरेशन,
जी : 4 लीसा अपार्टमेंट्स,
मरोल मरोती रोड,
फायर ब्रिगेड के पास,
अंधेरी (पूर्व)
मुम्बई-400059

164. यूको बैंक,
बिल्डिंग नं. डी, मिस्कीटा नगर,
दहीसर (पूर्व)
मुम्बई-400068

165. यूको बैंक,
51, मुकुन्द नगर,
किलोसकर प्रेस के सामने,
मैसर्स बोरा ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग,
पुणे-411037

166. यूको बैंक,
त्रिमूर्ति टावर्स,
मामलातदार बाडी,
एस. बी. रोड,
मलाड पश्चिम,
मुम्बई-400084

167. यूको बैंक,
सेमगिरि सदन,
171, गिरगांव रोड,
मुम्बई-400004

168. यूको बैंक,
वैरावली (पूर्व) शाखा,
न्यू राजेन्द्र नगर,
(तालुपवाडी)

169. यूको बैंक,
सांडू गार्डन, चेंम्बूर शाखा,
चेंम्बूर डाकघर के नजदीक,
10वां रास्ता, चेम्बूर,
मुम्बई-400071

चंडीगढ़

170. यू को बैंक,
नंदी कालोनी, खस्रा
जिला-लुधियाना,
पिन-141026

171. यूको बैंक,
गांव व डाकखाना-सुजापुर,
जिला लुधियाना
पिन-142026

172. यूको बैंक,
गांव व डाकखाना-संघोल,
जिला-लुधियाना,
पिन-140302

173. यूको बैंक,
गांव व डाकखाना-रूमो,
बाया जगरांव,
जिला-लुधियाना

174. यूको बैंक,
गांव व डाकखाना-रौनी,
जिला-लुधियाना,
पिन-141415

175. यूको बैंक,
गांव व डाकखाना-रसूलपुर,
जिला -लुधियाना,
पिन-141035

176. यूको बैंक,
गांव व डाकखाना --रायपुर माजरी,
बाया खस्रा,
जिला-लुधियाना

177. यूको बैंक,
गांव व डाकखाना--भांघट
जिला -लुधियाना

178. यूको बैंक,
गांव व डाकखाना--झोरणा,
तहसील--जगरांव,
जिला--लुधियाना

179. यूको बैंक,
डाकघर--नेताजी नगर, सलीम टावरी
नई अनाज मण्डी,
लुधियाना

180. यूको बैंक,
म्युनिसिपल कमेटी,
जिला--लुधियाना

181. यूको बैंक,
पी० बी० 86, जी० टी० रोड,
मिलरंगज, लुधियाना,
जिला--लुधियाना

182. यूको बैंक,
दयानन्द मेडिकल कालेज,
एवं अस्पताल,
लुधियाना,
जिला—लुधियाना
183. यूको बैंक,
गांव व डाकखाना,—लालतों कलां,
जिला—लुधियाना,
पिन—141022
184. यूको बैंक,
गांव व डाकखाना,—कोहारा,
जिला—लुधियाना,
पिन—141112
185. यूको बैंक,
जुगियाना,
जिला—लुधियाना,
पिन—141120
186. यूको बैंक,
गांव व डाकखाना—घुरानी कलां,
जिला—लुधियाना
187. यूको बैंक,
गांव व डाकखाना—भुण्डरी,
तहसील—जगरांव,
जिला—लुधियाना
188. यूको बैंक,
गांव व डाकखाना—अयाली कलां
जिला—लुधियाना,
189. यूको बैंक,
दशमेश नगर, गली नं० 17,
गिल रोड, लुधियाना,
(आलमगीर) लुधियाना
190. यूको बैंक,
इंडस्ट्रीयल एरिया,
सरहिन्द रोड,
पटियाला—147001
191. यूको बैंक,
गांव व डाकखाना—झुम्बा,
जिला—भटिण्डा
192. यूको बैंक,
पोस्ट बाक्स नं० 2
प्रताप रोड, मोगा,
फरीदकोट
193. यूको बैंक,
डाकखाना—सिंह भगवन्तपुरा,
रोपड़
194. यूको बैंक,
पुल बाजार,
रोपड़
195. यूको बैंक,
गांव व डाकखाना—पुरखाली,
जिला—रोपड़
196. यूको बैंक,
आर०टी०पी० कम्पलेक्स,
नूहों,
(रोपड़)
197. यूको बैंक,
गांव—उयागांव,
डाकखाना—सक्रेटेरियट,
चण्डीगढ़
198. यूको बैंक,
डाकखाना—खिजराबाद,
जिला—रोपड़
पिन—140109
199. यूको बैंक,
जवाहर मार्केट,
प्रताप रोड,
तंगल
200. यूको बैंक,
गांव—डुमेवाल,
डाकखाना—जाजर,
वाया नूरपुर बेदी
201. यूको बैंक,
गांव व डाकखाना—भलां,
तहसील—आनन्दपुर साहिब
202. यूको बैंक,
गांव व डाकखाना—कालड़ा,
जिला—जालन्धर
203. यूको बैंक,
कपूरथला,
(पंजाब)
204. यूको बैंक,
भागवत कैम्प,
नकोदर रोड,
जालन्धर
205. यूको बैंक,
इन्डस्ट्रीयल एरिया,
जालन्धर शहर
206. यूको बैंक,
गुड़ मण्डी,
नजदीक बांसा बाजार,
जालन्धर

207. यूको बैंक,
अट्टा गोरया,
गोराया
208. यूको बैंक,
गांव व डाकखाना—भोलथ,
जिला—कपूरथला
209. यूको बैंक
रेलवे रोड,
पठानकोट,
जिला—गुरदासपुर
210. यूको बैंक,
गांव व डाकखाना—भैनी
जिला—गुरदासपुर
211. यूको बैंक,
जी० टी० रोड, बटाला,
जिला—गुरदासपुर,
212. यूको बैंक,
गांव व डाकखाना—बेरोवाल
तहसील—तरनतारन,
जिला—अमृतसर
213. यूको बैंक,
जी० टी० रोड,
छहरेटा
214. यूको बैंक,
राम बाग,
अमृतसर
215. यूको बैंक,
सिविल लाईन्स,
पोस्ट बाक्स नं० 74,
जिला—अमृतसर
216. यूको बैंक,
कटड़ा आहलूवालिया,
पोस्ट बाक्स 45,
अमृतसर
217. यूको बैंक,
रणजीतगढ़,
नूरमहल रोड,
डाकखाना-फिलौर,
जिला—जालन्धर
218. यूको बैंक,
गांव व डाकखाना—प्रतापपुरा,
जिला—जालंधर
219. यूको बैंक,
इन्डस्ट्रियल एरिया,
नवांशहर,
जिला—जालन्धर
पिन—144514
220. यूको बैंक,
ग्रेन मार्किट,
नकोदर,
जिला—जालन्धर
221. यूको बैंक,
गांव व डाकखाना—लमूड़ी,
जिला—जालन्धर
222. यूको बैंक,
गांव व डाकखाना—कोहाला,
जिला—जालन्धर
223. यूको बैंक,
क्षेत्रीय कार्यालय,
पंजाब (चण्डीगढ़)
सेक्टर 17-बी,
चण्डीगढ़
उत्तर प्रदेश
224. यूको बैंक,
“मरजू विलास”
ओक्डेनगंज,
बलिया—277001
225. यूको बैंक,
रेस कोर्स,
61/2, रेस कोर्स,
देहरादून
मध्य प्रदेश
226. यूको बैंक,
डाकघर—कृष्ण नगर,
जिला—रायपुर,
पिन—492012
227. यूको बैंक,
डाकघर—नेवरा प्रोजेक्ट,
जिला—बिलासपुर,
पिन—495452
बिहार
228. यूको बैंक,
अंचल कार्यालय,
मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स,
ब्लाक “ए”, चतुर्थ तल,
न्यू डाक बंगला रोड,
पटना—800001
229. यूको बैंक,
क्षेत्रीय कार्यालय, पटना II
147 बी, आर्य कुमार रोड,
राजेन्द्र नगर,
पिन—800016

बिहार—जारी

230. यूको बैंक,
चकार्ई,
पुलिस स्टेशन के सामने,
डाकघर—चकार्ई,
जिला—जमुई
231. यूको बैंक,
सासाराम,
आनंदी बाजार,
सासाराम,
जिला—रोहतास
232. यूको बैंक,
क्लब रोड, मुजफ्फरपुर,
मुजफ्फरपुर,
पिन—842001
233. यूको बैंक,
बेगूसराय,
पो०बा० नं० 28,
मारवाडी मोहल्ला,
जिला—बेगूसराय,
पिन—851101
234. यूको बैंक,
लाभगांव,
गांव व डाकघर—लाभगांव
जिला—खगड़िया,
पिन—851204
235. यूको बैंक,
मंसूरचक,
गांव व डाकघर—मंसूरचक,
जिला—बेगूसराय ।
236. यूको बैंक,
मानिकपुर,
गांव—मानिकपुर,
डाकघर—रहिकपुर थिला,
जिला—अररिया ।
237. यूको बैंक,
सदानंदपुर,
गांव व डाकघर—सदानंदपुर,
जिला—बेगूसराय,
पिन—851101
238. यूको बैंक,
सहरसा,
महादेव ट्रेडिंग कंपनी के ऊपर,
धर्मशाला रोड,
सहरसा ।
239. यूको बैंक,
एक्विब्रिशन रोड,
पटना—800001

बिहार—जारी

240. यूको बैंक,
राजेन्द्र मार्केट,
बिस्कोमान कोल डिपो के पास,
कंकड़बाग,
पटना—800020
241. यूको बैंक,
पार्टलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया,
अल्पना मार्केट,
पार्टलिपुत्र,
पटना—800013
242. यूको बैंक,
बहादुरपुर शाखा,
गांव व डाकघर—बहादुरपुर
बिहार स्पन सिल्क मिल के साथ
जिला—भागलपुर (बिहार),
पिन—840001
243. यूको बैंक,
बांका शाखा,
दोलानिया मार्केट,
पोस्ट—बांका
जिला—बांका (बिहार)
244. यूको बैंक,
बेलडिहा शाखा,
गांव—बेलडिहा,
डाकघर—अहिरो,
वाया—घोघा,
जिला—बांका (बिहार),
पिन—813205
245. यूको बैंक,
बेलहर शाखा,
स्थान व डाकघर—बेलहर
जिला—बांका (बिहार)
पिन—813202
246. यूको बैंक,
भागलपुर (मुख्य) शाखा,
किशोरपुरिया मार्केट,
पहला तल्ला,
डी०एन० सिंह रोड,
भागलपुर (बिहार),
पिन—812002
247. यूको बैंक,
भागलपुर गोरहट्टा चौक शाखा,
शिवगौरी फ्लोर मिन कंटाउंड,
गोरहट्टा चौक,
भागलपुर (बिहार),
पिन—812202

बिहार—जारी

248. यूको बैंक,
तिलक मांझी शाखा,
सेंट्रल जेल रोड,
तिलक मांझी चौक,
भागलपुर (बिहार),
पिन-812001
249. यूको बैंक,
भनरा शाखा,
ग्राम-भनरा,
डाकघर-चांदन,
जिला-बांका (बिहार),
पिन-814131
250. यूको बैंक,
धोआवे शाखा,
गांव व डाकघर-धोआवे,
जिला-भागलपुर (बिहार)
251. यूको बैंक,
डुमरवां शाखा,
गांव व डाकघर-डुमरवां
जिला-बांका (बिहार)
पिन-813701
252. यूको बैंक,
फतेहपुर शाखा,
इंजीनियरिंग कालेज कैम्पस,
डाकघर-फतेहपुर,
जिला-भागलपुर (बिहार),
पिन-813233
253. यूको बैंक,
गंगानिया शाखा,
गांव व डाकघर-गंगानिया,
जिला-भागलपुर (बिहार)
254. यूको बैंक,
गोराडीह शाखा,
गांव व डाकघर-गोराडीह
बाया-सबौर
जिला-भागलपुर (बिहार),
पिन-813210
255. यूको बैंक,
जगदीशपुर शाखा,
डाकघर-जगदीशपुर,
जिला-भागलपुर (बिहार),
पिन-813105
256. यूको बैंक,
जयपुर शाखा,
गांव व डाकघर-जयपुर,
जिला-बांका (बिहार),
पिन-814112

बिहार—जारी

257. यूको बैंक,
जावरा शाखा,
गांव व डाकघर-जावरा,
जिला-बांका (बिहार)
258. यूको बैंक
करहरिया शाखा,
गांव व डाकघर-करहरिया
बाया-मुलतानगंज
जिला-भागलपुर (बिहार)
पिन-813213
259. यूको बैंक
कटियागा शाखा,
गांव-कटियागा,
डाकघर-साला,
जिला-बांका (बिहार)
पिन-813105
260. यूको बैंक,
कटोरिया शाखा,
गांव व डाकघर-कटोरिया
जिला-बांका (बिहार)
पिन-813106
261. यूको बैंक
येसर शाखा
गांव व डाकघर-येसर,
जिला-बांका (बिहार)
पिन-813207
262. यूको बैंक,
नारायणपुर शाखा
गांव व डाकघर-नारायणपुर
जिला-भागलपुर (बिहार)
पिन-853203
263. यूको बैंक,
रतनपुर (रतनगंज) शाखा,
गांव-रतनपुर (रतनगंज)
डाकघर-कुल्डीहा
जिला-भागलपुर (बिहार)
पिन-812006
264. यूको बैंक,
सबौर शाखा,
बिहार एग्रि. कालेज कैम्पस,
डाकघर-सबौर
जिला-भागलपुर (बिहार)
पिन-813210
265. यूको बैंक,
साहेबगंज शाखा,
गांव व डाकघर-मथुरा
साहेबगंज
जिला-बांका (बिहार)
पिन-813202

266. यूको बैंक,
संहीला शाखा,
गांव व डाकघर—संहीला
जिला—भागलपुर (बिहार)
पिन—813225
267. यूको बैंक,
सूइया शाखा,
गांव व डाकघर—सूइया,
जिला—बांका (बिहार)
पिन—813106
268. यूको बैंक,
सुल्तानगंज शाखा,
गांव व डाकघर—सुल्तानगंज
जिला—भागलपुर (बिहार)
पिन—813213
269. यूको बैंक,
तुलसीपुर जगुनिया शाखा,
गांव व डाकघर—तुलसीपुर जगुनिया
वाया—नौगछिया
जिला—भागलपुर (बिहार)
पिन—853202
270. यूको बैंक,
विजयगढ़ शाखा,
वाया—पुनसिया
जिला—बांका (बिहार)
पिन—813102
271. यूको बैंक,
क्षेत्रीय कार्यालय,
सेंट्रल जोन रोड,
जवाईपुर,
तिलकामांझी रोड,
भागलपुर (बिहार)
272. यूको बैंक,
अग्रणी बैंक कार्यालय,
सुखराज राय रोड,
भागलपुर (बिहार)
पिन—812001
273. यूको बैंक,
बरियारपुर
स्टेशन रोड, डाकघर के नजदीक
डाकघर—बरियारपुर
जिला—मुंगेर
पिन—813211
274. यूको बैंक
तारापुर
सुल्तानगंज बेलहर रोड
डाकघर—तारापुर
जिला—मुंगेर
पिन—813221
275. यूको बैंक,
गिद्धौर,
डाकघर—गिद्धौर
वाया मांझा
जिला—जमुई
पिन—811305
276. यूको बैंक,
मांझा, जे.सी. शॉ रोड,
डाकघर मांझा
जिला—जमुई
पिन—811308
277. यूको बैंक,
वक्सर
वाया कॉम्प्लेक्स, आमला टोली
डाकघर व जिला—वक्सर,
पिन—802101
278. यूको बैंक,
बेतिया शरण सदन,
कविश्वर नेपाली पथ,
डाकघर—बेतिया
जिला—पश्चिम चंपारण
पिन—845438
279. यूको बैंक,
हाजीपुर,
सोनी अलंकार कॉम्प्लेक्स,
गुदडी रोड, हाजीपुर,
डाकघर—जहाजीपुर, जिला वैशाली;
पिन—844101
280. यूको बैंक,
अग्रणी बैंक कार्यालय,
मुंगेर, बेकापुर मुंगेर
पिन—811201
281. यूको बैंक,
अग्रणी बैंक कार्यालय,
जमुई,
डाकघर—जमुई,
जिला—जमुई
पिन—811307
282. यूको बैंक;
अग्रणी बैंक कार्यालय;
खगड़िया;
एस डी ओ रोड, खगड़िया
पिन—851204
283. यूको बैंक;
अग्रणी बैंक कार्यालय;
बेगूसराय;
कपासिया चौक,
आई ओ सी, टाउनशिप,
बेगूसराय

284. यूको बैंक,
कोचाधामन,
डाकघर-कोचाधामन,
वाया-सोंधा
जिला-किशनगंज,
पिन-855115

285. यूको बैंक,
महना,
डाकघर-महना,
जिला-बेगूसराय

286. यूको बैंक,
आई ओ सी टाउनशिप,
कपासिया चौक,
डाकघर-रिफाइनरी टाउनशिप
जिला-बेगूसराय

287. यूको बैंक,
अकोरा डाकघर-आकोपुर
वाया-मंझोल,
जिला-बेगूसराय
पिन-848202

288. यूको बैंक,
साकची,
6, ठाकुरवाडी रोड,
जमशेदपुर,
पिन-831001

289. यूको बैंक,
गुमला थाना रोड,
डाकघर-गुमला
जिला-रांची
पिन-835207

290. यूको बैंक,
मेसरा,
बिडला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी,
मेन बिल्डिंग,
मेसरा, रांची,
पिन-835215

291. यूको बैंक,
गया
(पोस्ट बाक्स-8)
हिगुआ मार्केट,
गौतम बुद्ध रोड, गया,
पिन-833001

292. यूको बैंक,
भानगो,
इकबाल चैम्बर,
पुरुलिया हाईवे,
भानगो, जमशेदपुर,
पिन-831012

294. यूको बैंक,
क्षेत्रीय कार्यालय,
जे एंड के डिवीजन कैम्प,
हाउस नं. 33, सेक्टर 5 ए
त्रिकुट नगर
जम्मू-180004
(जम्मू और कश्मीर)

294. यूको बैंक,
कटरा शाखा,
गांव व डाकघर-कटरा
वैष्णव देवी
जिला-ऊधमपुर
(जम्मू और कश्मीर)
पिन-182301

नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचना

1. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. अचलपुर कैप,
जिला: अमरावती,
महाराष्ट्र

2. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. अकोला,
कपड़ा बाजार के पास,
जिला अकोला,
महाराष्ट्र

3. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. अमरावती,
श्याम चौक,
जिला : अमरावती,
(महाराष्ट्र)

4. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. अन्दोरी,
तहसील : देवली,
जिला: वर्धा
(महाराष्ट्र)

5. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. बल्लारपुर,
जिला : चन्द्रपुर
(महाराष्ट्र)

6. पंजाब नेशनल बैंक,
भुसावल,
बालाजी गली,
जिला : जलगांव,
(महाराष्ट्र)
7. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. चन्द्रपुर,
मेन रोड,
जिला : चन्द्रपुर,
(महाराष्ट्र)
8. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. गोंदिया,
फूलचुर रोड, गुरुनानक गेट,
जिला : भंडारा,
(महाराष्ट्र)
9. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. हिंगण घाट,
जिला : वर्धा,
(महाराष्ट्र)
10. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. जलगांव
नवीपेठ, एम.जी. रोड,
जिला : जलगांव,
(महाराष्ट्र)
11. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. कापसी (बु.)
पो. भांडेवाडी (पारडी)
तहसील कामठी,
जिला : नागपुर,
(महाराष्ट्र)
12. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. खामगांव,
जिला : बुलढाना,
(महाराष्ट्र)
13. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. नांदेड़,
ओल्ड मोश्रा,
जिला : नांदेड़,
(महाराष्ट्र)
14. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. पुसद,
मेन रोड,
जिला : यवतमाल,
(महाराष्ट्र)
15. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. साटक,
तहसील पार सिवनी,
जिला : नागपुर,
(महाराष्ट्र)
16. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. सावदा,
जिला : जलगांव,
(महाराष्ट्र)
17. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. तलेगांव,
ब्लाक उमरी,
जिला : नांदेड़
(महाराष्ट्र)
18. पंजाब नेशनल बैंक,
यवतमाल,
मेन रोड,
जिला : यवतमाल
(महाराष्ट्र)
19. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. भरतनगर, नागपुर
जिला : नागपुर,
(महाराष्ट्र)
20. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का.सी.ए. रोड,
नागपुर, 44, सैन्ट्रल एवन्स,
जिला : नागपुर,
(महाराष्ट्र)
21. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. धरमपेठ, नागपुर,
कोठारी सवन, वेस्ट हार्ड कोर्ट रोड,
जिला : नागपुर
(महाराष्ट्र)
22. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. गांधी बाग, नाग
सेवा सवन, सी.ए. रोड,
जिला : नागपुर
(महाराष्ट्र)
23. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. हनुमान नगर, नागपुर,
मैडिकल कालेज चौक,
जिला : नागपुर
(महाराष्ट्र)
24. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. इंदोरा चौक, नागपुर,
जिला : नागपुर,
(महाराष्ट्र)

25. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. किरजवे, नागपुर,
पी एन बी हाउस नागपुर,
जिला नागपुर
(महाराष्ट्र)
26. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. खामला नागपुर
जिला नागपुर,
(महाराष्ट्र)
27. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. कान्हान,
तहसील कामठी,
जिला नागपुर,
(महाराष्ट्र)
28. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. लकड़गंज नागपुर
जिला नागपुर
(महाराष्ट्र)
29. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. एम.आर्च.डी.सी.,
नागपुर, हिंगणा रोड,
जिला नागपुर (महाराष्ट्र)
30. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. पाटनी भवन नागपुर,
गांधी बाग, जिला नागपुर,
(महाराष्ट्र)
31. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. सीता बर्डी नागपुर,
जिला : नागपुर (महाराष्ट्र)
32. पंजाब नेशनल बैंक,
संपर्क कक्ष,
सूरज सदन, गांधीबाग,
नागपुर,
जिला नागपुर
(महाराष्ट्र)
33. पंजाब नेशनल बैंक,
क्षेत्रीय वसूली केन्द्र,
सीताबर्डी, नागपुर,
जिला : नागपुर,
(महाराष्ट्र)
34. पंजाब नेशनल बैंक,
अंचल लेखन सामग्री केन्द्र
रामदास पेठ, जिला नागपुर
(महाराष्ट्र)
35. पंजाब नेशनल बैंक,
अंचल प्रशिक्षण केन्द्र,
तिलक रोड, साँ कालेज चौक
नागपुर
(महाराष्ट्र)
36. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का.के.एस. राव रोड,
मंगलूर
37. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. मुल्तान पुर रोड,
जिला कपूरथला
पंजाब
38. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. काला संधियां,
जिला कपूरथला,
पंजाब
39. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. दीपावाली,
मुल्तानपुर लोधी कपूरथला,
पंजाब
40. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. दिल्लीवां,
तहसील : भूलस्थ
जिला कपूरथला
पंजाब
41. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. रेलवे रोड, फगवाड़ा
जिला : कपूरथला,
पंजाब
42. पंजाब नेशनल बैंक
शा.का. टाण्डा रोड, बेगोवाल
भूलस्थ
जिला : कपूरथला,
पंजाब
43. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. भण्डाल बेट,
कपूरथला,
जिला कपूरथला,
पंजाब
44. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. मानेक बाहेद
फगवाड़ा,
जिला : कपूरथला,
पंजाब

45. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. रामगढ़, भुलत्थ,
जिला : कपूरथला
पंजाब
46. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. सिद्धाणा दोनों
कपूरथला पंजाब
47. पंजाब नेशनल बैंक,
अग्रणी बैंक जिला प्रबन्धक,
कपूरथला,
पंजाब
48. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. श्रीलख, बटाला,
जिला गुरदासपुर,
पंजाब
49. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. हनुमान चौक,
गुरदासपुर,
पंजाब ।
50. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. डेहरीवाल,
बटाला, गुरदासपुर
पंजाब
51. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. धारीवाल-बटाला रोड,
तहसील बटाला,
जिला : गुरदासपुर पंजाब
52. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. धौरांगला, गुरदासपुर
जिला गुरदासपुर,
पंजाब
53. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. मोहन मार्किट,
पठानकोट,
जिला : गुरदासपुर, पंजाब
54. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. पंडोरी बीसां,
जिला : गुरदासपुर, पंजाब
55. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. प्रेम नगर, बटाला
जिला : गुरदासपुर, पंजाब
56. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. माडी बुच्चियां
बटाला; गुरदासपुर
पंजाब
57. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. मामून कैंट,
पठानकोट, गुरदासपुर,
पंजाब
58. पंजाब नेशनल बैंक,
अग्रणी बैंक जिला प्रबन्धक
गुरदासपुर, पंजाब
59. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. बस्ती दानिशमंदां
जालंधर, पंजाब
60. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. फोकल प्वाइंट,
जालंधर, पंजाब
61. पंजाब नेशनल बैंक,
अंतर्राष्ट्रीय कारोबार शाखा,
जालंधर, पंजाब
62. पंजाब नेशनल बैंक,
विशेष लघु उद्योग शाखा,
जालंधर, पंजाब
63. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. भौड़,
जालंधर, पंजाब
64. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. नूरमहल,
जालंधर, पंजाब
65. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. फराला,
जालंधर, पंजाब
66. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. सरीह,
जालंधर, पंजाब
67. पंजाब नेशनल बैंक,
क्षेत्रीय बसूली केन्द्र,
जालंधर, पंजाब
68. पंजाब नेशनल बैंक,
प्रचल लेखन सामग्री केन्द्र,
जालंधर, पंजाब
69. पंजाब नेशनल बैंक,
बि.प. गुलाब देवी अस्पताल,
जालंधर, पंजाब
70. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. कन्या महाविद्यालय,
जालंधर, पंजाब

71. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. नकोवर रोड,
जालन्धर, पंजाब
72. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. पुरानी रेलवे रोड,
जालन्धर, पंजाब
73. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. भलावलपुर
जालन्धर, पंजाब
74. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. बलाचौर,
जालन्धर, पंजाब
75. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. बंगा-दाना मण्डी,
जालन्धर, पंजाब
76. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. बहलूर कलां,
जालन्धर, पंजाब
77. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. भटनूरा जाखिया,
जालन्धर, पंजाब
78. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. गोराया भट्टा,
जालन्धर, पंजाब
79. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. जाडला,
जालन्धर, पंजाब
80. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. जंझियाला,
जालन्धर, पंजाब
81. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. करतारपुर-जी.टी. रोड,
जालन्धर, पंजाब
82. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. लंगड़ोघा,
जालन्धर, पंजाब
83. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. मक्खूपुर
जालन्धर, पंजाब
84. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. माहल गेहूला
जालन्धर, पंजाब
85. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. मुकन्तपुर,
जालन्धर, पंजाब
86. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. नकोवर,
भड्डा मेहतपुर,
जालन्धर, पंजाब
87. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. नवां शहर,
रेलवे रोड,
जालन्धर, पंजाब
88. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. नूरमहल,
अनाज मंडी,
जालन्धर, पंजाब
89. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. पोजेवाल,
जालन्धर, पंजाब
90. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. फिल्लौर-अनाज मण्डी,
जालन्धर, पंजाब
91. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. राहों मेन बाजार,
जालन्धर, पंजाब
92. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. रैल माजरा,
जालन्धर, पंजाब
93. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. सड़ोघा,
जालन्धर, पंजाब
94. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. तलवण्डी माधो,
जालन्धर, पंजाब
95. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. उड़ापड़
जालन्धर, पंजाब ।
96. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का., जी.टी. रोड,
जालन्धर, पंजाब
97. पंजाब नेशनल बैंक;
वि.प.: हंसराज महिला महाविद्यालय;
जालन्धर, पंजाब
98. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. लीडर इंजीनियरिंग,
जालन्धर, पंजाब
99. पंजाब नेशनल बैंक,
अग्रण्डी बैंक कार्यालय,
नवां शहर,
जालन्धर, पंजाब

100. पंजाब नेशनल बैंक,
शा.का. जैहर,
ब्लाक कछड,
जिला श्रीरंगवादा
महाराष्ट्र
101. पंजाब नेशनल बैंक,
शाखा कार्यालय जवण,
पोस्ट पोणानगर,
तालुका मावल, जिला पुणे;
महाराष्ट्र ।
102. पंजाब नेशनल बैंक,
शाखा कुंभाले, तालुका पेठ,
जिला-नासिक, महाराष्ट्र ।
103. पंजाब नेशनल बैंक,
शाखा कसया, जिला कुशीनगर,
उत्तर प्रदेश ।
104. पंजाब नेशनल बैंक,
निथनोल शाखा,
जिला महाराज गंज,
उत्तर प्रदेश ।
105. पंजाब नेशनल बैंक,
शाखा-नौतनवां,
273/164, मेन रोड,
नौतनवां, जिला-महाराजगंज,
उत्तर प्रदेश ।
106. पंजाब नेशनल बैंक,
शाखा-रामकोला
जिला-कुशीनगर,
उत्तर प्रदेश ।
107. पंजाब नेशनल बैंक
शाखा, थाना भवन,
जिला-मुजफ्फरनगर,
उत्तर प्रदेश
108. पंजाब नेशनल बैंक,
शाखा-सैटेलाइट
आशापुरा काम्प्लेक्स,
प्रियमल हाऊस के पास,
अहमदाबाद
109. पंजाब नेशनल बैंक,
अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग शाखा,
नीलकमल बिल्डिंग,]
आश्रम रोड, अहमदाबाद
110. पंजाब नेशनल बैंक,
शाखा डोम्बिवली,
शंकर स्मृति अनेक्स,
सुभाष रोड, विष्णुनगर,
डोम्बिवली(प) 421202
111. पंजाब नेशनल बैंक,
शाखा कांदीवली (प),
ठाकुर हाउस, पहला माला,
कुर्ली रोड के सामने,
कांदीवली (प), मुम्बई-400101
112. पंजाब नेशनल बैंक,
शाखा मापसा, गोवा,
बापसीन रेसीडेन्सी,
सिविल रजिस्टर्ड कार्यालय के सामने,
अन्साभाट, मापसा,
गोवा-403507 ।
1. आन्ध्रा बैंक
ए-1, I एवेन्यू,
सेन्थिल टॉवर्स,
अशोक नगर
चेन्नै
तमिलनाडु—600003
2. आन्ध्रा बैंक
प्लॉट नंबर 42,
डां. ए. रामस्वामी रोड
के. के. नगर
चेन्नै
तमिलनाडु-600078
3. आन्ध्रा बैंक
12-22-43/1
सीतमपेटा, काथुरा रोड
अर्यापुरम
राजमंड़ी
पिन-533104
4. आन्ध्रा बैंक
मेन रोड, दुर्गा थेंटर के पास
धवलेश्वरम
राजमंड़ी
पिन-533 104
5. आन्ध्रा बैंक
डोर नंबर 4-6-14
रेलवे स्टेशन रोड]
अलकाट मार्डेंस
राजमंड़ी
पिन-533 104
6. आन्ध्रा बैंक
मेन रोड
मल्लिकपुरम
राजोल तालुक
पूर्वी गोदावरी जिला
आन्ध्रा प्रदेश
पिन-533 253

7. आन्ध्रा बैंक
केशववामुपालेम
राजोल मंडल
पूर्वी गोदावरी जिला
आन्ध्र प्रदेश
पिन-533 252
8. आन्ध्रा बैंक
13-104
प्रकाशनगर
राजमंड्री
पूर्वी गोदावरी जिला
आन्ध्र प्रदेश
पिन-533 103
9. आन्ध्र बैंक
3-119, जी टी रोड
जेड, रंगमपेट
जगमपेट पोस्ट
पूर्वी गोदावरी जिला
आन्ध्र प्रदेश
पिन-533 435
10. आन्ध्रा बैंक
काट्टेबुलपल्ली
जगमपेट मंडल
पूर्वी गोदावरी जिला
आन्ध्र प्रदेश
11. आन्ध्रा बैंक
7/11-13-6
फोर्ट गेट सेंटर
राजमंड्री
आन्ध्र प्रदेश
पिन-533 101
12. आन्ध्रा बैंक
29-14-6, लक्ष्मीनारपुपेट
देवी चौक
राजमंड्री
आन्ध्रा प्रदेश
पिन-533 104
13. आन्ध्रा बैंक
46-7-33, मेन रोड
दानबाईपेट
राजमंड्री
आन्ध्र प्रदेश
पिन-533 103
14. आन्ध्रा बैंक
18-278, ए वी मुन्नाराव रोड
कटारीनगर
राजमंड्री
आन्ध्र प्रदेश
पिन-533 103
15. आन्ध्रा बैंक
गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स अस्पताल
नं. 4 लालाचेरुडु
राजमंड्री
आन्ध्रा प्रदेश
16. आन्ध्रा बैंक
4-50 मेन रोड
अंबीजीपेट
अमलापुरम तालुक
पूर्वी गोदावरी जिला
आन्ध्र प्रदेश
पिन-533 214
17. आन्ध्र बैंक
3-134 चलापल्लीवारी स्ट्रीट
कडियम
राजमंड्री तालुक
पूर्वी गोदावरी जिला
आन्ध्र प्रदेश
पिन-533 126
18. आन्ध्रा बैंक
3-46 संरुपायना राजा स्ट्रीट
सुगंडा
पूर्वी गोदावरी जिला
आन्ध्र प्रदेश
पिन-533 524
19. आन्ध्रा बैंक
मेन रोड
पी. गन्नवरम
गन्नवरम मंडल
पूर्वी गोदावरी जिला
आन्ध्र प्रदेश
पिन-533 248
20. आन्ध्रा बैंक
4-157/ए बापुजी रोड
राजोल
पूर्वी गोदावरी जिला
आन्ध्र प्रदेश
पिन-533 242

21. आन्ध्रा बैंक
पश्चिम गोतगुडेम
कोरुकोडा तालुक
पूर्वी गोदावरी जिला
आन्ध्र प्रदेश
पिन—533 289
22. आन्ध्रा बैंक
सीतानगरम
विजयनगरम जिला
पिन—535 546
आन्ध्र प्रदेश
23. आन्ध्रा बैंक
एस यू कैपस
क्वार्टर सं. 3/18
एस यू प्रोफेसर क्वार्टर्स
विशाखापट्टणम
पिन—530 003
24. आन्ध्रा बैंक
मेन रोड
गोनेडा
पेद्दपुरम तालुक
पूर्वी गोदावरी जिला
आन्ध्र प्रदेश
पिन—533 437
25. आन्ध्रा बैंक
12-8-1 मेन रोड,
मंडपेट
पूर्वी गोदावरी जिला
आन्ध्र प्रदेश
पिन—533 308
26. आन्ध्रा बैंक
1-481, मेन रोड
डारपुडि
अलसूरु तालुक
पूर्वी गोदावरी जिला
आन्ध्र प्रदेश
पिन—533 341
27. आन्ध्रा बैंक
5/30, मेन रोड
बेलंगी
काकिनाडा तालुक
पूर्वी गोदावरी जिला
आन्ध्र प्रदेश
पिन—533 260
28. आन्ध्रा बैंक
डोर नंबर 2-3
सिरिगिदलपाडु
- रंपाचोदवरम पोस्ट
पूर्वी गोदावरी जिला
आन्ध्र प्रदेश
पिन—533 288
29. आन्ध्रा बैंक
मोबिलिपिटा
अमलापुरम
रंपाचोदवरम पोस्ट
पूर्वी गोदावरी जिला
आन्ध्र प्रदेश
पिन—533 202
30. आन्ध्रा बैंक
डांकराई
येस्लावरम तालुक
पूर्वी गोदावरी जिला
आन्ध्र प्रदेश
पिन—531 110
31. आन्ध्रा बैंक
91, मेन रोड
वडिसालेरु
पूर्वी गोदावरी जिला
आन्ध्र प्रदेश
पिन—533 327
32. आन्ध्रा बैंक
5-22, ए. बी.
उप्पलमुप्तम
पूर्वी गोदावरी जिला
आन्ध्र प्रदेश
पिन—533 227
33. आन्ध्रा बैंक
मेन रोड
मुम्मिडिवरम
पूर्वी गोदावरी जिला
आन्ध्र प्रदेश
पिन—533 216
34. आन्ध्रा बैंक
मेन रोड
नागुलंका
पूर्वी गोदावरी जिला
आन्ध्र प्रदेश
पिन—533 249
1. 8-8-95, डा. पो. सं. 71
कापरिशम बैंक
बरंगल शाखा
जे. पी. एन. रोड,
बरंगल—506002
आन्ध्र प्रदेश
सीरकुला शाखा

नीरकुला शाखा

2. एस. बी. पी. रोड, रंगमपेट
वरंगल—506007
आन्ध्र प्रदेश

ऊकल हवेली शाखा

3. बार्ड सं. 3
धर्मावरम से होकर
ऊकल हवेली—506330
वरंगल जिला, आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद मुख्य शाखा नं. 4

4. प्रथम तल, सं. 15-1-551/23,
गोयल मार्केट, पो. बा. सं. 1120,
सिद्धियाम्बर बाजार,
हैदराबाद—500012 आन्ध्र प्रदेश

आदोनी शाखा

5. क. नं. 18/641-8,
मुनिसिपल मेन रोड, पो. बा. सं. 25
आदोनी—518301
कर्नूल जिला, आन्ध्र प्रदेश

कृष्णा शाखा

6. मेन रोड
कृष्णा—509352
मेहबूब नगर जिला, आन्ध्र प्रदेश

1. सिडिकोट बैंक
ब्रह्मदेवम शाखा
ब्रह्मदेवम
मुदुक्कुर मंडल
नेल्लूर जिला
आन्ध्र प्रदेश-524346

2. सिडिकोट बैंक,
बोराबारिसन्नम शाखा
बोराबारिसन्नम मंडल,
नेल्लूर जिला,
आंध्र प्रदेश -524123

3. सिडिकोट बैंक,
इस्कपल्लि शाखा,
म.सं. 1/156 मुख्य बाजार
इस्कपल्लि
अल्लूर द्वारा
नेल्लूर जिला
आंध्र प्रदेश-524324

4. सिडिकोट बैंक,
बुच्चिरेड्डि पालेम शाखा
बी 3-135 मुख्य रास्ता,
बुच्चिरेड्डिपालेम
नेल्लूर जिला,
आंध्र प्रदेश-524305

5. सिडिकोट बैंक,
गंगापटनम शाखा
म.सं. 1/49 राजवीदी,
गंगापटनम
द्वारा मयपाळु
नेल्लूर जिला (आं.प्र.)
पिन कूट-524313

6. सिडिकोट बैंक,
मंडिथेट शाखा
द्वारा येल्लारेड्डि
निजामाबाद जिला
आंध्र प्रदेश
पिन कूट-503122

7. सिडिकोट बैंक,
जन्नापल्लि शाखा
म.सं. 3-64/2
जन्नापल्लि
निजामाबाद जिला
आंध्र प्रदेश
पिन कूट-503246

8. सिडिकोट बैंक
जरासंगम शाखा
मुख्य रास्ता
जरासंगम, मेंडक जिला,
आंध्र प्रदेश, पिन कूट-502246

9. सिडिकोट बैंक
चिखली शाखा
डूम्बरे निवास,
चिखली, हावेसी तालुक
जिला पुणे, महाराष्ट्र,
पिन कूट-410501

10. सिडिकोट बैंक,
मालेगांव शाखा
428 भाषसार समाज बिल्डिंग,
तिलक रोड, गुरुव लेन,
सोमवार पेट, पो. सं. 73,
मालेगांव नासिक, महाराष्ट्र
पिन कूट-423203

11. सिडिकोट बैंक,
नासिक शाखा,
431/1, विश्व अपार्टमेंट
अशोक स्तंभ के पास
पुराना आगरा रोड,
डा. पे. सं. 150,
नासिक, महाराष्ट्र,
पिन कूट-422002

12. सिडिकेट बैंक,
सोलापुर, पश्चिम मंगलवार पेठ
824, पश्चिम मंगलवारपेठ
डा. पे. सं. 115, सोलापुर,
महाराष्ट्र, पिन कूट-413002
13. सिडिकेट बैंक
तालेगांव दाभाडे शाखा
सत्य कमल, तालेगांव
चकन रोड, तालेगांव जनरल हास्पिटल
डा.का., तालेगांव दाभाडे,
मावळ तालुक पुणे जिला
महाराष्ट्र, पिन कूट-410507
14. सिडिकेट बैंक
चिचवाड पुणे शाखा
202, गावडे एस्टेट,
मुंबई पुणे मार्ग
डा. पे. सं. 14,
चिचवाड (पूर्व) पुणे
पिन कूट -411019
15. सिडिकेट बैंक
खंडाला शाखा
होटल शबाना बिल्डिंग,
शिवाजी पथ, खंडाला,
जिला पुणे, महाराष्ट्र,
पिन कूट-410301
16. सिडिकेट बैंक
सोलापुर साखारपट शाखा
98, गुरुवारपेट, साखारपेट,
सोलापुर, महाराष्ट्र,
पिन कूट-413005
17. सिडिकेट बैंक
टिंगरी शाखा, टिंगरी,
मालेगांव तालुक, नासिक जिला,
महाराष्ट्र, पिन कूट-423005
18. सिडिकेट बैंक
मंसूर लश्कर मोहल्ला शाखा
डा. पे. सं. 16, 2938
बगलूर-नीलगिरी मार्ग,
लश्कर मोहल्ला, मंसूर
कर्नाटक राज्य, पिन कूट-570001
19. सिडिकेट बैंक
सिद्धवारपुर शाखा
श्री महालक्ष्मी बिल्डिंग,
टेंपल स्ट्रीट, सिद्धवारपुर,
उत्तर कन्नड़ जिला, कर्नाटक,
पिन कूट-581355
20. सिडिकेट बैंक
अंबिकानगर शाखा,
कर्नाटक पावर कार्पोरेशन लि., कालोनी
अंबिकानगर, हलियाल तालुक,
उत्तर कन्नड़ जिला, कर्नाटक
पिन कूट-581363
21. सिडिकेट बैंक
मेन रोड,
कडवा शाखा-67422
पुनूर तालुक
(कर्नाटक राज्य)
22. सिडिकेट बैंक
5/23ए स्कूल रोड,
मुलूर ग्राम
गुरपुर शाखा-574146
मंगलूर तालुक,
(कर्नाटक राज्य)
23. सिडिकेट बैंक
गंजीमठ सहकारी दूध उत्पादनकर्ता
सोसाइटी बिल्डिंग,
गंजीमठ शाखा 57414
मंगलूर तालुक
दक्षिण कन्नड़ जिला
(कर्नाटक राज्य)
24. सिडिकेट बैंक
थोटा ग्राम
ऐडस्पिट, बेंगरे शाखा
मंगलूर-575001
मंगलूर तालुक
दक्षिण कन्नड़ जिला
(कर्नाटक राज्य)
25. सिडिकेट बैंक
मेन रोड, डा. पे. सं. 3,
बेल्लंगडी शाखा-574214
बेल्लंगडी तालुक
(कर्नाटक राज्य)
26. सिडिकेट बैंक
डोर नं. 14.1.43
पिडोस लेन सर्कल शाखा
वासुदेव काम्प्लेक्स, प्रथम तल,
करंगल पाडी,
मंगलूर-575003
कर्नाटक राज्य

27. सिडिकेट बैंक
बेणूर शाखा
मूडबित्री बेलतंगडी रोड
महावीर नगर
बेणूर-574242
बेलतंगडी तालुक
दक्षिण कन्नड़ जिला
कर्नाटक राज्य
28. सिडिकेट बैंक
सिडिकेट बैंक बिल्डिंग,
बैंक रोड, डा.पे. सं. 28
कासरगोड-870121 (केरल राज्य)
29. सिडिकेट बैंक
नेल्लिकुट्टी-670632
डा.का. नेल्लिकुट्टी
द्वारा चम्बेरी, कन्नूड जिला,
केरल राज्य
30. सिडिकेट बैंक
मिलर्स रोड शाखा
71/1 मिलर्स रोड,
सेंट अनीस कानबट के सामने
बेंगलूर-560052
31. सिडिकेट बैंक
जयमहल शाखा
25/1, 1 मेन क्रॉस, पो. बा. न. 4825
जयमहल एक्सटेशन
बेंगलूर-560046
32. सिडिकेट बैंक
ग्रोद्योगिक वित्त शाखा
284-287 नार्थ ब्लॉक
मणिपाल सेक्टर, डिफेन्स रोड,
बेंगलूर-560042
33. सिडिकेट बैंक
मंडल कार्यालय
2951/2, पहला तल
जे एल बी रोड
चामुंडीपुरम
मैसूर-570004
34. सिडिकेट बैंक
बेलगोला इंडस्ट्रियल क्षेत्र
मेटागल्ली
मैसूर-570018
35. सिडिकेट बैंक
बिमानपुरा शाखा
एच ए एल कालोमी
जेसुकुपा काम्प्लेक्स
बेंगलूर-560017

36. सिडिकेट बैंक
"राम निलय"
मदवन्ने-572162
कुनिगल तालुक
तुमकुर जिला
37. सिडिकेट बैंक
विशेश्वरपुरम शाखा
स. 112, आना कृष्णाराव रोड
विशेश्वरपुरम
बेंगलूर-580004
38. सिडिकेट बैंक
मल्लेश्वरम 18वीं क्रॉस शाखा
सं. 65, ममर्गोस रोड
पी बी सं. 5554, 18 क्रॉस
मल्लेश्वरम
बेंगलूर-560055
39. सिडिकेट बैंक
सदाशिवनगर शाखा
394, सदाशिवनगर, 13 क्रॉस
बेंगलूर-560080
40. सिडिकेट बैंक
शेशाद्रिपुरम शाखा
79, 1 मेन रोड,
शेशाद्रिपुरम
बेंगलूर-560020

पंजाब एंड सिंध बैंक

राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत
अधिसूचित कराने हेतु शाखाओं की सूची :

1. मुद्रा पेटिका
1/28, आसफगली रोड,
नई दिल्ली
2. शाखा बिक्रीकर भवन
आई.बी. एस्टेट,
नई दिल्ली
3. शाखा एन.आर. आई.
गलोबल बैंकिंग सेंटर,
डी-45/47 कनाट सर्कस,
नई दिल्ली
4. क्षेत्रीय वसूली केन्द्र,
ई-6 कनाट प्लेस,
नई दिल्ली
5. दि.प. देशबन्धु कांफेज,
नई दिल्ली

6. दि.प. गणेश अमरदास पब्लिक स्कूल
डोरीवालो करोन बाग,
नई दिल्ली
 7. दि.प. गुरु हरकृष्ण नगर,
नई दिल्ली
 8. दि.प. हरिनगर,
नई दिल्ली
 9. दि.प. एस.एम. मोहत सिंह,
सीनियर सैकेंड्री स्कूल,
ब्लॉक ए-4/सी,
जनकपुरी, नई दिल्ली
 10. दि.प. माता गूजरी पब्लिक स्कूल
ग्रेटर कैलाश-1,
नई दिल्ली
 11. दि.प. लाजपत नगर,
नई दिल्ली
 12. दि.प. अनाज मंडी,
नजफगढ़, नई दिल्ली,
 13. दि.प. पुष्पांजली एन्क्लेव पीतमपुरा
दिल्ली
 14. दि.प. विवेकानन्द स्कूल
आनन्द विहार, दिल्ली
 15. दि.प. डेरा सतपुरा
तिलक नगर, नई दिल्ली
 16. प्रांचलिक कार्यालय,
सी 14/16, आश्विनाराम हाऊस,
कनाट प्लेस, नई दिल्ली
- स्टेट बैंक आफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर
1. निमराना (अलवर) शाखा,
जिला अलवर,
राजस्थान
 2. कालावाड़ (झोरावाड़ा) शाखा,
जयपुर, राजस्थान
 3. अग्रणी बैंक कार्यालय,
बीकानेर
जिला-बीकानेर
राजस्थान
 4. जयनारायण व्यास कालोनी,
बीकानेर,
जिला-बीकानेर,
राजस्थान
 5. अग्रणी बैंक कार्यालय,
हनुमानगढ़,
जिला-हनुमानगढ़
6. दाता शाखा,
जिला-सीकर,
राजस्थान
 - यूनियन बैंक आफ़ इंडिया
 1. सी आर एम जाट कालेज,
परिसर हिसार,
हरियाणा-125001
 2. एस ए जैन कन्या उच्च विद्यालय,
अम्बाला शहर, सराफा बाजार,
हरियाणा-134002
 3. सिवानी शाखा, पुराने बस स्टैंड के पास,
जिला सिवानी,
हरियाणा-125046
 4. मानेसर शाखा,
गांव एच पोस्ट मानेसर,
जिला गुड़गांव
 5. बादशाहपुर शाखा
गांव एच पोस्ट बादशाहपुर,
जिला गुड़गांव
 6. वैश्य टैक्नीकल इंस्टीट्यूट,
वैश्य टैक्नीकल इंस्टीट्यूट कपाऊड,
रोहतक
 7. बीडज शाखा
साबरमती आश्रम गौशाला कैम्पस,
पोस्ट लाली, तालूका मेमबाबाद,
बीडज, जिला खेड़ा-387120
 8. खदारी क्रिसिग शाखा,
328, ए/2डी एच कैम्पस,
खदारी चौराहा, भागरा
 9. विशेषीकृत बचत शाखा, आगाखान महल,
प्लॉट क्र. 8, गुलमोहर कालोनी,
पुणे नगर मार्ग, पुणे-411006
 10. विशेषीकृत बचत शाखा रायपर,
15/154, जवाहर नगर, रायपर,
मध्य प्रदेश-492001
 2. यूनियन बैंक आफ़ इंडिया
 11. विशेषीकृत बचत बैंक शाखा,
रथवाला क्रिसिग, 58/52, ए 2 महाराज बाग,
वाराणसी-221001, उत्तर प्रदेश
 12. गोमती नगर शाखा,
लखनऊ
 13. इंदिरानगर शाखा,
ए-1039, शाहीभार चौराहा,
लखनऊ-226016

14. विशेषीकृत बचत बैंक शाखा,
काला दूगी रोड,
हल्द्वानी, जिला नैनीताल-224216
15. उच्च तकनीक कृषि शाखा,
रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंहनगर-262308
16. खटीमा शाखा,
सितारगंज रोड ब्लाक के सामने,
खटीमा, जिला ऊधमसिंहनगर-262308
17. काशीपुर शाखा, रामनगर रोड,
काशीपुर, जिला ऊधमसिंहनगर-262308
18. विशेषीकृत बचत बैंक शाखा,
राजकीय इंटर कालेज के सामने, पोस्ट बाक्स क्र. 93,
बेगम त्रिज रोड, मेरठ-250001
19. एस.एस.आई. जालंधर,
ई-9, फोकल पाइंट, जालंधर
20. एस एस बी शाखा,
शक्ति नगर चौक, मजीठ मंडी के नजदीक,
अमृतसर-143001
21. एस एस बी शाखा,
जी टी रोड, गोराया,
जिला जालंधर-144409
22. एस एस बी शाखा,
जी टी रोड, मिलर राज.
लुधियाना-141003
23. 1030, एल ग्रार कालेज रोड,
जगराओ, लुधियाना-142026
24. बचत विशेष शाखा, चिपलूण
अमीन अपार्टमेंट्स, प्रभात गल्ली,
पो. बा. क्र. 44, चिपलूण-416606
जिला रत्नागिरि
पुणे ग्रामीण क्षेत्र
1. बडगाव भावल शाखा
बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
681, गुजर (साबकार) सदन
बडगाव भावल 412106
(जि. पुणे)
2. तलेगाव वामाडे शाखा,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
ईगल फ्लास्क कंपाउंड,
तलेगाव, पुणे
3. बडगाव मुदुक शाखा
बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
मन कुंज अपार्टमेंट 1 ली मंजिल
मर्वे क्र. 33/8/1, माणिक याम
पुणे-सिंहगड मार्ग, बडगाव मुदुक
जि. पुणे-411051
- अहमदाबाद क्षेत्र
4. सेवा शाखा
बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
मबालंकर हवेली, बसंत चौक
भद्र, अहमदाबाद-380001
नासिक क्षेत्र
5. सेवा शाखा,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
जनमंगल, 189, जी.आई.
टिलक मार्ग, नासिक-422101
6. विटको कालेज नासिक शाखा
बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
विटको कालेज कॉम्प्लेक्स
नासिक-पुणे रोड
नासिक-4220101
अमरावती क्षेत्र
7. वरुद्ध शाखा
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
काले कॉम्प्लेक्स
विजय टॉकीज के सामने,
वरुद्ध जि. अमरावती-444906
8. साईनगर अमरावती शाखा,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
मुंदडा कॉम्प्लेक्स, साईनगर चौक,
पुराना बडगेरा मार्ग
अमरावती-444605
अकोला क्षेत्र
9. दापकी रोड अकोला शाखा,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
पहला माला,
डा. छावा देशमुख अस्पताल
दापकी रोड, पुराना शहर
अकोला-444001
नागपुर क्षेत्र
10. कर्वेनगर नागपुर शाखा;
बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
"मरुयोदय", 7, कर्वेनगर
वर्धा रोड, नागपुर-440025
सोलापुर क्षेत्र
11. आनंदनगर उस्मानाबाद शाखा,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
श्री ए. बी. कवम भवन
ब्लाक क्रमांक 1, आनंदनगर
उस्मानाबाद-413501
12. एस.एस.पी.एम. लाशी शाखा,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
शिवाजी शिक्षण प्रसारण मंडल,
शिवाजी नगर, बाली

जलगांव क्षेत्र

13. कालेज कैम्पस जलगांव शाखा
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
जलगांव-425002

कोल्हापुर क्षेत्र

14. आटपाडी शाखा
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
श्री सिद्धनाथ चित्र मंदिर के पास
प्रकाशवाडी, बिमांची रोड
आटपाडी (जि. सांगली)-415310

रत्नागिरी क्षेत्र

15. लोक शाखा
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
आनंदी पार्वती अपार्टमेंट
सी.एस.सं. 2175 व 2176/बी
कण्ठी झली, डाकघर रोड
जि. रत्नागिरी-415700

मुंबई शहर क्षेत्र

16. आदर्शनगर मुंबई शाखा
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
जनता शिक्षण संस्था
आदर्शनगर, बरली
मुंबई-400025

दिल्ली क्षेत्र

17. यू.पी. एस.सी. शाखा
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
धोलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड,
नई दिल्ली-110001

जबलपुर क्षेत्र

18. सतना शाखा
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
के.बी. कॉम्प्लेक्स, प्रथम मंजिल
सीमारीया चौक, रीबा रोड,
सतना-485001 (मध्य प्रदेश)

रायपुर क्षेत्र

19. भिलाई शाखा
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
अलंकार व्यवसाय पेंसिलर
पुराना विजय टॉकीज कम्पाउंड
पहिली मंजिल, जी.ई. रोड
पावर हाउस
भिलाई (जि. दुर्ग)-480001
(मध्य प्रदेश)

New Delhi, the 2nd September, 1998

S.O. 1787.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (Use for Official purposes of the Union) Ruls, 1976 the Central Government, hereby, notifies the listed offices/branches of the following banks in the attached annexure, more than 80% of the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi:—

S.No.	Name of the Bank	Number of Offices/Branches
1.	Uco Bank	294
2.	Punjab National Bank	112
3.	Andhra Bank	034
4.	Corporation Bank	006
5.	Syndicate Bank	040
6.	Punjab & Sind Bank	016
7.	State Bank of Bikaner & Jaipur	006
8.	Union Bank of India	024
9.	Bank of Maharashtra	019
		Total 551

[F.No. 11016/2/98-Hindi]

REMESH BABU ANIYERY, Dy. Director (O.L.)

1. UCO Bank
Koramangala
146|2-350|1
Koramangala
BANGALORE-560 034.
2. UCO Bank (Computerised),
M.G. Road Branch,
P.B. 5132,
83, M.G. Road,
BANGALORE-560 001.
3. UCO Bank,
Ramamurthy Nagar Branch,
No. 42 Munikalappa Layout
Banasaawadi
Ramamurthy Nagar,
BANGALORE-560 016.
4. UCO BANK,
KSR Road,
Hampanakatta
MANGALORE-575 001.
5. UCO Bank,
Vill. Doddalahalli,
P.O. Kanakapura,
Dist. BANGALORE
Pin-562 117.
6. UCO Bank,
P.O. Kodihalli
Kanakapura Taluk
BANGALORE-562 119.
7. UCO Bank,
Main Road,
P.O. Maralawadi
Kanakapura Taluk
BANGALORE-562 121.
13. UCO Bank,
Jalahalli branch
HMT Post Office,
Jalahalli
BANGALORE-560 031.
14. UCO Bank,
Mysore Road, Next to Kengeri Police
Station,
Kengeri,
BANGALORE-560 060.
15. UCO Bank,
2891|92, Siddannayar
Chambers, Kade Bazaar
BELGAUM-590 002.
16. UCO Bank,
P.O. AMINBHAVI
Dist. Dharwar,
Pin-581 201.
17. UCO Bank,
Town : Gulbarga,
No. 32, Super Market
First Floor,
P.O. Dist.-Gulbarga
18. UCO Bank,
87|80, Devaraj Urs Road,
Mysore-570 001.
19. UCO Bank,
Specialised Recovery Branch
13|22, Kempe Gowda Road,
Bangalore-560 009.
20. UCO Bank,
Vellarathu Building
Gullen Road,
Alleppey-688 001

SOUTHERN ZONE

8. UCO Bank, (Computerised),
Bangalore City,
P.B. No. 9523,
B|22, K.G Road,
BANGALORE-560 009.
9. UCO Bank,
Banashankari branch
4010, New K.R. Road,
Banashankari II Stage,
BANGALORE-560 070.
10. UCO Bank,
Indiranagar Branch,
531, Binnamangala II stage,
Indiranagar.
BANGALORE-560 038.
11. UCO Bank,
Frazer Town Branch,
14|14A, Mosque Road,
Fraser Town,
BANGALORE-560 005.
12. UCO Bank,
Javanagar branch,
238|35, 9th Main Road,
III Block, Javanagar
BANGALORE-560 011.
21. UCO Bank,
Post Bag No. 127
Jayanthi Buildings,
Palayam Junction
KOZHIKODE-673 001.
22. UCO Bank
Mallapuzhassary,
P.O. Nellikala, Va Elanathur,
Dist. Pethanamthitta
Pin-689-643.
23. UCO Bank,
Vill. Arackal
P.O. Thadicaud
Distt. Quilon-691 806.
24. UCO Bank,
Post Bag No. 509,
Khaise Building,
Beach Road,
Quilon-691 001.
25. UCO Bank,
Swaraj Round,
C-24|955, High Road,
Trichur-680 001.
26. UCO Bank,
Post Box 79
XIII|5, Cross Junction
Tiruvalla-689101

- | | |
|---|---|
| 27. UCO Bank,
Varakala
M.G.E.
(Kerala) | 41. UCO Bank
Nagalapuram
Dist.-Chittoor,
Pin-517589. |
| 28. UCO Bank,
CC XXIX 257A
S. N. Park Road
Kannur-607001
(Kerala) | 42. UCO Bank
132, T.P. Area
Opp. Venkateswar Temple
Bus Stop
Tirupati
Pin-517501. |
| 29. UCO Bank
UCO Bank Bldg. IC.25 2286 1
Over Bridge Junction
Trivandrum-695001. | 43. UCO Bank
Omkar Complex (1st Floor)
Near Big Mosque, Main Road
Rajahmundry (East Godavari)
Pin-533101. |
| 30. UCO Bank,
10 1229 A, SS Peter & Pauls
Church Compound
P.O.-Fort Cochin
Cochin-632 001. | 44. UCO Bank
9 1, Arundelpat
Guntur-522002. |
| 31. UCO Bank
P.B. No. 2564
Kaveri Building,
Cloth Bazar Street,
Ernakulam-682031. | 45. UCO Bank
Main Road
P.O. Husnabad
Dist.-Karimnagar (A.P.)
Pin-505467. |
| 32. UCO Bank,
P.B. No. 281
Mattancherry,
Cochin-682002. | 46. UCO Bank
G.N.T Road
Hanuman Junction
Dist.-Krishna
Pin-521105. |
| 33. UCO Bank,
M.G. Branch,
1, XXXV 2361, Ravipuram
Ernakulam-682016. | 47. UCO Bank
(Post Box No. 12)
26-15-7 1, Main Road,
Visakhapatnam-530001. |
| 34. UCO Bank
P.B. No. 581
Willingdon Island
Cochin-682 003. | 48. UCO Bank
Hindustan Shipyard Colony
Gandhigram
Visakhapatnam-530005. |
| 35. UCO Bank
P.O. Karukutty
Via Angamali
Ernakulam-683576 | 49. UCO Bank
Hindustan Zinc Smelter
Factory Branch,
Zinc Smelter Post Office,
Visakhapatnam-530 015. |
| 36. UCO Bank
Post Bag No. 1 50A
New Munambam Ferry
PC Pallipport
Munambam,
Dist. Ernakulam (Kerala). | 50. UCO Bank,
Q No. 18 A, VSP Township
Visakhapatnam-530 031. |
| 37. UCO Bank
Birlakottam
Mavoor-673661. | 51. UCO Bank,
Marikal,
Distt. Mehaboobnagar,
Pin-509 351. |
| 38. UCO Bank
PB. No. 325, No. 20 609
Market Road,
Falghat-678014. | 52. UCO Bank,
Vill & P.O. Maganoor,
Dist. Mehaboobnagar,
Pin-509-208. |
| 39. UCO Bank
Sadasivpet Taluk
Atmakur
Dist. Medak
Pin-502292. | 53. UCO Bank,
Nava Bazar,
P.O. Wananarthy,
Dist. Mehaboobnagar,
Pin-509 103. |
| 40. UCO Bank
1-10, Bazar Street,
P.O. Irula
Dist. Chittoor
Pin-517130. | 54. UCO Bank,
10-14-1 A, Main Road,
P.O. Sanareddy,
Madak-502 001. |

55. UCO Bank,
Vill. Patighanpur, via-Muthangi
Dist. Medak,
Pin-502 300.
56. UCO Bank
Vill. & P.O. Pondichinapally,
Dist.-Medak,
Pin-502 110.
57. UCO Bank,
Post Box No. 10,
Subedarpet Nellore.
Distt. Nellore (Andhra Pradesh),
Pin-524 001.
58. UCO Bank,
1/30, Main Road,
Devarapalli,
Dist. Visakhapatnam (A.P.),
Pin-531 030.
59. UCO Bank,
Vill. & P.O. Kakrapadu,
Block-Kovvuru,
Chinatapalli Taluk,
Dist. Visakhapatnam,
Pin-531 099.
60. UCO Bank,
Vill. & P.O. Koduru
Via Makavaranaalem,
Dist. Visakhapatnam,
Pin-531 113.
61. UCO Bank,
Vill. & P.O. Lammasingi,
Taluk-Chintapalli
Dist. Visakhapatnam,
Pin-531 116.
62. UCO BANK,
Vill. & P.O. Raghavendranagar,
Gudem Kothe,
Dist. Visakhapatnam,
Pin-531 133
63. UCO Bank,
Ramratan Manson, P.B. No. 27,
Near GHT Road,
Powerpet-Eluru
Dist. West Godavari
Pin-532 001.
64. UCO Bank,
Vill. & P.O. Madaram,
Taluk-Kalwakurty,
Dist. Mehaboobnagar,
Pin-509 357
65. UCO Bank,
P.B. No. 323,
D. No. 27/18/47,
Congress Office Road,
Governorpet, Vijayawada
Dist. Krishna (Andhra Pradesh),
Pin-520 002.
66. UCO Bank,
Post Box No. 176,
Rangannavari Street,
Vijayawada,
Dist. Krishna-520 001.
67. UCO Bank,
Thotavalluru Mandir,
P.O. Thotavalluru,
Dist. Krishna,
Pin-521 163.
68. UCO Bank,
Vill. Surampalli,
P.O. Nunna,
Dist. Krishna,
Pin-521 212.
69. UCO Bank,
Post Box No. 3,
5-1-908, Main Road,
Pushpanjali Complex,
Rear Block, Ground Floor,
Koti, Hyderabad,
Pin-500 195.
70. UCO Bank,
Abid Circle,
5-8-600 to 604, I Floor,
Mubarak Bazar,
Hyderabad-500 001.
71. UCO Bank,
Road No. 11 Banjara Hills,
Hyderabad-500034.
72. UCO Bank,
16-2-705/28, Malakpet
Muntaj College Road,
P.O. & Dist. Hyderabad
Andhra Pradesh
Pin-500036.
73. UCO Bank,
2-2-147/1 M. G. Road,
Secunderabad-500003.
74. UCO Bank,
Post Box No. 26,
9-1-167/168 S.D. Road,
Secunderabad (A.P.)
75. UCO Bank,
Chittoor-Bangarupalam Main Road
Arogonda,
Dist. Chittoor,
Pin-517129.
76. UCO Bank,
Opp. Vysya Hostel,
Kamalanagar,
Anantapur-515001.
77. UCO Bank,
Venkateswarapuram, 1st Floor,
Labbipt,
Vijayawada,
Pin-520010.
78. UCO Bank,
8-1-21, Plot No. 12,
Survanagar, Tolichowki,
Hyderabad 500008.
79. UCO Bank,
10-12-34 Anjaneya Swamy
Temple Street,
Attul,
Dist. West Godavari,
Pin-534134.
80. UCO Bank,
Mirzalguda Malkajgiri Road,
13-1/41, Sairani,
Hyderabad-500047.

81. UCO Bank,
Samdari Building,
Opp. Gomtesh Market,
Near Umbarya Gonapati,
Aurangabad-431001.
82. UCO Bank,
79, Mahatma Gandhi Road,
Post Box No. 33
Pune-1.
83. UCO Bank,
659, Sadashiv Peth,
Near Nimbarya Gonapati,
Pune-411030
84. UCO Bank,
Hamam Street Branch,
Rajabhadur Bhawan,
18/18-A, Ambalal Doshi Road,
Mumbai-400023.
85. UCO Bank,
'Gokul'
66/A, Dr. Atmaram Merchant Road,
Bhuleswar,
Mumbai-400002.
86. UCO Bank,
Khar Branch,
502, Linking Road,
Bandra,
Mumbai-500040.
87. UCO Bank,
'Alankar'
208, Samuel Street,
Mandvi,
Mumbai-400003.
88. UCO Bank,
Gool Annex of Kerawalas Lodge,
Station Road, Santacruz (West)
Mumbai-400054.
89. UCO Bank,
Sansgiri Sadan,
171, Girgaum Road,
Mumbai-400004.
90. UCO Bank,
Thana Belapur Br.
Indrayani Building,
Kalwa (East),
Dist. Thane.
91. UCO Bank,
Mohan House,
55, Warden Road,
Mumbai-400026.
92. UCO Bank,
'Century Bhawan',
Dr. Anne Besant Road,
Worli,
Mumbai-400015.
93. UCO Bank,
Y.W.C.A. Building Annex
10, Madam Cama Road,
Mumbai-400001.
94. UCO Bank,
Pimpri P.F.
Pune-411010.
95. UCO Bank,
(Post Box 64), 1st Floor,
Laxmi Bhavan,
Mount Road. Exten
Nagpur-440001.
96. UCO Bank,
Khed Shivapur Branch.
Laxmi Nivas
Near Apsara Hotel
Khed Shivapur Baug
Taluka Haveli,
Dist. Pune-412205.
97. UCO Bank,
Dhulia Branch,
'Kalpana', 11096 Nagar Paliti,
Dhulia-424001.
98. UCO Bank,
Yeshwant Mandal
Ravivar Peth
Nasik City.
99. UCO Bank,
Quarter No. 7151/2 & 3
Type II, Ordnance Factory,
Ambajhari,
P.O. Ambajhari Defence Project,
Dist. Nagpur.
100. UCO Bank,
Village Survey No. 360,
P.O. Kalamb
Taluk Ambegaoan,
Dist. Pune-410515.
101. UCO Bank,
G.S.C.E. Board Building,
Shivajinagar,
Pune-411010.
102. UCO Bank,
30 New Aaviwar Peth,
Pune.
103. UCO Bank,
Shivasagar Apartments,
Ganeshhind Road, 161-A, Modi Bldg.,
Pune-411016.
104. UCO Bank,
1137-B Yerwads
Opp. Chitra Talkies
Pune-411006.
105. UCO Bank,
Jiyaji Mansion,
225/9-A, Pune Sholapur Road,
Hadapsar,
Pune-411028.
106. UCO Bank,
Artillery Centre Branch,
Dr. Thol's Building,
Plot No. 32B/Survey No. 38,
Opp. Jain Bhavan,
Artillery Road,
Nasik Road, 422101.
107. UCO Bank,
Khedgaon,
Taluk-Dindori,
Dist. Nasik 422203.
108. UCO Bank,
Cloth Market,
Akola
Dist. Akola.
109. UCO Bank,
Ahmednagar Branch
Chitale Marg,
Ahmednagar.
110. UCO Bank,
18, Navi Peth,
Jalgaon-425001.
111. UCO Bank,
Bhusaval Branch,
Near Pandurang,
Talkies New Area,
Bhusaval 425201.
112. UCO Bank,
'Uma Chitra Mandir',
Bhagwat Chitra Nagar,
Morarji Peth,
P.B. No. 81,
Sholapur-413001.

113. UCO Bank,
Warha Branch,
Gram Panchayat Warha,
Toluk Foesa,
Dist. Amravati.
114. UCO Bank,
Vill. and P.O. Nagaratnan,
Taluka Waijapur,
Dist. Aurangabad.
115. UCO Bank,
Mahakali,
P.O. and Dist. Chandrapur.
116. UCO Bank,
Ghughus Branch,
Ghughus Gram Panchayat
Dist. Chandrapur.
117. UCO Bank,
Ballarpur Branch,
Ballarsha,
Dist. Chandrapur-442503.
118. CO Bank
New Majri Colliery,
P.O. Shivan Nager,
Dist. Chandrapur-442503.
119. UCO Bank,
Mardol,
Goa-403404.
120. UCO Bank,
Subaraya Building,
Near Municipal Market,
P.B. No. 29
Mapusa-403507 (Goa).
121. UCO Bank,
1002, Budhwar Peth,
Pune-411002.
122. UCO Bank,
Baramati Branch,
Baramati Agriculture Produce
Market Committee,
Principal Market Yard,
Baramati-413102.
123. UCO Bank,
Shivaji University,
Vidyanagar,
Kolhapur-4.
124. UCO Bank,
Opp. Old Railway Station Corner,
Sangli Miraj Main Road,
429/40, Khan Bhag,
Sangli-416416.
125. UCO Bank,
Chanda Rayatvari Branch,
At & P.O. Chandrapur-442040.
126. UCO Bank,
Hindustan Lalpeth Branch,
P.O. Hindustan Lalpeth Colliery,
Dist. Chandrapur.
127. UCO Bank,
Nagar Parishad Market
Complex,
Second Floor,
Chandrapur,
Dist. Chandrapur.
128. UCO Bank,
Korpavali Branch,
Taluka Yawal,
Dist. Jalgaon-525301.
129. UCO Bank,
Virwada Branch,
Taluka Chopda,
Dist. Jalgaon-425107.
130. UCO Bank,
Mungi Branch,
At & P.O. Mungi,
Teh. Shevagaon
Dist. Ahmednagar-414503.
131. UCO Bank,
Kanholibara Branch,
Taluka Hingna,
Dist. Nagpur-441110.
132. UCO Bank,
Yeshwant Apartments,
C.T.S. No. 1032,
Opp. Petrol Pump,
Shukrawar Peth,
Tink Marg,
Pune-411002.
133. UCO Bank,
Sangvi Branch,
Sangvi,
Taluka Baramati,
Dist. Pune.
134. UCO Bank,
At & P.O. Varshi,
Sindkheda Block,
Dist. Dhule.
135. UCO Bank,
Kondhava Housing Complex Br.
Neha Apartments,
5-A/1-A, Kondhava,
Pune-411022.
136. UCO Bank,
Lakhpuri Branch,
Gram Panchayat Office,
Daryapur Benosa Road,
Taluka Murtajapur,
Dist. Akola-444116.
137. UCO Bank,
Chincholi Badruk Branch,
Gram Panchayat Building,
Daryapur Anjanagar Surji Road,
Taluka Anjanagar Surji
Dist. Amravati-445205.
138. UCO Bank,
Girnara Branch,
Madhav Rao Waman Shetya House
At & P.O. Girnara,
Teh & Dist. Nasik,
Pin-22203.
139. UCO Bank,
At & P.O. Sirsi,
Tehsil Umred,
Dist. Nagpur.
140. UCO Bank,
Mehendi House,
Vill. Veljanath,
Taluka Karjat,
Dist. Raigad.
141. UCO Bank,
Vill. Nagardhan,
P.O. Ratan Lal Jagannath,
Baiswal Pholing,
Dist. Nagpur-441106.
142. UCO Bank,
Rahu Branch,
Jain Sthanak Sangh,
House No. 337,
At & P.O. Rahu,
Tehsil Daund,
Dist. Pune-412207.
143. UCO Bank,
Survey No. 1/1,
Near Kothrud Post Office,
Kothrud, Pune-411029.

144. UCO Bank,
Nimba Seva Sahakari Society,
Tehsil Balapur,
Dist. Akola.
145. UCO Bank,
Yashodhan Aparartments,
Jayprakash Road, Fear Bunglow,
Andheri (West),
Mumbai-400058.
146. UCO Bank,
354, Abdul Rehman Street,
Mumbai-400008.
147. UCO Bank,
Pipewala Building,
62, Kolaba Road,
Mumbai-400005.
148. UCO Bank,
Puj Shikarpur Panchayat,
Sarvodaya Society,
(Near Golf Club),
Plot No. 112 and 113,
Chembur Colony, Chembur,
Mumbai-400074.
149. UCO Bank,
Goregaon Branch, 'Shilpanjali',
Survey No. 411-H.S.V. Road,
Goregaon (West) 400082.
150. UCO Bank,
'Alankar', 187 Baham Street,
Off. Grant Road,
Mumbai-400007.
151. UCO Bank,
Jay Apartments,
Junction of D.P. Road and
M.G. Road,
Kandivali (West),
Mumbai-400067.
152. UCO Bank,
Kanshi Kunj, Ground Floor,
S.V. Road, Malad (West),
Mumbai-400064.
153. UCO Bank,
Lakshmi House, Flat No. 1
Ground Floor,
84, Lady Harding Road,
Matunga (Western Railway),
Mumbai-400016.
154. UCO Bank,
Mulund Branch,
Anandi Villa, Block-A,
Ganesh Gavde Road, Mulund (W)
Mumbai-400080.
155. UCO Bank,
Gautam Appartment,
72, Pali Hill,
Bandra, Mumbai.
156. UCO Bank,
'Vimal', 184 Khetwadi Main Rd.
Mumbai-400004.
157. UCO Bank,
Mumbai, Physical Culture
Association Stadium,
Bhartiya Krida Mandir
Naigaum,
Mumbai-400081.
158. UCO Bank,
Vile Parle (East) Branch
Jashoda Niwas,
Vile Parle (East),
Mumbai-400057.
159. UCO Bank,
Borivali (West) Branch,
Ganapati Appartments, Lokmanya
Tilak Road,
Borivali (West)
Mumbai-400092.
160. UCO Bank,
Shrirang Housing Society,
Shopping Centre, Near Castle,
Mills,
Thane West (Central Railway)
161. UCO Bank,
Juhu Vile Parle Branch,
At Nemat Building,
Plot No. 3/21
Juhu Vile Parle Development
Scheme,
Juhu Road. Vile Parle (W),
Mumbai-400056.
162. UCO Bank,
Azim Manzil,
308, Kotna Gate,
Bhiwandi, Dist. Thane.
163. UCO Bank,
M/s. Meghna Corporation
G : 4 Lisa Appartments
Marol Maroshi Road,
Next to Fire Brigade Stn.
Andheri (East),
Mumbai-400059.
164. UCO Bank,
Building No. 'D'
Misquita Nagar,
Dahisar (East),
Mumbai-400068,
165. UCO Bank,
51, Mukund Nagar,
Opp. Kirloskar Press
M/s. Bora Transport Bldg.
Pune-411037.
166. UCO Bank,
Trimurti Towers,
Mamlatdar Wadi,
S. V. Road,
Malad West,
Mumbai-400084.
167. UCO Bank,
Sazgiri Sadan,
171, Girgaum Road,
Mumbai-400004.
168. UCO Bank,
Borivali (East) Branch,
Garden View, Rajendra Nagar,
(Kulunwadi),
Borivali (East),
169. UCO Bank,
Sandu Garden, Chembur Branch,
Near Chembur Post Office,
10th Road,
Chembur,
Mumbai-400071.

CHANDIGARH

170. UCO Bank,
Nandi Colony, Khanna,
Distt. Ludhiana,
Pin-141026.
171. UCO Bank,
Village and P.O. Sujapur,
Dist. Ludhiana,
Pin-142026.
172. UCO Bank
Village & P.O. Sangulol,
Distt. Ludhiana,
Pin-140802.

173. UCO Bank,
Village & P.O. Rumi,
Via Jagraon,
Distt. Ludhiana.
174. UCO Bank,
Village & P.O. Rauni,
Distt. Ludhiana,
PIN-141415.
175. UCO Bank,
Village & P.O. Rasulpur,
Distt. Ludhiana,
PIN-141035.
176. UCO Bank,
Village & P.O. Raipur Majri,
Via Khanna,
Distt. Ludhiana.
177. UCO Bank,
Village & P.O. Manghat,
Distt. Ludhiana.
178. UCO Bank,
Village & P.O.—Jhorana,
Teh.—Jagraon,
Distt.-Ludhiana.
179. UCO Bank,
P.O.—Netaji Nagar, Salim Tabri,
New Anaj Mandi,
Ludhiana.
180. UCO Bank,
Municipal Committee,
Ludhiana,
Distt.-Ludhiana.
181. UCO Bank,
P.B. 86, G T. Road,
Miller Ganj, Ludhiana,
Distt.-Ludhiana.
182. UCO Bank,
Davanand Medical College
and Hospital,
Ludhiana,
Distt.-Ludhiana.
183. UCO Bank,
Village & P. O.—Lalton Kalan,
Distt.-Ludhiana,
PIN-141 022.
184. UCO Bank,
Village & P. O.-Kohara,
Distt.-Ludhiana,
PIN-141 112.
185. UCO Bank,
Jugiana,
Distt.-Ludhiana,
PIN-141 120.
186. UCO Bank,
Village & P.O. Ghurani Kalan,
Distt.-Ludhiana.
187. UCO Bank,
Village & P. O.-Bhundri,
Teh.-Jagraon,
Distt.-Ludhiana.
188. UCO Bank,
Village & P. O.-Ayali Kalan,
Distt.-Ludhiana.
189. UCO Bank,
Dashmesh Nagar, Gali No. 17,
Gill Road, Ludhiana,
(Alamgir), Ludhiana.
190. UCO Bank,
Industrial Area,
Sirhind Road,
Patiala-147 001.
191. UCO Bank,
Village & P.O.-Jhumba,
Distt.-Bhatinda.
192. UCO Bank,
F. B. No. 2,
Partap Road, Moga,
Faridkot.
193. UCO Bank,
P.O.-Singh Bhagwantpura,
Distt.-Ropar.
194. UCO Bank,
Pul Bazar,
Ropar.
195. UCO Bank,
Village & P.O.-Purkhali,
Distt.-Ropar.
196. UCO Bank,
R.T.P. Complex,
Nuhon,
(Ropar).
197. UCO Bank,
Village-Nayagaon,
P.O.-Secretariat,
Chandigarh.
198. UCO Bank,
P.O.-Khizrabad,
Distt.-Ropar,
PIN-140109.
199. UCO Bank,
Jawahar Market,
Partap Road,
Nangal.
200. UCO Bank,
Village-Dumewal,
P.O.-Jaijar,
Via Nurpur Bedi.
201. UCO Bank,
Village & P.O.-Bhallan,
Tehsil-Anandpur Sahib.
202. UCO Bank,
Village & P.O.-Kalra,
Distt.-Jalandhar.
203. UCO Bank,
Kaurthala,
(Punjab).
204. UCO Bank
Bharwara Camp,
Nakodar Road,
Jalandhar.
205. UCO Bank
Industrial Area,
Jalandhar City.

206. UCO Bank,
Gur Mandi,
Near Bansa Bazar,
Jalandhar.
207. UCO Bank,
Atta Goraya,
Goraya.
208. UCO Bank,
Village & P.O.-Bholath,
Distt.-Kapurthala.
209. UCO Bank,
Railway Road,
Pathankot,
Distt.-Gurdaspur.
210. UCO Bank,
Village & P.O.-Bhaini Mian Khan,
Distt.-Gurdaspur.
211. UCO Bank,
G.T. Road, Batala,
Distt.-Gurdaspur.
212. UCO Bank,
Village & P.O.-Verowal,
Teh.-Tarantaran,
Distt.-Amritsar
213. UCO Bank,
G. T. Road,
Chheharta.
214. UCO Bank,
Ram Bagh,
Amritsar.
215. UCO Bank,
Civil Lines,
P.B. No. 74,
Distt.-Amritsar.
216. UCO Bank,
Katra Ahluwalia,
P.B. No. 45,
Amritsar.
217. UCO Bank,
Ranjitgarh,
Nurmahal Road,
P.O.-Phillaur,
Distt.-Jalandhar.
218. UCO Bank,
Village & P.O.-Fartappura
Distt.-Jalandhar.
219. UCO Bank,
Industrial Area,
Lawanshahr,
Distt.-Jalandhar,
PIN-144514
220. UCO Bank,
Grain Market,
Nakodar
Distt.-Jalandhar.
221. UCO Bank,
Village & P.O.-Lasuri,
Distt.-Jalandhar.
222. UCO Bank,
Village & P.O. Kohala,
Distt.-Jalandhar.

- 223 UCO Bank,
Regional Office,
Punjab (Chandigarh),
Sector—17-B,
Chandigarh.

UTTAR PRADESH

224. UCO Bank,
'Sarju Vilash',
Octdenganj,
Ballia-277001.

225. UCO Bank,
Race Course,
61/2, Race Course,
Dehradun.

MADHYA PRADESH

226. UCO Bank,
P.O.-Krishak Nagar,
Distt.-Raipur,
FIN-492012.

227. UCO Bank,
P.O.-Gavra Project,
Distt.-Bilaspur,
FIN-495452.

BIHAR

228. UCO Bank,
Zonal Office,
Maurya Lok Complex,
Block 'A', 4th Floor,
New Dak Bunglow Road,
Fatna-80001.

229. UCO Bank,
Regional Office, Patna II,
147-B, Arva Kumar Road,
Rajendra Nagar,
Patna-800016.

230. UCO Bank,
Chakai,
Opposite Police Station,
P.O.-Chakai,
Distt.-Jamui.

231. UCO Bank,
Sasaram,
Anandi Bazar,
Sasaram,
Distt.-Rohtas.

232. UCO Bank,
Club Road, Muzaffarpur,
Muzaffarpur,
FIN-842001.

233. UCO Bank,
Beausarai,
P.B. No. 28,
Marwari Mohalla,
Distt.-Beausarai,
PIN-851101.

234. UCO Bank,
Lahagan
Village & P.O. Lahagan
Distt. Khagaria,
PIN-851204.

- | | |
|--|--|
| <p>235. UCO Bank,
Mansoorchak,
Village & P.O.-Mansoorchak,
Distt.-Begusarai.</p> <p>236. UCO Bank,
Manikpur,
Village-Manikpur,
P.O.-Rohikpur, Thila Mohan,
Distt.-Araria.</p> <p>237. UCO Bank,
Sadanandpur,
Village & P.O.-Sadanandpur,
Distt.-Begusarai,
PIN-851101.</p> <p>238. UCO Bank,
Saharsa,
Above Mahadeo Trading Co.,
Dharmasala Road,
Saharsa.</p> <p>239. UCO Bank,
Exhibition Road,
Patna-800001.</p> <p>240. UCO Bank,
Rajendra Market,
Near Biscoman Coal Depot,
Karnkarbagh
Patna-800020.</p> <p>241. UCO Bank,
Patliputra Industrial Area,
Alpana Market,
Patliputra,
Patna-800013.</p> <p>242. UCO Bank,
Bahadurpur Branch,
Village & P.O.-Bahadurpur,
Opp. Bihar Spun Silk Mill,
Distt.-Bhagalpur (Bihar),
PIN-846001.</p> <p>243. UCO Bank,
Banka Branch,
Dokania Market,
P.O.-Banka,
Distt.-Banka (Bihar).</p> <p>244. UCO Bank,
Beldiha Branch,
Village-Beldiha,
P.O. Ahir,
Via-Ghogha,
Distt.-Banka (Bihar),
PIN-813205.</p> <p>245. UCO Bank,
Belhar Branch,
AT & P.O.-Belhar,
Distt.-Banka (Bihar),
PIN-813 202.</p> <p>246. UCO Bank,
Bhagalpur (Main Branch),
Kishorepuria Market,
First Floor,
D N Siroh Road,
Bhagalpur (Bihar),
PIN-812002.</p> | <p>247. UCO Bank
Bhagalpur—Gorhatta Chowk Branch,
Hivgouri Flour Mill Compound
Gorhatta Chowk,
Bhagalpur (Bihar)
Pin-812 202.</p> <p>248. UCO Bank
Tilkamanjhi Branch
Central Jail Road
Tilkamanjhi Chowk
Bhagalpur (Bihar)
Pin-812001.</p> <p>249. UCO Bank
Bhanra Branch
Vill.-Bhanra
P.O.-Chandan
Diset.-Banka (Bihar)
Pin-814 131.</p> <p>250. UCO Bank
Dhoawe Branch
Vill. & P.O.-Dhoawe
Dist.-Bhagalpur (Bihar)</p> <p>251. UCO Bank
Dumrawan Branch
Vill. & P.O.-Dumrawan
Dist.-Banka (Bihar)
Pin-813 701.</p> <p>252. UCO Bank,
Fatehpur Branch,
Engineering College Campus
P.O.-Fatehpur
Dist.-Bhagalpur (Bihar)
Pin-813 233.</p> <p>253. UCO Bank
Gangania Branch
Vill. & P.O.-Gangania
Dist.-Bhagalpur (Bihar)</p> <p>254. UCO Bank
Goradih Branch
Vill. & P.O.-Goradih
Via-Sabour
Dist.-Bhagalpur (Bihar)
Pin-813 210.</p> <p>255. UCO Bank
Jagdishpur Branch
P.O.-Jagdishpur
Dist.-Bhagalpur (Bihar)
Pin-813 105.</p> <p>256. UCO Bank
Jaipur Branch,
Vill. & P.O.-Jaipur
Dist.-Banka (Bihar)
Pin-814 112.</p> <p>257. UCO Bank
Jawara Branch
Vill. & P.O.-Jawara
Dist.-Banka (Bihar)</p> <p>258. UCO Bank
Karharia Branch,
At & P.O. Karharia
Via-Sultanganj,
Dist.-Bhagalpur (Bihar)
Pin-813 213.</p> |
|--|--|

259. UCO Bank
Ktiyama Branch
Vill.-Katiyama
P.O. Sanjha
Dist.-Banka (Bihar)
Pin-813 105
260. UCO Bank
Katoria Branch
Vill. & P.O.-Katoria
Dist.-Banka (Bihar)
Pin-813 106
261. UCO Bank
Khesar Branch
Vill. & P.O.-Khesar
Dist.-Banka (Bihar)
Pin-813 207
262. UCO Bank
Narayanpur Branch
Vil. & P.O.-Narayanpur
Dist.-Bhagalpur (Bihar)
Pin.-853 203
263. UCO Bank
Ratanpur (Ratanganj) Branch
Vill-Ratanpur (Ratanganj)
P.O.-Kuldiha
Dist.-Bhagalpur (Bihar)
Pin-812 006
264. UCO Bank
Sabour Branch
Bahar Agri College Campus
P.O.-Sabour
Dist.-Bhagalpur (Bihar)
Pin-813 210
265. UCO Bank
Sahebganj Branch
Vill. & P.O.-Mathura
Sahebganj
Distt.-Banka (Bihar),
Pin-813 202
266. UCO Bank
Sanhaula Branch
Vill & P.O.-Sanhaula
Dist.-Bhagalpur (Bihar)
Pin-813 225.
267. UCO Bank
Suiva Branch
Vill. & P.O.-Suiya
Dist.-Banka (Bihar)
Pin-813 106
268. UCO BANK
Sultanganj Branch
Vill & P.O. Sultanganj
Dist. Bhagalpur (Bihar)
PIN—813213.
269. UCO BANK
Tulsipur Jamunia Branch
Vill. & P.O. Tulsipur Jamunia
Via Nangachhla
Dist. Bhagalpur (Bihar)
PIN—853202.
270. UCO BANK
Vijayhat Branch
Via Punasia
Dist. Banka (Bihar)
PIN—813109.
271. UCO BANK
Regional Office
Central Jail Road
Jawanpur
Tilakamanjhi Road
Bhagalpur (Bihar)
272. UCO BANK
LEAD BANK OFFICE
SUKHRAJ ROY ROAD
BHAGALPUR (BIHAR)
PIN—812001.
273. UCO BANK
Bariarpur
Station Road, Near Post Office
PO. Bariarpur
Dist. Munger
Pin-811211
274. UCO BANK
Tarapur
Sultanganj Belhar Road
P.O. Tarapur
Distt. Munger
Pin—813221
275. UCO BANK
Gidhaur, P.O.—Gidhaur
Via—Jhajha
Dist. Jamui
Pin—811305
276. UCO BANK
Jhajha
J. C. Shaw Road
PO. Jhajha
Distt.—Jamui
Pin—811308
277. UCO BANK
Buxar
Baba Complex, Amla Toli
PO. & Distt.—Buxar
Pin—802101
278. UCO Bank
Bettiah
Sharan Sadan
Kavivar Nepali Path
PO.—Bettiah
Distt. West Champaran
Pin.—845438
279. UCO BANK
Hajipur
Soni Alankar Complex
Gudri Road, Hajipur
PO.—Hajipur
Distt.—Vaishali
Pin—844101
280. UCO BANK
Lead Bank Office
Munger
Bekarur. Munger
Pin-811201
281. UCO BANK
Lead Bank Office
Jamui
PO. Jamui
Distt.—Jamui
Pin.—811307
282. UCO BANK
Lead Bank Office
Khagaria
SDO Road, Khagaria
Pin—851204

283. UCO BANK
Lead Bank Office
Begusarai
Kapasas Chowk, IOC Township
Begusarai
284. UCO BANK
Kochadhaman
P.O. Kochadhaman
Via-Sontha
Distt.—Kishanganj
Pin—855115
285. UCO BANK
Mahana
P.O.—Mahana
Distt.—Begusarai
286. UCO BANK
IOC Township
Kapasas Chowk
P.O.—Refinery Township
Dist. Begusarai
287. UCO BANK
Akora
P.O. Akopur
Via—Manjhaul
Distt. Begusarai
Pin.—848202
288. UCO BANK
Sakchi
6. Thakurbhari Road, Jamshedpur
Pin—831001
289. UCO BANK
GUMLA
Thana Road
P.O.—Gumla
Distt.—Ranchi
Pin-835207
290. UCO BANK
Mesra
Birla Institute of Technology
Main Building
Mesra, Ranchi
Pin-835215
291. UCO BANK
Gaya
(Post Box-8)
Hisua Market
Gautam Budh Road, Gaya
Pin-823001
292. UCO BANK
Mango
Iqbal Chambers
Purulia Highway
Mango, Jamshedpur
Pin-831012
293. UCO BANK
Regional Office,
J & K Division Camp
House No. 88, Sector 5A,
Tirkuta Nagar,
Jammu-180004
(J & K)
294. UCO BANK,
Katra Branch
Vill. & P.O. Katra,
Vaishno Devi,
Distt. Udhampur
(Jammu & Kashmir)
Pin-182301.
1. Punjab National Bank,
BO Achalpur Camp
Distt. Amravati,
Maharashtra.
2. Punjab National Bank,
BO Akola,
Near Textile Market
Distt. Akola,
Maharashtra.
3. PUNJAB NATIONAL BANK
BO Amravati
Shyam Chowk
Distt. Amravati
(Maharashtra)
4. PUNJAB NATIONAL BANK
BO Andori
Tehsil Devli
Distt. Vardha
(MAHARASHTRA)
5. PUNJAB NATIONAL BANK
BO Ballarpur
Distt. Chandrapur
(MAHARASHTRA)
6. PUNJAB NATIONAL BANK
Bhusaval
Balaji Gali
Distt. Jalgaon
(MAHARASHTRA)
7. PUNJAB NATIONAL BANK
BO Chandrapur
Milan Road
Distt. Chandrapur
(MAHARASHTRA)
8. PUNJAB NATIONAL BANK
Phulchur Road, Gurunanak Gate
Distt. Bhandara
(MAHARASHTRA)
9. PUNJAB NATIONAL BANK
BO Hinganghat
Distt. Vardha
(MAHARASHTRA)
10. PUNJAB NATIONAL BANK
BO Jalgaon
Navipeth M. G. Road
Distt. Jalgaon
(MAHARASHTRA)
11. PUNJAB NATIONAL BANK
BO Kaansi(bu)
PO Bhandevadi (Pardi)
Tehsil Kamthi,
Distt. Nagpur (MAHARASHTRA)
12. PUNJAB NATIONAL BANK
BO Khamgaon
Distt. Buldana
(MAHARASHTRA)
13. PUNJAB NATIONAL BANK
BO Nandedh
Old Mongha
Distt. Nandedh
(MAHARASHTRA)
14. PUNJAB NATIONAL BANK
BO Pusad
Main Road
Distt. Yavatmal
(MAHARASHTRA)
15. PUNJAB NATIONAL BANK
BO Santak
Parsiyani
Distt. Nagpur (MAHARASHTRA)
16. PUNJAB NATIONAL BANK
BO Saavada
Distt. Jalgaon
(MAHARASHTRA)
17. Punjab National Bank
BO Talegaon
Block Umri
Distt. Nandedh (Maharashtra)

- | | |
|--|---|
| 18. Punjab National Bank
BO Yawatmal
Main Road
Distt. Yawatmal (Maharashtra) | 33. Punjab Natitnal Bank
Regional Recovery Centre
Sita Bardi, Nagpur
Distt. Nagpur (Maharashtra). |
| 19. Punjab National Bank
BO Bharatnagar, Nagpur
Distt. Nagpur. | 34. Punjab National Bank
Zonal Stationary Centre
Amdas Feth, Distt. Nagpur
(Maharashtra). |
| 20. Punjab National Bank
BO C.A. Road, Nagpur
44, Central Avenue
Distt. Nagpur (Maharashtra) | 35. Punjab National Bank
Zonal Training Centre
Tilak Road, Law College Chowk
Nagpur (Maharashtra). |
| 21. Punjab National Bank
BO Dharampeth, Nagpur
Kothari Sadan, West High Court
Road,
Distt. Nagpur (Maharashtra). | 36. Punjab National Bank
BO K. S. Rao Road
Manglore. |
| 22. Punjab National Bank
BO Gandhi Bagh, Nagpur
Sewa Sadan, C.A. Road,
Distt. Nagpur (Maharashtra) | 37. Punjab National Bank
BO Sultanpur Road
Distt. Kapurathla Punjab. |
| 23. Punjab National Bank
BO Hanuman Nagar, Nagpur
Medical College Chowk
Distt. Nagpur (Maharashtra). | 38. Punjab Natonal Bank,
BO Kala Sindhia
Distt. Kapurathla
Punjab. |
| 24. Punjab National Bank
BO Indora Chowk, Nagpur
Distt. Nagpur (Maharashtra). | 39. Punjab National Bank
BO Deepanwali
Sultanpur Lodhi Kapurathla
Punjab. |
| 25. Punjab National Bank
BO Kingsway, Nagpur
PNB House, Nagpur
Distt. Nagpur (Maharashtra). | 40. Punjab National Bank
BO : Dhillwan
Tehsil Bholatth
Distt. Kapurathla
Punjab. |
| 26. Punjab National Bank
BO Khamla Nagar
Distt. Nagpur
(Maharashtra). | 41. Punjab National Bank
BO Railway Road Phagwara
Distt. Kapurathla
Punjab. |
| 27. Punjab National Bank
BO Kanhan
Tehsil Kamthi Nagpur
Distt. Nagpur (Maharashtra). | 42. Punjab National Bank
BO Tanda Road, Begowal
Bholatth
Distt. Kapurthla
Punjab. |
| 28. Punjab National Bank
BO Lakkadganj, Nagpur
Distt. Nagpur (Maharashtra). | 43. Punjab National Bank
BO Bhandal Bet
Kapurathla
Distt. Kapurathla
Punjab. |
| 29. Punjab National Bank
BO M.I.D.G.,
Nagpur, Hingna Road,
Distt. Nagpur (Maharashtra). | 44. Punjab National Bank
BO : Manek Wahed
Phagwara
Distt. Kapurathla
Punjab. |
| 30. Punjab National Bank
BO Patni Bhawan, Nagpur
Gandhi Bagh, Distt. Nagpur
(Maharashtra). | 45. Punjab National Bank
BO Ram Garh, Bholatth
Distt. Kapurathla
Punjab |
| 31. Punjab National Bank
BO Sita Bardi, Nagpur
Distt. Nagpur (Maharashtra). | 46. Punjab National Bank
BO Siddwan Dona
Kapurathla
Punjab |
| 32. Punjab National Bank
Link Cell
Suraj Sadan, Gandhi Bagh, Nagpur
Distt. Nagpur (Maharashtra). | 47. Punjab National Bank
Lead Bank Distt. Manager,
Kapurathla
Punjab. |

- | | |
|---|--|
| 48. Punjab National Bank
Aulakh, Batala
Distt. Kapurathala
Punjab. | 65. Punjab National Bank
BO Pharala
Jalandhar, Punjab |
| 49. Punjab National Bank
BO Hanuman Chowk
Gurdaspur
Punjab. | 66. Punjab National Bank
BO Sarinh
Jalandhar Punjab. |
| 50. Punjab National Bank
BO Dehriwal
Batala, Gurdaspur
Punjab. | 67. Punjab National Bank
Regional Recovery Centre
Jalandhar Punjab. |
| 51. Punjab National Bank
BO Dhariwal, Batala Road
Tehsil Batalla Road
Distt. Gurdaspur Punjab. | 68. Punjab National Bank
Zonal Stationary Centre
Jalandhar Punjab. |
| 52. Punjab National Bank
BO Dorangla Gurdaspur
Distt. Gurdaspur
Punjab | 69. Punjab National Bank
Extn. Counter Gulab Devi Hospital
Jalandhar Punjab. |
| 53. Punjab National Bank
BO Mohan Market
Pathankot
Distt. Gurdaspur Punjab. | 70. Punjab National Bank
BO Kanya Mahavidyalaya
Jalandhar Punjab |
| 54. Punjab National Bank
BO Pandori Baisaan
Distt. Gurdaspur, Punjab | 71. Punjab National Bank
BO Nakodar Road
Jalandhar Punjab. |
| 55. Punjab National Bank
BO Prem Nagar, Batala
Distt. Gurdaspur Punjab. | 72. Punjab National Bank
BO Old Railway Road
Jalandhar Punjab. |
| 56. Punjab National Bank
BO Mari Buchchian
Batala, Gurdaspur
Punjab. | 73. Punjab National Bank
BO Alawalpur
Jalandhar Punjab. |
| 57. Punjab National Bank
BO Mamoon Cantt.
Pathankot, Gurdaspur
Punjab. | 74. Punjab National Bank
BO Balachaur
Jalandhar Punjab. |
| 58. Punjab National Bank
Distt. Lead Bank Manager
Gurdaspur Punjab. | 75. Punjab National Bank
BO Banga-Dana Mandi
Jalandhar Punjab. |
| 59. Punjab National Bank
BO Basti Danishmandan
Jalandhar Punjab. | 76. Punjab National Bank
BO Bahloor Kalan
Jalandhar Punjab. |
| 60. Punjab National Bank
BO : Focal Point
Jalandhar Punjab | 77. Punjab National Bank
BO Bhatnura Jadian
Jalandhar Punjab. |
| 61. Punjab National Bank
International Banking Br.
Jalandhar Punjab. | 78. Punjab National Bank
BO Goraya Atta
Jalandhar Punjab. |
| 62. Punjab National Bank
Special Small Scale Industries Br.
Jalandhar Punjab. | 79. Punjab National Bank
BO Jadla
Jalandhar Punjab. |
| 63. Punjab National Bank
BO Aur
Jalandhar Punjab. | 80. Punjab National Bank
BO Jandiala
Jalandhar Punjab. |
| 64. Punjab National Bank
BO Noor Mahal
Jalandhar Punjab. | 81. Punjab National Bank
BO Kartarpur GT Road
Jalandhar Punjab. |
| | 82. Punjab National Bank
BO Langroya
Jalandhar Punjab. |
| | 83. Punjab National Bank
BO Makhupur
Jalandhar Punjab. |

- | | |
|---|--|
| 84. Punjab National Bank
BO Mahil Gehlan
Jalandhar Punjab. | 102. Punjab National Bank,
B/O Kumbhale, Taluka Peth,
Distt. Nasik, Maharashtra. |
| 85. Punjab National Bank.
BO Mukandpur
Jalandhar Punjab. | 103. Punjab National Bank,
B/O Kasya, Distt. Kushinagar,
U.P. |
| 86. Punjab National Bank
BO Nakodar, Adda
Mechatpur, Jalandhar Punjab. | 104. Punjab National Bank,
B/O Nichannaui,
Distt. Maharajganj,
U.P. |
| 87. Punjab National Bank
BO Nawanshahar Railway Road
Jalandhar Punjab. | 105. Punjab National Bank,
B/O Nautanvan,
273/164 Main Road,
Nautanvan, Distt. Maharajganj,
U.P. |
| 88. Punjab National Bank
BO Noor Mahal-Grain Market
Jalandhar Punjab. | 106. Punjab National Bank,
B/O Ramkola,
Distt. Kushinagar,
U.P. |
| 89. Punjab National Bank
BO Pojewal
Jalandhar Punjab. | 107. Punjab National Bank,
B/O Thana Bhawan,
Distt. Muzaffarnagar,
U.P. |
| 90. Punjab National Bank
BO Phillaur-Grain Market
Jalandhar Punjab. | 108. Punjab National Bank,
B.O. Settelite
Ashapura Complex
Near Sayamal House,
Ahmedabad. |
| 91. Punjab National Bank
BO Rahon Main Bazar
Jalandhar Punjab. | 109. Punjab National Bank,
International Banking Branch,
Neel Kamal Building,
Ashram Road, Ahmedabad. |
| 92. Punjab National Bank
BO Rai Majra
Jalandhar Punjab. | 110. Punjab National Bank,
B/O Dombivali,
Shankar Samriti Anex,
Subhash Road,
Dombivali (W) 421202. |
| 93. Punjab National Bank
BO Saroya
Jalandhar Punjab. | 111. Punjab National Bank,
B/O Kandivali (East),
Thakur House, 1st Floor,
In front of Akurli Road,
Kandivali (E) Bombay-400101. |
| 94. Punjab National Bank
BO Talwandi Madho
Jalandhar Punjab. | 112. Punjab National Bank,
B/O Mapoa Goa,
Bapeca Residensi,
In front of Civil Registrar's Office,
Anabhat, Mapsa,
Goa-403507. |
| 95. Punjab National Bank
BO Urapar (Udapat)
Jalandhar Punjab. | |
| 96. Punjab National Bank
BO GT Road
Jalandhar Punjab. | |
| 97. Punjab National Bank
Extn. Coun. Hansraj Mahila
Mahavidyalaya Jalandhar
Punjab. | |
| 98. Punjab National Bank
BO Leader Engg.
Jalandhar Punjab. | |
| 99. Punjab National Bank
Lead Bank Office
Nawanshahar
Jalandhar, Punjab. | |
| 100. Punjab National Bank,
B/O Jalhur,
Block Kannad,
Distt. Aurangabad,
Maharashtra. | |
| 101. Punjab National Bank,
B/O Javan, Post Ponanagar,
Taluka Maval,
Distt. Pune,
Maharashtra. | |

ANDHRA BANK

1. Andhra Bank,
A-1, First Avenue,
Senthil Towers,
Ashoknagar
Chennai,
Tamilnadu-600083.
2. Andhra Bank,
Plot No. 42,
Dr. A. Ramaswamy Road
K. K. Nagar
Chennai,
Tamilnadu-600078.
3. Andhra Bank,
12-22-43/1
Seetapeta, Kathur Road
Aryapuram
Rajahmundry
Pin-533104.
4. Andhra Bank,
Main Road, Near Durga Theatre
Dowelswaram
Rajahmundry
Pin-533104.

5. Andhra Bank,
D. No. 4-6-14
Railway Station Road
Aloot Gardens
Rajahmundry
Pin-533104.
6. Andhra Bank,
Main Road
Malkipuram
Razole Tq.
East Godavari Dist.
Andhra Pradesh
Pin-533253.
7. Andhra Bank,
Kesavadasupalem
Razole Mandal
East Godavari Dist.
Andhra Pradesh
Pin-533252.
8. Andhra Bank,
13-104
Prakashnagar
Rajahmundry
East Godavari Dist.
Andhra Pradesh
Pin-533103.
9. Andhra Bank,
3-119, G.T. Road
Z. Rangampet
Jaggampet Post
East Godavari Dist.
Andhra Pradesh
Pin-533435.
10. Andhra Bank,
Katrevulpally
Jaggampet Mandal
East Godavari Dist.
Andhra Pradesh.
11. ANDHRA BANK
7/11-13-6,
Fort Gate Centre,
Rajahmundry,
Andhra Pradesh,
Pin-533 181.
12. ANDHRA BANK
29-14-6, Lakshmivarapupet,
Devi Chowk,
Rajahmundry,
Andhra Pradesh,
Pin-533 104
13. ANDHRA BANK
46-7-33, Main Road,
Danvaipet,
Rajahmundry,
Andhra Pradesh,
Pin-533 103.
14. ANDHRA BANK
18-278, A. V. Subha Rao Road,
Katarinagar,
Rajahmundry,
Andhra Pradesh,
Pin-533 103.
15. ANDHRA BANK
Govt. Head Quarters Hospital,
No. 4, Lalacheruvu,
Rajahmundry,
Andhra Pradesh,
16. ANDHRA BANK
4-50, Main Road,
Ashajipet,
Amlapuram Tq.
East Godavari Distt.,
Andhra Pradesh,
Pin-533 214.
17. ANDHRA BANK
3-134, Challapallivari St.,
Kadium,
Rajahmundry Tq.
East Godavari Distt.
Andhra Pradesh,
Pin-533 126.
18. ANDHRA BANK
3-46, Sankhyayana Raja St.,
Munganda,
East Godavari Distt.,
Andhra Pradesh,
Pin-533 524
19. ANDHRA BANK
Main Road,
P. Gannavaram Mandal,
East Godavari Distt.,
Andhra Pradesh
Pin-533 248.
20. ANDHRA BANK
4-157/A, Bapuji Road,
Razole,
East Godavari Distt.,
Andhra Pradesh
Pin-533 242.
21. ANDHRA BANK
West Gonegudem,
Korukonda Tq.,
East Godavari Distt.,
Andhra Pradesh,
Pin-533 289.
22. ANDHRA BANK
Seethanagaram,
Vizianagaram Distt.,
Andhra Pradesh,
Pin-535 546.
23. ANDHRA BANK
S. U. Campus,
Quarter No. 3/18,
S. U. Professors Quarters,
Vishakhapatnam.
Pin-530 003.
24. ANDHRA BANK
Main Road,
Goneda,
Peddapuram Tq.
East Godavari Distt.,
Andhra Pradesh,
Pin-533 437.
25. ANDHRA BANK
12-8-1, Main Road,
Mandapeta,
East Godavari Distt.,
Andhra Pradesh,
Pin-533 388.

- | | |
|---|--|
| <p>26. ANDHRA BANK
1-481, Main Road,
Dwarapudi,
Alsuru Tq.
East Godavari Distt.,
Andhra Pradesh,
Pin-533 341.</p> <p>27. ANDHRA BANK
5/38, Main Road,
Velangi,
Kakinada Tq.,
East Godavari Distt.,
Andhra Pradesh,
Pin-533 260.</p> <p>28. ANDHRA BANK
Dor No. 2-3,
Sirigindalpadu
Rampachodvaram Post,
East Godavari Distt.,
Andhra Pradesh,
Pin-533 288.</p> <p>29. ANDHRA BANK
Moberlipeta,
Amalapuram,
Rampachodvaram Post,
East Godavari Distt.,
Andhra Pradesh,
Pin-533 202.</p> <p>30. ANDHRA BANK
Dontarai,
Yellavaram Tq.,
East Godavari Distt.,
Andhra Pradesh,
Pin-531 110.</p> <p>31. ANDHRA BANK
91, Main Road,
Vadisaleru,
East Godavari Distt.,
Andhra Pradesh,
Pin-533 327.</p> <p>32. ANDHRA BANK
5-22, A. B.,
Uppalaguptam,
East Godavari Distt.,
Andhra Pradesh,
Pin-533 227.</p> <p>33. ANDHRA BANK
Main Road,
Mumaidivaram,
East Godavari Distt.,
Andhra Pradesh,
Pin-533 216.</p> <p>34. ANDHRA BANK
Main Road,
Nagulanka,
East Godavari Distt.,
Andhra Pradesh,
Pin-533 249.</p> | <p>2. S.V.P. Road, Rangampet
Warangal-506 007,
A.P.</p> <p>3. Ward No. 3,
Via Dharmaram,
Ookal Haveli-560 330,
Warangal, A.P.</p> <p>4. 1st Floor, No. 15-1-551/23,
Goyal Market, P.B. No. 1120,
Siddiambar Bazaar,
Hyderabad-500 012,
A.P.</p> <p>5. Door No. 18/641-8,
Municipal Main Road,
P.B. No. 88,
Adoni-518 301,
Kurnool District, A.P.</p> <p>6. Main Road,
Krishna-509 352,
Mehaboob Nagar Dt., A.P.</p> <p>1. Syndicate Bank
Brahmadevan Branch
Brahmadevan
Muthukur Mandal
Nellore Dist.
ANDHRA PRADESH-524346</p> <p>2. Syndicate Bank
Doravari Satram Branch
Doravarisatram
Doravarisatram Mandal, Nellore Dist.
ANDHRA PRADESH-524123.</p> <p>3. Syndicate Bank
Iskapalli Branch
D. No : 1/156 Main Bazar
Iskapalli
Via Allur, Nellore Dist.
ANDHRA PRADESH-524324</p> <p>4. Syndicate Bank
Buchireddinallam Branch
B 3-135 Main Road
Buchireddinallam
Nellore Dist.
ANDHRA PRADESH-524305,</p> <p>5. Syndicate Bank
Gangapatnam Branch
D. No : 1/49 Rajaveedi
Gangapatnam
Via Mypadu, Nellore Dist.
ANDHRA PRADESH-524313.</p> <p>6. Syndicate Bank
Gandiveti Branch
Via Yellareddy
Nizamabad Dist.
ANDHRA PRADESH-503122</p> <p>7. Syndicate Bank
Jannapalli Branch
H. No. 3-64/2
Jannapalli
Nizamabad Dist.
Andhra Pradesh-503246</p> <p>8. Syndicate Bank
Jara Sangam Branch
Main Road, Jarasangam,
Dist : Medak
Andhra Pradesh-502246</p> <p>9. Syndicate Bank
Chikhali Branch
Dumbhari Niwas, Laxmi Road
Chikhali Haveli Taluk
Dist. Pune
Maharashtra-410501</p> |
|---|--|
- CORPORATION BANK
1. 8-8-95, P.B. No. 71,
I.P.N. Road,
Warangal-506 002,
A.P.

10. Syndicate Bank
Malegaon Branch
428 Bhavsarsamaj Building
Tilak Road Gurav Lane
Somvar Peth P.B. No. 73
Malegaon, Nasik
Maharashtra-423203
11. Syndicate Bank
Nasik Branch
431/1, Vishwa Apartment
Near Ashoka Stambh
Old Agra Road, PB No : 150
Nasik
Maharashtra-422002
12. Syndicate Bank
Sholapur West Mangalwar Peth
824, West Mangalwar Peth
PB No : 115
Sholapur, Maharashtra-413002
13. Syndicate Bank
Talegaon Dabhade, Maval Taluk,
Talegaon Dabhade Branch
Chakan Road, Talegaon Gen. Hospital P.O.
Talegaon Dabhad, Maval Taluk,
Pune, Maharashtra-410507
14. Syndicate Bank
Chinchwad Pune Branch
202, Gawade Estate
Mumbai Pune Road
P.B. No. 14
Chinchwad Pune Branch
Pune-411019
15. Syndicate Bank
Khandala Branch
Hotel Sabana Building.
Shivaji Peth
Khandala, Dist : PUNE
Maharashtra-410301
16. Syndicate Bank
Sholapur Sakhar Peth Branch
98, Guruwarpeth Sakharpeth
Shola Pur, Maharashtra-413005.
17. Syndicate Bank
Tingri Branch, Tingri
Malegaon Taluk
Nasik Dist.,
Maharashtra-423 003.
18. Syndicate Bank
Mysore Laskhar Mohalla Branch
PB No. 16, 2938,
Bangalore-Nilgiri Road
Laskhar Mohalla, Mysore
Karnataka-570 001.
19. Syndicate Bank
Siddapur Branch
Sri Mahalakshmi Building
Temple Street
Siddapur-581355
U.K. Dist
Karnataka
20. Syndicate Bank
Ambikanagar Branch
Karnataka Power Corporation Ltd. Col.
Ambikanagar-581 363
Haliyal Talak
U.K. Dist.
Karnataka
21. Syndicate Bank
Main Road
Kadaba Branch-574 221
Karnataka State
Puttur Taluk
22. Syndicate Bank
53/23A, School Road
Mulur Village
Gurpur Branch-574 145
Mangalore Taluk
Karnataka State
23. Syndicate Bank
Ganjimutt Co-op Milk Producers
Society Building
Ganjimutt-574 144
Mangalore Taluk
Dakshina Kannada Dist.
Karnataka State
24. Syndicate Bank
Thota Village
Sandapit, Bengre
Mangalore Taluk
Dakshina Kannada Dist.,
Karnataka State
25. Syndicate Bank
Main Road
P.B. No. 3
Belthangdy-574 214
Belthangdy Taluk
Karnataka State
26. Syndicate Bank
Door No. 14-1-43
Pintos Lane Circle Branch
Vasudev Complex 1st Floor
Karangalpady
Bangalore-575 003.
Karnataka
27. Syndicate Bank
Venur Branch
Moodbidri Belthangdy Road,
Mahaveer Nagar
Venur-574 242
Belthangdi Taluk
Dakshina Kannada Dist.
Karnataka State
28. Syndicate Bank
Syndicate Bank Building
Bank Road P.B. No. 28
Kasargod-670 121
Kerala State
29. Syndicate Bank
Nellikutty-870632
P.O. Nellikutty
Via Chemberi
Kannur District
Kerala State
30. Syndicate Bank
Millers Road Branch
71/1, Millers Road
Opp. St. Annes Convent
Bangalore-560 052.

- | | |
|---|--|
| <p>31. Syndicate Bank
Jayamahar Branch
25/1, 1 Main cross
P.B. No. 4625
Jayamahal Extn.,
Bangalore-588 846</p> <p>32. Syndicate Bank
Industrial Finance Branch
284-287 North Block
Municipal Centre
Dickenson Road
Bangalore-588 842.</p> <p>33. Syndicate Bank
Divisional Office
2951/2, 1st Floor
J. L. B. Road
Chamundipuram
Mysore-571 004.</p> <p>34. Syndicate Bank
Belgola Industrial Area
Metagalli
Mysore-570 018.</p> <p>35. Syndicate Bank
Vimanapura Branch
HAL Colony
Jesukrupa Complex
Bangalore-500 017.</p> <p>36. Syndicate Bank
'Ram Nilaya'
Yadevanne-572 162
Kunigal Taluk
Tumkur District</p> <p>37. Syndicate Bank
Vishweshwarapuram Branch
No. 112 As Na Krishna Rao Road
Vishweshwarapuram
Bangalore-500 004</p> <p>38. Syndicate Bank
Malleswaram 18th Cross Branch
No. 65, Morgosa Road
P. B. No. 5554, 18th Cross
Malleswaram
Bangalore-500 055</p> <p>39. Syndicate Bank
Sadashivanagar Branch
304, Sadashivanagar, 13th Cross
Bangalore-500 000</p> <p>40. Syndicate Bank
Sheshadripuram Branch
79, 1 Main Road
Sheshadripuram
Bangalore-500 000</p> | <p>2. Kalwar Road (Jhotwara) Branch
Jaipur, Rajasthan</p> <p>3. Lead Bank Office
Bikaner
Distt. Bikaner
Rajasthan</p> <p>4. Jayanarayan Vyas Colony
Bikaner
Distt. Bikaner
Rajasthan</p> <p>5. Lead Bank Office
Hanuman Garh
Distt. Hanuman Garh
Rajasthan</p> <p>6. Danta Branch
Distt. Sikar
Rajasthan</p> |
|---|--|

PUNJAB & SIND BANK
LIST OF BRANCHES

1. Currency Chest,
1/20, Asaf Ali Road,
New Delhi
2. Bikrikar Bhavan,
L. P. Estate,
New Delhi
3. N. R. I. Global Banking Center,
B-45/47 Con. Circus,
New Delhi
4. Regional Collection,
Centre, E-6 Conn. Circus,
New Delhi
5. Ext. Counter Desh Bandhu
College,
New Delhi
6. Ext. Counter Guru Amar Das,
Public School. Doriwala,
Karol Bagh,
New Delhi
7. Ext. Counter Guru
Harkrishan Nagar,
New Delhi
8. Ext. Counter Hari Nagar
New Delhi
9. Ext. Counter S. S. Mohta Singh,
Block A-4/C, Janak Puri,
New Delhi-58.
10. Ext. Counter Lajpat Nagar,
New Delhi
11. Ext. Counter Mata Gujri
Public School,
Greater Kailash-I
12. Ext. Counter Annaj Mandi,
New Delhi

STATE BANK OF BIKANER & JAIPUR

1. State Bank of Bikaner & Jaipur
Nimrana (Alwar) Branch
Distt. Alwar Rajasthan

13. Ext. Counter Pushpanjali,
New Delhi
14. Ext. Counter Vivekanand School,
Anand Vihar,
New Delhi
15. Ext. Counter Dera Sant Pura.
Tilak Nagar,
New Delhi
16. Zonal Office,
C 14/16, Attma Ram House
Connaught Place,
New Delhi

UNION BANK OF INDIA

1. C.R.M. Jat College,
Parisar Hissar,
Haryana-125001.
2. S.A. Jain Kanya High School,
Ambala City, Sarafa Bazar,
Haryana-134002.
3. Sivani Branch, Near Old Bus Stand,
Dist. Sivani,
Haryana-125046.
4. Manesar Branch,
At and Post Manesar,
Dist. Gurgaon.
5. Badshahpur Branch,
At and Post Badshahpur,
Dist. Gurgaon.
6. Vaishva Technical Institute,
Vaishva Technical Institute Compound,
Rohtak.
7. Bidaj Branch,
Sabarmati Ashram Goshala Campus,
Post : Lali, Taluka : Memdabad,
Bidaj, Dist. Kheda-387120.
8. Khandari Crossing Branch,
3/28-A/2 A.D.H. Campus,
Khandari Chauraha, Agra.
9. Specialised Saving Branch,
Achakhan Mahal,
Plot No. 8,
Gulmohar Colony,
Pune Nagar Marg, Pune-411006.
10. Specialised Saving Branch Raipur,
15/154, Jawahar Nagar, Raipur,
Madhya Pradesh-492001.
11. Rathvatra Crossing,
58/52, A-2 Maharaj Baug,
Varanasi-221001,
Uttar Pradesh.
12. Gomti Nagar Branch,
Lucknow.
13. Indira Nagar Branch,
A-1039, Shalimar Chauraha,
Lucknow-226016.
14. Specialised Saving Bank Branch,
Kala Dungi Road,
Haldwani, Distt. Nainital-224216.
15. High Technique Agricultural Branch.
Rudrapur, Distt. Udham Singh
Nagar-262308.
16. Khatima Branch,
Opposite Sitargunj Road Block.
Khatima, Dist. Udham Singh
Nagar-262308.
17. Kashipur Branch, Ramnagar Road.
Kashipur, Dist. Udham Singh
Nagar-262308.
18. Special Saving Bank Branch,
Opposite Rajakiya Inter College,
P. O. No. 93, Begum Bridge Road,
Meerut-250001.
19. S.S.I., Jalandhar,
E-9, Focal Point, Jalandhar.
20. S.S.B. Branch,
Shakti Nagar Chowk,
Near Majith Mandi,
Amritsar-143001.
21. S.S.B. Branch,
G.T. Road, Goraya,
Dist. Jalandhar-144409.
22. S.S.B. Branch,
G.T. Road, Miller Gunj,
Ludhiana-141003.
23. 1030, L.R. College Road,
Jagrao, Ludhiana-142026.
24. Specialised Saving Bank. Chiplun,
Amin Apartments. Prabhat Lane,
P.O. Box No. 44, Chiplun-415605,
Dist. Ratnagiri.

BANK OF MAHARASHTRA

Pune Rural Region

1. Vadgaon Maval Branch
Bank of Maharashtra
681, Gujar (Savkar) Sadan
Vadgaon Maval-412 106
(Dist. Pune)
2. Talegaon Dabhade Branch
Bank of Maharashtra
Fable Flask Compound
Talegaon, Pune
3. Vadgaon Andruk Branch
Bank of Maharashtra
Man Kuni Anntt. 1st Floor
Survey No. 33/8/1, Manik Bag
Pune—Sinhad Road,
Vadgaon Bk. Dist. Pune-411051,

Ahmedabad Region

4. Service Branch
Bank of Maharashtra
Mavalankar Haveli, Vasant Chouk
Bhadra, Ahmedabad-380 001

Nasik Region

5. Service Branch
Bank of Maharashtra
Janmangal, 109, G.E.
Tilak Road, Nasik-422 001
6. Bitco College Nasik Branch
Bank of Maharashtra
Bitco College Complex
Nasik, Pune Road
Nasik-422 101

Amravati Region

7. Varud Branch
Bank of Maharashtra
Kale Complex
Opp. Vijay Talkies
Varud, Distt. Amravati-444 906
8. Sainagar Amravati Branch
Bank of Maharashtra
Mundada Complex, Sainagar Chouk
Ostad Badnara Road
Amravati-444 605

Akola Region

9. Dapaki Road Akola Branch
Bank of Maharashtra
1st Floor,
Dr. Chaya Deshmukh Hospital
Dapaki Road, Old City
Akola-444 001

Nagpur Region

10. Karvenagar Nagpur Branch
Bank of Maharashtra
"Arunodaya", 7, Karvenagar
Wardha Road, Nagpur-440 025

Solapur Region

11. Anandnagar Osmanabad Branch
Bank of Maharashtra
Dr. A. B. Kadam Bhavan
Block No. 1, Anandnagar
Osmanabad-413 001
12. S.S.P.M. Barshi Branch
Bank of Maharashtra
Shivaji Shikshan Prasarak Mandal
Shivajinagar, Bashi

Jalgaon Region

13. College Campus Jalgaon Branch
Bank of Maharashtra
Jalgaon-425002

Kolhapur Region

14. Atpadi Branch
Bank of Maharashtra
Near Shri Siddhnath Chitra Mandir
Prakashwadi, Dighanchi Road
Atpadi (Distt. Sangali)-415310

Ratnagiri Region

15. Khed Branch
Bank of Maharashtra
Anandi Parvati Appartment
C. S. No. 2175 and 2176/B
Kashti Ali, P.O. Khed
Distt. Ratnagiri-415700

Mumbai City Region

16. Adarshnagar Mumbai Branch
Bank of Maharashtra
Janta Shikshan Sanstha
Adarshnagar, Worli
Mumbai-400025

Delhi Region

17. U.P.S.C. Branch
Bank of Maharashtra
Dholpur House, Shahajan Road
New Delhi-110001

Jabalpur Region

18. Satana Branch
Bank of Maharashtra
K.B. Complex, First Floor
Simaria Chouk, Riva Road
Satana-485001 (Madhya Pradesh)

Raipur Region

19. Bhilai Branch
Bank of Maharashtra
Alankar Vyavsay Parisar
Old Vijay Talkies Compound
First Floor, G.E. Road
Power House
Bhilai (Distt. Durg)-490001
(Madhya Pradesh)

खराब और उपभोक्ता मामले मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1998

का.आ. 1788.—केन्द्रीय सरकार का मैसर्स गुडलैस नेरोलेक पेन्टस लिमिटेड, पोस्ट बाक्स सं. 16322, मुम्बई-400013 द्वारा उसे प्रस्तुत किये गए तकनीकी आंकड़े/जानकारी पर विचार करने के पश्चात् समाधान हो गया है कि तकनीकी कारणों से उक्त कम्पनी के लिए बाट और माप मानक (पैक की हुई वस्तुएं) नियम, 1977 की

तृतीय अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट मानक मात्राओं में पेन्ट को उनकी पूर्ण स्वचालित कम्प्यूटरीकृत डिस्पेंसिंग मशीन के माध्यम से परिदाम के लिए पहले पैक करना संभव नहीं है;

पूर्ण स्वचालित कम्प्यूटरीकृत डिस्पेंसिंग मशीन को आधार सामग्री की किसी पूर्व परिनिश्चित मात्रा में चयनित शेड तैयार करने के लिए एक या एक से अधिक रंजकों को मिलाने के लिए बनाया जाता है और जो पूर्व योजनाबद्ध कम्प्यूटरों द्वारा नियंत्रित होती है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, माट और माप मानक (पैक की हुई वस्तुएं) नियम 1977 के नियम 5 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स गुडलास नेरोलैक पेन्ट्स लिमिटेड, पोस्ट बाक्स सं. 16322, मुम्बई-400013 को इस प्रविष्टि के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पेन्ट की आधार सामग्री को 450 मि.ली. 990 मि.लि. 3.60 लीटर, 9 लीटर और 18 लीटर के आकार में पहले पैक करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

- (1) आधार सामग्री के डिब्बे पर शुद्ध अन्तर्वस्तु के साथ-साथ वह स्पष्ट रूप से लिखित उल्लिखित किया जाएगा कि वह पेन्ट और अंतिम पेन्ट के लिए आधार सामग्री है जो ऐसे रंजकों के साथ के पश्चात् होगी जो कम्प्यूटरीकृत मशीन की सहायता से व्यवहारी द्वारा मिलाए जाएंगे।
- (2) व्यवहारी के परिसर में व्यवहारी उपभोक्ता की जानकारी के लिए सहज दृश्य स्थान पर पेंट की, आवश्यक शेड के लिए रंजकों को मिलाने के पश्चात् खुदरा विक्रय कीमत जैसी उक्त कंपनी द्वारा नियत की गई है, संप्रदर्शित करेगा।
- (3) व्यवहारी शेड का नाम, आधार सामग्री में रंजकों को मिलाने के पश्चात् तैयार पेंट की शुद्ध अन्तर्वस्तु तैयार पेंट की विक्रय कीमत और पेंट की प्रति लीटर कीमत और तारीख के व्योरो के साथ व्यवहारी का पता/पहचान चिन्ह सहित एक नकद रसीद का मुद्रित कम्प्यूटर पर्ची जारी करेगा।
- (4) उक्त कंपनी पेंट की शुद्ध अन्तर्वस्तु और शेड से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए उत्तरदायी होगी।
- (5) उपरोक्त वर्णित अनुज्ञात प्राकारों से संबंधित आधार सामग्री की शुद्ध अन्तर्वस्तु की जांच पड़ताल निदेशक, विधिक मिट्रोलाजी या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार विनिर्माण परिसर पर ही की जाएगी।

[फा.सं. डब्ल्यू.एम. 10/(3)/98]

राजीव श्रीवास्तव, अपर सचिव

MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS

(Department of Consumer Affairs)

New Delhi, the 28th August, 1998

S.O. 1788.—Whereas the Central Government, after considering the technical data/information furnished by M/s. Goodlass Nerolac Paints Limited, Nerolac House, P.O. Box 16322, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 is satisfied that for technical reasons it is not possible for the said company to prepack paints for delivery through their fully automatic computerised dispensing machine for paints in the standard quantities as specified in Third Schedule to the Standards of Weights and Measures (Packaged Commodities) Rules, 1977 ;

Whereas, the fully automatic computerised dispensing machine is designed to mix one or more colourants, to prepare the selected shades, and is controlled by a pre-programmed computer in a pre-defined quantity of base material ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to rule 5 of the Standards of Weights and Measures (Packaged Commodities) Rules, 1977, the Central Government hereby authorises M/s. Goodlass Nerolac Paints Limited, Nerolac House, P.O. Box-16322, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 to prepack base material of paints in sizes 450 ml, 990 ml, 3.60 litre, 9 litre and 18 litre for a period of five years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, subject to the following conditions, namely :—

- (1) On the base material tin, in addition to net content it shall be clearly mentioned that it is a base material for paint and the final paint shall be after addition of the colourant(s), which shall be added by the dealer with the help of the computerised machine.
- (2) In the dealers's premises the dealer shall display the retail sale price of the paint on addition of the colourant(s), for the shade(s) required, as fixed by the said company, at a conspicuous place for the information of the consumer.
- (3) The dealer shall issue a cash receipt or printed computer slip with address/identification mark of the dealer with details of name of shade, net content of finished paint after addition of colourants to the base material, the sale price of the finished paint and price per litre of paint and the date.
- (4) The said company shall be responsible for any complaint in respect of the net content and shade(s) of the paint.
- (5) The net content checking shall be carried out of the base material at manufacturing premises with respect to the above mentioned permitted sizes by the Director, Legal Metrology or the authorised person, according to the prescribed procedure.

[File No WM-10/3/98]

RAJIV SRIVASTAVA, Addl. Secy.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 जून, 1998

का.भा. 1789.—केन्द्रीय सरकार, पुरातत्व और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 (1972 का 52) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिसे उसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है और संस्कृति विभाग (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 211 (अ) तारीख 18 अप्रैल, 1980 को अधिकांत करते हुए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-2 में उल्लिखित व्यक्तियों को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापन अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अनुज्ञापन अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, उक्त सारणी के स्तम्भ-3 तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अधिकारिता के भीतर करेंगे,

क्रम सं.	अधिकारी का पदाभिधान और पता	क्षेत्र की सीमाएं
1	2	3
1.	अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आगरा मंडल, 22 माल रोड, आगरा-282001 (उत्तर प्रदेश)	आगरा, अलीगढ़, अल्मोड़ा, बदायूं, बरेली, बिजनौर, बुलंदशहर, चमोली, देहरादून, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, हरिद्वार, महामाया नगर, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पीलीभीत, पिथौरागढ़, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, टिहरी गढ़वाल, ऊधम सिंह नगर, और उत्तर काशी—उत्तर प्रदेश के जिले।
2.	अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, बंगलौर मंडल, पांचवां तल, "एफ" विंग, केन्द्रीय सदन, 17 मुख्य मार्ग, कोरमंगला, बंगलौर-560034 (कर्नाटक)	बंगलौर शहरी और ग्रामीण, बल्लारी चामराज नगर, चिकमगलूर, चिन्नबुर्ग, दक्षिण कन्नड़, दावणगेरे, हसन, कोलार, माण्ड्या, मैसूर, शिमोगा, तुमकूर, उडुपी—कर्नाटक के जिले।
3.	अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भोपाल मंडल, दूसरा तल, बी—ब्लॉक, जी टी बी काम्प्लेक्स, टी.टी.नगर, भोपाल-462003 (मध्य प्रदेश)	वालाघाट, बैतुल, भिंड, भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, बेवास, धार, गुना ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, झुझा, खंडवा (पूर्वनिमाड) खरगोन, (पश्चिम निमाड), मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सिबनी, साहूवा, शाजापुर, शिवपुरी, सीधी टीकमगढ़, उज्जैन और विदिशा—मध्य प्रदेश के जिले।
4.	अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भुवनेश्वर मंडल, ओल्ड टाउन, भुवनेश्वर-751002 (उड़ीसा)	अंगुल, बलंगीर, बालेश्वर, बारगढ़, बौध, भाद्रक, कटक, देवगढ़, धनकैनास, गजपति, गंजाम, जगतसिंहपुर, जाजपुर, झारसुगुडा, कालाहण्डी, केन्द्रपारा, कर्कोत्तर, खुरदा कोरापुर, मल्कानगिरि, मयूरभंज, नबरंगपुर, नौपाडा, नयागढ़, फुलबनी, पुरी, रायगढ़, सोनपुर और सुन्वरगढ़—उड़ीसा के जिले और बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव और सरगुजा—मध्य प्रदेश के जिले।
5.	अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, कलकत्ता मंडल, बहुमंजिला कार्यालय भवन (चौथा तल) ब्लॉक डी एफ—साल्ट लेक सिटी कलकत्ता-700064 (पश्चिमी बंगाल)	बंकुरा, बीरभूम, बर्दवान, कलकत्ता, कूच बिहार, दार्जिलिंग, हुगली, हावड़ा, जलपाई, गुड़ी, मालदा, मिदनापुर, उत्तरी धीनाजपुर, उत्तर 24 परगना, पुरुलिया, दक्षिणी धीनाजपुर, दक्षिण 24 परगना और मुर्शिदाबाद—पश्चिमी बंगाल के जिले, सिक्किम और अरुणाचल और निकोबार द्वीप समूह।
6.	अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण चंडीगढ़ मंडल, एस सी ओ, 2909-10 सेक्टर 22-सी, चंडीगढ़-160022	अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पंचकूला, पानीपत, रिवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर—हरियाणा के जिले, अमृतसर, भाँडवा, फरीदकोट, फिरोजपुर, फतेहगढ़, साहिब गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मन्सा, मोहा, मुक्तसर, नवांशहर, पटियाला, रूपनगर और संगरूर—पंजाब के जिले, बिलासपुर चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नोर, कुल्लू, लाहौल और स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना—हिमाचल प्रदेश के जिले और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र।

1	2	3
7.	अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, चेन्नई मंडल, फोर्ट सेंट जार्ज, चेन्नई-600009 (तमिलनाडु)	चेन्नई, कोयम्बटूर, गुड्डालोर, धर्मपुरी, डिन्डिगुल, इरोडे, कांचीपुरम, कन्नूर, मदुराई, नागापट्टीनम, नामाक्कल, पुडु-कोट्टई, पेरम्बलूर, रामनाथपुरम, सलेम शिव-गंगई, थंजावुर, थैनी, तिरुवन्नामलाई, तिरुवरूर, तिरुपल्लूर, टूटीकोरन, तिरुची, वेल्लोर, विरुद्धनगर और विल्लुपुरम-तमिलनाडु के जिले, पांडिचेरी और पांडिचेरी की संघ राज्य क्षेत्र का रेंज।
8.	अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, धारवाड़ मंडल, 8वां क्रम, 17वां बाई, कल्याण नगर, धारवाड़-580007 (कर्नाटक)	बेलगाम, बीदर, बीजापुर, धारवाड़, गदग, गुलबर्गा, हवेली, कोप्पल, रायचूर तथा उत्तर कन्नड़-कर्नाटक के जिले।
9.	अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, गुवाहाटी मंडल, बीकन विल्ला, आनन्द नगर, दिसपुर, गुवाहाटी-781005 (असम)	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड तथा त्रिपुरा राज्य।
10.	अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, हैदराबाद मंडल, केन्द्रीय सदन, तीसरा तल, द्वितीय खंड, मुल्तान बाजार, हैदराबाद-510195 (आंध्र प्रदेश)	अदीलाबाद, अनंतपुर, चित्तूर, कुड्डलगा, पूर्व गोदावरी (काकीनाडा मुख्यालय), गुन्तूर, हैदराबाद, करीम नगर, खम्मम, कृष्णा (मछलीपटनम मुख्यालय), कुरनूल, महबूब नगर, मेडक (संगा रेड्डी मुख्यालय), नालगोंडा, नेल्लोर, निजामाबाद, प्रकाशम, रंगा रेड्डी (हैदराबाद मुख्यालय), श्रीकाकुलम, विजय नगरम्, विशाखापटनम, वारंगल तथा पश्चिम गोदावरी (एलूर मुख्यालय), आंध्र प्रदेश के जिले।
11.	अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जयपुर मंडल, सैक्टर-7, प्लैट स. 70/133-140, पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर-302020 (राजस्थान)	अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बरान, बारमेड़, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, झुंजरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झालवार, झुनझुन, जोधपुर, करोली, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद, मवाई माधोपुर, सीकर, सिरोंही, टोंक तथा उदयपुर-राजस्थान के जिले।
12.	अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, लखनऊ मंडल, बैल्लिक गार्ड कटिंग, पो.ओ. गोलामंज, लखनऊ-226018 (उत्तर प्रदेश)	इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, बहराइच, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, फैजाबाद, फतेहपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, झांसी, कबीर नगर, कानपुर शहर, कानपुर, देहात, कौशांबी, लखीमपुर, ललितपुर, लखनऊ, महाराज क्षेमपति साहू, महोबा, प्रतापगढ़, रायबरेली, सिद्धार्थ नगर, मुल्तानपुर, श्रावस्ती नगर, सीतापुर तथा उम्राव-उत्तर प्रदेश के जिले।
13.	अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, सायन पोर्ट, सायन, मुम्बई-400022 (महाराष्ट्र)	अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड़, भांडारा, बुलढाना, चन्द्रपुर, धुले, गडचिरोली, जलगांव, जलना, कोल्हापुर, लातूर, मुम्बई, नांदेड़, नागपुर, नासिक, उस्मानाबाद, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरि, सांगली, सतारा, सोलापुर, थाणे, वर्धा तथा योतमल-महाराष्ट्र तथा गोवा के जिले।
14.	अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, दिल्ली मंडल, सफदरजंग का मकबरा, नई दिल्ली-110003।	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली।
15.	अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जे.सी. रोड, पटना-800001, (बिहार)	अररिया, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, मौजपुर, बांकारो, बक्सर, बम्पारन (पूर्व) बम्पारन (पश्चिम), छत्र, दरभंगा, देवगढ़, धनबाद, गडवा, गया, गिरिडीह, गोड्डे, गोपालगंज, गुमला, हजारीबाग, जहानाबाद, जामुई, कैमुर, कटिहार, खगारियाँ, किशनगंज, लोहार डगा, माधेपुर, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पलामू, पटना, पूर्णिया, रांची, रोहतास, महरोआ, साहेबगंज, समस्तीपुर,

1

2

3

संथाल परगना, सारन, सिंहभूम, (पूर्व), सिंहभूम (पश्चिम) सीतामढ़ी, सिवान, मुपौल तथा बंशाली बिहार के जिले और आजमगढ़, बलिया, अदोही, चंदौली, देवरिया, गोरखपुर, गाजीपुर, जोनपुर, महाराजगंज, मिर्जापुर, पटना, मोनमद तथा वाराणसी—उत्तर प्रदेश के जिले।

16. अधीक्षण पुरातत्वविद्,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,
श्रीनगर मंडल, मंटो बिल्डिंग,
राजबाग, श्रीनगर, (कश्मीर)/नूथरा बिल्डिंग,
काची छावनी, जम्मू-180001
(जम्मू-कश्मीर)

अनंतनाग, बडगाव, बारामूला, कूपवाड़ा, फूलवामा तथा श्रीनगर—कश्मीर घाटी के जिले, लेह तथा कारगिल-लद्दाख के जिले और डोडा, जम्मू, कठुआ, पंछ, रजौरी एवं ऊधमपुर—जम्मू के जिले।

17. अधीक्षण पुरातत्वविद्,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,
त्रिसूर मंडल, थोप्पिनमूला, अरनाट्टकाडा,
त्रिसूर-680618 (केरल)

अलाप्पुजा, एरनाकुलम, इडुक्की, कन्नूर, कन्नूरगोड, कोल्लम, कोट्टायम, कोजीकोडे, मलाप्पुरम, पालक्काड, पथनथिट्टा, वनन्तपुरम, त्रिसूर तथा वायनाड केरल के जिले, कन्याकुमारी, नीलगिरी, (उदुपलम) तथा तिरुवेल्ली—तमिलनाडु के जिले, माहे—संघीय प्रदेश पांडेचेरी का जिला और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र।

18. अधीक्षण पुरातत्वविद्,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,
बडोदरा मंडल, माधव बाग,
भकरपुरा रोड, सपना हॉल के निकट,
बडोदरा-390009 (गुजरात)

अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, बनासकांथा, भावनगर, भावनगर, दहोड, डोंगम, गांधीनगर, गोधरा, जामनगर, जूनागढ़, खेडा, कच्छ, मेहसाणा, नर्मदा, (राजपीपला मुख्यालय), नवसारी, पाटन, पोरबंदर, राजकोट, सबरकांथ, सूरत, सुरेन्द्र नगर, बडोदरा (बडोदा) तथा बलसाव—गुजरात के जिले और दमण और दीव।

[फा.सं. 16-3/97-पुरा०]

जे. आर. अग्रवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

New Delhi, the 23rd June, 1998

S.O.1789.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Antiquities and Art Treasures Act, 1972 (52 of 1972) hereinafter referred to as the said Act and in supersession of the notification of the Department of Culture, (Archaeological Survey of India) NO. G.S.R. 211(E), dated the 18th April, 1980, the Central Government hereby appoints the persons specified in column 2 of the table given below, being Gazetted Officers of the Central Government, to be licensing officers for the purposes of the said Act who shall exercise the powers conferred on licensing, officers by or under the said Act within the jurisdiction specified in the corresponding entry in column 3 of the table namely:

Sl. No.	Designation and address of the officer	Limits of the area
1	2	3
1.	Superintending Archaeologist, Archaeological Survey of India, Agra Circle, 22, The Mall Road. Agra-282001 (Uttar Pradesh).	Agra, Aligarh, Almorah, Badaun, Bareilly, Bijnor, Bulandshahar, Chamoli, Dehradun, Etah, Etawah, Farrukhabad, Firozabad, Ghaziabad, Haridwar, Mahamayanagar, Mainpuri, Mathura, Meerut, Muradabad, Muzaffarnagar, Nainital, Pauri Garhwal, Pilibhit, Pithorgarh, Rampur, Saharanpur, Shahjahanpur, Tehri Garhwal, Udham Singh Nagar, and, Uttar Kashi districts of Uttar Pradesh,
2.	Superintending Archaeologist, Archaeological Survey of India, Bangalore Circle, 5th Floor, 'F' Wing, Kendriya Sadan, 17th Main Road, Koramangala. Bangalore-560034 (Karnataka).	Bangalore Urban and Rural, Bellary, Chamaraja Nagar, Chikmangalur, Chitradurga, Dakshina Kannada, Davanagere, Hassan, Kolar, Mandya, Mysore, Shimoga, Tumkur and Udupi districts of Karnataka.

1	2	3
3.	Superintending Archaeologist, Archaeological Survey of India, Bhopal Circle, IInd Floor, B-Block, G.T.B. Complex, T.T. Nagar, Bhopal-462 003 (Madhya Pradesh).	Balaghat, Betul, Bhind, Bhopal, Chhatarpur, Chhindwara, Damoh, Datia, Dewas, Dhar, Guna, Gwalior, Hoshangabad, Indore, Jabalpur, Jabhua, Khandwa (Nimar East), Khargone (Nimar West, Mandla, Mandsaur, Morena, Narsingpur, Panna, Raisen, Rajgarh, Ratlam, Rewa, Sagar, Satna, Sehore, Seoni, Shahdol, Shajapur, Shivapuri, Sidhi, Tikamgarh, Ujjain and Vidisha districts of Madhya Pradesh.
4.	Superintending Archaeologist, Archaeological Survey of India, Bhubneswar Circle, Old Town, Bhubneswar-751 002 (Orissa).	Angul, Balangir, Baleswar Baragarh, Baudh, Bhadrak, Cuttack, Deogarh, Dhenkanal, Gajapati, Ganjam, Jagatsinghpur, Jajpur, Jharsuguda, Kalahandi, Kendrapada, Keonjhar, Khurda, Korapur, Malkangiri, Mayurbhanj, Nabarangpur, Naupada, Nayagarh, Phulbani, Puri, Raygarh, Sonpur and Sundergarh, districts of Orissa; and Bastar, Bilaspur, Durg, Raigarh, Raipur, Rajnandgaon, and Sarguja districts of Madhya Pradesh.
5.	Superintending Archaeologist, Archaeological Survey of India, Calcutta Circle, Multi Storeyed, Office Building, (4th Floor), Block DF, Salt Lake City, Calcutta-700 064 (West Bengal).	Bankura, Birbhum, Burdwan, Calcutta, Cooch Behar, Darjeeling, Hooghly, Howrah, Jalpaiguri, Malda, Midnapore, North Dinajpur, North 24 Parganas, Purulia, South Dinajpur, South 24 Parganas and Murshidabad districts of West Bengal; Sikkim; and Andaman and Nicobar Islands.
6.	Superintending Archaeologist, Archaeological Survey of India, Chandigarh Circle, S.C.O. 2909-10, Sector-22-C, Chandigarh-160 022.	Ambala, Bhiwani, Faridabad, Fatehabad, Gurgaon, Hissar, Jhajjar, Jind, Kaithal, Karnal, Kurukshetra, Mahendergarh, Panchkula, Panipat, Rewari, Rohtak, Sirsa, Sonapat, and Yamuna- Nagar, districts of Haryana; Amritsar, Bhatinda, Faridkot, Ferozpur, Fatehgarh, Sahib, Gurdaspur, Hoshiarpur, Jalandhar, Kapurthala, Ludhiana, Mansa, Moga, Muktsar, Newanshahar, Patiala, Rupnagar, and Sangrur, districts of Punjab; Bialspur, Chamba, Hamirpur, Kangra, Kinnaur, Kullu, Lahaul and Spiti, Mandi, Shimla, Sirmaur, Solon and Unna districts of Himachal Pradesh; and Chandigarh Union Territory.
7.	Superintending Archaeologist, Archaeological Survey of India, Chennai Circle, Fort St. George, Chennai-600 009 (Tamil Nadu)	Chennai, Coimbatore, Guddalore, Dharampuri, Dindigul, Erode, Kanchipuram, Karur, Madurai, Nagapattinam, Namakkal, Pudukkottai, Perambalur, Ramanathapuram, Salem, Sivagangai, Thanjavur, Theni, Thiruannamalai, Thiruvallur, Thiruvallur, Tuticorin, Tiruchi, Vellore, Virudunagar and Villupuram districts of Tamil Nadu; Pondicherry and Karaikkal Range of Union Territory of Pondicherry.
8.	Superintending Archaeologist, Archaeological Survey of India, Dharwad Circle, 8th Cross, 17th Ward, Kalyan Nagar, Dharwad-580007 (Karnataka).	Belgaum, Bidar, Bijapur, Dharwad, Godag, Gulbarga, Haveri, Koppal, Raichur and Uttara Kannada districts of Karnataka.
9.	Superintending Archaeologist, Archaeological Survey of India, Guwahati Circle, Vican Villa, Ananda Nagar, Dispur, Guwahati-781005 (Assam).	Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura states.
10.	Superintending Archaeologist, Archaeological Survey of India, Hyderabad Circle, Kendriya Sadan, IIIrd Floor, IInd Block, Sultar Bazar, Hyderabad-510195 (Andhra Pradesh).	Adilabad, Anantapur, Chittoor, Cuddapah, East Godavari (Kakinada H.Q.), Guntur, Hyderabad, Karim Nagar, Khammam, Krishna, (Machilipatnam H.Q.) Kurnool, Mahabub Nagar, Medak (Sanga Reddy H.Q.), Nalgonda, Nellore, Nizamabad Prakasam, Ranga Reddy (Hyderabad H.Q.), Srikakulam, Vijaya Nagaram, Visakhapatnam, Warangal and West Godavari (Eluru H.Q.) districts of Andhra Pradesh.

1	2	3
11.	Superintending Archaeologist, Archaeological Survey of India, Jaipur Circle, Sector-7, Flat No. 70/133-140, Patel Marg, Mansrovar, Jaipur-302020 (Rajasthan).	Ajmer, Alwar, Banswara, Baran, Bermer, Bharatpur, Bhilwara, Bikaner, Bundi, Chittorgarh, Churu, Dausa, Dholpur, Dungarpur, Ganganagar, Hanumangarh, Jaipur,, Jaisalmer, Jalor, Jhalwar Jhunujhunu, Jodhpur, Karauli Kota, Nagaur, Pali, Rajsamand Sawai Madhopur, Sikar, Sirohi, Tonk and Udaipur, districts of Rajasthan.
12.	Superintending Archaeologist, Archaeological Survey of India, Lucknow Circle, Baille Gaurd, Cottage, P.O. Golaganj, Lucknow-226018 (Uttar Pradesh).	Allahabad, Ambedkarnagar, Balrampur, Bahraich, Banda, Barabanki, Basti, Faizabad, Fatehpur, Gonda, Hamirpur, Hardoi, Jalon, Jhansi, Kabir Nagar, Kanpur City, Kanpur Dehat, Kaushambi, Lakhimpur, Lalitpur, Lucknow, Maharaj Kshatrapati Sahu, Mahobe, Pratapgarh, Raibareili, Siddarth Nagar, Sitapur, Sravasti Nagar, Sultanpur and Unnao, districts of Uttar Pradesh.
13.	Superintending Archaeologist, Archaeological Survey of India, Sion Fort, Sion, Mumbai-400022 (Maharashtra).	Ahmednagar, Akola, Amaravati, Aurangabad, Beed, Bhandara, Buldhana, Chandrapur, Dhule, Gadchiroli, Jalgaon, Jalna, Kolhapur, Latur, Mumbai, Nanded, Nagpur, Nasik, Osmanabad, Pune, Raigarh, Ratnagir, Sangli, Satara, Solapur, Thane, Wardha and Yeotmal, districts of Maharashtra and Goa.
14.	Superintending Archaeologist, Archaeological Survey of India, Delhi Circle, Safdarjung Tomb, New Delhi-110003.	The National Capital Territory of Delhi.
15.	Superintending Archaeologist, Archaeological Survey of India, J.C. Road, Patna-800001 (Bihar).	Araria, Aurangabad, Begusarai, Bhagalpur, Bhojpur, Bokaro, Buxar, Champaran (East), Champaran (West), Chatra, Darbhanga, Deoghar, Dhanbad, Garhwa, Gaya, Giridih, Godde, Gopalganj, Gumla, Hazaribagh, Jahanabad, Jamui, Kaimur, Katihar, Khagaria, Kishanganj, Lohardaga, Madhepura, Madhubani, Munger, Muzaffarpur, Nalanda, Nawada, Palamu, Patna, Purnia, Ranchi, Rohtas, Saharoa, Sahibaganj, Samastipur, Santhal pargans, Saran, Singhbhum (West), Singhbhum (East), Sitamarhi, Siwan, Supaul and Vaishali, districts of Bihar; and Azamgarh, Ballia, Bhadohi, Chandauli, Deoria, Gorakhpur, Ghajipur, Jaunpur, Maharajganj, Mirzapur, Padrauna, Sonbhadra and Varanasi, districts of Uttar Pradesh.
16.	Superintending Archaeologist, Archaeological Survey of India, Srinagar Circle, Moonte Building, Raj Bagh, Srinagar, (Kashmir)/Luthra Building, Kachi Chawni, Jammu-180001 (Jammu & Kashmir).	Anantnag, Badgam, Baramulla, Kupwara, Pulwama and Srinagar districts of Kashmir Velly; Leh and Kargil districts of Ladakh and Doda, Jammu, Kathua, Punch, Rajouri and Udhampur districts of Jammu.
17.	Superintending Archaeologist, Archaeological Survey of India, Thrissure Circle, Thoppinmoola, Aranattukara, Thirure-680618 (Kerala).	Alappuzha, Ernakulam, Idukki, Kannur, Kasargoda, Kollam, Kottayam Kozhikode, Malappuram, Palakkad, Pathanamthitta, Thiruvananthapuram, Thirure and Wayanad, districts of Kerala; Kenyakumari, Nilgiris (Udhangamandalam) and Tirunelveli, districts of Tamil Nadu; and Mahe district of Pondicherry, Union Territory; and Lakshadweep Union Territory.
18.	Superintending Archaeologist, Archaeological Survey of India, Vadodara Circle, Madhav Baug, Makarpura Road, Near Sapna Hall, Vadodara-390009 (Gujarat).	Ahmedabad, Amreli, Anand, Banaskantha, Bharuch, Bhavnagar Dahod, Dongs, Gandhinagar, Godhara, Jamnagar, Junagadh, Kheda, Kutch, Mehsana, Narmada (H.Q. Rajpipla), Navsari, Patan, Porbandar, Rajkot, Sabarkantha, Surat, Surendranagar, Vadodara (Baroda), and Valsad, districts of Gujarat; Daman and Diu.

परमाणु ऊर्जा विभाग

आदेश

मुम्बई, 27 अगस्त, 1998

का. आ. 1790 :—केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रक तथा अपील), नियम, 1965 के नियम 9 के उपनियम (2) नियम 12 के उपनियम (2) के खंड (ख) तथा नियम 24 के उपनियम (i) के अनुपालन में, राष्ट्रपति एतद्वारा निर्देश देते हैं कि भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के दिनांक 3 मई, 1993 के का.आ. सं. 1044 के आदेश में आगे निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् उपर्युक्त आदेश की अनुसूची में—

(क) भाग-II सामान्य केन्द्रीय सेवाएं—वर्ग “ग” शीर्षक के अन्तर्गत क्रम सं. 14 के पश्चात् तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को डाला जाएगा, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6
“14ए	रेअर मैटेरियल प्लांट मैसूर में पद	मुख्य प्रशा. अधि. रेअर मैटेरियल प्लांट, मैसूर	मुख्य प्रशा. अधि. रेअर मैटेरियल प्लांट मैसूर	सभी	नियंत्रक भागा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई”

(ख) भाग-III सामान्य केन्द्रीय सेवाएं, वर्ग “घ” शीर्षक के अन्तर्गत क्रम सं. 14 के पश्चात् तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित डाला जाएगा, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6
“14ए	रेअर मैटेरियल प्लांट मैसूर में पद	मुख्य प्रशा. अधि. रेअर मैटेरियल प्लांट, मैसूर	मुख्य प्रशा. अधि. रेअर मैटेरियल प्लांट, मैसूर	सभी	मुख्य प्रशा. अधि. रेअर मैटेरियल प्लांट, मैसूर”

[सं. 1/6(1)/95-सतर्कता/653]

कु. जूथिका पाटणकर, उप सचिव

टिप्पणी :—मूल आदेश भारत के राजपत्र में दिनांक 3/5/93 के 16(1)/91-सतर्कता के अनुसार प्रकाशित किया गया तथा तदोपरांत संशोधित किया गया।

1. आदेश सं. 1/6(1)/95-सतर्कता/351 दिनांक 14-12-93
2. आदेश सं. 1/6(1)/95-सतर्कता/375 दिनांक 24-11-94
3. आदेश सं. 1/6(1)/95-सतर्कता/276 दिनांक 16-04-97
4. आदेश सं. 1/6(2)/96-सतर्कता/791 दिनांक 20-10-97

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

ORDER

Mumbai, the 27th August, 1998

S.O. 1790.—In pursuance of sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal), Rules, 1965, the President hereby directs that the following further amendments shall be made to the order of the Government of India in the Department of Atomic Energy, No. S.O. 1044, dated the 3rd May, 1993, namely:—

In the Schedule to the said order,—

- (a) under the heading "Part II-General Central Services Group C", after serial No. 14 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

1	2	3	4	5	6
"14A	Posts in the Rare Materials Plant, Mysore.	Chief Administrative Officer, Rare Materials Plant, Mysore.	Chief Administrative Officer, Rare Materials Plant, Mysore	All	Controller, Bhabha Atomic Research Centre Mumbai."

- (b) under the heading "Part-III—General Central Services Group D", after serial No. 14 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5	6
"14A.	Posts in the Rare Materials Plant, Mysore.	Administrative Officer-III, Rare Materials Plant, Mysore.	Administrative Officer-III, Rare Materials Plant, Mysore.	All	Chief Administrative Officer, Rare Materials Plant, Mysore."

[No. 1/6(1)/95-Vig./653]

Kum. Juthika Patankar, Dy. Secy.

Note :—The Principal Order was issued vide No. 1/6(1)/91-Vig. dated 3-5-93 and subsequently amended by:—

1. Order No. 1/6(1)/95-Vig./351 dated 14-12-93
2. Order No. 1/6(1)/95-Vig./375 dated 24-11-94
3. Order No. 1/6(1)/95-Vig./276 dated 16-4-97.
4. Order No. 1/6(2)/96-Vig./791 dated 20-10-97.

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1998

का० आ० 1791.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र भाग-II, खंड-3 उपखंड (ii) तारीख 28 मई, 1994 में प्रकाशित भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1250 तारीख 15-4-1994 को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के निम्नलिखित अधिकारियों को, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (1910 का 9) की धारा 36 के उपखंड (i) के अधीन नियुक्त केन्द्रीय विद्युत निरीक्षक की सहायता करने के लिए अधिकारी नियुक्त करती है, अर्थात्:—

क्र०सं० अधिकारी का नाम पदनाम

1	2	3
1. प्रेमचन्द		उप निदेशक
2. ए० के० जैन		उप निदेशक
3. कान्ति प्रसाद		उप निदेशक
4. ओ० पी० गुप्ता		उप निदेशक
5. आशोक नाथ		उप निदेशक

1	2	3
6. रविन्दर		अधीक्षण अभियन्ता
7. एस० सी० नाकिरा		उप निदेशक
8. एस० ए० खान		सहायक निदेशक
9. ए० के० वर्मा		सहायक निदेशक-2
10. पी० पटेल		अधीक्षण अभियन्ता
11. एम० हेमब्रम		उप निदेशक
12. एन० रामलिंगम		अधीक्षण अभियन्ता
13. एस० श्रीनिवासन		सहायक निदेशक-1
14. एस० एन० कायल		उप निदेशक
15. आर० पी० गुप्ता		सहायक निदेशक-2
16. एम० शिवकुमार		सहायक निदेशक-2

[का० सं० 25/1/90-डी (एस ई बी) खंड-2]

पी० आई० मृवरतन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 18th August, 1998

S.O.1791.—In exercise of the powers conferred by rule 4A of the Indian Electricity Rules, 1956 and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Power, No. S.O. 1250

dated the 15th April, 1994, published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, dated the 28th May, 1994, the Central Government hereby appoints the following officers of Central Electricity Authority to be the officers to assist the Electrical Inspector appointed under sub-section (1) of Section 36, of the Indian Electricity Act, 1910 (9 of 1910), namely;—

S. No.	Name of the officer	Designation
1	2	3
	S/Shri	
1.	Prem Chand	Deputy Director
2.	A.K. Jain	Deputy Director
3.	Kanti Prasad	Deputy Director
4.	O.P. Gupta	Deputy Director
5.	Ashish Nath	Deputy Director
6.	Ravinder	Superintending Engineer
7.	S.C. Nakra	Deputy Director
8.	S.A. Khan	Assistant Director-I
9.	A.K. Verma	Assistant Director-II
10.	P. Patel	Superintending Engineer
11.	M. Hembram	Deputy Director
12.	N. Ramalingam	Superintending Engineer
13.	S. Srinivasan	Assistant Director-I
14.	S.N. Kayal	Deputy Director
15.	R.P. Gupta	Assistant Director-II
16.	M. Shivakumar	Assistant Director-II

[F.No. 25/1/90-D(SEB)-Vol. II]

P. L. SUBRATHAN, Jt. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग)
शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 25 जून 1998

का.आ. 1792.—भारत के राजपत्र भाग-II, खंड-3, उपखण्ड (ii) तारीख 17 फरवरी, 1998 में प्रकाशित अधिसूचना सा.का. 518 में आए निम्नलिखित शब्दों को इस प्रकार पढ़ा जाए :—

1. पृष्ठ 1, पैरा 1, पंक्ति 6 में "संशोधन" को "संशोधित"
2. पृष्ठ 1, पैरा 2, पंक्ति-2 में "कमलेश्वर" को "कामेश्वर"
3. सं. बी. 26015(1) /92 को बी. 26015/1/92
4. पृष्ठ 2, नोट के क्र. सं. 3 में सा.का. 2313 को 2323
5. क्र.सं. 8 में "28 फरवरी" को "20 फरवरी"
6. क्र.सं. 13 में "1191" को "1911"
7. क्र.सं. 19 और 20 में "1986" को 1996
"द्वारा अन्तःस्थापित की"
8. क्र.सं. 4 में "923" को "923 (अ.)"

[संख्या-बी-26015/1/92-ए.ई./आई एस. एम. (तकनीकी)]
चिरंजी लाल, अवसर सचिव,

(Department of ISM&H)

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

CORRIGENDUM

New Delhi, the 25th June, 1998

S.O. 1792.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Indian System of Medicine and Homoeopathy), number S.O. 518, dated the 17th February, 1998 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 17th February, 1998 at page 2—

- (a) in line 3, for "1978 (48 of 1978)", read "1970 (48 of 1970)".
- (b) in line 4, for "ceutral", read "Central".
- (c) in the Foot Note, against serial number 40, for "S.O. 923", read "S.O. 923(E)".

[No. V-26015/1/92-AE/ISM(Tech.)]

CHIRANJI LAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1998

का.आ. 1793.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त दूसरी अनुसूची के भाग 1 में, "मध्यप्रदेश" शीर्षक के अधीन —

- (i) क्रम संख्या 45 के सामने स्तम्भ 4 में "1965 से आगे" शब्दों और अंकों के स्थान पर "1965 से 1982 तक" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(2). क्रम सं. 45 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

1	2	3	4
45क	बेनी ग्राहिया विश्वविद्यालय, इन्दौर	आयुर्वेदार्थ (बैथलर आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी)	बी.ए.एम. एस. 1983 से आगे

[सं. बी. 26015/3/96-आयु. एवं सिद्ध भा.चि./प. (टेक)]

कमल दास अवर सचिव

नोट : भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय अधिनियम, 1970 (1970 का 48) को दूसरी अनुसूची को उक्त अधिनियम के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिसूचना संख्या द्वारा प्रकाशित और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया था:—

1. सा.का. 4068 तारीख 30 नवम्बर, 1978
2. सा.का. 2635 तारीख 18 सितम्बर, 1980
3. सा.का. 2323 तारीख 20 अगस्त, 1981
4. सा.का. 2314 तारीख 22 अगस्त, 1981
5. सा.का. 137 तारीख 24 दिसम्बर, 1981
6. सा.का. 630 तारीख 25 जनवरी, 1982
7. सा.का. 661 तारीख 2 फरवरी, 1982
8. सा.का. 973 तारीख 20 फरवरी, 1982
9. सा.का. 354ई तारीख 6 मई, 1983
10. सा.का. 3350 तारीख 5 सितम्बर, 1983
11. सा.का. 804ई तारीख 11 नवम्बर, 1983
12. सा.का. 462ई तारीख 23 जून, 1984
13. सा.का. 1911 तारीख 17 अप्रैल, 1985
14. सा.का. 2745 तारीख 29 मई, 1985
15. सा.का. 3404 तारीख 5 जुलाई, 1985
16. सा.का. 4057 तारीख 14 अगस्त, 1985
17. सा.का. 5603 तारीख 2 दिसम्बर, 1985
18. सा.का. 5671 तारीख 5 दिसम्बर, 1985
19. सा.का. 832 तारीख 17 फरवरी, 1986 द्वारा अन्तः स्थापित की गई
20. सा.का. 1832 तारीख 16 अप्रैल, 1986 द्वारा अन्तः स्थापित की गई
21. सा.का. 627 तारीख 2 फरवरी, 1987
22. सा.का. 760 तारीख 25 फरवरी, 1987
23. सा.का. 1030 तारीख 30 मार्च, 1987
24. सा.का. 1946 तारीख 9 जुलाई, 1987
25. सा.का. 3186 तारीख 30 अक्टूबर, 1987
26. सा.का. 1697 तारीख 15 अप्रैल, 1988
27. सा.का. 1504 तारीख 22 अप्रैल, 1988
28. सा.का. 1040 तारीख 6 अप्रैल, 1989

1	2	3
29. सा.का.	1910 तारीख	21 जुलाई, 1989
30. सा.का.	2177 तारीख	14 अगस्त, 1989
31. सा.का.	2594 तारीख	21 सितम्बर, 1989
32. सा.का.	969ई तारीख	29 नवम्बर, 1989
33. सा.का.	2552 तारीख	22 अगस्त, 1990
34. सा.का.	3246 तारीख	31 अक्टूबर, 1990
35. सा.का.	2669 तारीख	29 अगस्त, 1991
36. सा.का.	630 तारीख	17 जनवरी, 1992
37. सा.का.	1435 तारीख	7 मई 1992
38. सा.का.	3110 तारीख	11 अक्टूबर, 1994
39. सा.का.	3375 तारीख	18 अक्टूबर, 1996
40. सा.का.	923ई तारीख	29 दिसम्बर, 1997
41. सा.का.	518 तारीख	17 फरवरी, 1998
42. सा.का.	170ई तारीख	6 मार्च, 1998

New Delhi, the 28th August, 1998

S.O.1793.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government, after consulting the Central Council of Indian Medicine hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely:—

In the said Second Schedule in Part I, under the heading “Madhya Pradesh” (i) against Serial No. 45, in column 4, for the words and figures “From 1965 onwards” the words and figures “From 1965 to 1982” shall be substituted, (ii) after serial No. 45 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

1	2	3	4
45A Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore	Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery)	BAMS	From 1983 onwards.

[No. V. 26015/3/96-Ay. & S./ISM (Tech.)]

KANWAL DASS, Under Secy.

NOTE :—The Second Schedule and Fourth Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) has been subsequently amended vide :—

1. S.O. 4068, dated the 30th November, 1979.
2. S.O. 2635, dated the 18th September, 1980.
3. S.O. 2323, dated the 20th August, 1981.
4. S.O. 2314, dated the 22nd August, 1981.
5. S.O. 137, dated the 24th December, 1981.
6. S.O. 638, dated the 25th January, 1982.
7. S.O. 661, dated the 2nd February, 1982.
8. S.O. 973, dated the 20th February, 1982.
9. S.O. 354(E), dated the 6th May, 1983.
10. S.O. 3550, dated the 5th September, 1983.
11. S.O. 804(E), dated the 11th November, 1983.

- | 1 | 2 | 3 |
|-----|---|---|
| 12. | S.O. 462(E), dated the 23rd June, 1984. | |
| 13. | S.O. 1911, dated the 17th April, 1985. | |
| 14. | S.O. 2745, dated the 29th May, 1985. | |
| 15. | S.O. 3404, dated the 5th July, 1985. | |
| 16. | S.O. 4057, dated the 14th August, 1985. | |
| 17. | S.O. 5603, dated the 2nd December, 1985. | |
| 18. | S.O. 5671, dated the 5th December, 1985. | |
| 19. | Inserted by S.O. 822, dated 17-2-86. | |
| 20. | Inserted by S.O. 1832, dated 16-4-1986. | |
| 21. | S.O. 627, dated the 2nd February, 1987. | |
| 22. | S.O. 760, dated the 25th February, 1987. | |
| 23. | S.O. 1030, dated the 30th March, 1987. | |
| 24. | S.O. 1946, dated the 9th July, 1987. | |
| 25. | S.O. 3186, dated the 30th October, 1987. | |
| 26. | S.O. 1697, dated the 15th April, 1988. | |
| 27. | S.O. 1504, dated the 22nd April, 1988. | |
| 28. | S.O. 1040, dated the 6th April, 1989. | |
| 29. | S.O. 1910, dated the 21st July, 1989. | |
| 30. | S.O. 2177, dated the 14th August, 1989. | |
| 31. | S.O. 2594, dated the 21st September, 1989. | |
| 32. | S.O. 969, dated the 29th November, 1989. | |
| 33. | S.O. 2552, dated the 22nd August, 1990. | |
| 34. | S.O. 3246, dated the 31st October, 1990. | |
| 35. | S.O. 2669, dated the 29th August, 1991. | |
| 36. | S.O. 630, dated the 17th January, 1992. | |
| 37. | S.O. 1435, dated the 7th May, 1992. | |
| 38. | S.O. 3110, dated the 11th October, 1994. | |
| 39. | S.O. 3375, dated the 18th October, 1996. | |
| 40. | S.O. 923 (E) dated the 29th December, 1997. | |
| 41. | S.O. 518 dated the 17th February, 1998. | |
| 42. | S.O. 170(E) dated the 6th March, 1998. | |

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय

(शहरी विकास विभाग)

(दिल्ली प्रभाग)

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1998

का.आ. 1794 --यतः निम्नांकित क्षेत्रों के बारे में कुछ संशोधन, जिन्हें केन्द्रीय सरकार अधोर्षणित क्षेत्रों के बारे में दिल्ली बृहद योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में प्रस्तावित करती है तथा जो दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 13-12-97 के नोटिस सं. एफ 3(44)/94-एम पी द्वारा प्रकाशित किये गये थे जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 11ए की उपधारा (3) में अपेक्षित आपत्तियों/सुझाव, उक्त नोटिस की तारीख के 30 दिन की अवधि में आमंत्रित किये गये थे।

और यतः प्रस्तावित संशोधनों के बारे में जनता से कुछ आपत्तियाँ और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं और यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पक्षों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली बृहद योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11ए की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली की उक्त बृहद योजना में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :--

संशोधन : पृष्ठ 155 (बायीं ओर) पर शीर्षक ए-3, ग्रामीण उपयोग जोन (ए-2 सहित) के तहत बी (ii) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाय :--

“सम्पीडित प्राकृतिक गैस (सी एन जी) उपयोग को “सार्वजनिक उपयोगिता” में शामिल किया तथा क्षेत्रीय पाकों व विकसित जिला पाकों के अलावा अन्य सभी उपयोग ज़ोनों में उसकी अनुमति दी जाये।”

पृष्ठ 162 (दायीं ओर) पर शीर्षक “पेट्रोल पंप” (030) के अन्तर्गत (iv) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाये:

“कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सी एन जी) मबर स्टेशन

(क) प्लॉट का आकार (अधिकतम) 36मी. × 30मी.

(ख) अधिकतम ग्राउंड कवरेज 20%

(ग) अधिकतम ऊंचाई 4.5 मी. (एक मंजिला)

(घ) भवन घटक नियंत्रण कक्ष कार्यालय वितरण यूनिट, अनुरक्षण कक्ष, स्टोर, पेट्री तथा डब्ल्यू.सी.”

[सं. के-20013/32/96-डीडी-आईबी]
बी.के. मिश्रा, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT

(Department of Urban Development)

(Delhi Division)

New Delhi, the 1st September, 1998

S.O. 1794.—Whereas certain modifications which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan regarding the area mentioned hereunder were published vide notice No. F 3(44)/94-MP dated 13-12-97 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas no objection was received with regard to the said modification and whereas the Central Govt. have after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(2) of Section 11 A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATIONS

On page 155 (LHS) under the heading A-3. Rural use Zone (including A-2) after b(ii), the following shall be added :

“Compressed Natural Gas (CNG) Use included in ‘Public Utility’ and permitted in all use zones except in Regional Parks and developed District Parks”.

On page 162 (RHS) under the heading ‘Petrol Pumps’ (030) after (iv), the following shall be added :

“Compressed Natural Gas (CNG) Mother Station.”

(a) Plot Size (Max.) 36m × 3m.

(b) Maximum Ground coverage 20 per cent

(c) Maximum height 4.5 (Single Storey)

(d) Building Components Control room[office]

Dispensing unit,
maintenance room,
store, pantry and WC”.

[No. K-20013/32/96-DDIB]
V K MISRA, Desk Officer

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1998

का.आ. 1795—केन्द्रीय सरकार एतद्वारा तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) की धारा 3 का उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव श्री टी. एस. विजयराघवन को श्री प्रवीर सैनगुप्ता के स्थान पर 28 अगस्त, 1998 से और अगले आदेशों तक तेल उद्योग विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[बंदवा जी-35012/3/92-वित्त-II]

मोहित सिन्हा, उप सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND

NATURAL GAS

New Delhi, the 31st August, 1998

S.O. 1795.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 3 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri T. S. Vijayaraghavan, Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas as the Chairman of the Oil Industry Development Board vice Shri Prabir Sengupta with effect from 28th August, 1998, and until further orders.

[No. G-35012/3/92-Fin. II]

MOHIT SINHA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1998

का.आ. 1796.— केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1317 तारीख 25 जून 1998, द्वारा पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में बिनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को 4 जुलाई, 1998 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में बिनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना चाहिए;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में बिनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है;

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार, केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए सभी विलुप्तियों से मुक्त होकर भारत ओमान रिफाइनरीज़ लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जिला का नाम	तालुका का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण सं./ खंड सं.	राज्य: गुजरात		
				क्षेत्र		
				हेक्टर	आरे	सेन्टीआरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
जामनगर	जामनगर	सापर	85 पैकी	0	30	45
		आमरा	584 पैकी	0	07	13
		वसई	32 पैकी	0	02	00
		कनसुमरा	295 पैकी	0	16	44
		जामनगर	1115/2	0	27	00
		अलीया वाडा	142/2	0	33	00
			163/2 पैकी	0	04	00
	धोल	रोझीया	90 पैकी	0	00	60
		हमापर	228	0	25	80
			227	0	20	45
			146	0	10	84
				0		
राजकोट	पह धरी	खजुरडी	254 पैकी	0	34	20
			2/1 पैकी	0	55	20
			2/1 पैकी	0	45	30
	वांकाणे	वाल्मसम्भ	151/2 पैकी	0	35	31
		पीपलीया राज	265/4	0	21	30
			265/3	0	19	58
		राजावड ला	246/2	0	31	04

[फा. सं. आर-31015/37/97-ओ आर. II]

के. सी. कटोच, अवर सचिव

New Delhi, the 7th September, 1998

S.O.1796.— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, No. S. O. 1317, dated the 25th day of June 1998 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transport of petroleum;

And whereas, the copies of the said gazette notification were made available to the public on the 4th day of July, 1998 ;

And whereas, the Competent authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest, free from all encumbrances, in the Bharat Oman Refineries Limited;

Schedule

Name of District	Name of Taluka	Name of Village	Survey No./ Block No.	State : Gujarat		
				Area		
				Hectare	Are	Centare
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jamnagar	Jamnagar	Sapar	85 Paiki	0	30	45
		Amra	584 Paiki	0	07	13
		Vasai	32 Paiki	0	02	00
		Kansumara	295 Paiki	0	16	44
		Jamnagar	1115/2	0	27	00
		Aliabada	142/2	0	33	00
			163/2 Paiki	0	04	00
	Dhrol	Rojhiya	90Paik	0	00	60
		Hamapar	228	0	25	80
			227	0	20	45
Rajkot	Padadhari	Khajurdi	146	0	10	84
			254Paiki	0	34	20
			2/1Paiki	0	55	20
	Wankaner	Valasan	2/1Paiki	0	45	30
			151/2 Paiki	0	35	31
			Pipaliya Raj	0	21	30
			265/3	0	19	58
		Rajavadla	246/2	0	31	04

[File No. R-31015/37/97-OR.II]

K. C Katoch, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1998

का.आ. 1797.— केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाईप-लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन तारीख 04 जुलाई, 98 के राजपत्र के पृष्ठ क्रमांक 2401 पर जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्रकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1319, तारीख 25 जून 1998 द्वारा पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ हितवन्ध व्यक्तियों को तारीख 18 जुलाई 1998 तक उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब उक्त अधिनियम का धारा 6 की उपधारा (1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार यह घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाता है।

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार, केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर भारत ओमान रियायनरीज लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

राज्य : मध्य प्रदेश

क्रम संख्यांक	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर / आर
1	2	3	4	5	6
1.	राजगढ़	सारंगपुर	सेमली लोढ़ा	544	0.350
			भ्याना	267	0.150
		ब्यावरा	बोंकपुरा	190	0.030
2.	गुना	राघौगढ़	कजलिया	161 / 1-2-3	0.334
3.	बिदिशा	लटेरी	बहादुरपुर	54	0.051
				142	0.506
		कुरवाई	दोंगी कुमारिया	272	0.021

के. सी. कटोच, अवर सचिव
(सं. आर 31015/39/97 - ओ.आर II)

New Delhi, the 7th September, 1998

S.O. 1797.— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 1319 dated 25th day of June, 1998, issued under subsection (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated 04th July, 1998, at page no. 2402, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transport of petroleum;

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public from 18th July, 1998;

And whereas, the Competent Authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas, the central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in lands specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest free from all encumbrances, in Bharat Oman Refineries Limited.

SCHEDULE

State : Madhya Pradesh

Sr. No.	District	Tehsil	Name of Village	Survey No.	Area
					Hectare / Are
1	2	3	4	5	6
1.	Rajgarh	Sarangpur	Samli Lodha	544	0.350
			Bhyana	267	0.150
2.	Guna	Biaora	Bankpura	190	0.030
3.		Raghogarh	Kajaliya	161 / 1-2-3	0.334
4.	Vidisha	Lateri	Bhadurpur	54	0.051
				142	0.506
		Kurwai	Dangi Kumariya	272	0.021

K.C.Katoch, Under Secy.
(No. R - 31015/39/97 - OR - II)

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1998

का.आ. 1798.— केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1315 तारीख 25 जून 1998, द्वारा पेट्रोलियम के परिवहन के लिए भारत ओमान रिफाईनरी लिमिटेड ने गुजरात राज्य में वाडीनार से मध्यप्रदेश राज्य में बीना तक पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को 21 जुलाई, 1998 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना चाहिए;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित किए जाते हैं;

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार, केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए सभी विल्लगों से मुक्त होकर भारत ओमान रिफाईनरी लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जिला का नाम	तालुका का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण सं./ खंड सं.	राज्य: गुजरात		
				क्षेत्र		
(1)	(2)	(3)	(4)	हेक्टर	आरे	सेन्टीआरे
वडोदरा	सावली	जाम्बुगोरल	477/1	0	11	50
		वच्छे सर	130/1/2	0	25	50
दाहोद	लिमखेडा	परप टा	44/8	0	14	58
		मान्ती	4/1	0	13	02
		अगारा	177/2	0	02	40

[फा. सं. आर-31015/2/98 -ओआर. II]

के. सी. कटोच, अवर सचिव

New Delhi, the 7th September, 1998

S.O. 1798.— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, No. S. O. 1315, dated the 25th June 1998 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transport of petroleum from Vadinar in the state of Gujarat to Bina in the state of Madhya Pradesh by the Bharat Oman Refineries Limited;

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 21st day of July, 1998 ;

And whereas, the competent authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest, free from all encumbrances, in the Bharat Oman Refineries Limited;

Schedule

State : Gujarat

Name of District	Name of Taluka	Name of Village	Survey No./ Block No.	Area		
				Hectare	Are	Centare
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Vadodara	Savli	Jambugoral	477/1	0	11	50
		Wacchesar	130/1/2	0	25	50
Dahod	Limkheda	Parpata	44/8	0	14	58
		Manli	4/1	0	13	02
		Agara	177/2	0	02	40

[File No. R-31015/2/98 -OR.II]

K. C. Katoch, Under Secy.

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1998

का.आ. 1799.—केंद्रीय सरकार, कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 §1973 का 26§ की धारा 3 की उपधारा §3§ के खण्ड §क§ के उपखण्ड§iii§ के मद §4§ द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का0आ0 151§अ§ तारीख 27 मार्च, 1996 को अधकृत करते हुए सैण्डल इण्डिया कोल कम्पनी लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 §1956 का 1§ के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है, द्वारा बार्ज I-IV यानोरा दीप और किलहौनी कोयला खानों से सैण्डल इण्डिया पावर कम्पनी लिमिटेड को, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 § 1956 का 1 § के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है, "तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए कोयले के प्रदाय को" उसके अन्तिम उपयोग के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :-

§i§ कोयले का प्रदाय और अन्य खनन सौकर्याप, महाराष्ट्र राज्य में ऑर्डनेंस कारखाना, चौदा की सोमा दीवार से तीन किलोमीटर की परिधि के भीतर, सैण्डल इण्डिया कोल कम्पनी लिमिटेड द्वारा यथास्थित, नहीं किया जाएगा या नहीं चलाई जाएगी;

§ii§ इस्पात ऊर्जा लिमिटेड, मारिशस, सभी समयों पर सैण्डल इण्डिया कोल कम्पनी लिमिटेड और सैण्डल इण्डिया पावर कम्पनी लिमिटेड प्रत्येक की मत देने संबंधी साधारण शेयर पूंजी का कम से कम 26 प्रतिशत धारण करेगा; और

§iii§ सैण्डल इण्डिया पावर कम्पनी लिमिटेड को कोयले का प्रदाय केवल एकमात्र तापीय विद्युत उत्पादन के प्रयोजन के लिए किया जाएगा ।

[फा. सं. 47011/3/93-सीपीए/सीए]

जी. बी. मुखर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 11th September, 1998

S.O. 1799.— In exercise of the powers conferred by item (4) of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (3) of section 3 of the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 (26 of 1973), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 151(E) dated the 27th March, 1996 the Central Government hereby specifies the "supply of coal for thermal power generation" by the Central India Coal Company Limited, a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956), from the coal mines of Baranj I-IV, Manora Deep and Kilhoni to the Central India Power Company Limited, a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956), as "an end use" on the following conditions, namely:-

- (i) that the supply of coal and other mining operations shall not be made or carried out, as the case may be, by the Central India Coal Company Limited within a radius of three kilometers from the boundary wall of the Ordnance Factory, Chanda in the State of Maharashtra;
- (ii) that the Ispat Urja Limited, Mauritius, shall hold, at all times, at least twenty-six per cent, of voting equity share capital of each of the Central India Coal Company Limited and the Central India Power Company Limited; and
- (iii) the supply of the coal shall be only to the Central India Power Company Limited and for the sole purpose of thermal power generation.

[F. No. 47011/3/93-CPA/CA]

G. B. MUKHERJI, Jt. Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1998

का०आ० 1800.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पश्चिम रेलवे, रतलाम (म०प्र०) के प्रबन्धतन्त्र के सम्बद्ध लियोजवों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर क पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-8-98 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-41011/33/91-आई०आर० (डी०यू०)]

पी० जे० माईकल, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 21st August, 1998

S.O. 1800.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Western Railway, Ratlam (M.P.) and their workman, which was received by the Central Government on 21-8-98.

[No. L-41011/33/91-IR(D.U.)]
P. J. MICHAEL, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, जबलपुर (म०प्र०)

डी० एन० दीक्षित

पीठासीन अधिकारी

एवाडे

(वि० 27-7-98 को पारित)

प्र०अ०सी०जी०आई०टी०/एल०सी०/आर०/201/91

1. इस आदेश के द्वारा नीचे लिखे प्रकरणों का निराकरण होता है :—

प्र०अ०सी०जी०आई०टी०/एल०सी०/आर०/201/91

श्री कुन्धन वर्मा और अन्य —प्रार्थी

एक्स-टिकट कलेक्टर,

पश्चिम रेलवे, रतलाम (म०प्र०)

विरुद्ध

डिवीजनल रेलवे मैनेजर, —प्रतिप्रार्थी

पश्चिम रेलवे, रतलाम (म०प्र०)

प्र०अ०सी०जी०आई०टी०/एल०सी०/आर०/218/93

श्री अरुण शर्मा और अन्य —प्रार्थी

द्वारा : श्री सूर्यकान्त पुत्र बसन्त राम

54, बारसी मार्ग, माधवनगर,

फ्रीगंज, उज्जैन (म०प्र०)

विरुद्ध

डिवीजनल रेलवे मैनेजर, —प्रतिप्रार्थी

पश्चिम रेलवे, रतलाम (म०प्र०)

प्र०अ०सी०जी०आई०टी०/एल०सी०/आर०/220/91

श्री दीपक कोहली और अन्य

—प्रार्थी

द्वारा : श्री डी० एन० कोहली,
सेवानिवृत्त मुख्य टिकट निरीक्षक,
दीपभवन, फ्रीगंज रोड,
रतलाम (म०प्र०)

विरुद्ध

डिवीजनल रेलवे मैनेजर,

—प्रतिप्रार्थी

पश्चिम रेलवे, रतलाम (म०प्र०)

प्र०अ०सी०जी०आई०टी०/एल०सी०/आर०/217/93

श्री संजय परिहार और अन्य

—प्रार्थी

शीतलामाता की गली,

फ्रीगंज रोड, रतलाम (म०प्र०)

विरुद्ध

डिवीजनल रेलवे मैनेजर,

पश्चिम रेलवे, रतलाम (म०प्र०)

—प्रतिप्रार्थी

2. (क) भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश न० एल-41011/33/91-आई०आर० (डी०यू०) दिनांकित 30-10-91 के द्वारा निम्नलिखित विवाद निराकरण हेतु इस अधिकरण को भेजा है :—

अनुसूची

"Whether the action of the management of Divisional Railway Manager, Western Railway, Ratlam in terminating the services of S/Sh. Kundan Verma, Ravikant, Pradip Bahdwar, Kailash Sharma, Kenny Sampson and Rakesh Pandey is justified? If not to what relief they are entitled to?"

(ख) भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली अपने आदेश सं० एल-41011/36/92-आई०आर० (डी०यू०) दिनांकित 5-10-93 के द्वारा निम्नलिखित विवाद निराकरण हेतु इस अधिकरण को भेजा है :—

अनुसूची

"Whether the action of the management of Western Railway in terminating the services of S/Shri Suryakant, Arun Kumar, Hemant Kumar, Mahesh Kumar, Mohd. Nseem, Surendra Singh and Kum. Mamta after engaging them as ABC/ALC/Volunteer T.C. in Ratlam Division during the summer season of the years 1982 to 1985 is justified? If not, to what relief the workmen are entitled to?"

(ग) भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने आदेश संख्या एल-41011/35/92-आई०आर० (डी०यू०) दिनांक 5-10-93 के द्वारा निम्नलिखित विवाद निराकरण हेतु इस अधिकरण को भेजा है :—

अनुसूची

"Whether the action of the management of Western Railway in terminating the services of S/Shri Sanjay Parihar, Ashok Bhargava, Ganpati Sharma, Bharat Singh Deevda and Rakesh Jindal, Voluntary Ticket Collectors, after engaging them for various periods during the years 1982 to 1985 is justified? If not, to what relief the workmen are entitled to?"

(ब) भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने अधिसूचना सं० एल-41012/29/91-आई०आर० (डी० यू०) दिनांक 19-11-91 के द्वारा निम्नलिखित विवाद निराकरण हेतु इस अधिकरण को भेजा है:—

अनुसूची

"Whether the action of the management of Divl. Railway Manager, Western Railway, Ratlan in terminating the services of S/Shri Deepak Kohli, Harish Chander, Kum. Philomena Peater, Kum. Savito Mehta, Vijayant Singh, Kum. Kshama Parihar and Narain Singh is justified? If not, what relief they are entitled to?"

3. चारों प्रकरणों में श्रमिक के अनुसार इन्होंने वर्ष 1983 से 1986 के बीच पश्चिम रेलवे के भिन्न-भिन्न स्टेशनों पर अस्थाई टिकट कलेक्टर के रूप में कार्य किया है। इन सभी ने 120 दिन से ज्यादा काम किया है। ऐसी स्थिति में पश्चिम रेलवे के नियमों के अनुसार वे टेम्पोरेरी कर्मचारी हो गए हैं। नियमों के अनुसार इन सभी श्रमिकों को तृतीय श्रेणी में प्रबन्धन को रखना चाहिए। मौखिक आदेश पर श्रमिकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। प्रत्येक श्रमिक को वर्ग-3 श्रेणी के कर्मचारी होने की शैक्षणिक योग्यता है। श्रमिकों ने लगातार प्रयास किया कि उनको तृतीय श्रेणी में ले लिया जाए, किन्तु वे सफल नहीं हुए। रेलवे बोर्ड ने अपने आदेश दिनांक 21-4-82, 20-4-85 और 29-10-85 के द्वारा यह निर्देश दिये हैं कि इस प्रकार के जिन कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता है तथा जिनकी आयु इस प्रकार के पद पाने के योग्य है तथा जिन्होंने तीन वर्ष तक रेलवे की सेवा की है, उनको तृतीय श्रेणी के पद दिए जाएं। रेलवे बोर्ड ने यह भी आदेश दिये कि टुकड़ों में भी अगर 120 दिन की सेवा श्रमिकों ने की है तो उनको टेम्पोरेरी स्टेटस दे दिया जाए। डिवीजनल रेलवे मैनेजर, रतलाम ने श्रमिकों को श्रेणी-4 का पद देने का सुझाव दिया। श्रमिकों के अनुसार इस प्रकार का प्रस्ताव अवैधानिक है। कर्मचारियों के अनुसार उन्होंने सभी अवधि तक रेलवे में काम किया है और इनको टेम्पोरेरी रेलवे कर्मचारी का स्टेटस मिल गया है। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। बिना नोटिस के श्रमिकों को निकालना अवैधानिक है। श्रमिक चाहते हैं कि उन्हें पुनः सेवा में लिया जाए तथा उन्हें तृतीय श्रेणी का पद दिया जाए। जितने दिनों श्रमिकों ने सेवा की अवधि में काम किया है, उसको जोड़कर उन्हें उनकी पावता के अनुसार तृतीय श्रेणी का पद दिया जाए।

4. प्रबंधन डिवीजनल रेलवे मैनेजर, रतलाम के अनुसार प्रत्येक श्रमिक को वालिंटियर के रूप में लिया गया था तथा प्रत्येक ने स्थाई रेलवे कर्मचारी की मदद की थी। इनको वर्ष 83 से 85 के बीच में प्रत्येक काम के दिन 8/- रुपये प्रतिदिन जेबवर्च दिया गया था। कोई भी श्रमिक टेम्पोरेरी स्टेटस पाने का पात्र नहीं है और वर्ग-3 का स्थाई पद पाने का पात्र नहीं है। रेलवे में वर्ग-तीन में नियुक्ति रेलवे रिज्यूमेंट बोर्ड के माध्यम से की जाती है। जिस अवधि में श्रमिक वालिंटियर के रूप में काम कर रहे थे, उसमें दूसरे लोगों के साथ रेलवे रिज्यूमेंट बोर्ड की

परीक्षा दे सकते थे। श्रमिकों को वालिंटियर के रूप में रखा गया था। इनको कोई पद नहीं दिया गया था। इन कार्य के लिए श्रमिकों को वेतन नहीं मिलता था। उनको जो 8/- रुपये प्रतिदिन दिया जाता था, वह जेबवर्च था। रेलवे बोर्ड के सरकूलर का सम्बन्ध अस्थाई कर्मचारियों से है जबकि श्रमिक केशन वालिंटियर थे। वर्ष 86 में वालिंटियर बनने की स्क्रीन समाप्त कर दी गई है। श्रमिकगण टेम्पोरेरी स्टेटस नहीं पा सकते, क्योंकि यह केवल मजदूरों को दिया जाता है। प्रबंधन चाहता है कि श्रमिकों ने अकारण ही विवाद उत्पन्न किया है और इन्हें व्यय सहित निरस्त किया जाए।

5. पश्चिम रेलवे का सरकूलर दिनांक 31-1-84 के प्रवर्णिकन से ज्ञात होता है कि बिना टिकट यात्रा रोकने के लिए वालिंटियर्स लिए गए थे जो कार्यरत रेलवे एम्पलाई थे, या के सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी थे और या रेलवे कर्मचारियों के बच्चे थे याधवा स्काउट या गाइड थे। इन वालिंटियर को प्रतिदिन 8/- रुपये जेबवर्च दिया जाता था। इस सरकूलर में यह स्पष्ट है कि वालिंटियर लिए गए तथा उनको 8/- रुपये प्रतिदिन जेबवर्च दिया गया है। इन वालिंटियर को अस्थाई और स्थाई नौकरी नहीं दी गई। इनको वेतनमान भी नहीं दिया गया। इसके लिये कोई शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा निर्धारित नहीं थी। किसे इस काम के लिए लेना है, यह पूर्णतः से डिवीजनल कार्मिशियल सुप्रीन्टेंडेंट के विवेक पर छोड़ दिया गया था। प्रतिदिन कितना काम करना है, यह भी विवेक पर छोड़ दिया गया था। इस प्रकार इस सरकूलर के अन्तर्गत किसी भी पद का निर्माण नहीं हुआ। इस सरकूलर के अंतर्गत किसी को नौकरी भी नहीं दी गई।

6. इस सरकूलर के अंतर्गत जिन वालिंटियर को लिया गया, उनका काम स्थाई टिकट कलेक्टर की मदद करना था। किसी भी वालिंटियर से स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं लिया गया। मात्र मदद ली गई। वालिंटियर की सेवाएं केवल गर्मी के मौसम में ली गई है।

7. टेम्पोरेरी स्टेटस वर्ग-चार के मजदूरों को दिया जाता है। ऐसा कोई नियम नहीं बताया गया कि वर्ग-3 के पद पर काम करने वाले कर्मचारियों को टेम्पोरेरी स्टेटस दिया जा सकता है। श्रमिकों को रेलवे कर्मचारी के परिवार का होने के कारण मदद के लिए रखा गया था। यह कार्य गर्मियों में होता था। रतन बहाने श्रमिकों से गर्मियों की छुट्टियों में काम मिल जाता था और जेबवर्च की आय होती थी। ये सुविधा उसी शहर के अन्य विद्यार्थियों को नहीं थी। वालिंटियर्स को नियुक्त करने की न तो कोई श्रमण परीक्षा थी और न स्त्रीनिंग कमेटी थी। कितने वालिंटियर्स लिए जाएं, यह संबंधित रेलवे कर्मचारी के विवेक पर निर्भर था। इस प्रकार श्रमिकों ने जो कार्य किया, वह अस्थाई कर्मचारियों के कार्य से भिन्न था। नियुक्ति प्रक्रिया भी बिना थी और दिनतः वेतन कार्य किया है।

8. रेलवे में वर्ग-तीन की नियुक्तियाँ रेलवे सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से की जाती हैं। भारत के सभी नागरिकों को इन पदों पर कार्य हेतु चयन प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार है और लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर रेलवे बोर्ड चयन करता है। इस चयन में आयु सीमा भी निर्धारित है। रेलवे वर्ग-3 के कर्मचारियों को एक समान वेतन देती है तथा उनकी नौकरी पर निगरानी रखती है। सभी कर्मचारियों की सेवा शर्तें भी एक भ्रसान हैं। इस प्रक्रिया के अतिरिक्त अगर कोई अन्य प्रक्रिया अपनाई जाती है तो इसका प्रभाव निर्धारित कर्मचारियों के अधिकारों के विपरीत होगा। जो पद रेलवे सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से भरे जाने हैं, उनके दूसरी प्रक्रिया से भरे जाने पर उत्तम पद रेलवे सिलेक्शन बोर्ड की पद्धति के बाहर हो जायेंगे। ऐसी स्थिति में नियम और आदेश के विपरीत होगी।

9. वालिंटियर के रूप में जो काम किया जाता है और लिया जाता है, उससे कोई क्लेम नहीं बनता। वर्तमान प्रकरण में जो काम श्रमिकों से लिया गया, उसके लिए कोई स्थाई पद पश्चिम रेलवे के पास नहीं था। यह स्कीम वर्ष 86 में समाप्त कर दी गई। टिकट कलेक्टर के पद पर रेलवे रिटायरमेंट बोर्ड के द्वारा चयनित उम्मीदवार प्रत्येक वर्ष आते रहें, ऐसी स्थिति में कोई भी पद ऐसा नहीं है, जो वर्तमान श्रमिकों को दिया जा सके। कभी भी श्रमिकों को यह लिखकर नहीं दिया गया कि उनको रेलवे में नियुक्ति दी जायेगी। श्रमिकों ने जो कार्य किया, उसका लेखा-जोखा नहीं है। कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण भी कभी नहीं किया गया। रेलवे सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा चयनित कर्मचारी पहले अस्थायी रूप से नियुक्त होते हैं। इनके कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है और संतोषप्रद पाने पर ही इनको स्थाई नियुक्ति दी जाती है। यह प्रक्रिया वर्तमान श्रमिकों के संबंध में संभव नहीं है।

10. श्रमिकों के शारीरिक क्षमता का परीक्षण भी कभी नहीं किया गया। जो कर्मचारी रेलवे सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा चयनित होते हैं, उन सभी का डाक्टरों की परीक्षण होता है और उन्हीं को नौकरी दी जाती है, जो शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं। वर्तमान श्रमिकों के संबंध में इस प्रकार का परीक्षण नहीं किया गया।

11. जो कर्मचारी रेलवे सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा चयनित होते हैं, उन्हें नौकरी देने से पहले उनके चरित्र और आचलन की जांच पुलिस से कराई जाती है। चरित्र उत्तम होने पर ही नौकरी में लिया जाता है। वर्तमान श्रमिकों के चरित्र के संबंध में कभी जांच नहीं हुई।

12. वर्तमान श्रमिक और रेलवे के बीच सेवा का कोई एग्रीमेंट नहीं है। इनके रिटायरमेंट नहीं किये गये हैं। ये लोग रेलवे के कर्मचारी नहीं थे। श्रमिकों के वेतन का भुगतान नहीं होता है।

13. माननीय उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद बैंक धिक्क प्रेमसिंह के निर्णय में जो 1997(1) यू०जे (एससी)

पृष्ठ-144 में सुनि है, यह निर्धारित किया है कि जहाँ पर श्रमिकों को कम अवधि के लिए प्रतिदिन के हिसाब से सेवा में रखा गया है, वहाँ सेवा का स्वरूप दैनिक कर्मचारी का होता है। जैसे यह अवधि समाप्त होती है, वैसे ही उसकी सेवा समाप्त हो जाती है। इस प्रकार के कर्मचारी को नियमित सर्विस पाने की पात्रता नहीं है। इस प्रकार के कर्मचारी को काम समाप्त के पश्चात् सेवा में रहे आने का कोई अधिकार नहीं है और वेतन पाने का भी अधिकार नहीं है। वर्तमान प्रकरण में प्रत्येक श्रमिक को रुपये 8/- प्रतिदिन जेबखर्च दिया गया है। श्रमिकों की जब आवश्यकता पड़ी तो उनसे मदद ली गई है। मदद की समयसीमा कभी निर्धारित नहीं की गई। ऐसी स्थिति में वर्तमान न्याय मिहान्त के प्रकाश में वर्तमान श्रमिक रेलवे में सेवा पाने के वालिंटियर के किए गए कार्य के एवज में अधिकारी नहीं हैं।

14. ऊपर लिखी विवेचना का निष्कर्ष यह है कि कोई भी श्रमिक पश्चिम रेलवे में वर्ग-तीन का पद पाने का अधिकारी नहीं है। श्रमिकगण की याचिकाएं सारहीन होने में निरस्त होने योग्य हैं। अवाई दिया जाता है कि रिफरेन्स क्रमांक 201/91, 218/93, 220/91 और 217/93 में कोई भी श्रमिक किसी भी सहायता को पाने का अधिकारी नहीं है। दोनों पक्ष इस प्रकरण का अपना-अपना व्यय वहन करें।

15. नियमानुसार अवाई की प्रतियाँ भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित की जाती है।

डी० एन० दीक्षित, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1998

का०आ० 1801.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेन्ट्रल रेलवे, झांसी के प्रबन्धतन्त्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-8-98 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-41012/132/92-आई०आर० (डी०यू०)/
बी० I]

पी० जे० माईकल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st August, 1998

S.O. 1801.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Railway, Jhansi and their workman, which was received by the Central Government on 21-8-98.

[No. L-41012/132/92-IR(DU)/B-I]
P. J. MICHAEL, Desk Officer.

ANNEXURE

BEFORE SHRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, DEOKI PALACE ROAD, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 95 of 1993

In the matter of dispute between :

President,
Rashtriya Chaturth Shreni Rail Mazdoor Congress,
4-Heerapur Nagra, Jhansi.

AND

1. Divisional Railway Manager,
Central Railway, Jhansi.
2. Divisional Engineer (Headquarter),
Central Railway, Jhansi.

APPEARANCES :

Shri Surender Singh for the Workman.
Mrigank Srivastava for the Management.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi vide its Notification No. L-41012/132/92-I.R. (D.U.) dated 20-10-93 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the action of Divisional Railway Manager, Central Railway, Jhansi in denying regularisation of Shri Nathoo Ram, S/o Shri Raja Ram, Casual Labour is justified? If not, what relief he is entitled to and from what date?"

2. The case of the concerned workman is that he had completed more than 120 days in 1983 as M.R.C.L. with the opposite party Central Railway. He was sent for screening on 4-4-83 and he was cleared in the Medical Test vide certificate dated 6-7-83. Yet he has not been regularised instead he has been removed from service. The date of removal has not been given in the claim statement.

3. The opposite party has filed written statement in which it has been alleged that the concerned workman was sent for screening for the post of gangman but he was not found fit as he could clear grade 'C' test. Hence he was not taken in service.

4. None of the parties adduce any evidence. As the concerned workman admittedly is not in service of the opposite party question of his regularisation does not arise. Further as he has failed in grade 'B' test he was not entitled for regularisation.

5. Accordingly my award is that the concerned workman is not entitled for regularisation. Consequently he is not entitled for any relief.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1998

कांआ० 1802.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबन्धतन्त्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-8-98 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12011/24/97-आई०आर० (बी० I)]

पी० जे० माईकल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st August, 1998

S.O. 1802.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Etawah Kshetriya Gramin Bank and their workman, which was received by the Central Government on 21-8-98.

[No. L-12011/24/97-IR (B-I)]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, DEOKI PALACE ROAD, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 46 of 1998

In the matter of dispute between :

R. K. Sharma,
General Secretary,
Etawah Kshetriya Gramin Bank,
Staff Association, 39 Kuncha Sheelchandra,
Etawah.

AND

Chairman,
Etawah Kshetriya Gramin Bank,
123 A, Civil Lines,
Etawah.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi vide its Notification No. L-12011/24/97-I.R. (B-D) dated 11th March, 1998 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

Whether the action of the management of Etawah Kshetriya Gramin Bank, Etawah of not issuing of publishing seniority list of messengers employed in their Bank is justified? If not, what relief the workman are entitled?

2. It is unnecessary to give the details of the case as after sufficient opportunity the concerned workman has not file the claim statement. Hence the reference is answered against the concerned workman for want of prosecution and proof and he is not entitled for any relief.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1998

कांआ० 1803.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पुरनापानी लाईमस्टोन एण्ड डैलोमाईट क्वारी के प्रबन्धतन्त्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, राउरकेला के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19-9-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-29011/25/95-आई०आर० (विशेष)]

बी० एम० डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 24th August, 1998

S.O. 1803.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Rourkela as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of

M/s. Purnapani Limestone and Dolomite Quarry, and their workmen, which was received by the Central Government on 21-8-98.

[No. L-29011/25/95-IR(Misc.)]
B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE COURT OF THE PRESIDING OFFICER,
INDUSTRIAL TRIBUNAL, ROURKELA

Industrial Dispute Case No. 97/97(63/95)(C)

Dated, the 14th July, 1998

PRESENT :

Sri R. N. Biswal, LL.M.,
Presiding Officer,
Industrial Tribunal,
Rourkela.

BETWEEN

The General Manager, Purnapani
Limestone and Dolomite Quarry,
R. M.D., SAIL, Rourkela.

—1st party.

AND

The Secretary, Rourkela
Shramik Sangha, (INTUC),
PO : Purnapani, Sundargarh.

—II party.

APPEARANCES :

For the 1st party—None.

For the IInd party—None.

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 have referred the following disputes for adjudication vide No. L-29011/25/95-IR(Misc.) dated 13-12-95 :

"Whether the action of the management of Purnapani Limestone and Dolomite Quarry of Raw Material Division, SAIL, PO : Rourkela, District : Sundargarh in not paying Rs. 500 to the workers of Purnapani Limestone and Dolomite Quarry as incentive earnings for the month of April, 1993 due to sudden stoppage of crushing plant on 02-4-93 was justified. If not, to what relief the workmen are entitled ?"

2. The case was fixed on 23-6-98 for hearing. Since neither of the parties appeared before this Tribunal on that date, it can be presumed that at present there is no dispute between them or they have amicably settled the dispute outside the court in the meantime. Accordingly No Dispute Award is passed.

R. N. BISWAL, Presiding Officer

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1998

कां०आ० 1804.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सुन्दरगढ़ माइनिंग लेबर कान्ट्रक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी लि० के प्रबन्धतन्त्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबन्ध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, राउरकेला के पंचाद को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-6-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-29011/34/94-आई०आर० (विविध)]

बी० एम० डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 24th August, 1998

S.O. 1804.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Rourkela as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Sundargarh Mining Labour Contract Co-op. Society Ltd., and their workman, which was received by the Central Government on 21-6-98.

[No. L-29011/34/94-IR(Misc.)]
B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE COURT OF PRESIDING OFFICER,
INDUSTRIAL TRIBUNAL, ROURKELA

Industrial Dispute Case No. 71/97(25/95)(C)

Dated, the 10th July, 1998

PRESENT :

Sri R. N. Biswal, LL.M.,
Presiding Officer,
Industrial Tribunal,
Rourkela.

BETWEEN

1. The Secretary, Sundargarh
Mining Labour Contract
Co-op. Society Ltd. Contractor
Purnapani Limestone and Dolomite
Quarry of RMD, SAIL, PO. Purnapani
Dist. Sundargarh.

2. General Manager, Raw Material
Division, SAIL, PO. Rourkela,
Dist. Sundargarh.

1st party

AND

The General Secretary, Purnapani
Mazdoor Union, P.O. Purnapani,
Dist. Sundargarh

IInd party

APPEARANCES :

For the 1st party—None.

For the IInd party—None.

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 have referred the following disputes for adjudication vide No. L-29011/34/94-IR(Misc.) dt. 3-4-95 :

"Whether the action of the management of Sundargarh Mining Labour Contract Co-op. Society Ltd., Contractor Purnapani, Limestone & Dolomite Quarry of RMD, SAIL, AT PO Purnapani, Dist. Sundargarh in not transferring shares to their direct dependants and relinquishing job in case of ill-health, death, becoming physically handicapped or weak to carry out day to day works of the mines in accordance with the provisions of the rules of the society is justified ? If not, what relief the workman are entitled to ?"

2. The case was fixed on 11-6-1998 for exparte hearing. Since neither of the parties appeared before this Tribunal on that date, it can be presumed that, at present there is no dispute between them or they have amicably settled the dispute outside the Court in the mean time. Accordingly No Dispute Award is passed.

R. N. BISWAL, Presiding Officer

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1998

कां०आ० 1805.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार राँ मैट्रियल डिबीजन के प्रबन्धतन्त्र के सम्बद्ध

नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, राउरकेला के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-8-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29012/53/95-आई.आर. (विधि)]

बी.एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 24th August, 1998

S.O. 1805.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Rourkela as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Raw Material Division and their workmen, which was received by the Central Government on the 21-8-98.

[No. L-29012/53/95-IR(Misc.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE COURT OF THE PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, ROURKELA

Industrial Dispute Case No. 95/97 (C)

Dated, the 14th July, 1998

PRESENT:

Shri R. N. Biswal, LL.M.,
(O.S.J.S. Sr. Branch)
Presiding Officer
Industrial Tribunal,
Rourkela.

BETWEEN

The General Manager,
Raw Material Division,
SAIL, Rourkela-II,
Dist. Sundergarh.

.. Ist party

AND

The General Secretary (INTUC)
Rourkela Shramik Sangh
Q. No. D/81, Sector-18
Rourkela-3, Dist. Sundergarh

IInd party

APPEARANCES:

For the Ist party—None.

For the IInd party—None.

AWARD

The Govt. of India in Ministry of Labour Department in exercise of their power conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 have referred the following dispute vide reference No. L-29012/53/95-IR(Misc.) dated 5-12-95 for adjudication :

"Whether the action of the management of Raw Material Division, Rourkela Zone, Rourkela not giving deputation allowance to the workers of Barsua Iron Mines, Kulda Iron Mines and Purnapani Lime Stone & Dolomite Quarry after the formation of Raw Material Division on 5-4-1990 is justified? If not, what relief the workmen are entitled to?"

2. The case was fixed on 25-6-98 for hearing. Since neither of the parties appeared before this Tribunal on that date. It can be presumed that, at present there is no dispute between them or they have amicably settled the dispute outside the Court in the mean time. Accordingly No Dispute Award is passed.

R. N. BISWAL, Presiding Officer

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1998

का.आ. 1806.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पुर्नापानी लाईमस्टोन एण्ड डोलोमाइट खनरी, राउरकेला-2, राउरकेला-3 के प्रबन्धन के सम्बन्ध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, राउरकेला के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-8-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29012/101/94-आई.आर. (विधि)]

बी.एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 24th August, 1998

S.O. 1805.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Rourkela as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Purnapani Limestone & Dolomite Quarry of RMD, SAIL and their workmen which was received by the Central Government on 21-8-98.

[No. L-29012/101/94-IR(Misc.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE COURT OF PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, ROURKELA

Industrial Dispute Case No. 70/97(24/95)(C)

Dated, the 14th July, 1998

PRESENT:

Sri R. N. Biswal, LL.M.,
Presiding Officer,
Industrial Tribunal,
Rourkela.

BETWEEN

The General Manager, Purnapani
Limestone and Dolomite Quarry of
RMD, SAIL, PO. Rourkela-II, Sundargarh—Ist party.

AND

The Secretary, Rourkela Shramik
Sangha (INTUC) PO: Purnapani, Sundargarh

—II party.

APPEARANCES:

For the Ist party—None.

For the IInd party—None.

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2-A) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 have referred the following disputes for adjudication vide No. L-29012/101/94-IR(Misc.) dt. 20-3-95 :

"Whether the action of the management of Purnapani Limestone & Dolomite Quarry of Raw Material Division, SAIL, PO. Purnapani, Dist. Sundargarh in not giving employment to the dependant of Late Karam Singh was justified? If not, what relief the dependant is entitled to?"

2. The case was fixed on 24-6-98 for experts hearing. Since neither of the parties appeared before this Tribunal on that date, it can be presumed that, at present there is no dispute between them or they have amicably settled the dispute outside the court in the meantime. Accordingly No Dispute Award is passed.

R. N. BISWAL, Presiding Officer

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1998

बताओ 1807.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के प्रबन्धतन्त्र के सम्बन्धे नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता के पचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-8-98 को प्राप्त हुआ था।

[मं० एल-32012/6/89-आई०आर० (निविष्ट)]

श्री० एस० डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 24th August, 1998

S.O. 1807.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Calcutta as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Calcutta Port Trust and their workman, which was received by the Central Government on the 21-8-1998.

[No. L-32012/6/89-IR(Misc.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 27 of 1998

PARTIES :

Employers in relation to the management of Calcutta Port Trust, Calcutta.

And

Their workmen

PRESENT :

Mr. Justice A. K. Chakravarty—Presiding Officer.

APPEARANCE :

On behalf of Management—Mr. G. Mukhopadhyay, Senior Labour Officer (IR).

On behalf of Workmen—Mr. S. Chatterjee, Joint Secretary of the Union.

STATE : West Bengal. INDUSTRY : Port

AWARD

By Order No. L-32012/6/89-IR(Misc.) dated 25th August, 1989 the Central Government in exercise of its powers under section 10(1)(d) and (2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

“Whether the action of the management of Calcutta Port Trust, Calcutta in imposing punishment on Shri R. P. Dutta, Shed Clerk, Gr. I under Traffic Department by way of deferment of his annual grade increment for a period of 1 year without permanent effect is justified. If not, what relief is the workman entitled to?”

2. Instant reference has arisen at the instance of Calcutta Port & Shore Mazdoor Union (hereinafter referred to as union) against the management of Calcutta Port Trust (in short management) for deferring annual grade increment for a period of one year of the concerned workman Shri R. P. Dutta as punishment for the offence alleged to have been committed by him.

3. Union's case, in short, is that on 30-10-1979 the concerned workman Shri Dutta was deployed to work as a Delivery Clerk of 'D' Netaji Subhas Dock which is a transit shed used for receiving cargoes for import and export and subsequent delivery of the shipment to the authorised consignee of the cargoes received there. He was served with a notice dated 27-6-1984 in which he was charged of carelessness and negligent work for his failure to return the shed delivery order after countersigning the same to the concerned Shed Writer as per procedure. It was proposed in the said notice that the management wants to punish him by deferring his annual increment for a period of one year without any permanent effect. The management thereafter passed an order to that effect by way of punishment. The concerned workman has challenged the said order of punishment on the ground that the notice was issued after almost 5 years after the incident had occurred and he could not defend himself properly as documents were not available after such long time. The plea of violation of natural justice was also taken. The concerned workman has also challenged the order imposing punishment as arbitrary, illegal and invalid provisions of the Calcutta Port Commissioner's Employees' (Discipline & Appeal) Rules, 1964 (hereinafter referred to as the Rules) was not followed. The union accordingly prayed for withdrawal of the punishment and compensation for the monetary loss suffered by the workman.

4. The management in its written statement has alleged that Shri Dutta, Shed Clerk, Grade-I, while working as Delivery Clerk of 'D' Shed in the first shift of 30-10-1979 did not return the shed delivery order in respect of delivery of 11 cases of King Pin Bushes to the Shed Writer after countersigning the same for delivery to the party as per procedure. Thus, the said shed delivery order could not be traced out and the delivery of the said cargoes turned out to be a fraudulent one. The matter was investigated by the Violence Department of management and it was reported that the shed delivery orders were not returned back to the Shed Writer by Shri Dutta after the delivery was effected. The disciplinary authority accordingly decided to initiate minor penalty proceeding against Shri Dutta in terms of Rule 12 of the Rules for the above carelessness and negligent work of Shri Dutta. Shri Dutta accordingly was asked to show cause alongwith the proposal for imposition of punishment and an explanation was submitted by Shri Dutta, but that being not found satisfactory, the disciplinary authority punished him by deferment of one grade increment without permanent effect. The management denied that the concerned workman was not supplied with the document or that punishment was imposed upon him arbitrarily in violation of the principles of natural justice. The disciplinary authority duly considered the representation of Shri Dutta and found him guilty after holding enquiry in terms

of aforesaid Rule 12. The management accordingly claimed that it was justified in imposing the punishment and prayed for dismissal of the claim of the union.

5. In its rejoinder, the union has alleged that the said delivery order was received by the consignee with acknowledgement in the Car Ticket and Delivery Register as per order of the authority concerned and the records of the same were kept in the custody of the management. The union denied the allegations of fraudulent delivery or enquiry by the Vigilance Dept. It also denied as baseless the non-delivery of the shed delivery order to the Shed Writer as those were taken back by the consignee under order from the authority concerned. The order of deferment of increment was also challenged as no reason was given there. Other allegations in the rejoinder are repetitions of the allegations made in the written statement of the union.

6. The management has produced certain documents and examined two witnesses in support of its case. No document was produced on behalf of the union and though the concerned workman was only examined on its behalf, he was not cross-examined by the management.

7. Admittedly, the management after lapse of about 5 years started the proceeding against the concerned workman charging him of carelessness and neglect of duty for not handing over the shed delivery order after his counter signature to the Shed Writer in respect of certain consignment. The representative of the union challenged the initiation of the proceeding after the lapse of 5 years on the ground that such inordinate delay in the initiation of the proceeding has caused loss of vital documents which might have supported his case. In this case the alleged incident of not handing over the shed delivery order to the Shed Writer had occurred on 30-10-1979 and the chargesheet was issued on 27-6-1984. Though no limitation is prescribed for initiation of a proceeding against any delinquent employee in the Rules, still then, the quest on must be approached from the view point of violation of the principles of natural justice, particularly when, no reason was given in the written statement of the management as to why the said proceeding was initiated after lapse of such a long time. There cannot be any doubt that if an employee is charged for commission of an offence all of a sudden for an incident which is alleged to have occurred 5 years back, it is not possible for such employee to properly defend himself, not only because of the failure to remember the incident occurring long ago, but also because the documents upon which the charge is sought to be refuted may not be readily available. In the instant case the workman had complained that he was not supplied with any document. The chargesheet issued against the workman shows that he was directed to give his explanation for the alleged offence. There is nothing to show that he was given an opportunity to produce evidence in support of his case. During the trial, it appears from the order dated 5-7-91 that even though the Tribunal directed the management to produce document, still then, that was not produced. In the said circumstances, initiation of the disciplinary proceeding after long lapse of about

5 years without showing any reason for doing the same shall be deemed to have violated the principles of natural justice as such passage of time itself takes away substantially the right of workman to demand himself properly. Adjudged from this view point, the initiation of the proceeding must be considered to be illegal and invalid.

8. The chargesheet issued against the workman is marked Ext. M-1 in this case. It appears from the chargesheet that there was a proposal for withholding one increment of the concerned workman for the alleged carelessness and neglect of duty. Mr. Mukhopadhyay, appearing for the management submitted that since a minor punishment was proposed, provisions of Rule 12 of the Rules were taken recourse to for conducting the proceeding against the concerned workman. No objection was taken on behalf of the union to the conducting of the proceeding under the said Rule. It was submitted by Mr. Mukhopadhyay that the disciplinary authority punished the concerned workman by issuing an order dated 17-10-1984 (vide Ext. M-3) on the basis of the admission of the workman. There is nothing on record to show that an admission was made by the concerned workman in this matter. As a matter of fact, it was the duty of the disciplinary authority to consider the representation filed by the workman in this matter. The representation filed by the workman and referred to in the order of punishment was not produced before this Tribunal. The order itself does not show that the disciplinary authority actually considered his representation. It merely shows that the disciplinary authority found him guilty after going through the charges framed against him and upon reading the representation. Since the representation itself was not produced by the management, it was not known what was there in the representation. Then again, the disciplinary authority has merely stated in the order that he is satisfied that the charges framed against Shri Rama Prosad Dutta have been established. A bald statement without any reason for coming to such conclusion makes the entire order defective. In this connection a reference may be made to Rule 12 of the Rules which shows that among other requirements, the record of the proceeding shall include the representation of the workman and the orders on the case together with the reasons therefore. I have already stated that the representation of the workman has not been made part of the record of the proceeding and the order of the case does not show any reason for coming to the conclusion of guilt of the concerned workman by the disciplinary authority. In the said circumstances, the disciplinary authority must be held to be acted illegally and accordingly the order passed by it must also be held to be bad, illegal and invalid.

9. Mr. Mukhopadhyay, representative of the management drew my attention to the appellate order, marked Ext. M-4 and tried to convince this Tribunal that the appellate authority have considered all aspects of the matter and found him guilty. Apart from the fact that the appellate authority was entirely wrong in upholding the order of the disciplinary authority for the reasons mentioned above, it appears from the order that it upheld the order of punishment as the concerned workman had violated the procedural norms in handing over the shed delivery order of the

consignee of the consignment in question though as per procedure he was to hand it over to the Shed Writer. No such procedure was produced before the Tribunal. The workman in his evidence also stated that he handed it over to the consignee as there was less delivery of three balance consignments and also because the consignee produced authority from the higher authority to deliver the same to him. He also stated that when full consignments are not delivered, the Delivery Clerk is required to hand over the shed delivery order to the consignee with endorsement of balance consignment. There was no cross-examination to contradict on this point. Mr. Mukhopadhyay, however, wanted to rely on the evidence of MW-1 who is an officer of the management. He said in his evidence that he thinks that the duty of the Delivery Clerk is to send the shed delivery order to the Shed Writer. Such thinking on his part is not sufficient to prove that it is the established procedure to handover the said delivery order to the Shed Writer. The management thus having failed to prove the procedural default by production of the procedure and the workman having proved by his uncontroverted evidence that he could handover the shed delivery order to the consignee in case of delivery of part consignment that I am to hold that the very basis of the punishment for working against the procedure has not been proved at all in this case.

10. It further appears from Ext. M-5 which is a report of the management that he found some other persons involved in the alleged offence. According to the management proceeding were drawn up against those persons. This report thus having totally exonerated the concerned workman, drawing up of proceeding against him after 5 years on the allegations of commission of a vague offence suggests the drawing up of such proceeding itself as vindictive.

11. Mr. Mukhopadhyay, representative of the management, lastly submitted on the basis of the averment of the management in the written statement that if for any reason the disciplinary proceeding is found to be defective, it should be given a fresh opportunity to prove the alleged offence against the concerned workman. Admittedly, no enquiry proceeding was drawn up in this case. The question of giving a fresh opportunity to the management for proving the alleged offence against its employee can arise if the enquiry proceeding is found to be defective or no enquiry is held. In the instant case, the Rule 12 of the Rules itself does not provide for drawing up any enquiry proceeding. Such enquiry proceeding is to be made under the provisions of Rule 11 in cases of commission of major offences. The Rules having thus admittedly not provided for enquiry through any enquiry proceeding and merely making provision for taking action against the delinquent by holding a summary enquiry into the matter, as contemplated in Rule 11 there is no question of providing any further opportunity to the management to prove its case afresh.

12. So, upon consideration of the facts and circumstances and the position of law in the matter, I am of the opinion that the action of the Calcutta Port

Trust, Calcutta in imposing punishment on Shri R. P. Dutta, Shed Clerk, Grade-I by way of deferment of his annual grade increment of a period of one year without permanent effect was arousing illegal and unjustified.

13. Management's order of deferment of annual increment of the concerned workman for a period of one year without punishment effect is accordingly set aside and it is directed to restore his annual grade increment for the said period as it was normally due to him.

This is my Award.
Dated, Calcutta,
The 10th August, 1998.

A. K. CHAKRAVARTY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1998

कांआ० 1808.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार देना बैंक के प्रबन्धतन्त्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-II, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-8-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-12012/28/91-आई०आर० (बी० II)]
सी. गंगाधरन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st August, 1998

S.O. 1808.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-II, Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Dena Bank and their workman, which was received by the Central Government on 20-8-1998.

[No. L-12012/28/91-IR (B-II)]
C. GANGADHARAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

B. B. Chatterjee, Presiding Officer.

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947

Reference No. 109 of 1991

PARTIES :

Employers in relation to the management of Dena Bank and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen—Shri P. N. Singh, Authorised Representative.

On behalf of the employers—Shri B. Saha, authorised representative.

STATE : Bihar

INDUSTRY : Banking

Dhanbad, the 11th August, 1998

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to

this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-12012/28/91-IR. (B-II) dated, the Nil.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Dena Bank in terminating the services of Shri Sita Ram Yadav, Casual Labour is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The concerned workman Sitaram Yadav put forward his claim for regularisation of his services with effect from 1-11-86 with full back wages and other benefits available to a subordinate cadre in Bank services by making out a case in his W.S. to the effect :—

That the concerned workman was in the services of Dena Bank at its Patna branch as Badli workman/Arm Guard in the year 1973 and he worked as such in that capacity upto 25-5-89 yet his service was terminated without any notice with effect from 26-5-89. The concerned workman worked in the Bank for more than 240 days in the year 1986-87 i.e. within a period of 12 months and that at the time of termination of service there were atleast 2 vacancies of watchman/arm guard in the Patna branch of the Bank created due to the retirement of Shri Sadhu Singh and Rameshwar Singh who retired from their services in 1986 and 1987 of the Bank and the practice of regularisation of services in such category in the relevant period was such i.e. the Branch Manager were entitled to engage and approve badli subordinate panel for the sake of regularisation of their services between the period of 2 to 4 years and in that order by services of the concerned workman was taken by the Bank as badli workman/Arm Guard in the year 1973 along with Paras Nath Singh and Sitaram Singh but although the services of Paras Nath Singh was regularised against permanent vacancy of Arm Guard at Bakhtiarpur branch of the Bank but the services of the concerned workman was terminated without such regularisation like that of Paras Nath Singh. The concerned workman even opted for services to any other subordinate category but even then the Bank management did not consider the case of the concerned workman and for the reasons best known to the management his services was terminated with effect from 26-5-89 and that too without service of any notice or payment of compensation as required under the law. The management refused to regularise the services of the concerned workman by taking the plea that the concerned workman neither possessed any Arm licence nor he was any Ex-army men which in fact amount to unfair labour practice in violation of Section 2(r) (a) sub-clause 10 of I. D. Act and was also in violation of second bipartite settlement clause 20.12. As the concerned workman was subjected to the acts of arbitrary abandonment of the principles of natural justice by way of termination of services by the management he is entitled to an order for regularisation of his services with effect from 1-11-86 with full back wages and other consequential benefits available to the subordinate category and has prayed for an Award in his favour to that effect in the reference. The concerned workman has put forward his claim in the fashion mentioned above by submitting an additional W.S.

3. The Bank management also submitted his W.S.-cum-rejoinder as against the W.S. and amended/additional W.S. on the side of the concerned workman wherein the management has challenged the maintainability of the reference as described in the W.S. of the concerned workman as mis-conceived, fabricated, mala fide etc for which the claim of the management is that the concerned workman Shri Sitaram Yadav is not entitled to any relief. In addition, the management in the rejoinder has made specific comments in respect of the different paras of the W.S. of the concerned workman and in doing so the management has abstained from making any comment in respect of para 1 of the W.S. as being matter of record. In respect of contents of para 2 of the W.S. the say of the management is that the badli workmen were never recruited by the Bank and

that there was no employer-employee relationship between the concerned workman and the management and that such recruitment or engagement on purely temporary basis during the leave vacancy of permanent workmen for which the management was specifically manpowered under the provision of Bipartite Settlement under para 20.7 and para 20.8 and thereby the management claimed that the engagement of the concerned workman Sitaram Yadav was intermittent as badli employee at Patna branch on as and when necessary basis.

4. The management abstained from making any comment against para 3 of the W.S. of the workman by admitting the same to be correct but the management has denied the contents of para 4 of the W.S.

5. In respect of contents of para 5 of the W.S. the claim of the management is that the Branch Managers were not at all entitled to engage as badli subordinate panel but for such recruitment in the Banking industries were made by the individual bank as per directive given by the Government from time to time. In doing so for the purpose of recruiting subordinate staff it was obligatory on the part of the management to notify the vacancy in the local employment exchange. The candidate should be between the age not below 18 and not above 26 years in case of general category candidates with some relationship upto 31 years a case of other categories, educational qualification required for the purpose was Class VIII standard for general category and Class IV post for SC/ST candidate. It is true that the Bank empanelled the name of the Badli candidate but without any assurance to any one of the panel for giving appointment in future without fulfilling the eligibility criteria.

6. In respect of the contents of para 6 of the W.S. the say of the management is that those being matters of record, required no comment and in respect of the contents of para 7 the claim of the management is that the question of the regularisation of the services of the concerned workman cannot arise as badli workman as they were never treated as employee of the Bank for which there was no employer employee relationship between the workman and the management and in that view of the matter the question of regularisation of the service of the concerned workman cannot arise. The concerned workman is therefore, not entitled to employment and thereby regularisation of his services in the Bank. In respect of the contents of para 9 of the W.S. of the workman the claim of the management is that the badli watchman were never given any assurance of appointment of permanent nature in future without fulfilling the eligibility criteria i.e. without being ex-service man arm handling licence etc. The management has claimed the justification, in the matter of regularisation of the service of Paras Nath Singh on the ground of his fulfilling eligibility criteria unlike that of the concerned workman Sitaram Yadav and in respect of the contents of para 11 of the W.S. the management has claimed that out of 31 subordinate staff who were regularised by way of an agreement with a majority of the union although none of them were armed guard/watchman/badli as alleged by the concerned workman Sitaram Yadav. The management abstained from making any comments in respect of the contents of para 12 of the W.S. of the workman and in respect of the contents of para 13 the management has reintroduced the terms and conditions of bipartite settlement as contained in clause 20.8 dated 19-10-66. The claim of the management in respect of para 14 of the W.S. is that the management wrote a letter to the applicant Sitaram Yadav for production of necessary arm licence certificate but he failed to produce the same and lastly in respect of para 15 the management has claimed that the concerned workman did not render continuous service of 90 days or intermittently 240 days in a year for which the case of the concerned workman was not considered which was well within the jurisdiction of the management and it was justified and on all these ground the management has claimed that the applicant is not entitled to get any benefit under the provision of I. D. Act. Naturally the management has prayed for an Award in their favour and against the prayer of the concerned workman.

7. The concerned workman as against the W.S.-cum-rejoinder filed on the side of the management against the additional W.S. of the workman has also submitted a reply by material parwise comments of such W.S.-cum-rejoinder of the management and in doing so the workman however abstained from making comments as against the contents of

para 1, 8, 10 and 12 and in respect of other paras the claim of the concerned workman is that the contents of those paras are not only incorrect but also misconceived in as much as in respect of para 2 I.D. Act, 1947 nowhere contemplates that an industrial dispute would come into existence in any specified or prescribed manner and that prior demand in writing for raising such dispute is not at all necessary yet in the instant case of the concerned workman the demand were sent to the management of Dena Bank by the ALC (C) Patna by the letter dated 17-3-89 and ALC (C) Patna dated 8-11-89 and in that view of the matter it can be safely said that the dispute has been properly raised and espoused as pre requirement of relevant provisions of I. D. Act.

8. The claim of the concerned workman in respect of the statement made in para 4 of the W.S.-cum-rejoinder of the management that the same is irrelevant while that of para 5 the same is incorrect for want of any notice for retrenchment or notice pay etc. In respect of statement made in para 6 the say of the concerned workman is that the reference as per schedule is for the purpose of adjudication the issue of termination of services of the concerned workman and not regularisation of badli appointment of the concerned workman. Similarly is the claim of the workman in respect of the contents of para 11 while in respect of contents of para 13 the claim of the concerned workman is not wholly correct and that the same is partially correct and as he served for more than 240 days continuously he is entitled to the relief prayed for because of the fact of non-service of any notice upon him by the management which renders the termination of the service of the concerned workman not only as unjustified but also is illegal. The concerned workman is entitled to get protection under Section 25 of the I. D. Act. The contention of the management that the badli workman is not entitled to any notice or notice pay or retrenchment compensation is in fact devoid of any merit.

9. The say of the concerned workman in respect of the statement of para 14 is that those statement are not only incorrect but also misleading in as much as the rules mentioned for recruitment by the management was not at all in existence in the year 1973 when the concerned workman was appointed in the Bank for service. Similarly the claim of the concerned workman in respect of contents of para 16, 17 and 18 that those are not at all correct. So far the statement made in para 18 are concerned the claim of the concerned workman is that those are not at all correct on the face of the record of the Bank and as the concerned workman served continuously for a period of more than 240 days he is entitled to the protection provided in Section 25-F of the I. D. Act and in respect of clause of bipartite settlement the claim of the concerned workman is that the clause contained therein cannot override the provision of the Act and the rules made there under and all those ground the concerned workman has claimed that in respect of his case only there was discrimination in the matter of employment in the Bank ignoring the practice and procedure adopted by the Bank for the purpose of absorbing temporary watchman in the permanent cadre. Naturally the concerned workman has again prayed for an Award in his favour and thereby granting him the relief prayed for in his W.S.

10. The management has in fact filed another W.S. against the comments of the rejoinder but in disguise of a petition duly verified by the Asstt. G.M. Dena Bank, Calcutta Region and as such when no leave was taken as I find from the ordersheet I am not inclined to incorporate the contents of that petition in the Award.

11. Both parties have adduced oral as well as documentary evidence by examining one witness by each side and by producing and proving a number of documents.

DECISIONS AND REASONS

12. The point for decision is whether the termination of the services of the concerned workman by the management of Dena Bank is justified or not ?

13. Before I enter into discussion of the evidentiary value of oral as well as documentary evidence etc. it may be

mentioned here that in the instant reference there are certain facts over which there is no dispute. These facts are that the concerned workman started working at Puna branch of Dena Bank as badli workman in the year 1971 is such a fact over which there is no dispute. Secondly there is also no dispute that the concerned workman since 1973 remained engaged at Dena Bank of Patna Branch from time to time intermittently till October 25, 1989. Then again there is no dispute that the services of the concerned workman was terminated without assigning any reason or without service of any notice, notice pay or even retrenchment compensation and with effect from 26-10-89. The concerned workman who figured as witness in the reference as WW-1, has tried to depose in terms of his W.S. by claiming that he started working in Dena Bank as workman from 1973. In addition to the duties of Watchman he also used to supply water and make movement of files from one table to other and several other duties till 1989. It is also his evidence that after retirement of one Sadhu Singh he worked in his place for a continuous period of 3 months and he also worked in the place of Rameshwar Singh, gunman after his retirement from service and that inspite of all these he was neither paid any retrenchment compensation nor notice, nor even any notice pay. This is the sum and substance of the evidence of the concerned workman in his examination-in-chief. During cross-examination so many questions were put to the witness about the manner of payment for his service, possession of any ex-army certificate, gun operating licence etc. but without challenging even by way of suggestion the claim of the concerned workman of his performing duties in place of the retired watchmen and of doing work like movement of files, registers, etc. from one table to another in addition to the work of carrying water. The evidence of this witness thus clearly proves that in fact the concerned workman served at Dena Bank at Patna branch from 1973 to October, 1989 though with interval i.e. intermittently.

14. On the other hand the management has also examined one witness namely Shri S. P. Ram who is an employee of the Bank of Calcutta branch. He was also attached to Patna branch of the Bank and as per his saying also the concerned workman worked in Patna branch of the Bank as badli watchman but at the same the witness has claimed during his examination-in-chief that there are guidelines for recruitment of gunman and watch and ward staff but during cross-examination the witness failed to give the actual number of days for which the concerned workman performed the duties of Badli watchman intermittently and that the papers produced on the side of the management would show the number of working days on which the concerned workman performed his duties as badli watchman. Then again during his cross-examination the witness admitted that the rule of recruitment in respect of Watch and Ward staff was not introduced from before the year 1986 and that it was enforced from before but since 1986 by virtue of certain decentralisation of the power for recruitment etc. were decentralised. During concluding part of the cross-examination the witness expressed his inability to say if any notice or any notice pay was given to the concerned workman while he was stopped from work. The evidence of this witness if given a careful consideration it is practically of no help to the management for the purpose of disbelieving the claim of the concerned workman. In addition to the oral evidence the management as well as the concerned workman have produced and proved papers. The papers produced on the side of the management and admitted in the evidence as Ext. M-1 to M-6 are certain letters, decentralisation of authorities for approval of panel of subordinate cadre including Watch and Ward staff and papers relating to the service of one Parasnath Singh. I fail to understand how those papers are of any help to the management with a view to justify the action taken by the management in terminating the services of the concerned workman who was serving in the Bank of Patna branch since 1973 not only as Badli watchman but by performing the duties of other subordinate cadres staff like Peon etc. I have already stated that the claim of the concerned workman while deposing in the Tribunal of performing the duties of staff of other categories like Peon by making availability of registers from one table to another and supplying water have not been challenged during cross-examination of WW-1. MW-1 has also obtained from denying by making any statement to the effect that the

concerned workman did not perform any such duties of making registers available from one table to another etc. It is true that the evidence on record are sufficient to show that in fact the concerned workman remained engaged in the Bank intermittently but there is no dispute that during the year of 1988 and 1989 he served for a period of more than 240 days continuously. If that be the position i.e. if the concerned workman worked in the Bank at Patna branch for more than 240 days continuously within a period of 12 months in the year 1988-89 and prior to that if he was performing the duties of badli watchman during the absence of permanent staff from 1973 I fail to understand what prevented the management in giving him notice showing therein the cause or his retrenchment or termination from service or even notice pay etc. Learned Representative on the side of the management tried to submit by drawing my attention to clause 20.7 about the status of temporary employees presumably for the purpose of showing that such type of employees are not entitled to any notice or notice pay etc. but careful perusal of 20.7 will show that only those employees will be classified as temporary who are appointed in a temporary vacancy caused by the absence by the particular permanent workman but in the instant case the claim of the concerned workman is that he served for a continuous period of 3 months after retirement of permanent watchman and that he served for a continuous period of 240 days during the year 1988-89 and as such the definition relied upon by the representative of the management as mentioned in clause 20.7 is practically of no help to the management for justifying the action of the management in terminating the services of the concerned workman. On the other hand representative on the side of the concerned workman has relied upon a decision reported in 1994-2 PLIR and also on the decision of Honble High Court in Civi Writ Jurisdiction Case No. 11195 or 1994 against an Award passed by this Tribunal in a reference case and by relying on those decisions it was submitted that since the concerned workman has claimed during his examination-in-chief that in addition to the duties of Watchman he used to supply water and make available registers of the Bank from one table to another and sometimes even to carry daks from one place to another his case should be placed in the same footing as it was before the Honble High Court in the decisions reported in 1994 as mentioned above. The representative on the side of the side of the management failed to give any satisfactory reply to all those points raised on the side of the concerned workman and since it has been well proved that in view of the nature of services rendered by the concerned workman in the Patna branch of the Bank was not only confined as badli watchman the action of the management to turn down his prayer for regularisation of his services for not having any ex-army man certificate or any gun operating licence cannot be treated as justified and in that view of the matter when no notice pay or notice or even retrenchment compensation was paid to the concerned workman and his services was terminated by the management, the action of the management in doing so cannot be treated as justified. I, therefore, on consideration of all these facts and circumstances, materials available on record including oral as well as documentary evidence and on consideration of the submission for and on behalf of the respective parties cannot but hold that the action of the management in terminating the services of the concerned workman Shri Sitaram Yadav was not at all justified. The concerned workman Sitaram Yadav is therefore entitled to be reinstated in the services of the Bank in the subordinate cadre but in view of the facts and circumstances of the case without any back wages. It is hereby ordered that the management shall reinstate the concerned workman Sitaram Yadav in the post of subordinate cadre of the Bank preferably at Patna Branch within a period of two months from the date of publication of this Award in the Gazette of India.

This is my Award.

B. B. CHATTERJEE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1998

का०आ० 1809.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक ऑफ इंडिया के प्रबन्धतन्त्र के सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निम्नलिखित औद्योगिक

विवाद में श्रम न्यायालय, पुणे के पंचाट का प्रकाशित करता है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-8-98 को प्राप्त हुआ था।

[नं० एल-12011/45/96-आई०आर० (बी० II)]

सी० गंगाधरण, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 24th August, 1998

S.O. 1809.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Labour Court, Pune as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Bank of India and their workman, which was received by the Central Government on 21-8-78.

[No. L-12011/45/96-IR(B-II)]

C. GANGADHARAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI V. T. KORE, PRESIDING OFFICER, SECOND LABOUR COURT, PUNE

Reference (IDA) No. 76/98

The Zonal Manager,
Bank of India, 1162/6,
Shivajinagar, Pune

.. First Party

V/s.

The General Secretary,
Bank of India Staff Union,
8-A, Dr. Goyalji Road,
Pune-1.

.. Second Party

CORAM : Shri V. T. Kore.

AWARD

The Desk Officer, Govt. of India, Ministry of Labour New Delhi, has made this reference under Clause (d) of Sub-Sec. (1) of Sub-Sec. 2-A of Sec. 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), between Bank of India and their workmen for adjudication of the dispute over the following demands as specified in Schedule annexed therein:

"Whether the action of the management of Bank of India, Zonal Office, Pune, by engaging seven badli sepoys namely S/s. Y. B. Satav, S. G. Kadam, C. H. Ghatpande, L. D. Kokate, A. B. Auti, R. B. Bhande, and R. D. Bhonde, continuously from the date mentioned against their names without making them permanent, is legal and justified? If not, to what relief the said workman are entitled?"

2. Second party was served with notice vide Ex-2 to appear and to submit S. C. on 20-4-98. But till today nobody did appear. On the last date S. C. was not filed and therefore, today it is for order. To day also no S. C. is filed. It seems that second party has no interest. Hence order.

"Reference stands dismissed for want of S. C. to substantiate the demand."

V. T. KORE, Presiding Officer

Pune.

Date : 31-7-98.

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1998

का०आ० 1810 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यूको बैंक के प्रबन्धन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में श्रम न्यायालय पुणे के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-8-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-12012/412/96-आई०आर०-बी-II]
सी० गंगाधरन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th August, 1998

S.O. 1810.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Labour Court, Pune as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of UCO Bank and their workman, which was received by the Central Government on 24-8-98.

[No. L-12012/412/96-IR(B-II)]
C. GANGADHARAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SMT. A. V. PALSULE, PRESIDING
OFFICER, THIRD LABOUR COURT, PUNE
Ref. (IDA) No. 40/1998

Divisional Manager,

UCO Bank Opp. Sangam Press,
Kothrud, Pune-29. ... First Party

AND

General Secretary,

UCO Bank Employees' Union,
C/o, UCO Bank, M.G. Road,
Pune-01. ... Second Party

AWARD

1. The Desk Officer, Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi-110 001 has made this reference under Clause (d) of Sub-Sec. (1) and Sub-Sec. 2(a) of Sec. 10 of the I. D. Act, 1947 (14 of 1947), for adjudication of the dispute between (1) UCO Bank (First Party) and (2) UCO Bank Employees Union (Second Party) over the following demands in schedule :—

'Whether the action of the management of Uco Bank in relation to Divl. Office in not extending the cut off date for computation of marks for educational qualification and for service from 31-12-92 in respect of Shri R. R. Sadhale, Clerk for the post of JMG-L In view of the reassessment of vacancies by the management is justified? If not, to what relief the workman is entitled?'

2. Both parties are absent when called out. No statement of claim is filed by the second party. Hence,

the reference is disposed of for want of statement of claim. No order as to costs.

SMT. A. V. PALSULE, Presiding Officer
Pune,

Dated :—29-06-98.

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1998

का०आ० 1811 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एल०आई०सी० ऑफ इंडिया के प्रबन्धन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-II, मुम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-8-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-17011/9/97-आई०आर०-बी-II]
सी० गंगाधरन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th August, 1998

S.O. 1811.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-II, Mumbai as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of LIC of India and their workman, which was received by the Central Government on 24-8-98.

[No. L-17011/9/97-IR(B-II)]
C. GANGADHARAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. II,
MUMBAI

PRESENT :

Shri S. B. Panse, Presiding Officer.

REFERENCE NO. CGIT-2/54 of 1998

Employers in relation to the management of Life
Insurance Corporation of India

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employer : Mr. D. K. Sharma, Representative.

For the Workmen : No Appearance.

Mumbai, dated 30th July, 1998

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-17011/3/97-IR(B-II) dated 21-4-98 had referred to the following Industrial Dispute for adjudication :

'Whether the action of the management of LIC of India in terminating the services of Sh. Ramesh, S/o Nathuji Ramat is legal and

justified ? If not, to what relief the said workman is entitled to ?”

2. After the receipt of the notice, Secretary of the Tribunal issued notices to the concerned parties. The representative of the management appeared after receipt of the notice. So far as the workman is concerned his envelope came back with an endorsement that ‘insufficient address, returned to the sender’. The address on the envelope is the same as is informed by the Ministry on the order of the reference. Thereafter inquiry was made to the representative of the management to furnish the address of the concerned workman from their record. It was informed that they do not have any address of the concerned workman it can be further seen that the copy of the order was also directly sent by the Desk Officer to the concerned workman. But he did not file any Statement of Claim as directed by the Desk Officer and also by the Secretary of the Tribunal. Under such circumstances, I pass the following order :

ORDER

The reference is disposed off for want of prosecution.

S. B. PANSE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1998

कां०आ० 1812:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नेशनल इन्श्योरेंस कॉ० लि० के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, चेन्नई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-8-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-17012/36/94-आई०आर०-बी-II]
सी० गंगाधरन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th August, 1998

S.O. 1812.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Chennai as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of National Insurance Co. Ltd., and their workman, which was received by the Central Government on 24-8-98.

[No. L-17012/36/94-(R (B-II))]
C. GANGADHARAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL
NADU, CHENNAI

Tuesday, the 16th day of June, 1998

PRESENT :

Thiru S. Ashok Kumar, M.Sc., B.L., Industrial Tribunal
Industrial Dispute No. 196 of 1994

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the Workmen and the Management of National Insurance Co. Ltd., Madras).

BETWEEN :

The Workman represented by :

The Regional Secretary,
Tamil Nadu General Insurance Employees
Association,
Bharath Insurance Bldgs., Annexe,
New No. 93, Mount Road, Madras-600 002.

AND

The Assistant General Manager,
National Insurance Co. Ltd.,
Madras Ro. 190, Mount Road,
Madras-600 006.

REFERENCE :

Order No. L-17012/36/94-IR (B-II), Ministry of Labour,
dated 8-11-94, Govt. of India, New Delhi.

This dispute coming on for final hearing on Friday, the 20th day of March, 1998, upon perusing the reference, claim, counter statements and all other material papers on record, and upon hearing the arguments of Thiru S. Shrinivasan, Advocate appearing for the petitioner-union and of Thiru M. R. Raghavan, Advocate appearing for the respondent-management and the dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following.

AWARD

This reference has been made for adjudication of the following issue :

“Whether the action of the management of National Insurance Co. Ltd., Madras in denying annual increment to Shri M. Dakshinamurthy, Security Guard w.e.f. 1-11-87 and other Benefits is legal and justified ? If not, what relief is the said workman entitled to ?”

2. The main averments found in the claim statement filed by the petitioner-union are as follows.—The workman is economically very poor. As petitioner could not pursue with his studies, he became a contract labourer with the contractors, “The Southern Security and Detective Services.” The petitioner-workman was deployed in the Regional office of the respondent management situated at Madras as Security Guard w.e.f. 1-11-86 by the Contractors. But factually the control of the petitioner was with the respondent management. Certificate dt. 12-5-89 has been issued by the contractor certifying that the petitioner workman was deployed with the respondent management from 1-11-1986 to 30-4-89. Since 1-11-86 the petitioner workman has been employed with the respondent management continuously without any leave. The petitioner-workman was served with a letter dt. 21-9-89 by the Principal Employer that the Principal Employer had entered into a contract with the Contractor for engaging the services of the petitioner-workman as Security Guard and that the said contract was terminated from 1-5-1989. The petitioner workman's services were utilised temporarily from 1-5-89 to 31-5-89 directly by the Principal Employer for a remuneration of Rs. 1,248.42. The petitioner-workmen had to put in long hours of work, much longer than the workmen under direct employment and he was denied all other attendant benefits which a workman under direct employment could get. The contract was renewed month after month under similar conditions depriving the petitioner workman of all the benefits which a permanent workman could get under similar circumstances was given to conditions till 14-6-90. Regular appointment was given to petitioner workman on 15-6-90 by the respondent management as Security Guard, in pursuance of an interview and this appointment letter is in clear violation of the labour laws and Rationalisation Scheme 1974 that the petitioner workman shall not be entitled to any benefits whatsoever for the petitioner workman's past temporary services. An Industrial dispute was raised by the petitioner-union before the Asst. Labour Commissioner (Central-I) at the office of the Regional Labour Commissioner (Central). The respondent management refused to accept the contentions of the petitioner union in spite of the fact that the Public Sector Institution is clearly prohibited from engaging work-

ment through middlemen contractors and thus the conciliation ended in failure. The denial of annual increment to the petitioner workman w.e.f. 1-11-87 and other attendant benefits is illegal, contrary to labour law principles and highly unjust. The Principal Employer management is clearly prohibited from engaging workmen through contractors vide notification dt. 9-12-76 under the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and as such the employment should be treated as an employment under direct control of the Principal employer. The Principal employer management has not produced any rules or regulation issued by the Apex Corporation viz. G.I.C. of India or by its Head office governing appointment on contract basis or for resorting to adhoc appointment during conciliatory proceedings. Action of the management is clearly in violation of Art. 14 of the Constitution of India as the petitioner workman was not paid the wages and other benefits which is payable to regular workman even though the petitioner workman was doing the same work. The petitioner prays to pass an award with costs directing the respondent management to grant annual increment and other attendant benefits to the petitioner workman with retrospective effect from 1-11-87.

3. The main averments found in the counter statement filed by the respondent are as follows.—The dispute itself is not maintainable in law or on facts. The issue has been referred for adjudication without proper adjudication of the facts and circumstances of the case. The very dispute has been raised belatedly and hence the dispute is liable to be dismissed on the ground of laches in limine. The petitioner-workman was engaged by a contractor viz., Southern Security and Detective Service, Madras-18. In pursuance of the contract, the said contractors were deputing personnel as Security Guards at the Company's premises and the petitioner was one such person. The respondent did not have direct relationship with the concerned workman nor had exercised any supervisory control whatsoever. There was no master servant relationship or employer employee relationship between the concerned workman and the company. The Company did not have any disciplinary control over this workman. The contractor was paid a lumpsum by the Company every month. The workman was on the rolls of the said contractor and was receiving remuneration from the said contractor. The contractors merely supplied the Security Guards. The allegation that the Security Guard was engaged by the Company is totally devoid of truth. The contractual agreement between respondent and Southern Security and Detective Services were terminated w.e.f. 1-5-89. Thereafter, the workman was engaged by the Company temporarily w.e.f. 1-5-89 on a month to month contract basis as there was no sanctioned post and was paid a consolidated sum for the services rendered by him during the month. The workman's services were purely utilised on temporary basis and hence is not entitled to the benefits that are available to the permanent employees of the Company. There are no dues to the workman from the Company. It is denied that the workman was continuously working in the company from 1-11-86 hence the question of entitlement of annual increment w.e.f. 1-11-87 does not arise. Upon sanctioning of permanent posts for security guards in the Company, the workman concerned submitted application for Security Guard in the Company. After an interview, the petitioner was offered appointment as security guard by an order dated 15-6-90. The Petitioner was appointed at a basic salary of Rs. 815/- n.m. in the Subordinate Staff scale of Rs. 815-25-840-35-1260-40-1380-45-1470-50-1520 with other allowances as per rules. In the appointment order, it was specifically stipulated there in that the workman shall not be entitled to any backwages or difference of salary continuity of service etc. for the period of his past temporary service in the Company. The concerned workman agreed to and accepted the above terms and joined duty on 18-6-90. The workman cannot therefore raise any dispute of this nature now and is estopped from raising the same having already accepted the terms of appointment. The workman by an order dt. 15-6-90 was appointed as the employee of the Company only on and from 18-6-90. Prior to that date there was no employer, employee relationship or master and servant relationship. The workman's claim for annual increment, leave, cost of uniform and stitching charges, cost of shoes, belts and washing allowance is unsustainable. Domiciliary medical benefits, ex-gratia, and

other benefits are also not payable to him. The claim made by the workman is not maintainable and it is belated. There had been no dispute regarding contractual employment between the contractor and management of the Company at any point of time when the contract entered into by the Company with M/s. Southern Security and Detective Services was in force. There was no employer, employee relationship during the said period. A consolidated sum was paid for temporary services of the workman each month. The workman is clearly estopped from challenging the terms of contractual/temporary employment at this stage. Upon sanctioning of the permanent post in the Company for Security Guards order of appointment was released by the Competent authority, and therefore, the issue raised in the I.D. is beyond the jurisdiction of the Tamil Nadu General Insurance Employees Association. The respondent is not empowered to appoint any one unless the post is sanctioned by the General Insurance Comm. of India. Only after the post was sanctioned the respondent company was enabled to offer permanent post of security guards on and from 1st June, 1990. The petitioner workman cannot in law lay any claim for a permanent post which was not a sanctioned post. Hence the reference is not competent. In other offices of the respondent in India, similar arrangements had been made for taking up security measures under contractual/temporary employment terms and thereafter on sanctioning of permanent posts for Security Guards order of appointment were released appointing permanent security guards and all benefits admissible for the said post has been extended on and from the said date. It is denied that such appointment was in violation of Labour Laws and Rationalisation Scheme 1974. The workman was appointed only on 18-6-90 by the Company as Security Guard and all benefits has been extended to the workman on and from the said date. The company is not liable to pay any amount to the workman prior to the said date. There are no merits in the claim of the petitioner. The respondent prays to dismiss the claim-petition.

5. Two witnesses were examined on behalf of the petitioner-workman. Ex. W-1 to W-7 have been marked on behalf of petitioner. One witness was examined on behalf of the respondent management. M.1 and M.2 were marked.

6. The Point for our consideration is.—Whether the action of the management of National Insurance Co. Ltd., Madras in denying annual increment to Shri M. Dakshinamurthy, Security Guard w.e.f. 1-11-87 and other benefits is legal and justified? If not, what relief is the said workman entitled to?"

7. The Point : The petitioner workman Dakshinamurthy was a contract labourer with Contractor by name "Southern security and Defective Services." Contractor deployed workman in the Regional Office of the respondent at Madras as Security Guard w.e.f. 1-11-86. The control of the petitioner was with the respondent management. The petitioner was so deployed with the respondent management from 1-11-86 to 30-4-89. From 1-11-86 the workman has been deployed with the respondent management continuously without any leave. The workman's services were utilised from 1-5-89 to 31-5-89 directly by the Principal employer for remuneration of Rs. 1,248 20. The workman had to put in long hours of work much longer than the workmen under the direct employment and he was denied all other attendant benefits which workmen of direct employment could get. The contract was renewed under similar conditions till 14-6-90. Regular appointment was given to the workman on 15-6-90 by the respondent management as Security Guard in pursuance of an interview. According to the petitioner, appointment letter is in clear violation of labour laws and rationalisation scheme 1974 that the workman shall not be entitled to any benefits whatsoever for the workman's past temporary services. The petitioner-union raised dispute before the Asst. Commissioner of Labour wherein the respondent management refused to accept the contentions of the petitioner union in spite of the fact that the public sector institutions are prohibited from engaging workmen through middle men contractors and thus conciliation ended in failure. According to the petitioner-union the denial of annual increment to the workmen w.e.f. 1-11-87 and other attendant benefits is illegal since the Principal

Employer management is prohibited from engaging workmen through contractors vide Notification dt. 9-12-76 under Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and as such the workman's employment should be treated as an employment under direct control of the principal employer. The action of the respondent management is in violation of the Art. 14 of the Constitution of India, as the workman was not paid wages and other benefits which is payable to regular workman even though the petitioner workman was doing the same work.

8. The contention of the respondent management is that the workman was engaged by a contractor with whom the respondent management has entered into a contract and as such the respondent did not have direct relationship with the concerned workman nor had any supervisory control over him and there was no master and servant relationship or employer, employee relationship between the concerned workman and the company. The respondent has further contended that the workman was on the rolls of the said contractor and was receiving remuneration from the contractor and services of the workman was utilised purely on temporary basis and hence he is not entitled to the benefits that the available to the permanent employee of the company.

9. The respondent management is a Government of India undertaking and the appropriate Government is the Central Government as far as the respondent management is concerned. By notification dated 9-12-76 marked as Ex. W-7, the Central Government has prohibited employment of contract labour on and from 1-3-77 for sweeping, cleaning, dusting and watching of the buildings, owned or occupied by establishments in respect of which the appropriate Government under the said Act is the Central Government. There is no dispute that the respondent is a Central Government undertaking and Ex. W-7 notification dated 9-12-76 is applicable to the respondent management. Both the petitioner as well as respondent admitted that the workman concerned was engaged as Security Guard in the premises of the respondent management from 1-11-86 through a Contractor by name Southern Security & Detective Services. The certificate issued by the founder Director of the said contractor is Ex. W-1 wherein it is mentioned that the workman Thiru Dakshinamurthy, was deployed in the regional office of the respondent from 1-11-86 to 30-4-89. Ex. W-2 series are appointment letters issued to the concerned workman directly for the months of June, July, August, September, October, November and December 1989. Ex. W-3 is appointment order dt. 15-6-90 to the concerned workman as regular employee of the respondent management. There is no dispute that the concerned workman was deployed in the services of the respondent management from 1-11-86. When the Central Government has specifically prohibited by a notification dated 9-12-76 to employ contract labour for sweeping cleaning or watching of the buildings the respondent management is employed as contract labourer in violation of the said notification, under the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970, a principal employer who engages contract labour should obtain a certificate of registration issued by the appropriate authority i.e. the Registering Officer under the Provisions of Sec. 7 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970. Similarly, the contractor with whom the Principal Employer enters into a contract should also obtain a licence from the Licensing officer under Sec. 12 of the said Act. The workman can be employed as contract labour only through licensed contractors. Unless both these conditions are complied with the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 could not be attracted. If one wishes to avail the provisions of the Act, both these conditions are required to be fulfilled. Even if one of the condition is not complied with, the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 could not be attracted. Therefore, in a constitution wherein either of these two conditions is not satisfied, the position would be that the workmen employed by an intermediary would be deemed to have been employed by the Principal employer. The above principle has been laid down in a judgement of the Division Bench of Hon'ble Gujarat High Court reported in 1990 I LLN P 972, Food Corporation of India workers Union vs. Food Corporation of India & Ors.

"Having regard to the provisions of the Contract Labour Regulation and Abolition) Act, 1970 it is evident

that :

(i) the principal employer should obtain a certificate of registration and

(ii) the workmen can be employed on contract labour only through licenced contractor.

The Certificate of registration is required to be obtained by the Principal employer issued by the appropriate Government under the provisions of S. 7 of the Act. The licence is to be obtained by the contractors under the provisions of S. 12 of the Act. The workmen can be employed as contract labour only through licensed contractors, unless both these conditions are complied with, the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 would not be attracted. Both these conditions are required to be fulfilled if one wishes to avail of the provisions of the Act. Even if one of the conditions is not complied with the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 would not be attracted. Therefore, in a situation wherein either of these two conditions is not sustained, the position would be that a workman employed by an intermediary would be deemed to have been employed by the Principal employer. From the facts of the case and the legal position, it becomes clear that for certain periods the Principal employer i.e. the Food Corporation of India, did not possess the certificate of registration as required under the provisions of Sec. 7 of the Act. Similarly, the contractors through whom the workmen were engaged also did not possess licence issued under S. 12 of the Act by the "appropriate government" for certain periods. Therefore, in relation to this period, the workmen can very well claim that the workmen employed directly by the principal employer i.e. Food Corporation of India."

In this case also, the respondent management has not made any whisper that they have obtained a certificate of registration issued by the Registering officer under the provisions of Sec. 7 of the Act, nor the said contractor has obtained the licence from the Licensing Officer under Sec. 12 of the Act. In the absence of certificate of registration for the respondent management, i.e. the principal employer, or a licence for the contractor i.e. Southern Security & Detective Services, the workman is deemed to have been employed by the principal employer.

10. The respondent management has contended that since sanction for the post was not available the contract labour was engaged and when the post was sanctioned, the same Security Guard was absorbed as per orders dated 20-2-90 and 27-10-89 which are marked as Ex. M.1 and M.2. When there is need for security guards even in 1986 the respondent management has not sanctioned posts for the above purpose and has gone for contract labour without obtaining necessary certificate of registration. When the appropriate Government has prohibited engagement of Contract Labour as per Ex. W-7 notification, the respondent management has engaged contract labour that too without having certificate of registration and also licence for the contractor as contemplated under Sec. 7 and Sec. 12 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970. Thus it could be seen that the respondent management has violated the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970 itself by engaging concerned workman on contract basis. Therefore, the respondent management is liable to pay an increment from 1-11-87 i.e. on completion of one year of service with other attendant benefits since the concerned workman is deemed to be under the direct employment of the principal employer. Award passed. No costs.

Dated, this the 16th day of June 1998.

S. ASHOK KUMAR, Industrial Tribunal.

WITNESSES EXAMINED

For Petitioner-workman :

W.W. 1 : Thiru M. Dakshinamurthy
W.W. 2 : Thiru Natarajan.

For Respondent-management

M.W. 1: Thiru A.K. Gajapathy.

DOCUMENTS MARKED

For Petitioner-workman :

- Ex. W-1/12-5-89 : Certificate issued by the Contractor to the Petitioner workman that he was deployed with the Principal employer from 1-11-86 to 30-4-89.
- Ex. W-2 21-9-89/3 10-89/1-11-89/4-11-89/3-1-90 : Letter issued by the Principal employer to the Petitioner workman.
- Ex. W-3 15-6-90 : Appointment order issued to the Petitioner workman by the Principal Employer giving him "regular employment".
- Ex. W-4/17-9-92 : Letter written by the petitioner workman to the Principal employer.
- Ex. W-5/30-6-94 : Conciliation failure report.
- Ex. W-6/30-6-94 : General Principles regarding increment.
- Ex. W-7/9-12-76 : Notification issued by Central Government.

For Management :

- Ex. M. 1/27-10-89 : Communication from Head office, to the Regional office.
- Ex. M-2/20-2-90 : Communication from Head Office to Regional Office.

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1998

कां.प्रा. 1813 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नेशनल इन्श्योरेंस कां. लि. के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण चेन्नई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-8-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-17012/37/94-आई.आर. (बी-II)]

सी. गंगाधरन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th August, 1998

S.O. 1813.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Chennai as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of National Insurance Co. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 24-8-98.

[No. L-17012/37/94-IR(B-II)]
C. GANGADHARAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL,
TAMIL NADU, CHENNAI

Tuesday, the 16th day of June 1998

PRESENT :

Thiru S. Ashok Kumar, M.Sc., B.L.,
Industrial Tribunal,

2335 GI/98—12

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 198 of 1994

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the Workman and the Management of National Insurance Co. Ltd., Madras).

BETWEEN :

The Workman represented by

The Regional Secretary,
Tamil Nadu General Insurance Employees Association, Bharat Insurance Building Annex, New No. 93, Mount Road, Madras—600002.

AND

The Assistant General Manager,
National Insurance Co. Ltd.,
Madras R.O. 190, Mount Road,
Madras-600006.

REFERENCE :

Order No. L-17012/37/94-IR (B. II), Ministry of Labour, dated 9-11-94, Govt. of India, New Delhi.

This dispute coming on for final hearing on Friday, the 20th day of March 1998, upon pursuing the reference, claim, counter statements and all other material papers on record, upon hearing the arguments of Thiru S. Shrinivasan, Advocate appearing for the petitioner-workman and of Thiru M. Raghavan, Advocate appearing for the respondent-management, and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following

AWARD

This reference has been made for adjudication of the following issue :

"Whether the action of the management of National Insurance Co. Ltd., Madras in denying annual increments to Shri K. Kathvarayan, Security Guard w. e. f. 1-6-89 and other benefits is legal and justified ? If not, what relief is the said workman entitled to ?"

2. The main averments found in the claim statement filed by petitioner-union are as follows :

The workman is economically very poor. As the petitioner workman could not pursue with his studies, he became a contract labourer with the contractors "The Southern Security and Detective Services". The petitioner workman was deployed in the Regional office of the respondent management situated at Madras as Security Guard w.e.f. 1-6-88 by the Contractors. But factually the control of petitioner was with respondent management,

Since then the petitioner workman is employed continuously without any leave including Sundays and other National holidays. The petitioner workman was issued with an appointment letter on monthly basis from 1-5-89 under the direct control of the respondent-management. Regular appointment was given to the petitioner-workman on 18-6-90 by the respondent management as Security Guard, in pursuance of an interview and this appointment letter is in clear violation of the Labour laws and Rationalisation Scheme, 1974 and that the petitioner workman shall not be entitled to benefits whatsoever for the petitioner workman's post temporary services. An Industrial dispute was raised by the petitioner-union before the Asst. Labour Commissioner (Central-I), at the office of the Regional Labour Commissioner (Central). The respondent management refused to accept the contentions of the petitioner-workman inspite of the fact that the public sector institution is clearly prohibited from engaging workmen through middlemen contractors and thus the conciliation ended in failure. The denial of annual increment to the petitioner workman with effect from 1-6-89 and other attendant benefits is illegal, contrary to labour, jurisprudence rules and highly unjust. The Principal Employer Management is clearly prohibited from engaging workmen by a Notification dt. 9-12-76 under the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and as such the employment should be treated as an employment under the direct control of the Principal Employer. The Principal Employer Management has not produced any rules or regulation issued by the Apex Corporation viz., G.I.C. of India, or by its Head Office governing appointment on contract basis or for resorting to adhoc appointments during conciliatory proceedings. Action of the management is clearly in violation of Art. 14 of the Constitution of India as the petitioner workman was not paid the wages and other benefits which is payable to regular workmen even though the petitioner-workman was doing the same work. The petitioner prays to pass an award with costs directing the respondent management to grant annual increment and other attendant benefits to the petitioner-workman with retrospective effect from 1-6-89.

4. The main averments found in the counter statement filed by the respondent management are as follows :

The dispute itself is not maintainable in law or on facts. The issue has been referred for adjudication without proper adjudication of the facts and circumstances of the case. The very dispute has been raised belatedly and hence the dispute is liable to be dismissed on the ground of laches in limine. The petitioner workman was engaged by a contractor viz. Southern Security and Detective Services, Madras-18. In pursuance of the contract, the said contractors were deputing personnel as

Security Guards at the Company's premises and the petitioner was one such person. The respondent did not have direct relationship with the concerned workman nor had exercised any supervisory control whatsoever. There was no master servant relationship or employer employee relationship between the concerned workman and the Company. The company did not have any disciplinary control over workman. The contractor was paid a lumpsum by the Company every month. The workman was on the rolls of the said contractor and was receiving remuneration from the said contractor. The contractor merely supplied the Security Guard. The allegation that the security guard was engaged by the Company is totally devoid of truth. The contractual agreement between respondent and Southern Security and Detective Services were terminated w.e.f. 1-5-89. The workman was engaged by the company temporarily on a month to month contract basis as there was no sanctioned post and was paid a consolidated sum for the services rendered by him during the month. The workman's services were purely utilised on temporary basis and hence is not entitled to the benefits that are available to the permanent employees of the respondent company. There are no dues to the workman from the Company. It is denied that the workman was continuously working in the Company from 1-6-89. Hence the question of entitlement of annual increment from 1-6-89 does not arise. Upon concerning of permanent posts for security guards in the Company, the workman concerned submitted application for Security Guard in the Company. After an interview, the petitioner was offered appointment as Security Guard by order dt. 18-6-90. The petitioner was appointed at a basic salary of Rs. 815-25-840-35-1260-40-1380-45-1470-50-1520 with other allowances as per rules. In the Appointment order, it was specifically stipulated therein that the workman shall not be entitled to any backwages or difference of salary continuity of service etc. for the period of his past temporary services in the company. The concerned workman agreed to and accepted the above terms and joined duty on 18-6-90. The workman cannot therefore raise any dispute of this nature now and is estopped from raising the same having already accepted the terms of appointment. The workman by an order dated 15-6-90 was appointed as the employee of the Company only on and from 18-6-90. Prior to that date there was no employer employee relationship or master and servant relationship. The workman's claim for annual increment, leave, cost, of uniform and stitching charges, cost of shoes, belts and washing allowance is unsustainable. Domiciliary medical benefits ex-gratia and other benefits are also not payable to him. The claim made by the workman is not maintainable and it is belated. There had been no dispute regarding contractual employment between the con-

tractor and management of the Company at any point of time when the Contract entered into by the company with M/s. Southern Security and Detective Services, was in force. There was no employer, employee relationship during the said period. The consolidated sum paid for temporary services of the workman each month. The workman is clearly estopped from challenging the terms of contractual/temporary employment at this stage. Upon sanctioning of the permanent post in the Company for Security Guard order of appointment was released by the Competent Authority, and therefore, the issue raised in the I.D. is beyond the jurisdiction of the Tamil Nadu General Insurance Employees Assn. The respondent is not empowered to appoint any one unless the post is sanctioned by the General Insurance Corpn. of India. Only after the post was sanctioned the respondent company was enabled to offer permanent post of security guards on and from 1st June 1990. The petitioner-workman cannot lay any claim for a permanent post which was not sanctioned post. Hence the reference is not competent. In other offices of the respondent in India, similar arrangements had been made for taking up security measures under contractual/temporary employment terms and thereafter on sanctioning of permanent posts for Security Guards order of appointment were released appointing permanent security guards and all benefits admissible for the said post has been extended on and from the said date. It is denied that such appointment is in violation of Labour Laws and Rationalisation Scheme, 1974. The workman was appointed only on 18-6-90 by the Company as a Security Guard and all benefits has been extended to the workman on and from the said date. The company is not liable to pay any amount to the workman prior to the said date. There are no merits in the claim of the petitioner. The respondent prays to dismiss the claim petition.

5. On behalf of the petitioner-union, one witness was examined. Ex. W-1 to W-5 have been marked. One witness was examined on behalf of the respondent-management and Exs. M. 1 and M. 2 have been marked.

6. The Point for our consideration is : Whether the action of the management of National Insurance Co. Ltd., Madras in denying annual increments to Shri K. Kathavarayan, Security Guard w.e.f. 1-6-89 and other benefits is legal and justified ? If not, what relief is the said workman entitled to ?

7. The Point : The petitioner workman Thiru K. Kathavarayan, was a contract labourer with Contractor by name "Southern Security and Detective Services." Contractor deployed the workman in Regional Office of the respondent at Madras as Security Guard w.e.f. 1-6-88. The control of

the petitioner was with the respondent management. The petitioner was so deployed with the respondent management from 1-6-88 to 30-4-89. From 1-6-88 the workman has been deployed with the respondent management continuously without any leave. The workman's services were utilised from 1-5-89 to 31-5-89 directly by the Principal employer for remuneration of Rs. 1,248.20 till regular appointment was given to him. The workman had put in long hours of work much longer than workmen under the direct employment and he was denied all other attendant benefits which workmen of direct employment could get. Regular appointment was given to the workman on 18-6-90 by the respondent management as Security Guard in pursuance of an interview. According to the petitioner, the appointment letter is in clear violation of labour laws and rationalisation Scheme 1974 that the workman shall not be entitled to any benefits whatsoever for the workman's past temporary services. The petitioner-union raised dispute before the Asst. Commissioner of Labour wherein the respondent management refused to accept the contentions of the petitioner-union in spite of the fact that the public sector institution are prohibited from engaging workmen through middle men contractors and thus conciliation ended in failure. According to the petitioner-union the denial of annual increment to the workman w.e.f. 1-6-89 and other attendant benefits is illegal. The Principal employer management is prohibited from engaging workman through contractors vide notification dated 9-12-76 under Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and as such the workman's employment should be treated as an employment under direct control of the principal employer. The action of the respondent management is in violation of Art. 14 of the Constitution of India, as the workman was not paid wages another benefits which is payable to regular workmen even though the petitioner was doing the same work.

9. The contention of the respondent management is that the workman was engaged by a contractor with whom the respondent management has entered into contract and as such the respondent did not have direct relationship nor had any supervisory control over him and there was no master servant relationship or employer employee relationship between concerned workman and the company. The respondent has further contended that the workman was on the rolls of the said contractor and was receiving remuneration from the contractor and services of the workman was utilised purely on temporary basis. and hence he is not entitled to the benefits that are available to the permanent employees of the Company.

10. The respondent management is a Government of India undertaking and the appropriate government is the Central Government as far as

the respondent management is concerned. By a notification dated 9-12-76 marked as Ex. W-5 the Central Government has prohibited from employing contract labour on and from 1-3-77 for sweeping, cleaning, dusting, and watching of the buildings owned or occupied by establishments in respect of which the appropriate Government under the said Act is the Central Government. There is no dispute that the respondent is a Central Government undertaking and Ex. W-5 notification dated 9-12-76 is applicable to the management. Both the petitioner as well as the respondent management admitted that the workman concerned was engaged as Security Guard in the premises of the respondent management from 1-6-88 through a contractor by name Southern Security & Detective Services. The certificate issued by the founder Director of the said Director is Ex. W-1 wherein it is mentioned that the workman Thiru Kathavarayan, was deployed in the regional office of the respondent from 1-6-88 to 30-4-89. Ex. W-2 is the letter written by petitioner workman to the respondent management. Ex. W-3 is the conciliation failure report. There is no dispute that the concerned workman was deployed in the services of the respondent management from 1-6-88. When the Central Government has specifically prohibited by a notification dated 9-12-76 to employ contract labour for sweeping, cleaning or watching the buildings of the respondent, management has employed contract labour in violation of the said notification. Under the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, a principal employer who engages contract labour should obtain a certificate of registration issued by the appropriate authority i.e. the Registering officer under the provisions of Sec. 7 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970. Similarly the contractor with whom the principal employer enters into a contract should also obtain a licence issued by the Licensing officer under Sec. 12 of the said Act. The workman can be employed as contract labour only through licensed contractors. Unless both these conditions are complied with the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 would not be attracted. If one wishes to avail the provisions of the Act, both these conditions are required to be fulfilled. Even if one of the conditions is not complied with, the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 could not be attracted. Therefore, in a constitution wherein either of these two conditions is not satisfied, the position would be that the workman employed by an intermediary would be deemed to have been employed by the Principal employer. The above principle has been laid down in a judgement of the Division Bench of Hon'ble High Court of Gujarat in 1990 1 LLN P 972, Food Corporation of India Workers Union Vs. Food Corporation of India & ORS.

"Having regard to the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 it is evident that,

- (i) the principal employer should obtain certificate of registration, and
- (ii) the workmen can be employed on contract labour only through licensed contractor.
- (iii) The certificate of registration is required to be obtained by the Principal employer issued by the appropriate Government under the provisions of Section 7 of the Act. The licence is to be obtained by the contractors under the provisions of Sec. 12 of the Act. The workmen can be employed as contract labour only through licensed contractors. Unless both these conditions are complied with, the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 would not be attracted. Both these conditions are required to be fulfilled, if one wishes to avail of the provisions of the Act. Even if one of the conditions is not complied with, the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 would not be attracted. Therefore, in a situation wherein either of these two conditions is not sustained, the position would be that a workman employed by an intermediary would be deemed to have been employed by the Principal Employer. From the facts of the case and the legal position, it becomes clear that for certain periods the Principal Employer, i.e. the Food Corporation of India, did not possess the certificate of registration as required under the provisions of S. 7 of the Act. Similarly, the contractor through whom the workmen were engaged also did not possess licence under S. 12 of the Act by the "appropriate Government" for certain periods. Therefore, in relation to this period, the workman can very well claim that the workmen were directly employed by the principal employer i.e. Food Corporation of India."

In this case also, the respondent management has not made any whisper that they have obtained certificate of registration issued by the Registering officer under the provisions of Sec. 7 of the Act, nor the said contractor has obtained a licence issued by the licensing officer under Sec. 12 of the Act. In the absence of certificate of registration for the respondent management, i.e. the principal employer or a licence for the contractor i.e. Southern Security & Detective Services, the workman is deemed to have been employed by the principal employer.

10. The respondent management has contended that since sanction for the post was not available the contract labour was engaged and when the post was sanctioned the same Security Guard was absorbed as per Orders dt. 20-2-90 and 27-10-89 which are marked as Ex. M. 1 and M. 2. When there is need for security guards even in 1986, the respondent-management has not sanctioned posts for this purpose and has gone for contract labour without obtaining necessary certificate for registration. When the appropriate Government has prohibited engagement of contract labour as per Ex. W-5 notification the respondent management has engaged contract labour that too without having certificate of registration and also licence for the contractor as contemplated under S 7 and 12 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970. Thus it could be seen that the respondent-management has violated the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 itself by engaging the concerned workman on contract basis. Therefore, the respondent management is liable to pay an increment from 1-6-89 i.e. on completion of one year of service with other attendant benefits since the concerned workman is deemed to be under direct employment of the principal employer. Award passed. No costs.

Dated, this the 16th day of June 1998.

S. ASHOK KUMAR, Industrial Tribunal
WITNESSES EXAMINED

For Petitioner-workman :

W.W. 1 : Thiru Kathavarayan

For Respondent Management :

M.W. 1 : Thiru A. G. Gajapathy

DOCUMENTS MARKED

For Petitioner-workman :

Ex. W-1|12-5-89 : Certificate issued by the Contractor to the petitioner-workman.

W-2|17-9-92 : Letter written by petitioner-workman to principal employer.

W-3|30-6-94 : Conciliation failure report.

W-4| : General Principles of officers, Supervisory, Clerical and subordinate staff regarding increments for the managements Personnel Manual.

Ex. W-5|9-12-76 : Notification issued by the Central Government.

For Respondent Management :

Ex. M. 1|27-10-89 : Communication from Head office to Regional office.

M. 2|20-2-90 : Communication from Head office to Regional office.

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1998

कां०प्रा० 1714 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इंडियन नैवल कैंटीन सर्विस, कोचीन के प्रबन्धन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, अरनाकुलम के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27-8-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-14012/9/88-डी० II(बी)]

के०वी०बी० उष्णी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th August, 1998

S.O. 1814.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Ernakulam as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Indian Naval Canteen Service, Cochin and their workman, which was received by the Central Government on the 27-8-1998.

[No. L-14012/9/88-D. II(B)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT LABOUR
COURT, ERNAKULAM

(Labour Court, Ernakulam)

(Tuesday, the 16th day of June, 1998)

PRESENT :

Shri. Varghese T. Abraham, B.A., LL.M.,
Presiding Officer.

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 1 OF 1989(C)

BETWEEN :

The Area Manager, Indian Naval Canteen
Service, Cochin-682 004.

And

Shri. M. J. Joseph, Mukkadayil House, Poonu-
runni, Cochin-19.

REPRESENTATIONS :

Sri. Alexander Skaria, Advocate, Bishop's
Garden, Kochi-1. .. For Management

Sri. A. V. Xavier, Advocate, Elamkulam,
Kochi-20. .. For Workman

AWARD

The Government of India originally as per order No. L-14012/9/88-D.II(B) referred the following industrial dispute for adjudication :

"Whether the action of the Indian Naval Canteen Service, Cochin in not offering re-employment to Sri. M. J. Joseph, casual

mazdoor is legal and justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?”

2. The above reference order is succeeded by several corrigendum. The above order No. is given since the I.D. is registered on its basis. The subsequent developments will be discussed later.

3. The present case depicts the hapless victim of unending litigation mainly because of the administrative inaction of the Central Government in making drafting and describing the Court in the above cited order.

PRELIMINARY FACTS :

4. The various stages under which the dispute had undergone are narrated in paras 1 to 5 of the claim statements. In the above cited order this court is wrongly described as Industrial Tribunal, Ernakulam-Kerala. The wrong description was corrected as per corrigendum dated 12-2-89. The schedule to the reference order did not reflect the real dispute between the parties. So the workman made representation to the Government of India for the amendment of it and it was turned down by the Government as per letter dated 23-8-89. So the workman filed O.P. No. 7081/89 before the Honourable High Court of Kerala to mandate the Government for correction and that O.P. was allowed on 7-4-1993. As per the direction of the judgment the Government issued another corrigendum dated 21-7-93 with the schedule as :

“Whether action of the management of Indian Naval Canteen Service, Kochi in denying employment by Sri M. J. Joseph, casual Mazdoor is legal and justified ? If not what relief the workman is entitled?”

That corrigendum order was forwarded to this court describing as Presiding Officer, Industrial Tribunal, Ernakulam. The dispute referred to the schedule was not happily worded. The workman made representation to the Government for necessary correction. Thereafter, another corrigendum dated 17-11-1993 has been issued to carry out the following changes.

- “1. In the schedule the word “casual mazdoor” may please be read as “Mazdoor engaged on daily wages.
2. The word “Industrial Tribunal, Ernakulam” appeared at endorsement No. 1, may please be read as “Labour Court, Ernakulam.”

5. On carrying out the change the present schedule before this Honourable Court is to be read as whether the action of the Management of Indian Naval Canteen Service, Cochin in denying employment to Sri. M. J. Joseph, Mazdoor engaged on daily wages is legal and justified ? If not what relief the workman is entitled ?

GRIEVANCE OF THE WORKMAN

6. He was employed as a Mazdoor in the management canteen service. He was posted in the warehouse section. There are different sections in the Canteen service. There are 60 workmen working there. He joined the service on 10-11-1983. He was

continuously working there till 17-9-1984. Except on holidays he was engaged on all other days, his daily wages was Rs. 18. The amount was paid at the end of every week. He has worked under the management more than 240 days. There were 7 mazdoors in the workmen's category and they were Sarvasree Mohanan, P. K. Sasi, M. J. Joseph, Anil Kumar, Sivadasan Pillai, Suresh and Tomy. Workman was 3rd in the rank.

7. He had an unblemished service. He was issued gate pass every month. On the expiry of that month the permit was returned to the command security officer who issued fresh permit. He was issued permit on 3rd September 1984 expiry date of which is 3-10-84. Attendance register was maintained by the warehouse Manager and workman has put signature in the said register from 10-11-83 onwards till 17-9-84. He signed vouchers before the cashier in the office of the canteen service when he was paid his wages on every week, the account books are maintained in the office of the management and it will show that he had worked from 10-11-83 onwards and he was paid till 15-9-84. Except the last entrance permit workman has no other documents in his possession to show that he is a workman. He went for work on 17-9-1984 after the days work on 15-9-84 as 16th September was a Sunday. He signed the attendance register. When he started work on 17-9-84 he was told by Mr. Lenin, a clerk under the management that he need not be allowed to continue the work. He stopped the work. He made enquiry as to why he was not allowed to work. He was told that his service was no longer required. He requested for work. The management turned a deaf ear. He was denied employment. The Indian Naval Canteen Service is an Industry and provisions of I.D. is applicable to it. The denial of employment to the workman is against the provisions of I.D. Act and hence illegal. He filed O.P. 8035/84-II. The Honourable High Court observed that the workman is bound to take his complaint involving violation of the provisions of the I.D. Act before the conciliation officer, a Labour Court or an Industrial Tribunal. After the dismissal of O.P. he raised an Industrial Dispute before the State Labour Authorities which convened conciliation proceedings. There was no settlement before the conciliation officer, the dispute was referred to the Labour Court, Ernakulam for adjudication with the issue “denial of employment to “Sri M. J. Joseph”. The dispute was numbered as I.D. 38/86 before this court. The employer contended in the written statement that the reference made by State Government is bad as it has no jurisdiction and hence incompetent and not maintainable. That issue was heard as preliminary point and an award was passed upholding the contention of the management. So, before the appropriate authority, Central Government workman raised the dispute & the Government of India referred this dispute to this Court as stated above. He had worked for more than 240 days of continuous service during the period from 10-11-83 to 17-9-84. He was denied employment in violation of provisions of I.D. Act. The management's contention in the earlier written statement is that the workman is only intermittently engaged on a purely casual basis and seasonal basis and the total number of days of his employment is 230 days

or no more. According to the workman their contentions are baseless and erroneous. The records of the management would reveal the nature of employment and the length of service. Now, he has no employment. Denial of employment is illegal and unjustified. He prays for reinstatement with back-wages and other attendant benefits.

RIVAL CONTENTIONS

8. It is correct to say that he was in continuous service from 10-11-83 till 17-9-84. He was engaged as a casual mazdoor on daily wages for the sole and specific purpose of clearing some extra workload that had accumulated at the management premises in 1983-84. He was engaged on 10-11-83 till 15-9-84, but with intermittent breaks on daily wages. He was engaged for a total number of 230 days during the said period and since the purpose of this engagement was over, his services was not further required. During the period of 10-11-83 to 17-9-84 the workman had been engaged for 209 full and 42 half days totalling 230 full days. A statement in detail of the working days the workman was engaged is filed along with the written statement as Annexure I. The payment made to him is not stated in Annexure I. Contrary allegations are not true. The Honourable High Court while disposing of O.P. 8035/1984 observed that the workman is bound to take his complaint involving violation of the provisions of I.D. Act before the conciliation officer, a Labour Court or an Industrial Tribunal as the case may be. That O.P. had not been withdrawn as not pressed, but was disposed of on merit with specific directions. Thus directions are therefore binding on the workman as well as on the management. When the management contended that the workman had worked only 230 days, the workman requested the court that the management may be directed to consider the case on compassionate ground. The management was amenable to that submission and made a submission in the court that re-entertainment of the petitioner in service in any future vacancy will be considered by the respondent. So the above O. P. was disposed as follows :

"In the view of the above, I am not in a position to grant the reliefs sought by the petitioner in these proceedings. The original petition is dismissed with the observation that the claim of the petitioner to the re-entertainment in service will be considered against the next arising vacancy. The dismissal of this original petition will not in any manner stand in the way of reconsideration of the petitioner's case by the respondent."

A copy of the judgment is in Annexure 2. Even during the conciliation proceedings, the management was agreeable to re-entertain the workman in service as undertaken before the High Court the workman was not ready to accept such re-entertainment in service as he had requested for and obtained a direction in that regard in the judgment in the O.P. The minutes dated 1-12-87 and 21-12-87 of conciliation proceedings between the management and the workman before the Asst. Labour Commissioner (Central), Ernakulam are Annexure 3 and 4. These shows that the management was ready for the re-entertainment in

service of the workman, but the workman was not amenable to the said O.P. He has been dragging this matter in various proceedings from 1984 onwards. His present claim for re-instatement in service with continuity of service and backwages and all other attendant benefits and costs is only wishful and experimental. This claim is unfounded and unsustainable.

REPLY BY THE WORKMAN

9. He has moved M.P. No. 33/98 in the above I.D. with the prayer to direct the respondent management to produce some documents to prove that he had enough continuous service to get protections under the I.D. Act. The management without producing the document called for has filed an affidavit dated 30-3-98 and produced some documents which are not relevant to decide the issue in the proceedings. In Annexure I the working days have been classified as full day and half day. That is not correct classification. On Saturdays, the godown section works only upto lunch time and Sundays are off whereas the Canteen (Sales) section works upto the lunch time on Sundays and Mondays are off. Even though the working time is upto lunch time as aforesaid those days are also treated as full days and full wages paid to the employees. That means those days are not treated as half days for the benefit due to the employees. They get full attendance and full remuneration. So the half days shown in the Annexure I are also to be treated as full days. Then the number of days according to Annexure I comes to 251 days during the period from 10-11-1983 to 15-9-84. That itself is sufficient so that the workman is entitled to get protections under the I.D. Act. The averments in para II of the affidavit of the management regarding attendance book and vouchers are unbelievable. There were no casual mazdoors. The workers like him were mazdoors. For them there was no attendance book as prescribed in the statutes, but there was a note-book to make the attendance of the mazdoors. He marked attendance book on the days he has worked in the management. The first day of marking the attendance is on 10-11-83 and the last day of working the attendance is 17-9-84. If that attendance book is produced it would show that his attendance was more than 251 days shown in the Annexure I and the vouchers would show that full wages are paid for the entire days. The averment regarding destruction of vouchers after five years as per order No. 5/80 dated 1-2-80 marked as Annexure V in the affidavit of the management is not helpful to their contentions, because in clause 2 of that order there is a stipulation that no documents relating to cases under investigation have to be destroyed until action has been completed. The case pertaining to denial of employment to his workman started in the year 1981 and the same has not been completed so far. So the management ought to have kept the records safe, with respect to the length of service and payments given to him. There ought to be records with the management regarding his service. Otherwise they could not have prepared Annexure I. So the documents are purposefully withheld by the management. Hence adverse inference has to be taken against the management. His right to challenge the action of the management for having violated the provisions in the I.D. Act has not

been curtailed by the judgment. As an alternative proposals and suggestions were made in the order to avoid prolonged litigation. The judgment in the O.P. is without taking into account his length of service and the right conferred under the I.D. Act and the denial of the same by the management. When the state Government referred the dispute the management had no contentions as raised by them in the present dispute. They had raised question only regarding the jurisdictional competency. So the management is estopped from raising contentions on the basis of the O.P. He has not been asked to apply for a post in the management establishment. The averment regarding employment of Mazdoors on daily wages in INCS is not correct. The Mazdoors are not employed as casual daily rated employees. No such designation INCS is not correct. The Mazdoors are not employed had been given to the Mazdoor. He has completed more than 240 days. The Mazdoors junior to him at the time of his denial of employment are absorbed in the management service without following the procedure as evidenced by Annexure VII. So he prays for appointing him as he had more than 240 days.

THE MANAGEMENT AGAIN COUNTERS

10. Only monthly rated regular employees get the benefit of half days and even holidays. Daily rated casual labourers are not paid full days wages for half day work. They do not get any wages on holidays. So he cannot be credited with having put in 251 days, counting half days as full days. No books are regularly maintained but kept only for the time being and not preserved. It shows that he was casual labourer not regular mazdoor. Contrary contentions of the workman are also denied Anil Kumar. Tommy who were shown in the annexure VI seniority list who were casual workers with him entered regular service as Mazdoors on 18-2-1987. Their serial Nos. are 17 and 18 in the Annexure. Another labourer Suresh mention by the workman has been admitted to regular service only in the year 1983. Annexure VII documents show the formalities of regular appointment. If only the workman had approached the management with application for regular appointment in the wake of judgment dated 27-9-84, he had every chance of such appointment in 1984 itself or later in 1985 in the next vacancy. Instead his wavering the two minds and without justification or good faith persuading him in haste to enter into these protracted proceedings has been patently vain and vexatious.

11. No oral evidence is adduced. Ext. Ws 1 to 5 produced on the side of workmen and Exts. M1 to M7 are produced on the side of management.

12. Points which emerge for consideration are :

1. Whether claimant is a workman, as defined under the I.D. Act ?
2. Whether he has continuously worked for more than 240 days in a year as alleged by him ?
3. Whether termination of the workman legal, valid and proper and if any what relief if he is entitled to get?

13. Points 1 to 3 : The definition of workman as contained in the I.D. Act does not make a distinction between the permanent workman, temporary workman

or between daily rated, monthly rated or piece rated workman. Even in Ext. W1 dated 3-9-86 temporary entry pass the workman is designated as Mazdoor and not as temporary, casual or daily rated mazdoor. According to the management he was temporary mazdoor engaged on daily wages. Daily rated workman is also a workman as defined in the I.D. Act. Ext. W2 is the printed copy of the award in I.D. 38/96 before this court. That dispute was referred by the Government of Kerala. It can be seen that a dispute was in existence between the management and the workman. What was referred is the denial of employment to Sri M. J. Joseph. In Ext. W3 the only contention of the management is that INCS is an establishment of India & that the Indian Naval Canteen Control Board, Naval Headquarters, New Delhi exercises the powers of organisation corrigendum as referred to above were made. In Ext. W4 judgment in O. P. 7081/89 are dated 7-4-93. Our High Court observed that the substantial question referred is whether there is denial of employment. It is further held that phraseology of reference may limit the reliefs in case reliefs as to be granted. The dispute relates to denial of employment and since the appropriate government have decided to make a reference, the reference must relate the denial of the employment.

12. The crucial questions to be considered in this case are whether the present claimant is a workman and secondly whether his service has been illegally terminated. Question of the number of working days is not relevant to decide whether a person is a workman. The number of working days is relevant only if it is found that there is violation of 25 of the I.D. Act and in such a case the question whether he has completed more than 240 days continuously is significant. It is well noted that there is no dispute between the management and the workman with regard to the date of joining service and date of termination. Ext. M4 is the Annexure I to written statement filed by the management. As per Ext. M4 from the period from 10-11-83 to 10-9-84 he has worked only for 209 full days and 42 half days. The defence case of the workman is that he has marked attendance register in note book and for the payment made to him, he issued vouchers. He called for these records by moving M.P. before this court. The management filed its affidavit stating inter alia that such note books are not regularly maintained and keep only for time being and not preserved. If these documents prepared by virtue of Ext. M3 order No. 5/80 the question to be posed for consideration and to be explained by the management, if on what materials details are given in Ext. M4. The litigation this case started way back in 1984. Para 2 of Ext. M3 runs as follows :

"Records are to be destroyed at the end of the stipulated period. In no case should a record connected with an audit objection be destroyed unless the objection has been finally settled by the appropriate audit authorities. Similarly, no document relating to cases under investigation are to be destroyed until action has been completed."

(Emphasis Supplied)

So the management was fully aware of the fact of litigation which is between the dwarf and giant. So as per above extracted provision in Ext. M3 the management is bound to retain these documents mainly the note book and the vouchers issued by him. Ext. M4 statement regarding details of work were filed along with the written statement on

21-1-98. How the management obtained the details lies in mystery. The legally settled position is that a party in whose possession the documents are must produce the documents before the court and if it wilfully withholds the document an adverse has to be drawn against him. In this case also withholding of this material documents will itself indicates that Ext. M4 is fabricated or prepared on an imaginary basis. Even accepting for argument sake as per the contentions of written statement that the total number of days work during this relevant period was for a total period of 230 full days. In Saturday the work is upto lunch time and Sunday is an off day. To controvert that stand taken by the workman no proof is forthcoming. The party in whose possession the best document are kept shall produce them and on failure to do so the court can draw an adverse inference against him. To support this view please go through the commentary on illustration (g) of S. 114 of the Evidence Act of Woodroffe and Ameer Ali 12th Edn. Vol. 3 page 2150, 2151, 2165 and Sarkars' Law of Evidence 13th Edn. pages 1045 to 1048 and the decisions in A.I.R. 1966 S.C. 629, A.I.R. 1968 S.C. 1413, A.I.R. 1974 S.C. 1957, A.I.R. 1962 Orissa 7 etc.

The explanation given by the management for non-production of these documents is a false explanation. A false explanation is worse than no explanation at all. Therefore, I unhesitatingly held that the management is adopting a hide and seek play. Ext. M5 is the copy of the judgment in O.P. 6035/84-D. In para 4 of Ext. M5 it is observed that the counsel for the petitioner submitted that the respondent may be directed to consider this case on compassionate ground and the Government Pleader submits that the management is prepared to entertain the petitioner in service in future vacancy. There is no adjudication of the I.D. and there was no disposal on merit. That O.P. was dismissed with a direction to reconsider the case of the petitioners by respondents therein. Para 3 of Ext. M5 shows that the petitioner is bound to make the complaint involving violation of provisions of I.D. Act before the appropriate authorities. Thus he has come up with reference, which was earlier made by the State Government and later by the Central Government with 2-3 corrigendum showing administrative in action. Ext. M5-M7 will show that conciliation conferences were held by the management and the workman. The management has a case that the workman has not made any application for re-engagement. Not even a single piece of paper is shown by the management demanding him to submit necessary application before the management. The management filed O.P. No. 836/1994 against a Single Bench decision taken by his Lord Ship Justice J. B. Koshy. The learned Single Judge had hold that whether 4th respondent the present workman is a casual employee or not, whether he has got any claim of service or not have to be decided by the Labour Court on the basis of evidence and that the Government which made the reference has got the power for correction. The direction was given to this Court to dispose the I.D. within 6 months from the date of receipt of copy of the judgment. Against that judgment the management filed writ appeal as W.A. 2155/97. The Division Bench of the High Court dismissed that appeal but the Division Bench at para 3 of the judgment has made the following observations:

"However in the light of Ext. judgment dismissing the Original Petition filed by the fourth respondent, we would direct the second respondent to consider specifically the objections raised by the appellant relying upon Ext. P1 judgment especially the validity of the order passed by the government referring the dispute to it. We are issuing the above direction for the reason that the appellant has a case that in the light of Ext. P1. Judgment the fourth respondent could not have legally raised on such a dispute for adjudication under the Industrial Disputes Act and the government could not have made a reference in law, while making the above observations, we should not be understood to have expressed any view on the merit of the above contention raised by the appellant. Second respondent may dispose of the matter on merits in accordance with law."

Ext. P1 judgment referred to there is the copy of the judgment in O.P. 8035/84-D dated 27-9-84. Ext. P1 is marked in this case as Ext. M5. What was held in that case is that the petitioner is bound to make complaint before the authorities under the I.D. Act alleging violation of provisions of that Act. In para 2 of Ext. M5 the counsel for the management made a submission that the petitioner did not have necessary period of 240 days, that he was a casual workman and that his service is liable to be terminated at any time. Thus as per Ext. M5 and the direction of the Division Bench in writ appeal cited supra the questions to be considered are whether the claimant is a workman and whether he has completed 240 days of continuous work and that whether there is violation of any provision of the I.D. Act. I have already stated that a mere nomenclature given to the status, as daily rated, piece-rated, monthly-rated temporary, the person is a workman if he comes under the provisions of the I.D. Act unless excluded by the provisions of I.D. Act. I have already observed that the calculation of total number of days as shown in Ext. M4 is false. The case of the workman that he had to work only after lunch time on Saturdays and Sundays are off days. If that be so the off days have also be computed and reckoned while considering the length of service. The half days have also to be considered as full days. In this manner I can inescapably conclude that the present claimant is a workman. He has completed more than 240 days of continuous service. No notice or notice pay is given to him. No compensation is paid. So the termination is illegal. The reference by the Central Government is valid. The workman is entitled to be reinstated, in the same position as he would have been as on date of termination of service namely 17-9-84. He is entitled to get 50 per cent back wages which have to be reckoned on the basis of the wages paid from time to time from 17-9-84 onwards to his immediate superior. He is also entitled to get other attendant service benefits and continuity of service.

In the result, an ward is passed directing the management to reinstate the workman with continuity of service and other attendant benefits, as he would have been on 17-9-1984 and he is entitled to get 50 per cent back wages as stated above. Ernakulam,

16-6-1998.

VARGHESE T. ABRAHAM, Presiding Officer

APPENDIX

Exhibits marked on the side of Management:

- Ext. M1.—Details of working days of the worker.
- Ext. M2.—Copy of judgment in O.P. 8035/84B dated 27-9-84.
- Ext. M3.—Copy of letter issued by Management to worker dated 1-12-97.
- Ext. M4.—Copy of notice No. 8(36)/87 ALC/EKM dt. 21-12-97.
- Ext. M5.—Copy of order of the General Manager dated 1-2-80.
- Ext. M6.—Seniority list of the firm dated 16-2-90.
- Ext. M7.—Copy of letter submitted to the management dated 21-6-93.

Exhibits marked on the side of Workman:

- Ext. W1.—Temporary permit issued to worker by management dated 3-9-86.
- Ext. W2.—G.O. (Rt.) No. 464/86/LBR dated 15-3-86.
- Ext. W3.—Copy of award in I.D. 38/86 dated 16-2-87.
- Ext. W4.—Copy of judgment in O.P. 7081/89R dated 7-4-93.
- Ext. W5.—Copy of judgment in O.P. 836/94Y dated 21-10-97.

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1998

SCHEDULE

का०आ० 1815.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, पोस्टल सिविल डिवीजन, पटना के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं० 2 धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27-8-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-40011/40/95-आई०आर० (डी.य.)]

के०वी०बी० उण्णी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th August, 1998

S.O. 1815.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Executive Engineer, Postal Civil Division, Patna and their workman, which was received by the Central Government on the 27-8-98.

[No. L-40011/40/95-JR(DU)]

K.V.B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri B. B. Chatterjee, Presiding Officer.

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1)(d) and Sub-section 2(k) of the I.D. Act, 1947.

REFERENCE NO. 78 OF 1996

PARTIES :

Employers in relation to the management of Postal Civil Division, Patna and their workman.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen : Shri D. K. Verma, Advocate.

On behalf of the employers : Shri H. C. Prasad, Advocate.

STATE : Bihar

INDUSTRY : Postal

Dated. Dhanbad, the 19th August, 1998

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) and sub-section 2(k) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No I-40011/40/95-I.R. (D.U.) dated. the 26th July, 1996.

"Whether the action of the management of Executive Engineer, Postal Civil Division, Patna in not regularising and demoting Sh. Tushar Kanti Roy from the post of casual driver to casual mazdoor without any reason is proper and justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. The reference on being taken up for hearing learned Advocate for the management and the representative of the workman by drawing my attention to two separate petition filed on the side of the management and the concerned workman on 24-7-98 submitted that the dispute has since been settled between the parties and they are not willing to proceed further with the reference as the concerned workman in terms of the settlement has already joined the services although no joint petition of compromise by the parties has been filed. That being the position when neither of the parties are interested in prosecuting the reference anymore I am left with no other option but to presume that at present there is no existence of any industrial dispute between the parties and as such an Award in the form of 'No dispute' Award is imperative. I do order accordingly.

B. B. CHATTERJEE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1998

का०आ० 1816.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार कलकत्ता टेलीफोन्स, कलकत्ता के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27-8-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-40012/1/85-डी० II (बी)]

के०वी०बी० उण्णी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th August, 1998

S.O. 1816.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Calcutta Telephones. Calcutta and their workman which was received by the Central Government on 27-8-1998.

[No. L-40012/1/85-D II(B)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 32 of 1985

PARTIES :

Employers in relation to the management of Calcutta Telephones.

AND

Their Workman.

PRESENT :

Mr. Justice A. K. Chakravarty,
....Presiding Officer.

APPEARANCE :

On behalf of Management : Mr. T.
Chowdhury, Advocate.

On behalf of Workman : Mr. S. Chatterjee,
Advocate.

STATE : West Bengal INDUSTRY : Telephones

AWARD

By Order No. L-40012(1)|85-D. II(B) dated 9-12-1985 and Corrigendum of even number dated 9-4-1986 the Central Government in exercise of its powers under Section 10(1)(d) and (2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

“Whether the action of the Calcutta Telephones, Calcutta-700001 in terminating the services of Shri Budhadev Thakur with effect from 1-9-1979 is legal and justified ? If not, to what relief the workman is entitled to ?”

2. Instant reference has arisen at the instance of the concerned workman Budhadev Thakur challenging the order of termination of his service dated 1-9-79 by the Calcutta Telephones.

3. The workman has alleged in his written statement that he was appointed as an employee of the Calcutta Telephones by the Assistant Engineer, Cable Construction and pressurisation. Howrah on 27-8-1978 and continued to remain in the said service for more than one year without any break. His service having been suddenly terminated on 1-9-1979 without assigning any reason and without payment of any compensation or notice, he represented to the management for reinstating him in service. The management having requested him to wait indefinitely, he sought intervention of the General Manager, Calcutta Telephones in the matter by his letter dated 9-8-1984. He informed the General Manager in his letter that one Tapan Kumar Jana whose service was terminated in the similar manner by the management was directed to be reinstated by the Hon'ble Calcutta High Court and appeal against the same was rejected by the Hon'ble Supreme Court. Since the workman was not favoured with any reply of the said letter, he referred the matter to the Regional Labour Commissioner (Central), Calcutta. But, all attempts of conciliation having failed, the matter was referred to the Central Government which drew up the present reference. The workman accordingly prayed for his reinstatement with full back wages as there

was blatant violation of the provisions of Section 25F of the Industrial Disputes Act, 1947 while terminating his service.

4. Management of Calcutta Telephones, in its written statement has alleged that the concerned workman was locally recruited as daily rated mazdoor for some specified jobs on no-work-no-pay basis and daily rated mazdoor is engaged purely on temporary basis and the attendance of the concerned workman was recorded to enable the authority to count his attendance and to pay him accordingly and that he was paid on monthly basis on muster roll. Further case of the management is that the service of a casual labourer can be terminated on the completion of the particular piece of work for which he is engaged and neither any question of notice nor payment of compensation arise in such circumstances. Management also has denied that the termination of the service was retrenchment under Section 2(oo) of the Industrial Disputes Act, 1947 and accordingly the workman is not entitled to any benefit under section 25F or 25G of the said Act. Management accordingly prayed for dismissal of the case of the workman.

5. In his rejoinder, the workman has denied the case of the management and further alleged that the management has indulged in unfair labour practice by terminating his service and that the management was not justified in not reinstating him in service when a similarly placed workman got relief from the Hon'ble Calcutta High Court.

6. Management of Calcutta Telephones also filed a counter rejoinder denying the allegations made by the concerned workman in his rejoinder.

7. Mr. Chowdhury, learned Advocate appeared for the management but none appeared on behalf of the concerned workman. It however appears from record that documents were exhibited and witnesses were examined by both the parties in this case. Since the Tribunal has got to decide the case on the basis of the materials on record, Mr. Chowdhury, learned Advocate for the management was directed to make his argument in this case.

8. It appears from record that the parties examined one witness each and documents were also exhibited in this case.

9. The workman in his evidence has admitted that after his initial termination of service in September, 1979 the management of Calcutta Telephones has again appointed him in 1988. Since he is paid at the lowest rate which is meant for new entrants because of his subsequent employment he was praying for payment for years in which he was kept idle and also for bonus and seniority.

10. The present reference is directed for determination of the question whether the termination of the service of the concerned workman from 1-9-1979 was justified. It is true that the workman has obtained appointment once again in 1988 as

it will appear from his evidence. That, however, cannot take away his right of reinstatement from the date of his termination if his service was wrongfully terminated and back wages from that date till the date of his fresh appointment if he was without any occupation during this period of time.

11. The sheet anchor of the workmen's case is the certificate issued in his favour by Mr. K. L. Das, Junior Engineer, Cable Planning, Construction and Pressurisation, Howrah dated 28-10-1982 marked Ext. W-1 in this case. It will appear from this certificate that he worked uninterruptedly from 27-8-1978 to 31-8-1979. Not a single word has been stated in the written statement as well as in the counter rejoinder filed by the management in respect of the certificate. Mr. Pijush Kanti Ghosal, present Assistant Engineer, Cable Construction while deposing in favour of the management frankly admitted in a question posed by the Tribunal that he cannot definitely say about the propriety of the certificate marked Ext. W-1. He also stated that he does not know whether he had the authority to grant such certificate or not. There is, therefore, no denial on the part of the management about the authority of the officer issuing the certificate in favour of the concerned workman and the propriety and genuineness of the same. The management, however, referred to Exts. M-1, M-2 and M-3 which are ACG vouchers showing the wages taken by the concerned workman from 16-5-1979 to 31-7-1979. Management also produced certain acquittance roll from August, 1978 to May, 1979, without furnishing such rolls from September, 1978 and October, 1978. Further, the workman's case is that he worked upto 31-8-1979. It is therefore clear from the acquittance rolls for the months of June, July and August, 1979 were also not produced. The workman has stated in his evidence that he worked till 31-8-1979. This was not denied by the management in its written statement. The acquittance rolls having thus not covered the entire period of work of the concerned workman cannot be relied upon for calculation of the days worked by the concerned workman.

12. It is true that the concerned workman has not produced any other document excepting the certificate (Ext. W-1) to prove that he worked from 27-8-1978 to 31-8-1979 uninterruptedly. The certificate was silent in respect of his nature of work, namely, whether it was continuous or uninterrupted. The management, in its written statement has not denied the period of service as stated by the workman in paragraphs 1 and 2 of his written statement. Management in its written statement without specifically denying the allegations of the workman that he worked during the above period, merely stated that he had not completed more than one year's continuous service. The management wanted to prove the break in service of the workman during this period by production of acquittance rolls and some ACG vouchers. I have already stated that the

acquittance rolls and ACG vouchers are merely for certain period of time and their discrepancy in respect of the period of work show that all those documents have not been produced. Suppression of such documents gave rise to the presumption that had these documents not been withheld, would not have supported the case of the management in respect of break in service of the workman. The best evidence in this matter would have been the attendance register. The management in its written statement has admitted that such attendance register used to be maintained, but no such attendance register has been produced in this case. The workman accordingly has succeeded in proving that he worked from 27-8-1978 to 31-8-1979 continuously and uninterruptedly by the unimpeachable evidence in the shape of the certificate issued by an officer of the management whose genuineness was not also contradicted either in the written statement or in the evidence of the management and also by withholding of the above documents by the management which gives rise to the presumption that had these documents been produced, they would have supported the case of the workmen's case of continuous and uninterrupted service during the above period. At any rate, the workman having succeeded in proving that he has rendered service for 240 days in a year from the date of termination of his service within the preceding 12 calendar months he shall be entitled to be reinstated in his service with back wages as admittedly the requirements of Section 25F of the Act were not complied with in this case.

13. The essential requirement of Section 25F is that the workman must be in continuous service for a period of one year for getting his relief as contemplated in that section. For computation of the above one year's service one is to take recourse to Section 25B(1) of the Act which shows that the completion of one year shall be considered on the basis of the continuous and interrupted service rendered by the workmen excepting of course, paid holidays, leave and other contingencies for which the workman could not attend to his duties. Section 25B(2) is a deeming provision which also prescribes that completion of 240 days of work within a year starting backward from the date of termination of service shall also be counted as one year service for the purpose of Section 25F of the Act.

14. In the instant case, I have shown that the workman has proved that he has rendered continuous and uninterrupted service for the period of one year and at any rate 240 days of service within a period of one year as required under section 25F of the Act. So, in any view of the matter, the service of the workman cannot be terminated without compliance of the provisions of section 25F of the Act. The management having not admittedly complied with the requirements of law as provided in that section, namely, service of notice and payment of compensation, the order of termination must be said to be illegal and void ab-initio.

15. The termination of the service of the concerned workman in 1979 having thus been found to be void, his reinstatement in the service from that date and back wages alongwith consequential benefits, including bonus till the date of his re-employment in 1988 shall follow as a matter of course as there is nothing on record to show that he had any alternative service or income during this period of his forced idleness. The management shall accordingly reinstate him in his service from 1-9-1979 and pay him all his back wages and consequential benefits, including bonus till the date of his fresh employment in 1988 without affecting his seniority in any way.

This is my Award.

Dated : Calcutta, the 18th August, 1998

A. K. CHAKRAVARTY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1998

का०आ० 1817.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार महानगर टेलीफोन निगम लि० मुम्बई के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं० 2, मुम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27-8-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-40012/8/97-आई०आर० (डी.यू.)]

के०वी०बी० उण्णी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th August, 1998

S.O. 1817.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2. Mumbai as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M.T.N.L., Mumbai and their workman, which was received by the Central Government on 27-8-98.

[No. L-40012/8/97-IR(DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. II, MUMBAI.

PRESENT :

Shri S. B. Panse, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-2/32 of 1998

BETWEEN

Employers in Relation to the Management of Mahanagar Telephone Nigam Ltd. Mumbai

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employers : Mr. O. K. Umashankar, Advocate

For the Workmen : No Appearance.

Mumbai, dated the 6th August, 1998.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-40012/8/97-IR(DU), dated 9-3-98, had referred to the following Industrial Dispute for adjudication :

"Whether the action of the management of Mahanagar Telephone Nigam Ltd. in removing Shri Rajendra Narayan Govilkar from the services w.e.f. 10-12-1988 is legal and justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

2. The Desk Officer while sending the order of reference to this Tribunal had also issued copies of the same to the concerned party including the workman. He was asked to file a statement of claim within the stipulated time mentioned therein.

3. The Secretary of the Tribunal after receipt of the order had issued notices to the management and the workman. The management appeared and filed a Vakalatnama of Mr. Masurkar Advocate. As against that even though the workman is duly served he did not appear. The matter was adjourned for filing Statement of Claim for six times that is between 4-5-98 to 6-8-98. The Learned Advocate for the management submitted that under such circumstances the matter may be disposed off. I find that sufficient opportunity was given to the workman to file a Statement of Claim but he did not. It appears that he is no more interested in the matter. Hence I pass the following order :

ORDER

The reference is disposed of for want of prosecution.

S. B. PANSE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1998

का०आ० 1818 —औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जयपुर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, कोटा के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27-8-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-42011/61/95-आई०आर० (डी०यू०)]

के०वी०बी० उण्णी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th August, 1998

S.O. 1818.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal. Kota as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bhartiya Puratatava Sarvekshan Vibhag, Jaipur and their workman, which was received by the Central Government on 27-8-98.

[No. L-42011/61/95-IR(DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

अनुबंध

न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण/केन्द्रीय/कोटा/राज०

निर्देश प्रकरण क्रमांक : औ० न्या० (केन्द्रीय) — 21/96

दिनांक स्थापित : 25-9-96

प्रसंग : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश
संख्या एल० 42011/61/95-आई०आर० (डी.यू.)
दिनांक 30-8-96

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

मध्य

रघुवीर सिंह द्वारा महामंत्री, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कर्म-
चारी संघ, चित्तौड़गढ़ ।

—प्रार्थी श्रमिक

एवं

अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, सी स्कीम,
जयपुर ।

—प्रतिपक्षी नियोजक

उपस्थित

श्री जगदीश प्रसाद शर्मा,

आर०एच०जे०एस०

प्रार्थी श्रमिक की ओर से प्रतिनिधि :—

श्री बलदेव सिंह गौड़

प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से प्रतिनिधि :—

केप्टिन आर०एस० ठाकुर

अधिनिर्णय दिनांक : 15-7-98

श्री एच०के० कथपाल

अधिनिर्णय

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निम्न
निर्देश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे तदुपरांत
“अधिनियम” से सम्बोधित किया जावेगा) की धारा 10(1)
(घ) के अन्तर्गत इस न्यायाधिकरण को अधिनिर्णयार्थ
सम्प्रेषित किया गया है :—

“क्या प्रबन्धन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग,
जयपुर मण्डल द्वारा कर्मकार श्री रघुवीर सिंह स्मारक
परिसर की सेवाएं दिनांक 6-4-93 से समाप्त करने

की कार्यवाही वैध एवं उचित है ? यदि नहीं तो
सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है और
किस तारीख से ?”

2. निर्देश न्यायाधिकरण से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर
किया गया व पक्षकारों को सूचना जारी की गयी । प्रार्थी
श्रमिक की ओर से क्लेम स्टेटमेंट प्रस्तुत कर संक्षेप में यह
अभिकथित किया गया है कि प्रार्थी श्रमिक रघुवीरसिंह द्वारा
प्रतिपक्षी प्रबन्धन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जयपुर
मण्डल (जिसे तदुपरांत “प्रतिपक्षी नियोजक” से सम्बोधित
किया जावेगा) के यहां नियोजन में दि० 21-5-85 से
सहायक कर्मचारी स्मारक परिसर के रूप में नियोजित
होकर दि० 5-4-93 तक निरन्तर कार्य कर हर क्लेण्डर
वर्ष में 240 दिवस से अधिक अवधि तक कार्य कर निरन्तर
सात वर्ष से अधिक अवधि की सेवा पूर्ण कर ली गयी थी ।
तब प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक को दि० 6-4-93
से अकारण ही, प्रार्थी श्रमिक से कनिष्ठ श्रमिकगण गोविन्दसिंह
व मन्नालाल को नियोजित रखने हुए और नियमित सेवाओं
का लाभ देने हुए “पहले आये बाद में जाये” सिद्धान्त की
अवहेलना करते हुए, बिना कोई जांच कार्यवाही किये बिना
कोई नोटिस अथवा नोटिस वेतन व छंटनी का मुआवजा
दिये अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों की अवहेलना
करते हुए, मौखिक ही सेवा से पृथक् कर दिया जो सर्वथा
अनुचित एवं अवैध है और प्रार्थी श्रमिक, तत्पश्चात् से ही
बेरोजगार रहा है । जब प्रार्थी श्रमिक, प्रतिपक्षी नियोजक
के यहां नियोजन में सेवा की निरन्तरता के साथ पिछले
सम्पूर्ण वेतन व अन्य समस्त लाभों सहित पुनः सेवा पर
बहाल करवाये जाने का अधिकारी है । अतः प्रार्थी श्रमिक
का यह क्लेम स्वीकार किया जावे ।

3. प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से जवाब क्लेम प्रस्तुत
कर प्रार्थी श्रमिक के उक्त क्लेम को अस्वीकार किया गया है
तथा संक्षेप में यह अभिकथित किया गया है कि “भारतीय
पुरातत्व सर्वेक्षण कर्मचारी संघ, चित्तौड़गढ़” के नाम से कोई
संघ प्रतिपक्षी विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं है और ना
ही उक्त संघ द्वारा सदस्यों की कोई सूची ही नियोजन विभाग
को प्रस्तुत की गयी है । प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी
श्रमिक को अकुशल श्रमिक के रूप में दैनिक वेतन पर केन्द्रीय
संरक्षित स्मारक, चित्तौड़गढ़ के साफ-सफाई स्वीकृत प्राक्कलनों
के समक्ष समय-समय पर अस्थायी कार्य के लिए मस्ट्रोल
पर लगाया जाता रहा था तब प्रार्थी श्रमिक द्वारा किसी भी
वित्तीय वर्ष में 240 दिवस कार्य नहीं किया गया है तथा
जो कार्य किया गया है वह वर्ष 87-88 में 172 दिवस,
वर्ष 88-89 में 206 दिवस, वर्ष 89-90 में 260 दिवस,
वर्ष 90-91 में 220 दिवस, वर्ष 91-92 में 211 दिवस,
वर्ष 92-93 में 250 दिवस व वर्ष 93-94 में मात्र 6
दिवस ही कार्य किया गया है तथा जो कार्य भी लगातार
240 दिवस तक नहीं किया गया है । प्रतिपक्षी नियोजक
द्वारा प्रार्थी श्रमिक को सेवा से पृथक् नहीं किया गया है
वरन् प्रार्थी श्रमिक द्वारा दि० 5-4-93 से ही स्वेच्छया से

कार्य पर आना बन्द किया गया है जो प्रार्थी श्रमिक, प्रतिपक्षी विभाग द्वारा लगातार सूचना भेजने व दि० 24-4-93 को नोटिस जारी किये जाने पर भी वापिस कार्य पर नहीं आया है। प्रार्थी श्रमिक द्वारा स्वयं सेवा त्याग किया गया है तब उसका मामला छंटनी का नहीं रहा है और प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से भी अधिनियम के प्रावधानों की पालना किये जाने का कोई औचित्य नहीं रहा है। वैसे भी प्रतिपक्षी विभाग "उद्योग" की श्रेणी में नहीं आता है तब उस पर अधिनियम के प्रावधान भी प्रभावी नहीं होते हैं। प्रार्थी श्रमिक द्वारा यह मामला पूर्व में भी केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जोधपुर बेंच के समक्ष प्रकरण सं० ओ०ए० नं० 334/93 के रूप में उठाया गया है जिसे उक्त अधिकरण द्वारा दि० 30-10-96 को सेरिट्स पर निरस्त भी कर दिया गया है। अतः प्रार्थी श्रमिक का प्रस्तुत क्लेम स्वीकार किया जावे।

4. प्रार्थी श्रमिक गोपाललाल ने साक्ष्य में 'स्वयं' का शपथपत्र प्रस्तुत किया है जिस पर प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से प्रतिपरीक्षा की गयी है। प्रलेखीय साक्ष्य में प्रलेख प्रदर्श ३३५० 1 लगायत ३३५० 47 तक प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये हैं जिनका यथोचित समय पर उल्लेख किया जावेगा।

5. प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से साक्ष्य में साक्षी कैप्टन आर०एस० ठाकुर सुरक्षा अधिकारी का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर प्रार्थी श्रमिक की ओर से प्रतिपरीक्षा की गयी है। प्रलेखीय साक्ष्य में प्रलेख प्रदर्श एम० 1 व एम० 2 प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये हैं जिनका यथोचित समय उल्लेख किया जावेगा।

6. मैंने दोनों पक्षों की बहस सुनी।

7. विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक पक्ष की यह बहस रही है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा अपनी मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से यह पूर्णतः प्रमाणित किया गया है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा प्रतिपक्षी नियोजक के यहां नियोजन में दि० 21-5-85 से नियोजित होकर 5-4-93 तक निरन्तर कार्य कर, उक्त नियोजनकाल में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 240 दिवस से अधिक कार्य कर, निरन्तर 11 वर्ष से अधिक अवधि की सेवा पूर्ण कर ली गयी थी तब प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा उसे दि० 6-4-93 से अधिनियम की धारा 25 के आजात्मक प्रावधानों की अवहेलना कर, अनुचित एवं अवैधानिक प्रकार से सेवा से पृथक किया गया है। प्रार्थी श्रमिक की उक्त साक्ष्य के खण्डन में प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक की कार्य मस्ट्रोल अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत भी नहीं की गयी है तब प्रार्थी श्रमिक द्वारा कथित नियोजनकाल व कार्य दिवस ही मान्य रहते हैं। प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से जवाब क्लेम में अभिकथित कर यह स्वीकार किया हुआ है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा वर्ष 1988-89 में 206 दिवस, वर्ष 1989-90 में 260 दिवस वर्ष 1990-91 में 220 दिवस, वर्ष 1991-92 में 220 दिवस वर्ष 1992-93 में 250 दिवस वास्तविक दिवस कार्य किया गया है, इन

वास्तविक कार्य दिवसों में वेतन देय साप्ताहिक दिवसों का और जोड़ दिया जाए तो निरन्तर पूर्ण वर्ष कार्य हो जाता है। प्रतिपक्षी नियोजक की साक्ष्य से यह कतई प्रमाणित नहीं हुआ है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा स्वयं कार्य का त्याग किया गया है। कथित नोटिस की कभी भी प्रार्थी श्रमिक को सूचना भी प्राप्त नहीं हुई है। प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से कभी भी समक्षीय अधिकारी के समक्ष कार्यवाही में भी भाग नहीं लिया गया है। प्रतिपक्षी विभाग अधिनियम में परिभाषित "उद्योग" की परिभाषा के अन्तर्गत है तथा इसका कर्मचारी "कर्मकार" की परिभाषा के अन्तर्गत है। प्रार्थी श्रमिक द्वारा दृष्टिगत अपना विवाद केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने व उक्त न्यायाधिकरण द्वारा बिना क्षेत्राधिकार के उसे गुणावगुण पर निरस्त कर दिये जाने मात्र से इस औद्योगिक न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रार्थी श्रमिक सेवा समाप्ति के पश्चात् से ही बेरोजगार रहा है तब प्रार्थी श्रमिक द्वारा प्रस्तुत इस क्लेम को पूर्णतः स्वीकार किया जावे।

8. विद्वान प्रतिनिधि प्रतिपक्षी द्वारा उक्त बहस का खण्डन करते हुए यह बहस की गयी है कि प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से अपनी मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से यह पूर्णतः प्रमाणित किया गया है कि प्रार्थी श्रमिक का नियोजनकाल वित्तीय वर्ष 87-88 से 92-93 तक का ही रहा है तब उसके द्वारा वर्ष 89-90 व वर्ष 92-93 के अतिरिक्त किसी भी वर्ष में निरन्तर पूर्ण वर्ष कार्य नहीं किया गया है। प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक को सेवा से पृथक नहीं किया गया है बल्कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा स्वयं दि० 5-4-93 से कार्य पर उपस्थित होता बन्द कर दिया गया है। प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से प्रार्थी श्रमिक को कार्य पर वापिस उपस्थित होने हेतु लगातार सूचना भी भिजवाई गयी है तथा दि० 24-4-93 को नोटिस भी जारी किया गया है तब प्रार्थी श्रमिक का मामला सेवा से छंटनी का नहीं रहा है जब प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से भी अधिनियम के प्रावधानों की परिपालना किये जाने का कोई औचित्य नहीं रहा है। प्रार्थी श्रमिक द्वारा यह मामला पूर्व में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जोधपुर बेंच के समक्ष उठाया गया है तब उक्त न्यायाधिकरण द्वारा उक्त मामले को गुणावगुण पर निरस्त कर दिया गया है जब इस औद्योगिक न्यायाधिकरण को उक्त मामले पर पुनः मुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिपक्षी विभाग अधिनियम में परिभाषित "उद्योग" की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं है तथा प्रतिपक्षी कर्मचारी भी परिभाषित "कर्मकार" की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं है तब उक्त मामले पर अधिनियम के प्रावधान प्रभावी नहीं होते हैं और इस औद्योगिक न्यायाधिकरण को भी उक्त मामले पर मुनवाई का क्षेत्राधिकार उपलब्ध नहीं रहता है। प्रार्थी श्रमिक सेवा त्याग के पश्चात् से ही अन्यत्र लाभकारी नियोजित रहा है जो उसके द्वारा स्वीकार भी किया हुआ है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत क्लेम स्वीकार किया जावे।

विद्वान् प्रतिनिधि द्वारा अपनी उक्त ब्रह्म समर्थन में “प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्त्विक स्थल और अश्वश्रेष्ठ अधिनियम 1958” व माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत “1997 एस०सी०सी० (एल० एण्ड एस०) 1079” “हिमांशु कुमार बनाम बिहार राज्य” को उद्धरित किया गया है।

9. मैंने दोनों पक्षों की बहस पर विचार किया तथा पत्रावली व अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

10. प्रार्थी श्रमिक की क्लेम समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र पर अपने नियोजनकाल व कार्य दिवसों के सम्बन्ध में मुख्यतः सुसंगत साक्ष्य यह रही है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा प्रतिपक्षी नियोजक के यहां नियोजन में दि० 21-5-85 से सहायक कर्मकार स्मारक परिचर के रूप में नियोजित होकर दि० 5-4-93 तक निरन्तर विभागीय कार्यों, मोन्यूमेन्ट सुरक्षा चौकीदार, निर्माण रख-रखाव तथा कार्यालय निर्देशानुसार रेस्ट रिलीवर के रूप में निरन्तर सेवा कार्य कर हर कलेण्डर वर्ष में 240 दिवस से अधिक समय तक कार्य किया जाकर, निरन्तर सात वर्ष से अधिक समय तक कार्यविधि पूर्ण की गयी है। शपथ-पत्र पर प्रतिपक्षी पर यह साक्ष्य भी रही है कि प्रार्थी की मौखिक ही सेवा पर रखा गया था तथा उसकी कार्य पर हाजिरी साहब लगाते थे जो हाजिरी अनुसार उसे कार्य का समस्त भुगतान भी हुआ है। प्रार्थी श्रमिक की उक्त साक्ष्य के छण्डन में प्रतिपक्षी साक्षी की इस सन्दर्भ में शपथ-पत्र पर यह साक्ष्य रही है कि प्रार्थी श्रमिक को प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा कुशल श्रमिक के रूप में दैनिक वेतन पर केन्द्रीय संरक्षित स्मारक, वित्तोद्भक्त पर साफ-सफाई हेतु स्वीकृत प्राक्कलनों पर समय-समय पर अस्थायी कार्यों के लिए मस्ट्रोल पर लगाया जाता रहा था तब प्रार्थी श्रमिक द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष में 240 दिवस कार्य नहीं किया गया है। शपथ-पत्र पर यह साक्ष्य भी रही है कि प्रार्थी श्रमिक का नियोजनकाल दि० 21-5-85 से प्रारम्भ न होकर सन् '87 से प्रारम्भ हुआ है। हमारे जवाब क्लेम के पैरा संख्या 2 में जो प्रार्थी श्रमिक के कार्यदिवसों का विवरण अभिकथित किया गया है वह सही किया गया है। प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से जवाब क्लेम के पैरा संख्या 2 में प्रार्थी श्रमिक द्वारा वित्तीय वर्ष 87-88 में 172 दिवस, वर्ष 88-89 में 206 दिवस, वर्ष 89-90 में 260 दिवस, वर्ष 90-91 में 220 दिवस, वर्ष 91-92 में 211 दिवस, वर्ष 92-93 में 250 दिवस व वर्ष 93-94 में 6 दिवस कार्य किया जाना स्वीकार किया हुआ है। इस प्रकार प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से ही यह स्वीकार्य रहा है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा वित्तीय वर्ष 89-90 में 260 दिवस व वर्ष 92-93 में 250 दिवस कार्य किया गया है तब प्रार्थी श्रमिक द्वारा हर उक्त दोनों वर्षों में 240 दिवस से अधिक कार्य कर निरन्तर वर्ष पूर्ण सेवा की गयी है। माननीय राज० उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत “1996(2) एल०एल०जे० 122-चीफ इजीनियर, सिन्धु विभाग बनाम कमलेश व अन्य” में यह न्याय सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया हुआ है कि श्रमिक के निरन्तर एक कलेण्डर वर्ष सेवा कार्य पूर्ण कर के

ही अधिनियम की धारा 25-एफ के प्रावधान पश्चात् ही जाने हैं तब श्रमिक द्वारा अपने नियोजनकाल के प्रत्येक वर्ष में 240 दिवस तक सेवा कार्य किया जाना आवश्यक नहीं है। “निरन्तर एक वर्ष सेवा” को प्रस्तुत मामले में अधिनियम की धारा 25-बी(2) में परिभाषित किया हुआ है जब बारह कलेण्डर मास में 240 दिवस पूर्ण वास्तविक कार्य किया जाना ही निरन्तर एक वर्ष सेवा पूर्ण माना गया है। प्रतिपक्षी साक्षी की इसी सन्दर्भ में यह साक्ष्य भी रही है कि प्रार्थी श्रमिक को समय-समय पर अस्थायी कार्यों पर मस्ट्रोल पर लगाया जाता रहा है परन्तु प्रतिपक्षी साक्षी यह बतलाने में असमर्थ रहा है कि प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा उक्त सन्दर्भित दो वर्षों में प्रार्थी श्रमिक को ब्रेक के साथ नियोजित किया गया। वैसे भी मेरे मत में जब अधिनियम की धारा 25-एफ में प्रकट हुए “निरन्तर एक वर्ष सेवा” को अधिनियम की धारा 25-बी(2) में परिभाषित करते हुए यह प्रावधित किया गया है कि बारह कलेण्डर मास में 240 दिवस सेवा कार्य पूर्ण कर लेने पर “निरन्तर एक वर्ष सेवा” पूर्ण कर लिया जाना माना जावेगा तब एक वर्ष के नियोजनकाल में, ब्रेक के साथ अथवा एक वर्ष की अल्पावधि के नियोजनकाल में भी 240 दिवस सेवा कार्य पूर्ण कर लिया गया है जब भी “निरन्तर एक वर्ष सेवा” पूर्ण कर लिया जाना माना जावेगा। मैं अपने उक्त मत का समर्थन माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय-दृष्टांत “1981(1) एन०एल०जे० 366—गुरेन्द्र कुमार वर्मा बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण, केन्द्रीय, दिल्ली व अन्य” में पारितपादित निम्न न्यायसिद्धांत से भी पाना हूँ :—

“Even if a workman has not been in ‘continuous service’ under an employer for a period of one year, he shall be deemed to have been in such ‘continuous service’ for a period of one year if he has actually worked under the employer for 240 days in the preceding period of twelve months. There is no stipulation that he should have been in employment or service under the employer for a whole period of twelve months. In fact, the thrust of the provision is that he need not be. That appears to be the plain meaning without gloss from any source.”

11. इस प्रकार प्रार्थी श्रमिक द्वारा प्रतिपक्षी नियोजक के यहां नियोजन में प्रतिपक्षी के अनुसार ही वित्तीय वर्ष 89-90 में 260 दिवस व वर्ष 92-93 में 250 दिवस कार्य कर प्रत्येक वर्ष सेवा कार्य पूर्ण किया गया है।

12. इसके अतिरिक्त प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा जवाब क्लेम में प्रार्थी श्रमिक द्वारा वित्तीय वर्ष 88-89 में 206 दिवस, वर्ष 90-91 में 220 दिवस व वर्ष 91-92 में 211 दिवस कार्य किया जाना स्वीकार किया गया है। इस सन्दर्भ में प्रतिपक्षी साक्षी की शपथ-पत्र पर यह साक्ष्य भी रही है कि हमारे द्वारा जो उक्त कार्यदिवस बतलाये

गये हैं वो वास्तविक कार्य दिवस हैं जिनमें साप्ताहिक अवकाशों को शामिल नहीं किया हुआ है। साक्षी की ओर यह साक्ष्य भी रही है कि प्रार्थी श्रमिक, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन राजस्थान सरकार द्वारा घोषित दैनिक वेतन प्राप्त श्रमिक रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम दैनिक वेतन का निर्धारण एक माह के न्यूनतम वेतन को 26 दैनिक दिवसों में विभक्त कर दिया गया है जब एक माह के 26 दिवसों के निर्धारित न्यूनतम दैनिक वेतन में उस माह के साप्ताहिक अवकाशों का वेतन भी सम्मिलित रहता है तब न्यूनतम दैनिक वेतन प्राप्त श्रमिक के साप्ताहिक अवकाश भी वेतन देय साप्ताहिक अवकाश रहते हैं, इस आशय की "टिप्पणी" भी राज्य सरकार की घोषणा में अंकित भी रहती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायदृष्टांत "ए०आई०आर० 1986 एस०सी० 458-वर्कमेंट आफ अमेरिकन, ई०आई०बी०सी० बनाम मैनेजमेन्ट आफ अमेरिकन, ई०आई०बी०सी०" में यह न्यायसिद्धांत भी प्रतिपादित किया हुआ है कि अधिनियम की धारा 25-बी(2) के अधीन श्रमिक के कार्यदिवसों की गणना में श्रमिक के वेतनदेय अवकाश व साप्ताहिक अवकाश भी जोड़े जावेगे। प्रस्तुत प्रकरण में, जब प्रार्थी श्रमिक के वर्ष 88-89 के 206, वर्ष 90-91 के 220 व वर्ष 91-92 के 211 वास्तविक कार्य दिवसों में प्रार्थीश्रमिक के वेतन देय साप्ताहिक अवकाशों के दिवसों को भी जोड़ दिया जावे तब प्रार्थी श्रमिक द्वारा उक्त हर वर्ष में भी 240 दिवस तक कार्य किया जाकर, प्रत्येक उक्त वर्ष में भी सेवा कार्य पूर्ण किया गया है।

13. इसके अतिरिक्त प्रार्थी श्रमिक की अपने नियोजन-काल व कार्यदिवसों के सन्दर्भ में शपथ-पत्र पर यह साक्ष्य नहीं है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा प्रतिपक्षी नियोजक के यहां नियोजन में 21-5-85 से नियोजित होकर 5-4-93 तक निरन्तर कार्य कर, उक्त नियोजनकाल में निरन्तर 7 वर्ष से अधिक अवधि तक सेवा कार्य किया गया है। शपथ-पत्र पर प्रतिपरीक्षा पर इस सन्दर्भ में यह साक्ष्य भी रही है कि प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा नियोजन में नियोजित करने पर प्रार्थी को नियुक्ति-पत्र तथा सेवा से पृथक् करने पर कोई सेवा-मुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। प्रार्थी की हाजिरी साहब लगाने थे व प्रार्थी के कार्य का भुगतान टिकट पर रसीद लेकर किया जाता था। इस प्रकार प्रार्थी श्रमिक के पास अपने नियोजनकाल व कार्यदिवसों के समर्थन में कोई प्रलेखीय साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं रही है। प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से भी किसी भी स्तर पर ऐसा मामला नहीं रहा है कि उनके द्वारा मस्ट्रोल पर नियोजित दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को उनके नियोजित किये जाने पर कोई नियोजन-पत्र, नियोजित रहने पर कोई जोब-कार्ड, वेज-स्लिप अथवा ऐसा कोई प्रलेख जिसमें श्रमिक के नियोजनकाल व कार्य-दिवसों का वर्णन अंकित रहता हो, दिये जाने हों तब प्रार्थी श्रमिक के पास अपने नियोजनकाल व कार्यदिवसों के प्रमाण में अपनी मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त कोई प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहती है जबकि प्रतिपक्षी नियोजक

के पास प्रार्थी श्रमिक के नियोजनकाल व कार्यदिवसों के प्रमाण के लिए सर्वोत्तम एवं निर्णायक साक्ष्य प्रार्थी श्रमिक का कार्य मस्ट्रोल व कार्य भुगतान सम्बन्धी लेखा-प्रलेख सदैव आधिपत्य में रहने पर सदैव उपलब्ध रहते हैं। तब प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक द्वारा कथित नियोजनकाल व कार्यदिवसों का प्रतिवाद किया गया है और प्रतिवाद में प्रार्थी श्रमिक ने अपने अनुसार नियोजनकाल व कार्यदिवस होना कथन किया है तब प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रतिवाद में बतलाये प्रार्थी श्रमिक के नियोजनकाल व कार्यदिवसों के प्रमाण में उनके आधिपत्य में रही सर्वोत्तम एवं निर्णायक साक्ष्य प्रार्थी श्रमिक के कार्य मस्ट्रोल व कार्य भुगतान सम्बन्धी लेखा-प्रलेखों को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक के कार्य मस्ट्रोल व भुगतान सम्बन्धी लेखा प्रलेखों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही प्रस्तुत न किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण ही दर्शाया गया है। प्रतिपक्षी नियोजक मात्र प्रमाण भार प्रार्थी श्रमिक पर होना कहकर उक्त सर्वोत्तम एवं निर्णायक प्रलेखीय साक्ष्य मस्ट्रोल व कार्य भुगतान सम्बन्धी लेखा-प्रलेख प्रस्तुत नहीं कर उनके विरुद्ध विपरीत निष्कर्ष निकाले जाने से नहीं बच सकता। मैं अपने उक्त मत का समर्थन माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत "ए०आई०आर० 1968 एस०सी० 1413-गोपालकृष्ण जी० केलकर बनाम मोहम्मद हाजी लतीफ" में प्रतिपादित निम्न न्यायसिद्धांत से भी पाता हूँ:—

"It is not, in our opinion a sound practice for those desirring to rely upon a certain set of facts to withhold from the Court the best evidence which is in their possession which could throw light upon the issues in controversy and the rely upon the abstract doctrine of onus of proof."

14. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत "1985(4) एस०सी०सी० 201-एच०डी० सिंह बनाम रिजर्व बैंक आफ इण्डिया" के मामले में उपस्थिति रजिस्टर अथवा भुगतान रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने पर व माननीय राज० उच्च न्यायालय द्वारा "1996(2) एल०एल०जे० 122-बीफ इंजीनियर, सिन्हाई विभाग बनाम कमलेश व अन्य" के मामले में कार्य मस्ट्रोल प्रस्तुत न किये जाने पर श्रमिक द्वारा कथित नियोजनकाल व कार्यदिवसों को ही माने जाने का निष्कर्ष निकाले जाने का अभिमत प्रकट किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी श्रमिक द्वारा अपनी साक्ष्य से यह पूर्णतया प्रमाणित किया गया है कि उसके द्वारा प्रतिपक्षी नियोजक के यहां नियोजन में 21-5-85 से नियोजित होकर 5-4-93 तक निरन्तर कार्य कर उक्त नियोजन-काल में निरन्तर 7 वर्ष से अधिक समय तक की अवधि तक कार्य किया गया है और उसने इस अवधि में हर एक कलेंडर वर्ष में 240 दिवस से अधिक समय तक कार्य कर लिया है।

15. प्रार्थी श्रमिक को आगे शपथ-पत्र पर यह साक्ष्य भी रही है कि प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक को 6-4-93 में अकारण ही उससे कनिष्ठ श्रमिकों को कार्य पर नियोजित रखते हुए व नियमित सेवाओं का लाभ देते हुए, पहले आये बाद में जाये सिद्धांत की अवहेलना करते हुए, बिना कोई जांच किये अथवा बिना नोटिस अथवा नोटिस वेतन व छंटनी का मुआवजा दिये अधिनियम की धारा 25-एफ की अवहेलना करते हुए मौखिक ही सेवा से पृथक् कर दिया जो सर्वथा अनुचित व अवैध है। प्रार्थी की प्रतिपरीक्षा में इस सन्दर्भ में यह साक्ष्य भी रही है कि यह कहना गलत है कि उसने काम पर आना बन्द कर दिया है बल्कि विभाग वालों ने ही उसे कार्य से हटाया है। प्रार्थी श्रमिक को नोटिस हटाने का भी लिखित में नहीं दिया मौखिक ही हटाया था। प्रार्थी श्रमिक ने उसे नौकरी से हटाने के बाद विभाग में दो-तीन पत्र पुनः नौकरी पर रखने हेतु लिखे थे परन्तु उन पत्रों पर कोई मुनवाई नहीं की गयी। आगे यह साक्ष्य भी रही है कि प्रार्थी को विभाग द्वारा जारी नोटिस दि० 24-4-93 का नौकरी पर बुलाने बाबत नहीं मिला।

16. इसके विपरीत प्रतिपक्षी साक्षी आर०एस० ठाकुर, सुरक्षा अधिकारी की यह साक्ष्य रही है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा स्वयं ही 5-4-93 से कार्य पर आना बन्द कर दिया गया जो कार्यालय द्वारा लगातार सूचना भेजने व 24-4-93 को नोटिस जारी किये जाने पर भी उपस्थित नहीं हुआ। शपथ-पत्र की प्रतिपरीक्षा पर यह साक्ष्य भी रही है कि प्रार्थी श्रमिक का नियोजनकाल इस साक्षी के प्रतिपक्षी विभाग में पदस्थापनकाल से पूर्व का रहा है। इस प्रकार प्रतिपक्षी साक्षी को प्रार्थी श्रमिक के नियोजनकाल व कार्यदिवसों व सेवा मुक्ति के सन्दर्भ में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं रही है तथा जो भी जानकारी रही है वह अभिलेख के आधार पर ही रही है। आगे यह साक्ष्य भी रही है कि हमारे द्वारा श्रमिक को बुलाने के लिए जो नोटिस जारी किया गया वह नोटिस-बोर्ड पर लगा दिया गया था, प्रार्थी श्रमिक को नहीं भिजवाया गया था। प्रतिपक्षी की ओर से इस सन्दर्भ में कथित नोटिस 24-4-93 की सत्यप्रतिलिपि भी प्रस्तुत की गयी है जो प्रदर्श एम० 1 है। प्रलेख प्रदर्श एम० 1 के अवलोकन पर यह प्रकट नहीं होता है कि उक्त प्रलेख विभाग के नोटिस-बोर्ड पर भी चरपा किया गया या नहीं, इस सन्दर्भ में कोई नोट अंकित नहीं है। प्रतिपक्षी साक्षी द्वारा अपने शपथ-पत्र की प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि प्रदर्श एम० 1 हमारे विभाग द्वारा प्रार्थी श्रमिक को नहीं भेजा गया तब उक्त प्रलेख प्रदर्श एम० 1 से यह निष्कर्ष कतई नहीं निकलता है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा स्वयं सेवा का त्याग किया गया हो। प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से इस सन्दर्भ में अन्य कोई प्रलेख न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह विदित होता हो कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा स्वयं सेवा से त्याग किया गया हो। प्रतिपक्षी साक्षी दि० 6-4-93 को प्रतिपक्षी विभाग में पद-स्वावधि भी नहीं रहा है तब उसे प्रार्थी श्रमिक के स्वतः

सेवा त्याग की भी कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है तथा जो भी जानकारी है वह अभिलेख के आधार पर ही रही है। प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से प्रार्थी श्रमिक का स्वतः सेवा त्याग किये जाने के सन्दर्भ में कोई प्रलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है तब प्रतिपक्षी साक्षी की शपथ-पत्र की यह साक्ष्य कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा स्वतः सेवा का त्याग किया गया है, किसी समर्थित प्रलेखीय साक्ष्य के अभाव में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं रहती है। इस प्रकार प्रार्थी श्रमिक द्वारा अपनी साक्ष्य से यह पूर्णतया प्रमाणित किया गया है कि उसे प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा दि० 6-4-93 ने सेवा से पृथक् किया गया है। प्रतिपक्षी साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि प्रतिपक्षी विभाग द्वारा प्रार्थी श्रमिक को कभी भी नोटिस अथवा नोटिस वेतन व छंटनी का मुआवजा नहीं दिया गया और अधिनियम की धारा 25-एफ के प्रावधानों की परिपालना नहीं की गयी है।

17. प्रार्थी श्रमिक के क्लेम स्टेटेमेंट प्रस्तुत कर यह अभिकथन भी रहे हैं कि प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक को 6-4-93 से प्रार्थी श्रमिक से कनिष्ठ श्रमिकों गोविन्दसिंह व मन्नालाल को यथावत सेवा में नियोजित रखते हुए बिना "पहले आये बाद जाये" सिद्धांत की पालना किये, अधिनियम की धारा 25-जी के विधि प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सेवा से पृथक् किया गया है। प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा जवाब क्लेम प्रस्तुत कर उक्त तथ्यों को स्वीकार नहीं किया गया है। प्रार्थी श्रमिक की क्लेम स्टेटेमेंट के उक्त अभिकथनों के सन्दर्भ में शपथ-पत्र पर उक्त कथित कनिष्ठ श्रमिकों गोविन्द सिंह व मन्नालाल के सन्दर्भ में कोई साक्ष्य नहीं है और तो और उक्त दोनों श्रमिकों के नामों का भी उल्लेख नहीं हुआ है। प्रार्थी श्रमिक द्वारा उक्त अभिकथनों के समर्थन में कोई प्रलेखीय साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गयी है और न ही प्रतिपक्षी नियोजक से ही कोई प्रलेख प्रस्तुत करवाये जाने का प्रयास ही किया गया है तब साक्ष्य अभाव में प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में उक्त सिद्धांत व अधिनियम की धारा 25-जी के विधि प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित नहीं होता है।

18. प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से जवाब क्लेम प्रस्तुत कर यह अभिकथन भी रहे हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ना तो किसी उद्योग की श्रेणी में आता है एवं ना ही अधिनियम की परिधि में आता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, केन्द्रीय सरकार द्वारा संरक्षित स्थल, स्मारक, पुरावशेषों और प्राचीन अभिलेख धरोहर तथा संस्कृति को जीवित रखने के उद्देश्य से उनका रख-रखाव का कार्य करता है। इस विभाग का कदापि यह उद्देश्य नहीं रहा है कि इन स्मारकों का रख-रखाव किसी प्रकार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अर्थ लाभ प्राप्त करने के लिए किया जावे तब भारतीय सर्वेक्षण विभाग उद्योग की परिभाषा में नहीं आता है। प्रतिपक्षी साक्षी केप्टिन आर०एस० ठाकुर, सुरक्षा अधिकारी के भी शपथ-पत्र पर उक्त प्रकार से ही कथन रहे हैं। इसी सन्दर्भ में प्रतिपक्षी साक्षी की प्रतिपरीक्षा में

यह साक्ष्य भी रही है कि प्रदर्श डब्ल्यू० 3 कार्यालय आदेश दिनांकित 25-10-93, प्रदर्श डब्ल्यू० 4 ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांकित 26-7-88, प्रदर्श डब्ल्यू० 5 ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांकित 7-6-88 व प्रदर्श डब्ल्यू० 6 ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांकित 23-8-89 हमारे विभाग के जारीशुदा है। आगे यह साक्ष्य भी रही है कि हमारे यहां श्रमिकों की आकिलोजीकल वर्क लोड से सेवायें शासित होती हैं। आगे यह भी साक्ष्य रही है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा हमारे स्मारकों की देखभाल व चौकीवारी का काम किया गया है। विद्वान प्रतिनिधि प्रतिपक्षी की भी उक्त कथनों के आधार पर यह बहस रही है कि प्रतिपक्षी विभाग अधिनियम में परिभाषित "उद्योग" की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं है तथा प्रतिपक्षी कर्मचारी भी परिभाषित "कर्मकार" की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं है तब उक्त मामले पर अधिनियम के प्रावधान प्रभावी नहीं होते हैं और इस औद्योगिक न्यायाधिकरण को भी उक्त मामले पर मूनवादी का क्षेत्राधिकार उपलब्ध नहीं रहता है। विद्वान प्रतिनिधि प्रतिपक्षी की ओर से उक्त अभिकथनों के समर्थन में प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 भी उद्धृत किया है तथा अपनी उक्त बहस के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत "1997 एस०सी०सी० (एल एण्ड एस) 1079—हिमांशु कुमार बनाम बिहार राज्य" को उद्धृत किया गया है। उद्धृत उक्त न्यायदृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामला बिहार राज्य के को-ऑपरेटिव ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट के कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी, सहायक चालकों व चपरासियों के सेवा से निष्कासन पर पुनः सेवा में नियोजित करने का रहा है तब माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में निम्न अभिमत प्रकट किया गया है:—

"Every Department of Government can not be treated to be Industry. Where the appointments are regulated by statutory rules, the concept of Industry to the extent stands excluded. The petitioners were not appointed to the posts in accordance with the rules but were engaged on the basis of need of the work. They are temporary employees working on daily wages. Their disengagement from service can not be construed to be retrenchment under the Industrial Dispute Act. The concept of retrenchment therefore can not be stretched to such an extent as to cover these employees. Since the petitioners are only daily wage employees and have no right to the posts, their disengagement is not arbitrary."

19. उद्धृत उक्त न्यायदृष्टांत में बिहार राज्य के को-ऑपरेटिव इन्स्टीट्यूट के स्थापना के क्या उद्देश्य रहे हैं तथा उक्त संस्थान द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, यह उक्त

निर्णय में उल्लेखित नहीं है। इस न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत इस प्रकरण में प्रतिपक्षी नियोजक का यह मामला होना भी प्रकट नहीं हुआ है कि उनके नियोजन में कार्यरत श्रमिकों की सेवायें कानूनी नियमों से शासित होती हैं। प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से उद्धृत "प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958" (जिसे तदुपरान्त संक्षेप में "अधिनियम, 1958" से सम्बोधित किया जावेगा) में अथवा उक्त अधिनियम की धारा 38 जिसके अधीन नियम बनाये जाने के प्रावधान है, में भी सेवायें श्रमिकों की सेवायें शासित करने के लिए कोई सेवा नियम बनाये जाने के प्रावधान नहीं हैं। प्रतिपक्षी साक्षी की शपथ-पत्र पर प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकारा कि भी रही है कि हमारे यहां श्रमिकों को आकिलोजीकल वर्क बोर्ड से सेवायें शासित होती हैं। प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से कथित उक्त वर्क बोर्ड को भी न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके विपरीत प्रार्थी श्रमिक की ओर से प्रतिपक्षी विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश व कार्यालय मेमोरेण्डम की प्रतियां प्रदर्श डब्ल्यू० 3 लगा० डब्ल्यू० 6 भी प्रस्तुत की गयी हैं जिन्हें प्रतिपक्षी साक्षी द्वारा प्रतिपक्षी विभाग द्वारा जारी किया जाना स्वीकार भी किया गया है। उक्त कार्यालय आदेश व मेमोरेण्डम के द्वारा दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के सेवा में नियोजन, वेतन, कार्य व सेवा में नियमन के सन्दर्भ में समय-समय पर प्रतिपक्षी विभाग द्वारा आदेश प्रसारित किया जाना भी प्रकट हुआ है तब प्रतिपक्षी नियोजक को उद्धृत उक्त न्यायदृष्टांत में प्रकट हुए अभिमत से प्रस्तुत प्रकरण में कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

20. प्रतिपक्षी विभाग अधिनियम की धारा 2(जे) में परिभाषित "उद्योग" की परिभाषा में आता है अथवा नहीं, इस सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत "1978(1) एल०एल०जे० 349—बैंगलूर वाटर सप्लाय एण्ड सीवरज बोर्ड बनाम ए० राजप्पा" के पैरा 131 में निम्न जांच सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:—

"IV. The dominant nature test :

- (a) Where a complex of activities, some of which qualify for exertion, others not, involves employees on the total undertaking, some of whom are not 'workmen' as in the University of Delhi case or some departments are not productive of goods and services if isolated, even then, the predominant nature of the services and the integrated nature of the departments as explained in the Corporation of Nagpur, will be the true test. The whole undertaking will be 'industry' although those who are not 'workmen' by definition may not benefit by the Status.
- (b) Notwithstanding the previous clauses, sovereign functions, strictly understood, alone qualify for exemption, not the welfare activities or economic adventures undertaken by Government or statutory bodies.
- (c) Even in departments discharging sovereign functions, if there are units which are industries and they are substantially severable, then they can be considered to come within S. 2(i).
- (d) Constitutional and competently enacted legislative provision, may well remove from the scope of the Act."

21. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त जांच सिद्धान्तों को अपने नवीनतम न्यायदृष्टांत (1) ए० आई०आर० 1998 एस०सी० 656-जी०एम० टेलीकम बनाम एस० श्रीनिवास राय व (2) 1996 (1) एल०एल० जे० 1223-चीफ कंजरवेटर आफ फोरेस्ट बनाम जगन्नाथ मुक्ति कंधारे" में पुनः मान्यता प्रदान की गयी है तथा उक्त जांच सिद्धान्तों के विपरीत रहे माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत "(1996) 8 एस०सी०सी० 489-मव डिवि० आफ पोस्ट वजकम बनाम थिय्यम जोसेफ तथा ए०आई०आर० 1997 एस०सी० 2817-बॉम्बे टेलीफोन केन्टीन एम्प्लोईज एसो० बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया" में प्रकट किये गये अभिमतों को निरस्त किया गया है और प्रथम न्यायदृष्टांत में टेलीकॉम विभाग को व द्वितीय न्यायदृष्टांत में वन विभाग को "उद्योग" की परिभाषा के अन्तर्गत होना माना गया है। द्वितीय न्यायदृष्टांत वन विभाग वाले प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त उद्भूत बंगलौर वाटर सप्लाय वाले प्रकरण पर विचार करते हुए निर्णय के पैरा 13, 16 व 17 में निम्न प्रकार अभिमत प्रकट किये गये हैं :—

"The aforesaid shows that if we were to extend the concept of sovereign function to include all welfare activities as contended on behalf of the appellants, the ratio in Bangalore Water Supply case (supra) would get eroded, and substantially. We would demur to do so on the face what was stated in the aforesaid case according to which except the strictly understood sovereign function, welfare activities of the State would come within the purview of the definition of industry, and not only this, even within the wider circle of sovereign function, there may be an inner circle encompassing some units which could be considered as industry if substantially severable.

The aforesaid being the crux of the scheme to implement which some of the respondents were employed, we are of the view that the same cannot be regarded as a part of inalienable or inescapable function of the State for the reason that the scheme was intended even to fulfil the recreational and educational aspirations of the people. We are in no doubt that such a work could well be undertaken by an agency which is not required to be even an instrumentality of the State.

This being the position, we hold that the aforesaid scheme undertaken by the Forest Department cannot be regarded as a part of sovereign function of the State and so, it was open to the respondents to invoke the provisions of the State Act. We would say the same qua the social foresting work undertaken in Ahmednagar district. There was, therefore, not threshold bar in knocking the door of the Industrial Courts by the respondents making a grievance about adoption of unfair labour practice by the appellants."

22. अधिनियम, 1958 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत संरक्षित संस्मारक अनुरक्षण को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि "अनुरक्षण" के अन्तर्गत है किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसे पुनरुद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षक या उस तक सुविधापूर्ण पहुंच सुनिश्चित

करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है।" इसी अधिनियम, 1958 के शीर्षक में "राष्ट्रीय गृहत्व के प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेषों के परिरक्षण का, पुरातत्वीय उत्खननों के विनियमन का और रूप कृतियों, तस्काशी और अन्य ऐसी वस्तुओं के संरक्षण का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम" अंकित हुआ है। अधिनियम, 1958 की धारा 18 के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्याधीन रहते हुए, जनता को किसी भी संरक्षित संस्मारक तक पहुंच का अधिकार दिया गया है। इसी अधिनियम, 1958 की धारा 6 के अधीन संरक्षित संस्मारक के अनुरक्षण के लिए उनके स्वामियों से सविदा करने का भी अधिकार कलेक्टर को दिया हुआ है। इसी अधिनियम, 1958 की धारा 15 के अधीन महानिदेशक को संरक्षित स्मारक के अनुरक्षण खर्च के निमित्त चन्दा आदि दिये जाने पर स्वीकार करने का भी अधिकार है। इसी अधिनियम, 1958 की धारा 21 के अधीन पुरातत्वीय उत्खनन के लिए लाईसेन्स भी जारी किये जाने का प्रावधान है। इसी अधिनियम की धारा 38(2)(सी) में संरक्षित प्राचीन संस्मारकों पर जनता की पहुंच व पहुंच के लिए शुल्क निर्धारित करने का भी प्रावधान है। इस प्रकार उक्त अधिनियम, 1958 के अवलोकन पर ऐसा प्रकट नहीं हुआ है कि प्रतिपक्षी विभाग द्वारा सरकार के प्रभुत्वसम्पन्न कार्यों का निष्पादन किया जाता है। प्रतिपक्षी विभाग द्वारा जो उक्त प्राचीन संस्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेषों के परिरक्षण, पुरातत्वीय उत्खननों के विनियमन, रूपकृतियों, तस्काशी व ऐसी अन्य वस्तुओं के संरक्षण का कार्य किया जाता है वो जनता तथा देशी-विदेशी पर्यटकों को आमोद-प्रमोद व शैक्षणिक लाभ सुलभ कराने के उद्देश्य से ही किया जाता है जिससे प्रत्यक्षतः शुल्क लगाकर व अप्रत्यक्षतः विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर विदेशी मुद्रा का कुछ सीमा तक लाभ भी अर्जित किया जाता है। प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय अवशेषों के परिरक्षण पर और संरक्षण पर कार्य किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा भी करवाया जा सकता है तब प्रतिपक्षी विभाग द्वारा किया गया उक्त कार्य किसी भी प्रकार से सरकार का प्रभुत्वसम्पन्न कार्य नहीं है। प्राचीन श्रमिक द्वारा स्वीकार्य रूप में उक्त प्रतिपक्षी विभाग में दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के रूप में मस्ट्रोल पर प्राचीन संस्मारक चिन्नोद्धार दुर्ग पर चौकीदारी व साफ-सफाई का कार्य किया जाता है तब प्रतिपक्षी नियोजक संस्थान अधिनियम की धारा 2(जे) के अधीन परिभाषित "उद्योग" होना तथा प्राचीन श्रमिक इसी अधिनियम की धारा 2(एस) में परिभाषित "कर्मकार" होना पाया जाता है।

23. विद्वान प्रतिनिधि प्रतिपक्षी की, प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जोधपुर बैंच के निर्णय दि० 30-10-96 प्रलेख प्रदर्शन एम० 2 को आधार बनाकर यह बहस भी रही है कि उक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा प्राचीन श्रमिक द्वारा प्रस्तुत विवाद नो गृणत्वगुण पर विचार कर निरस्त किया जा चुका है तब इस शैक्षणिक

न्यायाधिकरण को उक्त विवाद को पुनः सुनने का अधिकार नहीं रहता है। मैंने विद्वान प्रतिनिधि की उक्त बहस पर भी विचार किया। जब प्रतिपक्षी विभाग एक "उद्योग" है और उसका प्रार्थी श्रमिक एक "कर्मकार" है तब अधिनियम के प्रावधानों के अधीन प्रतिपक्षी नियोजक व प्रार्थी श्रमिक के मध्य रहे उक्त औद्योगिक विवाद को, औद्योगिक न्यायाधिकरण न्यायालय को ही एक मात्र श्रवणाधिकार प्रदत्त रहता है तथा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित उक्त निर्णय अपने आपमें उनके क्षेत्राधिकार से बाहर का रहता है और इस औद्योगिक न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार पर किसी भी प्रकार से विपरीत प्रभाव नहीं डालता तब प्रतिपक्षी नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि की उक्त बहस भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं रहती है।

24. अतः उक्त विवेचनोपरान्त निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रार्थी श्रमिक ने प्रतिपक्षी नियोजक के यहां दि० 21-5-85 से नियोजित होकर दि० 5-4-93 तक निरन्तर कार्य कर उक्त नियोजनकाल में निरन्तर 7 वर्ष से अधिक समय तक सेवाकार्य पूर्ण किया है तब प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक को दि० 6-4-93 से अधिनियम की धारा 25-एफ के प्रावधानों की अवहेलना करने हुए जो सेवा से पृथक् किया गया है वो किसी भी प्रकार से उचित एवं वैध नहीं है तब प्रार्थी श्रमिक प्रतिपक्षी नियोजक के यहां सेवा की निरन्तरता सहित पुनः सेवा में आने का अधिकारी घोषित होने योग्य रहता है।

25. जहां तक प्रार्थी श्रमिक के पिछले वेतन प्राप्त करने के अधिकारी होने का प्रश्न है, प्रार्थी की अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकारोक्ति रही है कि वह मजदूरी पर जाता है जो कभी मिलती है और कभी नहीं मिलती, उसे माह में कभी 15 व कभी 10 दिन मजदूरी मिलती है, मजदूरी में 30 रु० प्रतिदिन प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार प्रार्थी श्रमिक स्वयं की साक्ष्यानुसार सेवा से पृथक् किये जाने के पश्चात से आंशिक रूप से अन्यत्र लाभकारी नियोजित रहा है और इन तथ्यों व समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी श्रमिक पिछला 50% वेतन ही प्राप्त करने का अधिकारी रहता है।

26. अतः उक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा सम्प्रेषित निर्देश को इस प्रकार उल्लिखित किया जाना है कि प्रबन्धन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जयपुर मण्डल द्वारा प्रार्थी श्रमिक रघुवीर सिंह स्मारक परिचर की सेवाएं दिनांक 6-4-93 से समाप्त करने की कार्यवाही उचित एवं वैध नहीं है, फलस्वरूप प्रकरण की परिस्थितियों में प्रार्थी श्रमिक पिछले 50% वेतन व सेवा की निरन्तरता सहित पुनः सेवा में लिये जाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

इस अधिनियम को समुचित सरकार को नियमानुसार प्रकाशनार्थ भिजवाया जावे।

जगदीश प्रसाद शर्मा, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1998

का०आ० 1819.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जयपुर के प्रबन्ध-तंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, कोटा के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27-8-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-42011/62/95-आई०आर० (डी.यू.)]

के०वी०बी० उण्णी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th August, 1998

S.O. 1819.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Kota as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bhartiya Puratatava Sarvekshan Vibhag, Jaipur and their workman, which was received by the Central Government on 27-8-98.

[No. L-42011/62/95-IR(DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

अनुबन्ध

न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण/केन्द्रीय/कोटा/राज.
निर्देश प्रकरण क्रमांक : औ. - न्या. - (केन्द्रीय) - 18/96

दिनांक स्थापित : 12/8/96

प्रसंग : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या एल. 42011/62/95-आई०आर. (डी.यू.) दि.

दिनांक 26/7/96

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

मध्य

देवीसिंह द्वारा महामंत्री,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कर्मचारी संघ,
चित्तोड़गढ़

--प्रार्थी श्रमिक

एवं

अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग
सी स्कीम, जयपुर

--प्रतिपक्षी नियोजक

उपस्थित

श्री जगदीश प्रसाद शर्मा,
आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी श्रमिक की ओर

से प्रतिनिधि :

श्री बलदेव सिंह गौड़

प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से

प्रतिनिधि : कैप्टन आर.एस. ठाकुर
अभिनिर्णय दिनांक : 17-7-98 श्री एच. के. कथपाल

अभिनिर्णय

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निम्न निर्देश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे तदपरान्त "अधिनियम" से सम्बोधित किया जावेगा) की धारा 10(1)(घ) के अंतर्गत इस न्यायाधिकरण को अभिनिर्णयार्थ सम्प्रेषित किया गया है:-

"क्या प्रबन्धन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जयपुर मंडल द्वारा श्री देवीसिंह स्मारक परिसर की सेवाएं समाप्त किये जाने की कार्यवाही वैध एवं उचित है? यदि नहीं तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है और किस तारीख से?"

2. निर्देश न्यायाधिकरण में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व पक्षकारों को सूचना जारी की गयी। प्रार्थी श्रमिक की ओर से क्लेम स्टेटमेंट प्रस्तुत कर संक्षेप में यह अभिकथित किया गया है कि प्रार्थी श्रमिक देवीसिंह द्वारा प्रतिपक्षी प्रबन्धन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जयपुर मण्डल (जिसे तदुपरान्त 'प्रतिपक्षी नियोजक' से सम्बोधित किया जावेगा) के यहाँ नियोजन में दि. 5/11/89 से सहायक कर्मकार स्मारक परिचारक के रूप में नियोजित होकर दि. 5/4/93 तक निरन्तर कार्य कर हर कलेण्डर वर्ष में 240 दिवस से अधिक अवधि तक कार्य कर निरन्तर 4 वर्ष से अधिक अवधि की सेवा पूर्ण कर ली गयी थी तब प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक को दि. 6/4/93 से अकारण ही उससे कनिष्ठों को सेवा में रखते हुए "पहले आये बाद में जाये" सिद्धान्त की अवहेलना करते हुए, बिना कोई जांच कार्यवाही किये, बिना कोई नोटिस अथवा नोटिस वेतन व छुट्टी का मुआवजा दिये अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए, मौखिक ही सेवा से पृथक कर दिया जो सर्वथा अनुचित एवं अवैध है और प्रार्थी श्रमिक, तत्पश्चात् से ही बेरोजगार रहा है जब प्रार्थी श्रमिक, प्रतिपक्षी नियोजक के यहाँ नियोजन में सेवा की निरन्तरता के साथ पिछले सम्पूर्ण वेतन व अन्य समस्त लाभों सहित पुनः सेवा पर बहाल करवाये जाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी श्रमिक का क्लेम स्वीकार किया जावे।

3. प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से जवाब क्लेम प्रस्तुत कर प्रार्थी श्रमिक के उक्त क्लेम को अस्वीकार किया गया है तथा संक्षेप में या यह अभिकथित किया गया है कि "भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कर्मचारी संघ, चित्तोड़गढ़" के नाम से कोई संघ प्रतिपक्षी विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है और ना ही उक्त संघ द्वारा सदस्यों की कोई सूची ही नियोजन विभाग को प्रस्तुत की गयी है। प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक को अशुशल श्रमिक के रूप में दैनिक वेतन पर केन्द्रीय संरक्षित स्मारक, चित्तोड़गढ़ के साफ-सफाई हेतु स्वीकृत प्रावक्तकों के समक्ष समय-समय पर अस्थायी कार्य के लिए मस्ट्रोल पर लगाया जाता रहा था तब प्रार्थी श्रमिक द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष में 240 दिवस कार्य नहीं किया गया है तथा जो कार्य किया गया है वह वर्ष 89-90 में 82 दिवस, वर्ष 90-91 में 224 दिवस, वर्ष 91-92

में 82 दिवस, वर्ष 92-93 में 228 दिवस व वर्ष 93-94 में 79½ दिवस ही कार्य किया गया है तथा जो कार्य भी लगातार 240 दिवस तक नहीं किया गया है। प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक को सेवा से पृथक नहीं किया गया है वरन् प्रार्थी श्रमिक द्वारा दि. 5/4/93 से ही स्वेच्छया कार्य पर आना बन्द किया गया है जो प्रार्थी श्रमिक, प्रतिपक्षी विभाग द्वारा लगातार सूचना भेजने व दि. 24/4/93 को नोटिस जारी किये गये जाने पर भी वापस कार्य पर नहीं आया है। प्रार्थी श्रमिक द्वारा स्वयं सेवा त्याग किया गया है तब उसका सामान्य छुट्टी का नहीं रहा है और प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से भी अधिनियम के प्रावधानों की पालना किये जाने का कोई औचित्य नहीं रहा है। वैसे भी प्रतिपक्षी विभाग 'उद्योग' की श्रेणी में नहीं आता है तब उस पर अधिनियम के प्रावधान भी प्रभावी नहीं होते हैं। प्रार्थी श्रमिक द्वारा यह सामान्य पूर्व में भी केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जोधपुर बैच के समक्ष प्रकरण सं. ओ.ए.न. 331/93 के रूप में उठाया गया है जिसे उक्त अधिकरण द्वारा दि. 30/10/96 को मैरिट्स पर निरस्त भी कर दिया गया है। अतः प्रार्थी श्रमिक का प्रस्तुत क्लेम अस्वीकार किया जावे।

4. प्रार्थी देवीसिंह ने साक्ष्य में स्वयं का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिस पर प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से प्रतिपरीक्षा की गयी है। प्रलेखीय साक्ष्य में प्रलेख प्रदर्श डबल्य 1 लगा, डबल्य 14 तक प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये हैं। जिनका यथोचित समय उल्लेख किया जावेगा।

5. प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से साक्ष्य में साक्षी कैप्टन आर.एस. ठाकुर, सुरक्षा अधिकारी का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर प्रार्थी श्रमिक की ओर से प्रतिपरीक्षा की गयी है। प्रलेखीय साक्ष्य में प्रलेख प्रदर्श एम 1 व एम 2 प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये हैं जिनका यथोचित समय उल्लेख किया जावेगा।

6. मैंने दोनों पक्षों की बहस सुनी।

7. विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक पक्ष की यह बहस रही है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा अपनी मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से यह पूर्णतः प्रमाणित किया गया है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा प्रतिपक्षी नियोजक के यहाँ नियोजक में दि. 5/11/89 में नियोजित होकर 5/4/93 तक निरन्तर कार्य कर, उक्त नियोजन काल में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 240 दिवस से अधिक कार्य कर, निरन्तर 4 वर्ष से अधिक अवधि की सेवा पूर्ण कर ली गयी थी तब प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा उसे दि. 6/4/93 से अधिनियम की धारा 25 के आन्तर्गत प्रावधानों की अवहेलना कर, अनुचित एवं अवैधानिक प्रकार से सेवा से पृथक किया गया है। प्रार्थी श्रमिक की उक्त साक्ष्य के खण्डन में प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक की कार्य मस्ट्रोल न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत भी नहीं की गयी है तब प्रार्थी श्रमिक द्वारा कथित नियोजनकाल व कार्य दिवस ही मान्य रहते हैं। प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से जवाब क्लेम में अभिकथित कर यह स्वीकार किया हुआ है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा वर्ष 89-90 में 82 दिवस, वर्ष 90-91 में 224 दिवस, वर्ष 91-92 में 82 दिवस, वर्ष 92-93 में 228 दिवस व वर्ष 93-94 में 79 दिवस वास्तविक दिवस कार्य किया गया है,

इन वास्तविक कार्य दिवसों में वेतन देय साप्ताहिक दिवसों को और जोड़ दिया जाए तो निरन्तर पूर्ण वर्ष कार्य हो जाता है। प्रतिपक्षी नियोजक की माध्य से यह कतई प्रमाणित नहीं हुआ है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा स्वतः कार्य का त्याग किया गया है। कथित नोटिस की कभी भी प्रार्थी श्रमिक को सूचना भी प्राप्त नहीं हुई है। प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से कभी भी समझौता अधिकारी के समक्ष कार्यवाही में भी भाग नहीं लिया गया है। प्रतिपक्षी विभाग अधिनियम में परिभाषित 'उद्योग' की परिभाषा के अन्तर्गत है तथा इसका कर्मचारी 'कर्मकार' की परिभाषा के अन्तर्गत है। प्रार्थी श्रमिक द्वारा खूटिवंश अपना मामला केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने व उक्त न्यायाधिकरण द्वारा बिना क्षेत्राधिकार के उसे गुणावगुण पर निरस्त कर दिये जाने मात्र से इस औद्योगिक न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रार्थी श्रमिक सेवा समाप्ति के पश्चात् से ही बेरोजगार रहा है तब प्रार्थी श्रमिक द्वारा प्रस्तुत इस क्लेम का पूर्णतः स्वीकार किया जावे।

8. विद्वान प्रतिनिधि प्रतिपक्षी द्वारा उक्त बहस का खण्डन करने हुए यह बहस की गयी है कि प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से अपनी मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से यह पूर्णतः प्रमाणित किया गया है कि प्रार्थी श्रमिक का नियोजनकाल वित्तीय वर्ष 89-90 से 93-94 तक का ही रहा है तब उसके द्वारा किसी भी वर्ष में निरन्तर पूर्ण वर्ष कार्य नहीं किया गया है। प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक को सेवा से पृथक् नहीं किया गया है वरन् प्रार्थी श्रमिक द्वारा स्वयं दि. 5/4/93 से कार्य पर उपस्थित होना बन्द कर दिया गया है। प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से प्रार्थी श्रमिक को कार्य पर वापस उपस्थित होने हेतु लगातार सूचना भी भिजवायी गयी है तथा दि. 24/4/93 का नोटिस भी जारी किया गया है तब प्रार्थी श्रमिक का मामला सेवा से छुटती का नहीं रहा है जब प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से भी अधिनियम के प्रावधानों की परिकल्पना किये जाने का कोई औचित्य नहीं रहा है। प्रार्थी श्रमिक द्वारा यह माहला पूर्व में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जोधपुर बैच के समक्ष उठाया गया है तब उक्त न्यायाधिकरण द्वारा उक्त मामले का गुणावगुण पर निरस्त कर दिया गया है जब इस औद्योगिक न्यायाधिकरण को उक्त मामले पर पुनः मुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिपक्षी विभाग अधिनियम में परिभाषित 'उद्योग' की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं है तथा प्रतिपक्षी कर्मचारी भी परिभाषित 'कर्मकार' की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं है तब उक्त मामले पर अधिनियम के प्रावधान प्रभावी नहीं होते हैं और इस औद्योगिक न्यायाधिकरण को भी उक्त मामले पर मुनवाई का क्षेत्राधिकार उपलब्ध नहीं रहता है। प्रार्थी श्रमिक सेवा त्याग के पश्चात् से ही अन्यत्र लाभकारी नियोजित रहा है जो उसके द्वारा शपथ-पत्र पर प्रतिपरीक्षा पर स्वीकार भी किया हुआ है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत क्लेम अस्वीकार किया जावे। विद्वान प्रतिनिधि द्वारा अपनी उक्त बहस समर्थन में 'प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958' व 'माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांत (1997 एस सी. सी. एल एण्ड एस) 1079-(हिमांशु कुमार बनाम बिहार राज्य)' को उद्धृत किया गया है।

9. मैंने दोनों पक्षों की बहस पर विचार किया तथा पत्रावली व अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

10. प्रार्थी श्रमिक की क्लेम समर्थन में मुख्यतः सुसंगत साक्ष्य नियोजनकाल व कार्यदिवसों के संबंध में अपने शपथ-पत्र में यह रही है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा प्रतिपक्षी नियोजक के यहाँ नियोजन में दि. 5-11-89 से सहायक कर्मकार स्मारक परिचारक के रूप में नियोजित होकर दि. 5-4-93 तक निरन्तर विभागीय कार्यों, मोन्यूमेंट सुरक्षा चौकीदार, निर्माण रख-रखाव तथा कार्यालय निर्देशानुसार रैस्ट रिलीवर के रूप में निरन्तर सेवा कार्य कर हर कनेडर वर्ष में 240 दिवस से अधिक समय तक कार्य किया जाकर, निरन्तर 4 वर्ष से अधिक समय तक की कार्यवृद्धि पूर्ण की गयी है। शपथ-पत्र पर प्रतिपरीक्षा पर यह साक्ष्य भी रही है कि प्रार्थी को नौकरी पर लगाने समय नियुक्ति-पत्र नहीं दिया गया, मौखिक ही लगाया गया था तथा उसकी हाजिरी कार्यालय में अधिकारी ही लगाने थे। उसका विभाग की ओर कोई बकाया पैसा नहीं है। प्रार्थी श्रमिक की उक्त साक्ष्य के खण्डन में प्रतिपक्षी साक्षी की इस सन्दर्भ में शपथ-पत्र पर यह साक्ष्य रही है कि प्रार्थी श्रमिक को प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में दैनिक वेतन पर केन्द्रीय संरक्षित स्मारक, चितौड़गढ़ पर साफ-मफाई हेतु स्वीकृत प्राक्कलनों पर समय समय पर अस्थायी कार्यों के लिये मस्ट्रॉल पर लगाया जाता रहा है तब प्रार्थी श्रमिक द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष में 240 दिवस तक कार्य नहीं किया गया है। शपथ-पत्र पर यह साक्ष्य भी रही है कि हमारे जवाब क्लेम के पैरा सं. 2 में जो प्रार्थी श्रमिक के कार्यदिवसों का विवरण अभिकथित किया गया है वो सही किया गया है। प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से जवाब क्लेम के पैरा सं. 2 में प्रार्थी श्रमिक द्वारा वित्तीय वर्ष 89-90 में 82 दिवस, 90-91 में 224 दिवस, 91-92 में 82 दिवस, 92-93 में 228 दिवस व 93-94 में 79½ दिवस ही कार्य किया जाना स्वीकार किया गया है। इस संदर्भ में आगे प्रतिपक्षी साक्षी की यह साक्ष्य भी रही है कि हमारे द्वारा जो उक्त कार्य दिवस बतलाये गये हैं वो वास्तविक कार्यदिवस हैं जिनमें साप्ताहिक व वेतनदेय अन्य अवकाश शामिल नहीं किये हुए हैं। साक्षी की आगे यह साक्ष्य भी रही है कि प्रार्थी श्रमिक, राज्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम दैनिक वेतन प्राप्त श्रमिक रहा है परन्तु साक्षी को यह पता नहीं कि न्यूनतम दैनिक वेतन प्राप्त श्रमिक के साप्ताहिक अवकाशों का वेतन दिये गये दैनिक वेतन में सम्मिलित रहता हो। इस प्रकार प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से यह स्वीकार्य मामला रहा है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा वर्ष 90-91 में 224 दिवस व वर्ष 92-93 में 228 दिवस वास्तविक कार्य किया गया है। प्रार्थी श्रमिक न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अधीन राज्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम दैनिक

वेतन प्राप्त श्रमिक रहा है। राज्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन का निर्धारण एक माह के न्यूनतम वेतन को 26 दिवसों में विभक्त कर दिया गया है तब एक माह के 26 दिवसों के निर्धारित न्यूनतम वेतन में उस माह के साप्ताहिक अवकाशों का वेतन भी सम्मिलित रहता है और तब न्यूनतम वेतन प्राप्त श्रमिक के साप्ताहिक अवकाश भी वेतनदेय साप्ताहिक अवकाश रहते हैं। इस आशय की "टिप्पणी" भी राज्य सरकार की घोषणा में अंकित रहती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायदृष्टान्त "ए. आई. आर. 1986 एस. सी. 458—वर्कमैन आफ अमेरिकन, ई. आई. बी. सी. बनाम मैनेजमेंट आफ अमेरिकन, ई. आई. बी. सी." में यह न्यायसिद्धांत भी प्रतिपादित किया हुआ है कि अधिनियम की धारा 25-बी(2) के अन्तर्गत श्रमिक के कार्यदिवसों की गणना में श्रमिक के वेतनदेय अवकाश व साप्ताहिक अवकाश भी जोड़े जायेंगे। प्रस्तुत प्रकरण में, जब प्रार्थी श्रमिक के वर्ष 1990-91 के 224 दिवस व वर्ष 92-93 के 228 साप्ताहिक कार्यदिवसों में प्रार्थी श्रमिक के वेतन देय साप्ताहिक अवकाशों के दिवसों को भी जोड़ दिया जाये तब प्रार्थी श्रमिक द्वारा उक्त हर वर्ष में भी 240 दिवस तक कार्य किया जाकर, प्रत्येक उक्त वर्ष में भी वे सेवा कार्य पूर्ण किया गया है। माननीय राज. उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टान्त "1996 (2) एल. एम. जे. 122-चीफ इंजीनियर, सिंचाई विभाग बनाम कमलेश व अन्य" में यह न्यायसिद्धांत भी प्रतिपादित किया हुआ है कि श्रमिक के निरन्तर एक कैलेंडर वर्ष सेवा कार्य पूर्ण करने पर ही अधिनियम की धारा 25-एफ के प्रावधान प्रभावी हो जाते हैं तब श्रमिक द्वारा अपने नियोजनकाल के प्रत्येक वर्ष में 240 दिवस तक सेवा कार्य किया जाना आवश्यक नहीं है। "निरन्तर एक वर्ष सेवा" को प्रस्तुत मामले में अधिनियम की धारा 25-बी(2) में परिभाषित किया हुआ है जब बारह कैलेंडर मास में 240 दिवस पूर्ण वास्तविक कार्य किया जाना ही निरन्तर एक वर्ष सेवा पूर्ण माना गया है। प्रतिपक्षी साक्षी की इसी संदर्भ में यह साक्ष्य भी रही है कि प्रार्थी श्रमिक को समय-समय पर अस्थायी कार्यों पर मस्ट्रोल पर लगाया जाता रहा है परन्तु प्रतिपक्षी साक्षी यह बतलाने में असमर्थ रहा है कि प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा उक्त मन्दभित वर्षों में प्रार्थी श्रमिक को ब्रेक के साथ नियोजित किया गया। वैसे भी मेरे मत में जन अधिनियम की धारा 25-एफ में प्रकट हुए "निरन्तर एक वर्ष सेवा" को अधिनियम की धारा 25-बी(2) में परिभाषित करने हुए यह प्रावधानित किया गया है कि बारह कैलेंडर मास में 240 दिवस सेवा कार्य पूर्ण कर लेने पर "निरन्तर एक वर्ष सेवा" पूर्ण कर लिया जाना माना जायेगा तब एक वर्ष के नियोजकाल में, ब्रेक के साथ अथवा एक वर्ष की अल्पावधि के नियोजकाल में भी 240 दिवस सेवा कार्य पूर्ण कर लिया गया है जब भी "निरन्तर एक वर्ष

सेवा" पूर्ण कर लिया जाना माना जायेगा। मे अपने उक्त मत का समर्थन माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टान्त "1981 (1) एल. एल. जे. 366—सुरेन्द्र कुमार वर्मा बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण, केन्द्रीय दिल्ली व अन्य" में पारित निम्न न्यायसिद्धांत से भी पाता हूँ :—

"Even if a workman has not been in 'continuous service' under an employer for a period of one year, he shall be deemed to have been in such 'continuous service' for a period of one year if he has actually worked under the employer for 240 days in the preceding period of twelve months. There is no stipulation that he should have been in employment or service under the employer for a whole period of twelve months. In fact, the thrust of the provision is that he need not be. That appears to be the plain meaning without gloss from any source."

11. इसके अतिरिक्त प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा अपने जवाब क्लेय के पैरा सं. 2 में प्रार्थी श्रमिक द्वारा वित्तीय वर्ष 1991-92 में 82 दिवस कार्य किया जाना स्वीकार किया गया है। इस वित्तीय वर्ष 1991-92 के कार्य के संदर्भ में प्रार्थी श्रमिक की ओर से यह मामला भी रहा है कि प्रार्थी द्वारा प्रतिपक्षी नियोजक के यहां दि. 5/11/89 को नियोजित होकर 1/7/91 तक निरन्तर कार्य कर लिया गया था तब प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक को दि. 2/7/91 से अनुचित एवं अवैध प्रकार से सेवा से पृथक् कर दिया गया था जिसका विवाद प्रार्थी श्रमिक द्वारा श्रम समझौता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिस विवाद में प्रार्थी श्रमिक व प्रतिपक्षी नियोजक के मध्य एक समझौता दि. 10/2/92 को सम्पन्न हुआ था जो प्रदर्श डब्ल्यू 12 है और जिसके निष्पादन को प्रतिपक्षी साक्षी द्वारा भी अपनी साक्ष्य की प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया गया है। प्रार्थी श्रमिक का इस संदर्भ में घ्राणे यह मामला भी रहा है कि उक्त समझौते के अनुसार प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक को दि. 1/3/92 से पुनः सेवा में नियोजित किया गया था। प्रार्थी श्रमिक द्वारा उक्त अवधि के वेतन को प्राप्त नहीं करना तो स्वीकार किया गया था परन्तु सेवा की निरन्तरता का त्याग नहीं किया गया था। इसके विपरीत प्रतिपक्षी साक्षी की शपथ-पत्र की प्रतिपरीक्षा पर यह साक्ष्य रही है कि उक्त समझौते के द्वारा प्रार्थी श्रमिक को पिछला वेतन व सेवा की निरन्तरता प्रदान नहीं की गयी थी। मैंने इस संदर्भ में पक्षकारों द्वारा स्वीकार्य प्रलेख प्रदर्श डब्ल्यू. 12 का अवलोकन किया। जिसके अवलोकन पर प्रकट हुआ है कि प्रार्थी श्रमिक को पिछला वेतन तो नहीं दिलाया गया है, परन्तु प्रार्थी श्रमिक की सेवा की निरन्तरता नहीं दी जायेगी, इस संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं हुआ है तब प्रार्थी श्रमिक उक्त अवधि की सेवा की निरन्तरता भी प्राप्त करने का अधिकारी रहा है। इस प्रकार प्रार्थी श्रमिक द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष के वास्तविक कार्यदिवस जो 82 रहे हैं, में दि. 2/7/91 से 28/2/92 की सेवा की निरन्तरता को भी जोड़ दिया जाये तब प्रार्थी श्रमिक द्वारा उक्त वित्तीय

वर्ष में से भी 240 दिवस से अधिक कार्य कर-निष्पन्न-
एक वर्ष पूर्ण कार्य किया गया है।

12. इसके अतिरिक्त प्रार्थी श्रमिक की अपने नियोजनकाल व कार्यदिवसों के संदर्भ में शपथ-पत्र पर यह साक्ष्य रहा है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा प्रतिपक्षी नियोजक के यहां नियोजन में 5-11-89 से नियोजित होकर 5-4-93 तक निरन्तर कार्य कर, उक्त नियोजनकाल में निरन्तर 4 वर्ष से अधिक अवधि तक सेवा कार्य किया गया है। शपथ-पत्र पर प्रतिपरीक्षा पर इस संदर्भ में प्रार्थी श्रमिक की यह साक्ष्य भी रही है कि मुझे नौकरी पर लगाते समय नियुक्ति-पत्र नहीं दिया गया बल्कि मौखिक रूप से ही लगाया था। मेरी हाजिरी कार्यालय में अधिकारी ही लगाते थे। इस प्रकार प्रार्थी श्रमिक के पास अपने नियोजनकाल व कार्यदिवसों के समर्थन में कोई प्रलेखीय साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं रही है। प्रतिपक्षी नियोजन की ओर से भी किसी भी स्तर पर ऐसा मामला नहीं रहा है कि उनके द्वारा मस्ट्रोल पर नियोजित दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को उनके नियोजित किये जाने पर कोई नियोजन-पत्र, जाब-कार्ड, वेज स्लिप अथवा ऐसा कोई प्रलेख जिसमें कि श्रमिक के नियोजन काल व कार्यदिवसों का वर्णन अंकित रहता हो, दिये जाते हों, तब प्रार्थी श्रमिक के पास अपने नियोजनकाल व कार्यदिवसों के प्रमाण में अपनी मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त कोई प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहती है जबकि प्रतिपक्षी नियोजक के पास प्रार्थी श्रमिक के नियोजनकाल व कार्यदिवसों के प्रमाण के लिये सर्वोत्तम एवं निर्णायक साक्ष्य प्रार्थी श्रमिक का कार्य मस्ट्रोल व कार्य भुगतान संबंधी लेखा-प्रलेख सदैव आधिपत्य में रहने पर सदैव उपलब्ध रहते हैं। जब प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक द्वारा कथित नियोजनकाल व कार्यदिवसों का प्रतिवाद किया गया है और प्रतिवाद में प्रार्थी श्रमिक ने अपने अनुसार नियोजनकाल व कार्य दिवस होना कथन किया है तब प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रतिवाद में बतलाये प्रार्थी श्रमिक के नियोजनकाल व कार्यदिवसों के प्रमाण में उनके आधिपत्य में रही सर्वोत्तम एवं निर्णायक साक्ष्य प्रार्थी श्रमिक के कार्य मस्ट्रोल व कार्य भुगतान संबंधी लेखा-प्रलेखों को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक के कार्य मस्ट्रोल व भुगतान संबंधी लेखा-प्रलेखों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही प्रस्तुत न किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण ही दर्शाया गया है। प्रतिपक्षी नियोजक मात्र प्रमाण भार प्रार्थी श्रमिक पर होना कहकर उक्त सर्वोत्तम एवं निर्णायक प्रलेखीय साक्ष्य मस्ट्रोल व कार्य भुगतान संबंधी लेखा-प्रलेख प्रस्तुत नहीं कर उनके विरुद्ध विपरीत निष्कर्ष निकाले जाने से नहीं बच सकता। मैं अपने उक्त मत का समर्थन माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत "ए. आई. आर. 1968 एस.सी. 1413—गोपालकृष्ण जो केलकर बनाम मोहम्मद हाजी लथोफ" से प्रतिपादित निम्न न्यायसिद्धांत से भी पाता हूँ :—

"It is not, in our opinion a sound practice for those desiring to rely upon a certain set of facts to withhold from the Court the best evidence which is in their possession which could throw light upon the issues in controversy and the rely upon the abstract doctrine of onus of proof."

13. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत "1985(4) एस. सी. सी. 201-एच. डी. सिंह बनाम रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के मामले में उपस्थिति रजिस्टर अथवा भुगतान रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने पर व माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा "1996 (2) एल. एल. जे. 122-चीफ इंजीनियर, सिंचाई विभाग बनाम कमलेश व अन्य" के मामले में कार्य मस्ट्रोलस प्रस्तुत न किये जाने तर श्रमिक द्वारा कथित नियोजनकाल व कार्यदिवसों को ही माने जाने का निष्कर्ष निकाले जाने का अभिमत प्रकट किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी श्रमिक द्वारा अपना साक्ष्य से यह पूर्णतया प्रमाणित किया गया है कि उसके द्वारा प्रतिपक्षी नियोजक के यहां नियोजन में 5-11-89 से नियोजित होकर 5-4-93 तक निरन्तर कार्य कर उक्त नियोजनकाल में निरन्तर 4 वर्ष से अधिक समय तक की अवधि तक कार्य किया गया और उनसे इस अवधि में हर एक कलेंडर में 240 दिवस से अधिक समय तक कार्य कर लिया है।

14. प्रार्थी श्रमिक की आगे शपथ-पत्र पर यह साक्ष्य भी रही है कि प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक को 6-4-93 से अकारण ही उससे कनिष्ठ श्रमिकों को कार्य पर कार्यरत रखते हुए व नियमित सेवाओं का लाभ प्रदान करते हुए, पहले आये बाद में जाये सिद्धांत की अवहेलना करते हुए, बिना कोई जांच किये अथवा बिना नोटिस अथवा नोटिस वेतन व छुट्टी का मुआवजा दिये अधिनियम की धारा 25-एफ की अवहेलना करते मौखिक ही सेवा से पृथक कर दिया जो सर्वथा अनुचित व अवैध है। प्रार्थी की प्रति परीक्षा में इस संदर्भ में यह साक्ष्य भी रही है कि उसने काम पर आना बन्द नहीं किया बल्कि 6-4-93 से साहब ने उसे काम पर लेने से मना कर दिया। काम से हटाया तब उसे लिखकर नहीं दिया प्रार्थी श्रमिक ने उसे नौकरी से हटाने के बाद विभाग में दस बार टेलीग्राम दिये, अन्य प्रार्थना पत्र भी पुनः नौकरी पर रखे जाने बाबत दिया परन्तु विभाग वालों ने नहीं लिया। आगे यह साक्ष्य भी रही है कि प्रार्थी को विभाग द्वारा जारी नोटिस दि. 24-4-93 कभी प्राप्त नहीं हुआ।

15. इसके विपरीत प्रतिपक्षी साक्षी आर. एस. ठाकुर, सुरक्षा अधिकारी की यह साक्ष्य रही है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा स्वयं ही 5-4-93 से कार्य पर आना बन्द कर दिया गया जो कार्यालय द्वारा लगातार सूचना भेजने व 24-4-93 को नोटिस जारी किये जाने पर भी उपस्थिति नहीं हुआ। शपथ-पत्र की प्रति परीक्षा पर यह साक्ष्य भी रही है कि प्रार्थी श्रमिक का नियोजनकाल इस साक्षी के प्रतिपक्षी विभाग में पद स्थापना काल से पूर्व कर रहा है। इस प्रकार प्रतिपक्षी साक्षी को प्रार्थी श्रमिक के नियोजन काल व कार्यों दिवसों व सेवा मुक्ति के संदर्भ में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं रही है तथा जो भी जानकारी रही है वह अभिलेख के आधार

पर ही रही है। शायद यह साक्ष्य भी रही है कि हमारे द्वारा श्रमिक को बनाने के लिए जो नोटिस जारी किया गया वह नोटिस-बोर्ड पर चिपका दिया गया था। प्रतिपक्षी की ओर से इस संदर्भ में कथित नोटिस 24-4-93 की सत्य प्रतिनिधि भी प्रस्तुत की गयी है जो प्रदर्शन एम. 1 है। प्रलेख प्रदर्शन एम. 1 के अवलोकन पर यह प्रकट नहीं होता है कि उक्त प्रलेख विभाग के नोटिस-बोर्ड पर भी चिपका दिया गया या नहीं, इस संदर्भ में कोई नोटिस पर नोट अंकित नहीं है। प्रतिपक्षी साक्षी द्वारा यह ठोस आधार पर कथन नहीं किया गया है कि तथ्याकथित नोटिस प्रार्थी श्रमिक के घर पर व्यक्तिगत या डाक द्वारा भिजवाया गया हो तब उक्त प्रलेख प्रदर्शन एम. 1 में यह निष्कर्ष कतई नहीं निकलता है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा स्वयं सेवा का त्याग किया गया हो। प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से इस संदर्भ में अन्य कोई प्रलेख न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिसमें वह विदित होता हो कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा स्वयं सेवा से त्याग किया गया हो। प्रतिपक्षी साक्षी दि. 6-4-93 को प्रतिपक्षी विभाग में पद स्थापित भी नहीं रहा है तब उसे प्रार्थी श्रमिक के स्वतः सेवा त्याग की भी कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है तथा जो भी जानकारी है वह अभिलेख के आधार पर ही रही है। प्रार्थी प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से प्रार्थी श्रमिक का स्वतः सेवा त्याग किये जाने के संदर्भ में कोई प्रलेख भी प्रस्तुत नहीं किया गया है तब प्रतिपक्षी साक्षी की शपथ-पत्र का वह साक्ष्य कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा स्वतः सेवा को त्याग किया है, किसी समर्थित प्रलेखीय साक्ष्य के अभाव में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं रहती है। इस प्रकार प्रार्थी श्रमिक द्वारा अपनी साक्ष्य में यह पूर्णतया प्रमाणित किया गया है कि उसे प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा दि. 6-4-93 से सेवा से पृथक् किया गया है। प्रतिपक्षी साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि प्रतिपक्षी विभाग द्वारा प्रार्थी श्रमिक को कभी भी नोटिस अथवा नोटिस बेंचन व छंटनी का मुआवजा नहीं दिया गया और अधिनियम की धारा 25-एफ के प्रावधानों की परिपालना नहीं की गयी है।

16. प्रार्थी श्रमिक के क्लेम स्टेटमेंट प्रस्तुत कर यह अभिकथन भी रहे हैं कि प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक को 6-4-93 से सेवा से पृथक् करने समय उससे कनिष्ठों की सेवा में बनाये रखा है तथा बिना "पहले आये, बाद जाये" सिद्धांत की पालना किये, अधिनियम की धारा 25-जी के विधि प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा जवाब क्लेम प्रस्तुत कर उक्त तथ्यों को स्वीकार नहीं किया गया है। प्रार्थी श्रमिक द्वारा अपने से कनिष्ठ श्रमिकों के नाम न तो अपने क्लेम में वर्णित किये गये हैं और न ही अपने शपथ-पत्र में अंकित किये गये हैं। प्रार्थी श्रमिक द्वारा उक्त अभिकथनों के समर्थन में कोई प्रलेखीय साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गयी है और न ही प्रतिपक्षी नियोजक ने ही कोई प्रलेख प्रस्तुत करवाये जाने का प्रयास ही किया गया है तब साक्ष्य अभाव में प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में उक्त सिद्धांत व अधिनियम की धारा 25-जी के विधि प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित नहीं होता है।

17. प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से जवाब क्लेम प्रस्तुत कर यह अभिकथन भी रहे हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग न तो किसी उद्योग की श्रेणी में आता है और न ही अधिनियम की परिधि में आता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग केन्द्रीय सरकार द्वारा संरक्षित स्थल, स्मारक पुरावसेवो और प्राचीन अमूल्य धरोहर तथा संस्कृति को जीवित रखने के उद्देश्य से उनका रख-रखाव का कार्य करता है। इस विभाग का कदापि यह उद्देश्य नहीं रहा है कि इन स्मारकों का रख-रखाव किसी प्रकार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अर्थ लाभ प्राप्त करने के लिए किया जावे तब भारतीय सर्वेक्षण विभाग उद्योग की परिभाषा में नहीं आता है। प्रतिपक्षी साक्षी कैप्टन आर. एस. ठाकुर, सुरक्षा अधिकारी के भी शपथ-पत्र पर उक्त प्रकार से ही कथन रहे हैं। इसी संदर्भ में प्रतिपक्षी साक्षी की प्रतिपरीक्षा में यह साक्ष्य भी रही है कि प्रदर्शन डबल्यू. 5 लगा. 8 व 10 उनके कार्यालय के आदेश व मेमोरेण्डम जारी शुद्ध हैं। आये यह साक्ष्य भी रही है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा उनके स्मारकों की देख-भाल व साफ-सफाई का काम किया गया है। विद्वान प्रतिनिधि प्रतिपक्षी की भी उक्त कथनों के आधार पर यह बहस रही है कि प्रतिपक्षी विभाग अधिनियम में परिभाषित "उद्योग" की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं है तथा प्रार्थी श्रमिक कर्मचारी भी परिभाषित "कर्मकार" की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं है तब उक्त मामले पर अधिनियम के प्रावधान प्रभावी नहीं होते हैं और इस औद्योगिक न्यायाधिकरण को भी उक्त मामले पर सुनवायी का क्षेत्राधिकार उपलब्ध नहीं रहता है। विद्वान प्रतिनिधि प्रतिपक्षी की ओर से उक्त अभिकथनों के समर्थन में प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 भी उद्धरित किया गया है तथा अपनी उक्त बहस के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत "1997 एम. सी. सी. एल. एण्ड एम (1079-हिमांशु कुमार धनाम बिहार राज्य" को उद्धृत किया गया है। उद्धृत उक्त न्याय-दृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामला बिहार राज्य के को-आपरेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी, सहायक चालकों व चपरासियों के सेवा से निष्कासन पर पुनः सेवा में नियोजित करने का रहा है तब माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में निम्न अभिमत प्रकट किया गया है :—

"Every Department of Government cannot be treated to be Industry. Where the appointments are regulated by statutory rules, the concept of Industry to the extent stands excluded. The petitioners were not appointed to the posts in accordance with the rules but were engaged on the basis of need of the work. They are temporary employees working on daily wages. Their disengagement from service cannot be construed to be retrenchment under the Industrial Dispute Act. The concept of retrenchment therefore, can not be stretched to such an extent as to cover these employees. Since the petitioners are only daily wage

employees and have no right to the posts, their disengagement is not arbitrary”

18 उक्त उद्भूत न्यायदृष्टांत में बिहार राज्य के को-ऑपरेटिव इंस्टीच्यूट के स्थापना के क्या उद्देश्य रहे हैं तथा उक्त संस्थान द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, यह उक्त निर्णय में उल्लेखित नहीं है। इस न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिपक्षी नियोजक का यह मामला होना भी प्रकट नहीं हुआ है कि उनके नियोजन में कार्यरत श्रमिकों की सेवायें कानूनी नियमों से शासित होती हैं। प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से उद्भूत “प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (जिसे तदुपरांत संक्षेप में “अधिनियम, 1958” में संबंधित किया जावेगा) में अथवा उक्त अधिनियम की धारा 38 जिसके अधीन बनाये जाने के प्रावधान हैं, में भी सेवारत श्रमिकों की सेवायें शासित करने के लिए कोई सेवा नियम बनाये जाने के प्रावधान नहीं है। प्रतिपक्षी साक्षी की शपथपत्र पर अथवा प्रतिपरीक्षा में कहीं यह वर्णित नहीं हुआ है कि प्रार्थी श्रमिक की सेवायें किसी विशेष नियमों के अधीन शासित होती हों। इसके विपरीतप्रार्थी श्रमिक की ओर से प्रतिपक्षी विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश व मेमोरेण्डम की प्रति प्रदर्श डक्यू. 5 लगा, 8 व 10 भी प्रस्तुत की गयी है जिन्हें प्रतिपक्षी साक्षी द्वारा प्रतिपक्षी विभाग द्वारा जारी किया जाना स्वीकार भी किया गया है। उक्त कार्यालय आदेश व मेमोरेण्डम के द्वारा दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के सेवा में नियोजन, वेतन, कार्य व सेवा में नियमन के संदर्भ में समय-समय पर प्रतिपक्षी विभाग द्वारा आदेश प्रसारित किया जाना भी प्रकट हुआ है तब प्रतिपक्षी नियोजक को उद्भूत उक्त न्याय दृष्टांत में प्रकट हुए अभिमत से प्रस्तुत प्रकरण में कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

19. प्रतिपक्षी विभाग अधिनियम की धारा 2(जे) में परिभाषित “उद्योग” की परिभाषा में आता है अथवा नहीं, इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत “1978 (1) एल. एल. जे. 349-बंगलूर वाटर सप्लाई एण्ड सीवरेज बोर्ड बनाम एम. राजप्पा” के पैरा 131 में निम्न जांच सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :—

“IV. The dominant nature test :

- (a) Where a complex of activities, some of which qualify for exertion, others not, involves employees on the total undertaking, some of whom are not ‘workmen’ as in the University of Delhi case or some departments are not productive of goods and services if isolated, even then, the predominant nature of the services and the integrated nature of the departments as explained in the Corporation of Nagpur, will be the true test. The whole undertaking will be ‘industry’ although those who are not ‘workmen’ by definition may not benefit by the status.
- (b) Notwithstanding the previous clauses, sovereign functions, strictly understood, alone qualify for exemption, not the welfare activities of economic adventures undertaken by Government or statutory bodies.

- (c) Even in departments discharging sovereign functions, if there are units which are industries and they are substantially severable, then they can be considered to come within S. 2(j).
- (d) Constitutional and competently enacted legislative provisions may well remove from the scope of the Act.”

20. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त जांच सिद्धांतों को अपने नवीनतम न्यायदृष्टांत (1) “ए. आई. आर. 1998 एस.सी. 656-जी.एम. टेल्कीकाम बनाम एस. श्रीनिवास राय व (2) 1996 (1) एल. एल. जे. 1223 चीफ कंजरक्टर आफ फॉरेस्ट बनाम जगन्नाथ मूर्ति कंधारे” में पुनः मान्यता प्रदान की गयी है तथा उक्त जांच सिद्धांतों के विपरीत रहे माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत “(1996) 8 एस.सी. सी. 489 सब डिबिजन आफ पोस्ट व जकम बनाम थियरम जोसेफ तथा ए.आई. आर. 1997 एस.सी. 2817-बॉम्बे टेल्फीन केन्टीन एम्पलाईज एसो. बनाम यूनियन आफ इण्डिया” में प्रकट किये गये अभिमतों को निरस्त किया गया है और प्रथम न्यायदृष्टांत में टेल्फीन विभाग को व द्वितीय न्यायदृष्टांत में वन विभाग को “उद्योग” की परिभाषा के अन्तर्गत होना माना गया है। द्वितीय न्यायदृष्टांत वन विभाग वाले प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त उद्भूत बंगलूर वाटर सप्लाई वाले प्रकरण पर विचार करते हुए निर्णय के पैरा 13, 16 व 17 में निम्न प्रकार अभिगत प्रकट किये गये हैं :—

- (13) “The aforesaid shows that if we were to extend the concept of sovereign function to include all welfare activities as contended on behalf of the applicants, the ratio in Bangalore Water Supply case (supra), would get eroded, and substantially. We would demur to do so on the face what was stated in the aforesaid case according to which except the strictly understood sovereign function, welfare activities of the State would come within the purview of the definition of industry, and not only this, even within the wider circle of sovereign function, there may be an inner circle encompassing some units which could be considered as industry if substantially severable.
- (16) The aforesaid being the crux of the scheme to implement which some of the respondents were employed, we are of the view that the same cannot be regarded as a part of inalienable or inescapable function of the State for the reason that the scheme was intended even to fulfil the recreational and educational aspirations of the people. We are in no doubt that such a work could well be undertaken by an agency which is not required to be even an instrumentality of the State.
- (17) This being the position, we hold that the aforesaid scheme undertaken by the Forest Department cannot be regarded as part of sovereign function of the State and so, it was open to the respondents to invoke the provisions of the State Act. We would say the same qua the social foresting work undertaken in Ahmednagar district. There was, therefore, no threshold bar in knocking the door of the Industrial Courts by the respondents making a grievance about adopting of unfair labour practice by the appellants.”

21. अधिनियम, 1958 के शीर्षक में “राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेषों के परिरक्षण का, पुरातत्वीय उत्खननों के विनियमन का और रूप कृतियों नक्काशी और अन्य ऐसी वस्तुओं के संरक्षण का उपबंध करने के लिए अधिनियम” अंकित हुआ है। इसी अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अन्तर्गत

संरक्षित संस्मारक अनुरक्षण को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि "अनुरक्षण" के अन्तर्गत है किसी संरक्षित संस्मारक को बाढ़ से घेरना उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसे पुनरुद्धार करना और उसकी सफाई करना और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधापूर्ण पहुँच सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है। इसी अधिनियम 1958 की धारा 18 के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, जनता को किसी भी संरक्षित संस्मारक तक पहुँच का अधिकार दिया गया है। इसी अधिनियम, 1958 की धारा 6 के अधीन संरक्षित संस्मारक के अनुरक्षण के लिए उनके स्वामियों से सविदा करने का भी अधिकार कलेक्टर को दिया हुआ है। इसी अधिनियम 1958 की धारा 15 के अधीन महानिदेशक को संरक्षित संस्मारक के अनुरक्षण खर्च के निमित्त चन्दा आदि धिये जाने पर स्वीकार करने का भी अधिकार है। इसी अधिनियम, 1958 की धारा 21 के अधीन पुरातत्वीय उत्खनन के लिए लाईसेन्स भी जारी किये जाने का प्रावधान है। इसी अधिनियम की धारा 38(2)(सी) में संरक्षित प्राचीन संस्मारकों पर जनता की पहुँच व पहुँच के लिए शुल्क निर्धारित करने का भी प्रावधान है। इसी संदर्भ में स्वयं प्रतिपक्षी साक्षी ने भी अपनी प्रति परीक्षा में यह स्वीकार किया है कि यह सही है कि स्मारक को देखने आने वालों से टिकट के रूप में धनराशि भी एकत्रित की जाती है जो भीड़ को रेगुलेट करने के लिए की जाती है। इस प्रकार उक्त अधिनियम, 1958 के श्रवलोकन पर ऐसा प्रकट नहीं हुआ है कि प्रतिपक्षी विभाग द्वारा सरकार के प्रभुत्वसम्पन्न कार्यों का निष्पादन किया जाता है। प्रतिपक्षी विभाग द्वारा जो उक्त प्राचीन संस्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेषों के परीक्षण, पुरातत्वीय उत्खननों के विनियमन, रूपकृतियों नक्काशी व ऐसी अन्य वस्तुओं के संरक्षण का कार्य किया जाता है जो जनता तथा बेसी-बिवेशी पर्यटकों को आमोद-प्रमोद व शैक्षणिक लाभ-मुलभ कराने के उद्देश्य से ही किया जाता है जिससे प्रत्यक्षतः शुल्क लगाकर व अप्रत्यक्षतः विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर विदेशी मुद्रा का कुछ सीमा तक लाभ भी अर्जित किया जाता है। प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय अवशेषों के परीक्षण पर और संरक्षण पर कार्य किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा भी करवाया जा सकता है। तब प्रतिपक्षी विभाग द्वारा किया गया उक्त कार्य किसी भी प्रकार से सरकार का प्रभुत्वसम्पन्न कार्य नहीं है। प्राणी श्रमिक द्वारा स्वीकार्य रूप में उक्त प्रतिपक्षी विभाग में दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के रूप में मस्ट्रोल पर प्राचीन संस्मारक निस्तीङ्गठ दुर्ग पर साफ-सफाई का कार्य किया जाता है तब प्रतिपक्षी नियोजक संस्थान अधिनियम की धारा 2(जे) के अधीन परिभाषित "उद्योग" होना तथा प्राणी श्रमिक इसी अधिनियम की धारा 2(एस) में परिभाषित "कर्मकार" होना पाया जाता है।

22. विद्वान प्रतिनिधि प्रतिपक्षी, प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जोधपुर बेंच के निर्णय दि. 30-10-96 प्रलेख प्रदर्श एम. 2 को आधार बनाकर, यह बहस भी रही है कि उक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा प्राणी श्रमिक द्वारा प्रस्तुत विवाद की गुणावगुण पर विचार कर निरस्त किया जा चुका है तब इस आयोगिक न्यायाधिकरण को उक्त विवाद को पुनः सुनने का अधिकार नहीं रहता है। मैंने विद्वान प्रतिनिधि की उक्त बहस पर भी विचार किया। जब प्रतिपक्षी विभाग एक "उद्योग" है और उसका प्राणी श्रमिक एक "कर्मकार" है तब अधिनियम के प्रावधानों के अधीन प्रतिपक्षी नियोजक व प्राणी श्रमिक के मध्य रहे उक्त आयोगिक विवाद को, आयोगिक न्यायाधिकरण/न्यायालय को ही एक मात्र श्रवणाधिकार प्रदत्त रहता है तथा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित उक्त निर्णय अपने आप में उनके क्षेत्राधिकार से बाहर का रहता है और इस आयोगिक न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार पर किसी भी प्रकार से विपरीत प्रभाव नहीं डालता है तब प्रतिपक्षी नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि की उक्त बहस भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं रहती है।

23. अतः उक्त विवेचनोपरान्त निष्कर्ष यह निकलता है कि प्राणी श्रमिक ने प्रतिपक्षी नियोजक के यहाँ दि. 5-11-89 से नियोजित होकर दि. 5-4-93 तक निरन्तर कार्य कर उक्त नियोजनकाल में निरन्तर 4 वर्ष से अधिक समय तक सेवा-कार्य पूर्ण किया है। तब प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्राणी श्रमिक को दि. 6-4-93 से अधिनियम की धारा 25-एम के प्रावधानों की श्रवहेलना करते हुए जो सेवा से पृथक किया गया है वो किसी भी प्रकार से उचित एवं वैध नहीं है तब प्राणी श्रमिक प्रतिपक्षी नियोजक के यहाँ सेवा की निरन्तरता सहित पुनः सेवा में आने का अधिकारी घोषित होने योग्य रहता है।

24. जहाँ तक प्राणी श्रमिक के पिछले वेतन प्राप्त करने के अधिकारी होने का प्रश्न है, प्राणी की अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकारोक्ति रही है कि उसे मजदूरी मिलती है परन्तु एक रोज मिलती व दो रोज नहीं मिलती है, वैसे महीने में 8-10 दिन मजदूरी पर चला जाता है जिसमें उसे 30-32 रु० रोज प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार प्राणी श्रमिक स्वयं की साक्ष्यानुसार सेवा से पृथक किये जाने के पश्चात् से आंशिक रूप से अन्वय लाभकारी नियोजित रहा है और इन तथ्यों व समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रहते हुए प्राणी श्रमिक पिछला 50 प्रतिशत वेतन ही प्राप्त करने का अधिकारी रहता है।

25. अतः उक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा सम्प्रेषित निर्देश को इस प्रकार उत्तरित किया जाता है कि प्रबन्धन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जयपुर मण्डल द्वारा प्राणी श्रमिक देवीसिंह, स्मारक परिचर की सेवाएं दिनांक 6-4-93 से समाप्त किये जाने की कार्यवाही उचित एवं वैध नहीं है, फलस्वरूप प्रकरण की परिस्थितियों से प्राणी श्रमिक पिछले 50 प्रतिशत वेतन व सेवा की निरन्तरता सहित पुनः सेवा में लिये जाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

इस अधिनियम की समुचित सरकार की नियमानुसार प्रकाशनार्थ भिजवाया जाये।

जगदीश प्रसाद शर्मा, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1998

का.ग्रा. 1820.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जयपुर, के प्रबन्ध-तंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण कोटा के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27-8-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/60/95-आई आर (डी.यू.)]

के.वी.बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th August, 1998

S.O. 1820.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Kota as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bhartiya Puratatava Sarvekshan Vibhag, Jaipur and their workman, which was received by the Central Government on the 27-8-98.

[No. L-42012/60/95-IR(DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

अनुबन्ध

न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण / (केन्द्रीय) / कोटा, राज.

निर्देश प्रकरण क्रमांक : ओ.न्या. (केन्द्रीय) - 12/96

दिनांक स्थापित : 6/6/96

प्रसंग : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय नई दिल्ली, के आदेश सं. एल. 42012/60/95 आई.आर. (डी.यू.) दिनांक 30/5/96

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

मध्य

गोपाल लाल द्वारा महामन्त्री भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कर्मचारी संघ चित्तौड़गढ़

—प्रार्थी श्रमिक

एवं

अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, सी स्कीम, जयपुर

—प्रतिपक्षी नियोजक

उपस्थित

श्री जगदीश प्रसाद शर्मा,

आर.एच.जे. एस.

प्रार्थी श्रमिक की ओर से प्रतिनिधि:— श्री बलदेव सिंह गौड़
प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से प्रतिनिधि केप्टन आर.एस.ठाकुर
अधिनियम दिनांक : 17/7/98 श्री एच. के. नथयाल

अधिनियम :

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय नई दिल्ली, द्वारा निम्न निर्देश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे तदुपरान्त “अधिनियम” से सम्बोधित किया जायेगा) की धारा 10 (घ) के अन्तर्गत इस न्यायाधिकरण को अधिनियमार्थ संप्रेषित किया गया है :—

“क्या प्रबन्धन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जयपुर मण्डल द्वारा श्री गोपाल लाल सुथार की सेवाएँ समाप्त किये जाने की कार्यवाही वैध व उचित है? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुलोष का हक्कार है?”

2. निर्देश न्यायाधिकरण में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व पक्षकारों को सूचना जारी की गयी। प्रार्थी श्रमिक की ओर से क्लेम स्टेटमेन्ट प्रस्तुत कर संक्षेप में यह अभिकथित किया गया है कि प्रार्थी श्रमिक गोपाल लाल द्वारा प्रतिपक्षी प्रबन्धन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जयपुर मण्डल (जिसे तदुपरान्त “प्रतिपक्षी नियोजक” से सम्बोधित किया जावेगा) के यहाँ नियोजन में दि० 1-11-90 को सहायक कर्मचारी स्मारक परिचारक के रूप में नियोजित होकर दि० 5-4-93 तक निरन्तर कार्य कर हर क्लेण्डर वर्ष में 240 दिवस से अधिक अवधि तक कार्य कर निरन्तर 3 वर्षों से अधिक अवधि की सेवापूर्ण करली गयी थी तब प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक को दि० 6-4-93 से अकारण ही, प्रार्थी श्रमिक से कनिष्ठ श्रमिकगण गोविन्दसिंह व मन्नालाल को नियोजित रखते हुए और नियमित सेवाओं का लाभ देते हुए “पहले आये बाव में जाये” सिद्धांत की अवहेलना करते हुए, बिना कोई जांच कार्यवाही किये, बिना कोई नोटिस अथवा नोटिस वेतन व छठनी का मुआवजा दिये अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए, मौखिक ही सेवा से पृथक कर दिया जो सर्वथा अनुचित एवं अवैध है और प्रार्थी श्रमिक, तत्पश्चात् से ही बेरोजगार रहा है जब प्रार्थीश्रमिक, प्रतिपक्षी नियोजक के यहाँ नियोजन में सेवा की निरन्तरता के साथ पिछले सम्पूर्ण वेतन व अन्य समस्त लाभों सहित पुनः सेवा पर बहाल करवाये जाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी श्रमिक का यह क्लेम स्वीकार किया जावे।

3. प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से जवाब क्लेम प्रस्तुत कर प्रार्थी श्रमिक के उक्त क्लेम को अस्वीकार किया गया है तथा संक्षेप में यह अभिकथित किया गया है कि “भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कर्मचारी संघ, चित्तौड़गढ़” के नाम से कोई संघ प्रतिपक्षी विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है और न ही उक्त संघ द्वारा सदस्यों की कोई सूची ही निकोजन विभाग को प्रस्तुत की गयी है। प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक को अकुशल श्रमिक के रूप में दैनिक वेतन पर

केन्द्रीय संरक्षित स्मारक, चित्तोड़गढ़ के साफ-मफाई हेतु स्वीकृत प्रावधानों के समक्ष समय-समय पर अस्थायी कार्य के लिए मस्ट्रोल्स पर लगाया जाता रहा था तब प्रार्थी श्रमिक द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष में 240 दिवस कार्य नहीं किया गया है तथा जो कार्य किया गया है वह वर्ष 90-91 में 54 दिवस, वर्ष 91-92 में 210 दिवस, वर्ष 92-93 में 252 दिन व वर्ष 93-94 में मात्र 7 दिवस ही कार्य किया गया है तथा जो कार्य भी लगातार 240 दिवस तक नहीं किया गया है। प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक को सेवा से पृथक नहीं किया गया है वरन् प्रार्थी श्रमिक द्वारा दि० 5-4-93 से ही स्वेच्छया से कार्य पर आना बन्द किया गया है जो प्रार्थी श्रमिक, प्रतिपक्षी विभाग द्वारा लगातार सूचना भेजने व दि० 24-4-93 को नोटिस जारी किये जाने पर भी वापस कार्य पर नहीं आया है। प्रार्थी श्रमिक द्वारा स्वयं सेवा त्याग किया गया है तब उसका मामला छंटनी का नहीं रहा है और प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से भी अधिनियम, के प्रावधानों की पालना किये जाने का कोई औचित्य नहीं रहा है। वैसे भी प्रतिपक्षी विभाग "उद्योग" की श्रेणी में नहीं आता है तब उस पर अधिनियम के प्रावधान भी प्रभावी नहीं होते हैं। प्रार्थी श्रमिक द्वारा यह मामला पूर्व में भी केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जोधपुर के समक्ष प्रकरण सं० ओ०ए०नं० 332/93 के रूप में उठाया गया है जिसे उक्त अधिकरण द्वारा दि० 30-10-96 को मेरिट्स पर निरस्त भी कर दिया गया है। अतः प्रार्थी श्रमिक का प्रस्तुत क्लेम अस्वीकार किया जावे।

4. प्रार्थी श्रमिक गोपाललाल ने साक्ष्य में स्वयं का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिस पर प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से प्रतिपरीक्षा की गयी है। प्रलेखीय साक्ष्य में प्रलेख प्रदर्श डब्ल्यू० 1 लगा० डब्ल्यू० 4 तक प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये हैं जिनका यथोचित समय पर उल्लेख किया जावेगा।

5. प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से साक्ष्य में साक्षी कैप्टन आर०एम० ठाकुर, सुरक्षा अधिकारी का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर प्रार्थी श्रमिक की ओर से प्रतिपरीक्षा की गयी है। प्रलेखीय साक्ष्य में प्रलेख प्रदर्श एम० 1 व एम० 2 प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये हैं जिनका यथोचित समय पर उल्लेख किया जावेगा।

6. मैंने दोनों पक्षों की बहस सुनी।

7. विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक पक्ष की यह बहस रही है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा अपनी मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से यह पूर्णतः प्रमाणित किया गया है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा प्रतिपक्षी नियोजक के यहां नियोजन में दि० 1-11-90 से नियोजित होकर 5-4-93 तक निरन्तर कार्य कर, उक्त नियोजनकाल में प्रत्येक क्लेण्डर वर्ष में 240 दिवस से अधिक कार्य कर, निरन्तर 3 वर्ष से अधिक अवधि की सेवा पूर्ण कर ली गयी थी तब प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा उसे दि० 6-4-93 से अधिनियम की धारा 25-के अज्ञातमक

प्रावधानों की अवहेलना कर, अनुचित एवं अवैधानिक प्रकार से सेवा से पृथक किया गया है। प्रार्थी श्रमिक की उक्त साक्ष्य के खण्डन में प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक की कार्य मस्ट्रोल्स अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत भी नहीं की गयी है तब प्रार्थी श्रमिक द्वारा कथित नियोजनकाल व कार्य दिवस ही मान्य रहते हैं। प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से जवाब क्लेम में अभिकथित कर यह स्वीकार किया हुआ है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा वर्ष 90-91 में 54 दिवस, वर्ष 91-92 में 210 दिवस, वर्ष 92-93 में 252 दिवस व वर्ष 93-94 में मात्र 7 वास्तविक दिवस ही कार्य किया गया है, इन वास्तविक कार्यदिवसों में वेतन देय साप्ताहिक दिवसों को और जोड़ दिया जाय तो निरन्तर पूर्ण वर्ष कार्य हो जाता है। प्रतिपक्षी नियोजक की साक्ष्य से यह कतई प्रमाणित नहीं किया हुआ है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा स्वतः कार्य का त्याग किया गया है। कथित नोटिस की प्रार्थी श्रमिक को कभी भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से कभी भी समझौता अधिकारी के समक्ष कार्यवाही में भी भाग नहीं लिया गया है। प्रतिपक्षी विभाग अधिनियम में परिभाषित "उद्योग" की परिभाषा के अन्तर्गत है तथा इसका कर्मचारी "कर्मकार" की परिभाषा के अन्तर्गत हैं। प्रार्थी श्रमिक द्वारा त्रुटिवश अपना विवाद केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने व उक्त न्यायाधिकरण द्वारा बिना क्षेत्राधिकार के उसे गुणवगुण पर निरस्त कर दिये जाने मात्र से इस औद्योगिक न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रार्थी श्रमिक सेवा समाप्ति के पश्चात से ही बेरोजगार रहा है तब प्रार्थी श्रमिक द्वारा प्रस्तुत इस क्लेम को पूर्णतः स्वीकार किया जावे।

8. विद्वान प्रतिनिधि प्रतिपक्षी द्वारा उक्त बहस का खण्डन करते हुए यह बहस की गयी है कि प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से अपनी मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से यह पूर्णतः प्रमाणित किया गया है कि प्रार्थी श्रमिक का नियोजन-काल वित्तीय वर्ष 90-91 से 93-94 तक का ही रहा है तब उसके द्वारा वर्ष 92-93 के अतिरिक्त किसी भी वर्ष में निरन्तर पूर्ण वर्ष कार्य नहीं किया गया है। प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक को सेवा से पृथक नहीं किया गया है वरन् प्रार्थी श्रमिक द्वारा स्वयं दि० 5-4-93 से कार्य पर उपस्थित होना बन्द कर दिया गया है। प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से प्रार्थी श्रमिक को कार्य पर वापस उपस्थित होने हेतु लगातार सूचना भी भिजवायी गयी है तथा दि० 24-4-93 को नोटिस भी जारी किया गया है तब प्रार्थी श्रमिक का मामला सेवा से छंटनी का नहीं रहा है जब प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से भी अधिनियम के प्रावधानों की परिपालना किये जाने का कोई औचित्य नहीं रहा है। प्रार्थी श्रमिक द्वारा यह मामला पूर्व में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जोधपुर बैच के समक्ष उठाया गया है तब उक्त न्यायाधिकरण द्वारा उक्त मामले को गुणवगुण पर निरस्त कर दिया गया है जब इस औद्योगिक न्यायाधिकरण को उक्त मामले पर पुनः सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं

है। प्रतिपक्षी विभाग अधिनियम में परिभाषित "उद्योग की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं है तथा प्रतिपक्षी कर्मचारी भी परिभाषित "कर्मकार" की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं है तब उक्त मामले पर अधिनियम के प्रावधान प्रभावी नहीं होते हैं और इस औद्योगिक न्यायाधिकरण को भी उक्त मामले पर सुनवायी का क्षेत्राधिकार उपलब्ध नहीं रहता है। प्रार्थी श्रमिक सेवा त्याग के पश्चात् से ही अन्यत्र लाभकारी नियोजित रहा है जो उसके द्वारा स्वीकार भी किया हुआ है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत क्लेम अस्वीकार किया जावे। विद्वान प्रतिनिधि द्वारा अपनी उक्त बहस के समर्थन में "प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958" व माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत "1997 एस०सी०सी० (एल० एण्ड एस०) 1079-हिमांशु कुमार बनाम बिहार राज्य" को उद्धरित किया गया है।

9. मैंने दोनों पक्षों की बहस पर विचार किया तथा पन्नावली व अभिलेख का ध्यातपूर्वक अवलोकन किया।

10. प्रार्थी श्रमिक की क्लेम समर्थन में मुख्यतः सुसंगत साक्ष्य नियोजनकाल व कार्यदिवसों के सम्बन्ध में अपने शपथ-पत्र में यह रही है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा प्रतिपक्षी नियोजक के यहां नियोजन में दि० 1-11-90 से सहायक कर्मचारी स्मारक परिचर के रूप में नियोजित होकर दि० 5-4-93 तक निरन्तर विभागीय कार्यों, मोन्यूमेंट सुरक्षा चौकीदार, निर्माण रख-रखाव तथा कार्यालय निर्देशानुसार रेस्ट रिलीवर के रूप में निरन्तर सेवा कार्य कर हर क्लेण्डर वर्ष में 240 दिवस से अधिक समय तक कार्य किया जाकर, निरन्तर 3 वर्ष से अधिक समय तक कार्यविधि पूर्ण की गयी है। शपथ-पत्र की प्रतिपरीक्षा पर यह साक्ष्य भी रही है कि प्रार्थी को नौकरी पर लगाने समय लिखित में नियुक्ति आदेश नहीं दिया गया बल्कि मौखिक ही नौकरी से हटाया था। यह कहना गलत है कि उसने स्वयं काम पर आना बन्द कर दिया बल्कि उसे विभाग वालों ने ही काम से हटाया था। प्रार्थी श्रमिक की उक्त साक्ष्य के खण्डन में प्रतिपक्षी साक्षी की इस सन्दर्भ में शपथ-पत्र पर यह साक्ष्य रही है कि प्रार्थी श्रमिक को प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में दिहाड़ी पर केन्द्रीय संरक्षित स्मारक, चित्तौड़गढ़ पर साफ-सफाई हेतु स्वीकृत प्राक्कलनों पर समय-समय पर अस्थायी कार्यों के लिए मस्ट्रोल पर लगाया जाता रहा है तब प्रार्थी श्रमिक द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष में 240 दिवस निरन्तर कार्य नहीं किया गया है। प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से जवाब क्लेम के पैरा सं० 2 में प्रार्थी श्रमिक द्वारा वित्तीय वर्ष 90-91 में 54 दिवस, वर्ष 91-92 में 210 दिवस, 92-93 में 252 दिवस व वर्ष 93-94 में 7 दिवस कार्य किया जाना स्वीकार किया हुआ है। इस प्रकार प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से ही यह स्वीकार्य रहा है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा वित्तीय वर्ष 92-93 में 252 दिवस कार्य किया गया है तब प्रार्थी श्रमिक द्वारा उक्त एक वर्ष में 240 दिवस से अधिक कार्य कर निरन्तर पूर्ण वर्ष सेवा की गयी है। माननीय राज० उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत "1996(2) एल०एल०जे० 122-चोक इंजीनियर

मिचार्ड विभाग बनाम कमलेश व अन्य" में यह न्यायसिद्धांत भी प्रतिपादित किया हुआ है कि श्रमिक के निरन्तर एक क्लेण्डर वर्ष सेवा कार्य पूर्ण कर लेने पर ही अधिनियम की धारा 25-गफ के प्रावधान प्रभावी हो जाते हैं तब श्रमिक द्वारा अपने नियोजनकाल के प्रत्येक वर्ष में 240 दिवस तक सेवा कार्य किया जाना आवश्यक नहीं है। "निरन्तर एक वर्ष सेवा" को प्रस्तुत मामले में अधिनियम की धारा 25-बी(2) में परिभाषित किया हुआ है जब बारह क्लेण्डर मास में 240 दिवस पूर्ण वास्तविक कार्य किया जाना ही निरन्तर एक वर्ष सेवा पूर्ण माना गया है। प्रतिपक्षी साक्षी की इसी सन्दर्भ में यह साक्ष्य भी रही है कि प्रार्थी श्रमिक को समय-समय पर अस्थायी कार्यों पर मस्ट्रोल पर लगाया जाता रहा है परन्तु प्रतिपक्षी साक्षी यह बतलाने में असमर्थ रहा है कि प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा उक्त सन्दर्भित वर्ष में प्रार्थी श्रमिक को ब्रेक के साथ नियोजित किया गया हो। वैसे भी मेरे मन में जब अधिनियम की धारा 25-गफ में प्रकट हुए, "निरन्तर एक वर्ष सेवा" को अधिनियम की धारा 25-बी(2) में परिभाषित करते हुए यह प्रावधानित किया गया है कि बारह क्लेण्डर मास में 240 दिवस सेवा कार्य पूर्ण कर लेने पर "निरन्तर एक वर्ष" सेवा पूर्ण कर लिया जाना माना जावेगा तब एक वर्ष के नियोजनकाल में, ब्रेक के साथ अथवा एक वर्ष की अल्पावधि के नियोजनकाल में भी 240 दिवस सेवा कार्य पूर्ण कर लिया गया है जब भी "निरन्तर एक वर्ष सेवा" पूर्ण कर लिया जाना माना जावेगा। मैं अपने उक्त मत का समर्थन माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत "1981 (1) एल०एल०जे० 368-मुरेन्द्र कुमार वर्मा बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण, केन्द्रीय दिल्ली व अन्य" में प्रतिपादित निम्न न्यायसिद्धांत से भी पाता हूँ :—

"Even if a workman has not been in 'continuous service' under an employer for a period of one year, he shall be deemed to have been in such 'continuous service' for a period of one year if he has actually worked under the employer for 240 days in the preceding period of twelve months. There is no stipulation that he should have been in employment or service under the employer for a whole period of twelve months. In fact, the thrust of the provision is that he need not be. That appears to be the plain meaning without gloss from any source."

11. इस प्रकार प्रार्थी श्रमिक द्वारा प्रतिपक्षी नियोजक के यहां नियोजन में प्रतिपक्षी के अनुसार ही वित्तीय वर्ष 92-93 में 252 दिवस कार्य कर एक वर्ष सेवा कार्य पूर्ण किया गया है।

12. इसके अनिर्गुण प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा जवाब "क्लेम में प्रार्थी श्रमिक द्वारा वित्तीय वर्ष 91-92 में 210 दिवस कार्य किया जाना स्वीकार किया गया है। इस सन्दर्भ में प्रतिपक्षी साक्षी की शपथ-पत्र व प्रतिपरीक्षा में यह साक्ष्य भी रही है कि हमारे द्वारा जो कार्यदिवस बतलाये गये हैं वो वास्तविक कार्य दिवस हैं जिनमें माप्ताहिक अवकाशों को शामिल नहीं किया हुआ है। साक्षी को आगे यह साक्ष्य भी रही है कि प्रार्थी श्रमिक, न्यूनतम वेतन अधिनियम,

1948 के अधीन राजस्थान सरकार द्वारा घोषित दैनिक वेतन प्राप्त श्रमिक रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम दैनिक वेतन का निर्धारण एक माह के न्यूनतम वेतन को 26 दैनिक दिवसों में विभक्त कर दिया गया है जब एक माह के 26 दिवसों के निर्धारित न्यूनतम दैनिक वेतन में उस माह के साप्ताहिक अवकाशों का वेतन भी सम्मिलित रहता है तब न्यूनतम दैनिक वेतन प्राप्त श्रमिक के साप्ताहिक अवकाश भी वेतन देय साप्ताहिक अवकाश रखते हैं, इस आशय की "टिप्पणी" भी राज्य सरकार की घोषित घोषणा में अंकित भी रहती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायदृष्टांत "ए०आई०आर० 1986 एस०सी० 458-बर्कमेन ऑफ अमेरिकन, ई०आई०बी०सी० बनाम मैनेजमेन्ट ऑफ अमेरिकन, ई०आई०बी०सी०" में यह न्याय-सिद्धांत भी प्रतिपादित किया हुआ है कि अधिनियम की धारा 25 बी(2) के अधीन श्रमिक के कार्यादिवसों की गणना में श्रमिक के वेतनदेय अवकाश व साप्ताहिक अवकाश भी जोड़े जावेंगे। प्रस्तुत प्रकरण में, जब प्रार्थी श्रमिक के वर्ष 1991-92 के 210 वास्तविक कार्य दिवसों में प्रार्थी श्रमिक वेतन देय साप्ताहिक अवकाशों के दिवसों को भी जोड़ दिया जावे तब प्रार्थी श्रमिक द्वारा उक्त वर्ष में भी 240 दिवस तक कार्य किया जाकर, उक्त वर्ष में भी सेवा कार्य पूर्ण किया गया है।

13. इसके अतिरिक्त प्रार्थी श्रमिक की अपने नियोजन-काल व कार्यादिवसों के सन्दर्भ में शपथ-पत्र पर यह साक्ष्य रही है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा प्रतिपक्षी नियोजक के यहां नियोजन में 1-11-90 से नियोजित होकर 5-4-93 तक निरन्तर कार्य कर, उक्त नियोजनकाल में निरन्तर 3 वर्ष से अधिक अवधि तक सेवा कार्य किया गया है। शपथ-पत्र पर प्रतिपरीक्षा में इस सन्दर्भ में प्रार्थी श्रमिक की यह साक्ष्य भी रही है कि प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा नियोजन में नियोजित करने पर प्रार्थी को कोई नियुक्ति-पत्र तथा सेला से पृथक करने पर कोई सेवा-मुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। प्रार्थी श्रमिक द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उससे भुगतान पर रसीदी टिकट लगाकर रसीद ली जाती थी। इस प्रकार प्रार्थी श्रमिक के पास अपने नियोजनकाल व कार्यादिवसों के समर्थन में कोई प्रलेखीय साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं रही है। प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से भी किसी भी स्तर पर ऐसा मामला नहीं रहा है कि उनके द्वारा मस्ट्रोल पर नियोजित दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को उनके नियोजित किये जाने पर कोई नियोजन-पत्र, नियोजित रहने पर कोई जोय-कार्ड, वेज-स्लिप अथवा ऐसा कोई प्रलेख जिसमें श्रमिक के नियोजन-काल व कार्यादिवसों का वर्णन अंकित रहता हो, दिये जाने हो तब प्रार्थी श्रमिक के पास अपने नियोजनकाल व कार्यादिवसों के प्रमाण में अपनी मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त कोई प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहती है जबकि प्रतिपक्षी नियोजक के पास प्रार्थी श्रमिक के नियोजनकाल व कार्यादिवसों के प्रमाण के लिए सर्वोत्तम एवं निर्णायक साक्ष्य प्रार्थी श्रमिक की कार्य मस्ट्रोल व कार्य भुगतान सम्बन्धी लेखा प्रलेख सदैव आधिपत्य में रहने पर सदैव उपलब्ध रहने हैं।

जब प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक द्वारा दिया नियोजनकाल व कार्यादिवसों का प्रतिवाद किया गया है और प्रतिवाद में प्रार्थी ने अपने अनुसार नियोजनकाल व कार्यादिवस होना कथन किया है तब प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रतिवाद में बतलाये प्रार्थी श्रमिक के नियोजनकाल व कार्यादिवसों के प्रमाण में उनके आधिपत्य में रही सर्वोत्तम एवं निर्णायक साक्ष्य प्रार्थी श्रमिक के कार्यमस्ट्रोल व भुगतान सम्बन्धी लेखा-प्रलेखों को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही प्रस्तुत न किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण ही बर्शाया गया है। प्रतिपक्षी नियोजक मात्र प्रमाण भार प्रार्थी श्रमिक पर होना कहकर उक्त सर्वोत्तम एवं निर्णायक साक्ष्य मस्ट्रोल व कार्य भुगतान सम्बन्धी लेखा-प्रलेख प्रस्तुत नहीं कर उनके विरुद्ध विपरीत निष्कर्ष निकाले जाने से नहीं बच सकता। मैं अपने उक्त मत का समर्थन माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत "ए०आई०आर० 1968 एस०सी० 1413-गोपालकृष्ण जी केलकर बनाम मोहम्मद हाजी लतीफ" में प्रतिपादित निम्न न्यायसिद्धांत से भी पाता हूँ :-

"It is not, in our opinion a sound practice for those desiring to rely upon a certain set of facts to withhold from the Court the best evidence which is in their possession which could throw light upon the issues in controversy and the rely upon the abstract doctrine of onus of proof."

14. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत "1985(4) एस०सी०सी० 201-एच०बी० मिह बनाम रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया" के मामले में उपस्थिति रजिस्टर अथवा भुगतान रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने पर व माननीय राज० उच्च न्यायालय द्वारा "1996(2) एल०एल०जे० 122-चीफ इंजीनियर, मिचाई विभाग बनाम कमलेश व अन्य" के मामले में कार्य मस्ट्रोल प्रस्तुत न किये जाने पर श्रमिक द्वारा कथित नियोजनकाल व कार्यादिवसों को ही माने जाने का निष्कर्ष निकाले जाने का अभिमत प्रकट किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी श्रमिक द्वारा अपनी साक्ष्य से यह पूर्णतया प्रमाणित किया गया है कि उसके द्वारा प्रतिपक्षी नियोजक के यहां नियोजन में 1-11-90 से नियोजित होकर 5-4-93 तक निरन्तर कार्य कर उक्त नियोजनकाल में निरन्तर 3 वर्ष से अधिक समय तक की अवधि तक कार्य किया गया है। उसने एक कलेण्डर वर्ष में 240 दिवस से अधिक समय तक कार्य कर लिया है।

15. प्रार्थी श्रमिक की आगे शपथ-पत्र पर यह साक्ष्य भी रही है कि प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक को 6-4-93 से अकारण ही उससे कनिष्ठ श्रमिक गोविन्दसिंह व मन्नालाल इत्यादि को कार्य पर नियोजित रखते हुए व नियमित सेवाओं का लाभ देने हुए, पहले आये बाद में जाये सिद्धांत की अवहेलना करते हुए, बिना कोई जांच किये अथवा बिना नोटिस अथवा नोटिस वेतन व छंटनी का मुआवजा दिये अधिनियम की धारा 25-एफ की अवहेलना करते हुए मौखिक ही सेवा से पृथक कर दिया जो सर्वथा अनुचित व अवैध है। प्रार्थी की प्रतिपरीक्षा में इस सन्दर्भ

में यह साक्ष्य भी रही है कि यह कहना गलत है कि उसने काम पर आना बन्द कर दिया हो बल्कि विभाग वालों ने ही उसे कार्य से हटाया है। प्रार्थी श्रमिक को नौकरी से हटाने का कोई लिखित आदेश नहीं दिया बल्कि मौखिक ही नौकरी से हटाया था। प्रार्थी श्रमिक ने काम से हटाने के बाद विभाग वालों को पुनः काम पर रखने के पत्र लिखे व टेलीग्राम किये परन्तु विभाग में कोई सुनवायी नहीं की गयी। आगे यह साक्ष्य भी रही है कि उसे नौकरी से हटाने के बाद विभाग की ओर से प्रदर्श एम० 1 नोटिस दि० 24-4-93 कभी प्राप्त नहीं हुआ।

16. इसके विपरीत प्रतिपक्षी साक्षी आर०एस० ठाकुर, सुरक्षा अधिकारी की यह साक्ष्य रही है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा स्वयं ही 5-4-93 से कार्य पर आना बन्द कर दिया गया जो कार्यालय द्वारा लगातार सूचना भेजने व 24-4-93 को नोटिस जारी किये जाने पर भी उपस्थित नहीं हुआ। शपथपत्र की प्रतिपरीक्षा पर यह साक्ष्य भी रही है कि प्रार्थी श्रमिक का नियोजनकाल इस साक्षी के प्रतिपक्षी विभाग में पदस्थापनकाल से पूर्व का रहा है। इस प्रकार प्रतिपक्षी साक्षी को प्रार्थी श्रमिक के नियोजनकाल व कार्य-दिवसों व सेवा मुक्ति के सन्दर्भ में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं रही है तथा जो भी जानकारी रही है वह अभिलेख के आधार पर ही रही है। आगे यह साक्ष्य भी रही है कि हमारे द्वारा श्रमिक को बुलाने का नोटिस दिनांकित 24-4-93 नोटिस बोर्ड पर चम्या किया गया था। उसने यह भी कथन किया है कि वह यह नहीं कह सकता कि इस नोटिस की प्रार्थी श्रमिक को तामील हुई या नहीं। प्रतिपक्षी की ओर से इस सन्दर्भ में कथित नोटिस 24-4-93 की सत्यप्रतिनिधि भी प्रस्तुत की गयी है जो प्रदर्श एम० 1 है। प्रलेख प्रदर्श एम० 1 के अवलोकन पर यह प्रकट नहीं होता है कि उक्त प्रलेख विभाग के नोटिस-बोर्ड पर चम्या किया गया या नहीं, इस सन्दर्भ में कोई नोटिस पर नोट अंकित नहीं है। प्रतिपक्षी साक्षी द्वारा अपने शपथपत्र की प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया कि वह यह नहीं कह सकता कि तत्कालीन नोटिस की तामील प्रार्थी श्रमिक को हुई अथवा नहीं तब उक्त प्रलेख प्रदर्श एम० 1 में यह निष्कर्ष कतई नहीं निकलता है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा स्वयं सेवा का त्याग किया गया हो। प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से इस सन्दर्भ में अन्य कोई प्रलेख न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह विदित होता हो कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा स्वयं सेवा में त्याग किया गया हो। प्रतिपक्षी साक्षी दि० 6-4-93 को प्रतिपक्षी विभाग में पदस्थापित भी नहीं रहा है तब उसे प्रार्थी श्रमिक के स्वतः सेवा त्याग की भी कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है तथा जो भी जानकारी है वह अभिलेख के आधार पर ही रही है। प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से प्रार्थी श्रमिक का स्वतः सेवा त्याग किये जाने के सन्दर्भ में कोई प्रलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है तब प्रतिपक्षी साक्षी की शपथपत्र पर की यह साक्ष्य की प्रार्थी श्रमिक द्वारा स्वतः सेवा का त्याग किया गया है, किसी समर्थित प्रलेखीय साक्ष्य के अभाव में स्वीकार

किये जाने योग्य नहीं रहती है। इस प्रकार प्रार्थी श्रमिक द्वारा अपनी साक्ष्य से यह पूर्णतया प्रमाणित किया गया है कि उसे प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा दि० 6-4-93 से सेवा से पृथक किया गया है। प्रतिपक्षी साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि प्रतिपक्षी विभाग द्वारा प्रार्थी श्रमिक को कभी भी नोटिस अथवा नोटिस वेतन व छंटनी का मुआवजा नहीं दिया गया और अधिनियम की धारा 25-एफ के प्रावधानों की परिपालना नहीं की गयी है।

17. प्रार्थी श्रमिक के क्लेम स्टेटमेन्ट प्रस्तुत कर यह अभिकथन भी रहे है कि प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक को 6-4-93 से प्रार्थी श्रमिक से कनिष्ठ श्रमिकों गोविन्दसिंह व मन्नालाल को यथावत सेवा में नियोजित रखते हुए बिना "पहले आये बाद जाये" सिद्धान्त की पालना किये, अधिनियम की धारा 25-जी के विधि प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सेवा से पृथक किया गया है। प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा जवाब क्लेम प्रस्तुत कर उक्त तथ्यों को स्वीकार नहीं किया गया है। प्रार्थी श्रमिक की क्लेम स्टेटमेन्ट के उक्त अभिकथनों के सन्दर्भ में शपथपत्र पर उक्त कथित कनिष्ठ श्रमिकों गोविन्दसिंह व मन्नालाल के सन्दर्भ में कोई साक्ष्य नहीं है और तो और उक्त दोनों श्रमिकों के नामों का भी उल्लेख नहीं हुआ है। प्रार्थी श्रमिक द्वारा उक्त अभिकथनों के समर्थन में कोई प्रलेखीय साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गयी है और न ही प्रतिपक्षी नियोजक से ही कोई प्रलेख प्रस्तुत करवाये जाने का प्रयास ही किया गया है तब साक्ष्य अभाव में प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में उक्त सिद्धान्त व अधिनियम की धारा 25-जी के विधि प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित नहीं होता है।

18. प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से जवाब क्लेम प्रस्तुत कर यह अभिकथन भी रहे है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ना तो किसी उद्योग की श्रेणी में आता है एवं ना ही अधिनियम की परिधि में आता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, केन्द्रीय सरकार द्वारा संरक्षित स्थल, स्मारक, पुरावशेषों और प्राचीन अमूल्य धरोहर तथा संस्कृति को जीवित रखने के उद्देश्य से उनका रख-रखाव का कार्य करता है। इस विभाग का कदापि यह उद्देश्य नहीं रहा है कि इन स्मारकों का रख-रखाव किसी प्रकार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अर्थ लाभ प्राप्त करने के लिए किया जावे तब भारतीय सर्वेक्षण विभाग उद्योग की परिभाषा में नहीं आता है। प्रतिपक्षी साक्षी कैप्टन आर०एस० ठाकुर, सुरक्षा अधिकारी के भी शपथपत्र पर उक्त प्रकार से ही कथन रहे है। इसी सन्दर्भ में प्रतिपक्षी साक्षी की प्रतिपरीक्षा में यह साक्ष्य भी रही है कि प्रदर्श डब्ल्यू० 2 व 3 उनके विभाग के आदेश व मेमोरेण्डम हैं। आगे यह साक्ष्य भी रही है कि हमारे विभाग में प्रार्थी श्रमिक द्वारा स्मारकों की साफ-सफाई, निगरानी व मरम्मत आदि का कार्य किया गया है। विद्वान प्रतिनिधि प्रतिपक्षी की उक्त कथनों के आधार पर यह बहम रही है कि प्रतिपक्षी विभाग अधि-

नियम में परिभाषित "उद्योग" की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं है तथा प्रार्थी कर्मचारी भी परिभाषित "कर्मकार" की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं है तब उक्त मामले पर अधिनियम के प्रावधान प्रभावी नहीं होते हैं और इस औद्योगिक न्यायाधिकरण को भी उक्त मामले पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार उपलब्ध नहीं रहता है। विद्वान प्रतिनिधि प्रतिपक्षी की ओर से उक्त अभिकथनों के समर्थन में प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 भी उद्धृत किया गया है तथा अपनी उक्त बहस के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत "1997 एस०सी०सी० (एल एण्ड एस) 1079—हिमांशु कुमार बनाम बिहार राज्य" को उद्धृत किया गया है। उद्धृत उक्त न्यायदृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामला बिहार राज्य के को-ऑपरेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी, महायक चालकों व चपरासियों के सेवा से निष्कासन पर पुनः सेवा में नियोजित करने का रहा है तब माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में निम्न अभिमत प्रकट किया गया है :—

"Every Department of Government can not be treated to be Industry. Where the appointments are regulated by statutory rules, the concept of Industry to the extent stands excluded. The petitioners were not appointed to the posts in accordance with the rules but were engaged on the basis of need of the work. They are temporary employees working on daily wages. Their disengagement from service can not be construed to be retrenchment under the Industrial Disputes Act. The concept of retrenchment therefore can not be stretched to such an extent as to cover these employees. Since the petitioners are only daily wage employees and have no right to the posts, their disengagement is not arbitrary."

19. उक्त उद्धृत न्यायादृष्टांत में बिहार राज्य के को-ऑपरेटिव इंस्टीट्यूट के स्थापना के क्या उद्देश्य रहे हैं तथा उक्त संस्थान द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, यह उक्त निर्णय में अंकित नहीं है। इस न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत इस प्रकरण में प्रतिपक्षी नियोजक का यह मामला होना भी प्रकट नहीं हुआ है कि उनके नियोजन में कार्यरत श्रमिकों की सेवाएं कानूनी नियमों में शामिल होती हैं। प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से उद्धृत "प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (जिसे तदुपरान्त संक्षेप में "अधिनियम 1958 से सम्बोधित किया जायेगा) में अथवा उक्त अधिनियम की धारा 38 जिसके अधीन नियम बनाये जाने के प्रावधान हैं, में भी सेवारत श्रमिकों की सेवायें शामिल करने के लिए कोई सेवा नियम बनाये जाने के प्रावधान नहीं है। प्रतिपक्षी नियोजक साक्षी की शपथ-पत्र पर अथवा प्रतिपरीक्षा में कहीं यह वर्णित नहीं हुआ है कि प्रार्थी श्रमिक की सेवायें किसी विशेष नियमों के अधीन शासित होती हैं। इसके विपरीत प्रार्थी श्रमिक की ओर से प्रतिपक्षी विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश व मेमोरेण्डम की प्रतियां प्रदर्शित रखीं, 2 व 3 भी प्रस्तुत की गयी हैं जिन्हें प्रतिपक्षी साक्षी द्वारा प्रतिपक्षी विभाग द्वारा जारी

किया जाना स्वीकार भी किया गया है। उक्त कार्यालय आदेश व मेमोरेण्डम के द्वारा दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के सेवा में नियोजन, वेतन, कार्य व सेवा में नियमन के सन्दर्भ में समय-समय पर प्रतिपक्षी विभाग द्वारा आदेश प्रसारित किया जाना भी प्रकट हुआ है तब प्रतिपक्षी नियोजक को उद्धृत उक्त न्यायदृष्टांत में प्रकट हुए अभिमत से प्रस्तुत प्रकरण में कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

20. प्रतिपक्षी विभाग अधिनियम की धारा 2 (जे) में परिभाषित "उद्योग" की परिभाषा में आता है अथवा नहीं, इस सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत "1978 (1) एल. एल. जे. 349—बैंगलोर वाटर सप्लाय एण्ड सीवरेज बोर्ड बनाम ए. राजप्पा" के पैरा 131 में निम्न जांच सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :—

"IV. The dominant nature test :

(a) Where a complex of activities, some of which qualify for exertion, others not, involves employees on the total undertaking, some of whom are not 'workmen' as in the University of Delhi case or some departments are not productive of goods and services if isolated, even then, the predominant nature of the services and the integrated nature of the departments as explained in the Corporation of Nagpur, will be the true test. The whole undertaking will be 'industry' although those who are not 'workmen' may not benefit by the Status.

(d) Constitutional and competently enacted sovereign functions, strictly understood, alone qualify for exemption, not the welfare activities or economic adventures undertaken by Government or statutory bodies.

(c) Even in departments discharging sovereign functions, if there are units which are industries and they are substantially severable, then they can be considered to come within S.2(j).

(d) Constitutional and competently enacted legislative provisions may well remove from the scope of the Act."

21. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त जांच सिद्धांतों को अपने नवीनतम न्यायदृष्टांत (1) "ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 656—जी. एस. टेलीकॉम बनाम एस. श्रीनिवास राय व (2) 1996 (1) एल. एल. जे. 1223—बीफ कंजरबेटर आफ फोरेस्ट बनाम जगन्नाथ मूर्ति कंधारे" में पुनः मान्यता प्रदान की गयी है तथा उक्त जांच सिद्धांतों के विपरीत रहे माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत " (1996) 8 एस. सी.

सी. 489—सब जजि. आफ पोस्ट बजकम बनाम थियम जोसेफ तथा ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 2817—
 बाम्बे टेलीफोन केन्टीन एम्प्लोईज एसो. बनाम यूनियन आफ इण्डिया” में प्रकट किये गये अभिमतों को निरस्त किया गया है और प्रथम न्यायदृष्टांत में टेलीकोम विभाग को व द्वितीय न्यायदृष्टांत में वन विभाग को “उद्योग” की परिभाषा के अन्तर्गत होना माना गया है। द्वितीय न्यायदृष्टांत वन विभाग वाले प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त उद्धृत बैंगलूर वाटर सप्लाई वाले प्रकरण पर विचार करते हुए निर्णय के पैरा 13, 16 व 17 में निम्न प्रकार अभिमत प्रकट किये गये हैं—

“(13) The aforesaid shows that if we were to extend the concept of sovereign function to include all welfare activities as contended on behalf of the appellants, the ratio in Bangalore Water Supply case (*supra*) would get eroded, and substantially. We would demur to do so on the fact what was stated in the aforesaid case according to which except the strictly understood sovereign function, welfare activities of the State would come within the purview of the definition of industry; and not only this, even within the wider circle of sovereign function, there may be an inner circle encompassing some units which could be considered as industry if substantially severable.

(16) This aforesaid being the crux of the scheme to implement which some of the respondents were employed, we are of the view that the same cannot be regarded as a part of inalienable or inescapable function of the State for the reason that the scheme was intended even to fulfil the recreational and educational aspirations of the people. We are in no doubt that such a work could well be undertaken by an agency which is not required to be even an instrumentality of the State.

(17) This being the position, we hold that the aforesaid scheme undertaken by the Forest Department cannot be regarded as a part of sovereign function of the State and so, it was open to the respondents to invoke the provisions of the State Act. We would say the same quathe social foresting work undertaken in Ahmednagar district. There was, therefore, no threshold bar in knocking the door of the Industrial Courts by the respondents making a grievance about adoption of unfair labour practice by the appellants.”

27. अधिनियम, 1958 के शीर्षक “राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थल

और अवशेषों के परिरक्षण का, पुरातत्वीय उत्खननों के विनियमन का और रूपकृतियों, नक्काशी और अन्य ऐसी वस्तुओं के संरक्षण का उपबन्ध करने के लिए “अधिनियम” “अंकित हुआ है। इसी अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अन्तर्गत संरक्षित संस्मारक अनुरक्षण को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि “अनुरक्षण” के अन्तर्गत किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसे पुनरुद्धार करना और उसकी सफाई करना और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधापूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है। इसी अधिनियम, 1958 की धारा 18 के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्याधीन रहते हुए, जनता को किसी भी संरक्षित संस्मारक तक पहुंच का अधिकार दिया गया है। इसी अधिनियम, 1958 की धारा 6 के अधीन संरक्षित संस्मारक के अनुरक्षण के लिए उनके स्वामियों से संबंधित करने का भी अधिकार कलेक्टर को दिया हुआ है। इसी अधिनियम, 1958 की धारा 15 के अधीन महानिदेशक को संरक्षित संस्मारक के अनुरक्षण खर्च के निमित्त चन्दा आदि दिये जाने पर स्वीकार करने का भी अधिकार है। इसी अधिनियम, 1958 की धारा 21 के अधीन पुरातत्वीय उत्खनन के लिए लाइसेंस भी जारी किये जाने का प्रावधान है। इसी अधिनियम की धारा 38 (2) (सी) में संरक्षित प्राचीन संस्मारकों पर जनता की पहुंच के लिए शुल्क निर्धारित करने का भी प्रावधान है। इसी सन्दर्भ में स्वयं प्रतिपक्षी साक्षी ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि यह सही है कि हमारे द्वारा स्मारक देखने वाले से पहले 50 पैसे व अब दो रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से लिये जाने है जो भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिये जाने है। इस प्रकार उक्त अधिनियम, 1958 के अवलोकन पर ऐसा प्रकट नहीं हुआ है कि प्रतिपक्षी विभाग द्वारा सरकार के प्रभुत्वसम्पन्न कार्यों का निष्पादन किया जाता है। प्रतिपक्षी विभाग द्वारा जो उक्त प्राचीन संस्मारकों, तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेषों के परीक्षण, पुरातत्वीय उत्खननों के विनियमन, रूपकृतियों, नक्काशी व ऐसी अन्य वस्तुओं के संरक्षण का कार्य किया जाता है जो जनता तथा देशी-विदेशी पर्यटकों का आमोद-प्रमोद व शैक्षणिक लाभ मुलभ कराने के उद्देश्य से ही किया जाता है जिससे प्रत्यक्षतः शुल्क लगाकार व अप्रत्यक्षतः विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर विदेशी मुद्रा का कुछ सीमा तक लाभ भी अर्जित किया जाता है। प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय अवशेषों के परीक्षण पर और संरक्षण पर कार्य किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा भी करवाया जा सकता है तब प्रतिपक्षी विभाग द्वारा किया गया उक्त कार्य किसी भी प्रकार से सरकार का प्रभुत्वसम्पन्न कार्य नहीं है। प्राचीन श्रमिक द्वारा स्वीकार्य रूप में उक्त प्रतिपक्षी विभाग में दैनिक वेतन भांगी श्रमिक के रूप में मस्ट्रोल पर प्राचीन संस्मारक चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर साफ-सफाई का कार्य किया जाता है तब प्रतिपक्षी नियोजक संस्थान, अधिनियम, की धारा 2 (जे) के अधीन परिभाषित “उद्योग” होता तथा

प्रार्थी श्रमिक इसी अधिनियम की धारा 2 (एस) में परिभाषित "कर्मकार" होता पाया जाता है।

23. विद्वान प्रतिनिधि प्रतिपक्षी, प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जोधपुर बैच के निर्णय दि. 30-10-96 प्रत्येक प्रदर्श एम. 2 को आधार बनाकर, यह बहस भी रही है कि उक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण, द्वारा प्रार्थी श्रमिक द्वारा प्रस्तुत विवाद की गुणाव-गुण पर विचार कर निरस्त किया जा चुका है तब इस औद्योगिक न्यायाधिकरण को उक्त विवाद को पुनः मुनने का अधिकार नहीं रहता है। मैंने विद्वान प्रतिनिधि की उक्त बहस पर भी विचार किया। जब प्रतिपक्षी विभाग एक "उद्योग" और उसका प्रार्थी श्रमिक एक "कर्मकार" है तब अधिनियम के प्रावधानों के अधीन प्रतिपक्षी नियोजक व प्रार्थी श्रमिक के मध्य रहे उक्त औद्योगिक विवाद को, औद्योगिक न्यायाधिकरण न्यायालय को ही एक मात्र श्रवणाधिकार प्रवृत्त रहता है तथा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित उक्त निर्णय अपने आपमें उनके क्षेत्राधिकार से बाहर का रहता है और इस औद्योगिक न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार पर किसी भी प्रकार से विपरीत प्रभाव नहीं डालता है तब प्रतिपक्षी नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि की उक्त बहस भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं रहती है।

24. अतः उक्त विवेचनोपरान्त निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रार्थी श्रमिक ने प्रतिपक्षी नियोजक के यहां दि. 1-11-90 से नियोजित होकर दि. 5-4-93 तक निरन्तर कार्य कर उक्त नियोजनकाल में निरन्तर 3 वर्ष से अधिक अवधि तक सेवा कार्य पूर्ण किया है तब प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक को दि. 6-4-93 से अधिनियम की धारा 25-एफ के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए जो सेवा से पृथक् किया गया है वो किसी भी प्रकार से उचित एवं वैध नहीं है तब प्रार्थी श्रमिक प्रतिपक्षी नियोजक के यहां सेवा की निरन्तरता सहित पुनः सेवा में आने का अधिकारी घोषित होने योग्य रहता है।

25. जहां तक प्रार्थी श्रमिक के पिछले वेतन प्राप्त करने के अधिकारी होने का प्रश्न है, यद्यपि प्रार्थी श्रमिक ने इस संदर्भ में अपने शपथ-पत्र में यह कथन तो रहे है कि वह बेरोजगार रहा है और बायजूद प्रयास के कोई स्थाई रोजगार नहीं मिला है परन्तु प्रतिपक्षी में उसके यह कथन भी रहे हैं कि मेरे पिता मेरे से काम करने के लिए कहते हैं, मैं इसलिए काम नहीं करता क्योंकि मेरा केस चल रहा है जिसमें मुझे पैसे मिलने हैं। इस प्रकार इन तथ्यों से ऐसा आभास होता है कि प्रार्थी श्रमिक ने स्वयं ने अन्यत्र काम मिलते हुए काम करने में अपनी अभिरुचि नहीं दिखाना पसन्द किया है, अतः इन तथ्यों की रोशनी में प्रार्थी श्रमिक पिछला 40% वेतन ही प्राप्त करने का अधिकारी रहता है।

26. अतः उक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा सम्प्रेषित निर्देश को इस प्रकार उद्धृत किया जाता है कि प्रबन्धन भारतीय

पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जयपुर मण्डल द्वारा प्रार्थी श्रमिक गोपाललाल, स्मारक परिसर की सेवाएं दिनांक 6-4-93 से समाप्त करने की कार्यवाही उचित एवं वैध नहीं है, फलस्वरूप प्रकरण की परिस्थितियों में प्रार्थी श्रमिक पिछले 40% वेतन व सेवा की निरन्तरता सहित पुनः सेवामें लिये जाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

इस अधिनिर्णय को समुचित सरकार को नियमानुसार प्रकाशनार्थ भिजवाया जाये।

जगदीश प्रसाद शर्मा, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1998

का. आ. 1821.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जयपुर के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण कोटा के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27-8-98 को प्राप्त हुआ था।

[मं. एन.-42012/216/94-आई. आर. (डी. यू.)]

के. वी. बी. उण्णी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th August, 1998

S.O. 1821.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Kota as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bhartiya Puratatava Sarvekshan Vibhag, Jaipur and their workman, which was received by the Central Government on the 27-8-98.

[No. L-42012/216/94-IR(DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

अनुबन्ध

न्यायाधीश औद्योगिक न्यायाधिकरण केन्द्रीय कोटा/गजस्थान निर्देश प्रकरण क्रमांक: औ. न्या. (केन्द्रीय)-95 दिनांक: स्थापित: 16-1-96

प्रमग भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या एन 42012/216/94 आई. आर. (डी यू.) दिनांक 27-28-12-95

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 मध्य

पारसनाथ यादव, बेलदाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, विसलदेव जी मन्दिर, विसलदेव जिला टोक।

—प्रार्थी श्रमिक

एवं

अधीक्षण, पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जयपुर मण्डल, जयपुर।

—प्रतिपक्षी नियोजक

उपस्थित

श्री जगदीश प्रसाद शर्मा,

आर०एच०जे०एस०

प्रार्थी श्रमिक की ओर से प्रतिनिधि:— प्रद्युम्न शर्मा

प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से प्रतिनिधि:—श्री केप्टिन आर०एस०

ठाकुर

श्री एच०के० काठपाल

दिनांक 20-7-98

अधिनिर्णय

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निम्न निर्देश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे तदुपरान्त "अधिनियम" से सम्बोधित किया जावेगा) की धारा 10 (1)(घ) के अन्तर्गत इस न्यायाधिकरण को अधि-निर्णयार्थ सम्प्रेषित किया गया है:—

"क्या अधीक्षण पुरातत्वविद भारतीय, पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर मण्डल, जयपुर द्वारा कर्मकार पारसनाथ यादव की सेवाएं दि. 2-4-93 से समाप्त करने की कार्यवाही उचित एवं न्यायसंगत है? यदि नहीं तो कर्मकार, श्री पारसनाथ यादव किस अनुतोष का हकदार है?"

2. निर्देश न्यायाधिकरण में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व पक्षकारों को सूचना जारी की गयी। प्रार्थी श्रमिक की ओर से क्लेम स्टेटमेंट प्रस्तुत कर संक्षेप में यह अभिकथित किया गया है कि प्रार्थी पारसनाथ द्वारा प्रतिपक्षी अधीक्षण पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर मण्डल, जयपुर एवं संरक्षण सहायक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण/उप-मण्डल, अजमेर (जिन्हें तदुपरान्त क्रमशः "प्रतिपक्षी नियोजकगण से सम्बोधित किया जायेगा") के यहां नियोजन में दि. 8-12-90 को बेलदार के पद पर नियोजित होकर 27-5-93 तक कार्य कर हर कलैण्डर वर्ष में 240 दिवस से अधिक अवधि तक कार्य कर निरन्तर द्वाई वर्ष से अधिक अवधि तक सेवा पूर्ण करली गई थी तब प्रतिपक्षीगण नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक को दि. 27-5-93 को अकारण ही, बिना कोई कारण बताये प्रार्थी श्रमिक से कनिष्ठ श्रमिकों को नियोजित रखते हुए "पहले आये पीछे जाये सिद्धांत" की अवहेलना करते हुए, बिना कोई नोटिस अथवा नोटिस वेतन व छंटनी का मुआवजा दिये अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए सेवा से पृथक कर दिया जो सर्वथा अनुचित व अवैध है। अतः प्रार्थी श्रमिक को प्रतिपक्षी नियोजक के यहां पिछले सम्पूर्ण वेतन मय समस्त लाभ व सेवा की निरन्तरता सहित पुनः सेवा पर बहाल करवाये जाने का अधिनिर्णय प्रदान किया जावे।

3. प्रतिपक्षीगण नियोजक की ओर से जवाब क्लेम प्रस्तुत कर उक्त क्लेम को अस्वीकार किया गया है तथा संक्षेप में यह अभिकथित किया गया है कि प्रार्थी श्रमिक को स्वीकृत वार्षिक मरम्मत प्राक्कलन के समक्ष दिनांक 8-12-90 को प्रतिपक्षी नियोजक क्रम 2 संरक्षण सहायक ने केन्द्रीय सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक की साफ-सफाई जैसे पूर्णतया अस्थायी प्रवृत्ति के कार्य हेतु बेलदार दैनिक वेतन भोगी अकुशल श्रमिक, के रूप में मस्ट्रोल पर लगाया था। यह भी अभिकथित किया गया है कि स्मारक को का मरम्मत कार्य यदा-कदा होने व आवश्यकता होने पर श्रमिकों को लगा लिया जाता है और कार्य समाप्ति पर उनको कार्य से हटा दिया जाता है। उनके यहां बेलदार पदनाम से कोई नियमित अथवा अस्थायी पद स्वीकृत नहीं है। प्रार्थी श्रमिक को बीच-बीच में कार्य न होने पर कार्य-विच्छेद किया गया था अर्थात् प्रार्थी श्रमिक ने दि. 23-3-91 से 22-4-91 तक 31 दिन, 24-5-91 से 23-6-91 तक 10 दिन, 24-4-92 से 23-5-92 तक 23 दिन व 25-3-93 से 24-4-93 तक की अवधि में 23 दिन कार्य-विच्छेद रखा अथवा अनुपस्थित रहा। प्रार्थी श्रमिक ने प्रतिपक्षी विभाग में वित्तीय वर्ष 90-91 में 88 दिन, वर्ष 91-92 में 289 दिन, वर्ष 92-93 में 291 दिन व 93-94 में 22 दिन ही कार्य किया है जो कार्य लगातार 240 दिवस तक नहीं किया गया है। यह भी अभिकथित किया गया है कि प्रार्थी श्रमिक को प्राक्कलन स्वीकृत न होने पर कार्य से हटा देना, सेवा में अलग कर देने की परिभाषा में नहीं आता है। प्रार्थी श्रमिक को देहाड़ी बेलदार, अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य पर लगाया गया था और उसे नियमानुसार 22 रु. प्रतिदिन के हिसाब से कार्य दिवसों का भुगतान किया गया है। यह भी अभिकथित किया गया है कि प्रतिपक्षी विभाग, अधिनियम, 1947 की परिधि में नहीं आता और न ही विभाग कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान है, अतः प्रार्थी श्रमिक को कार्य से हटाने से पूर्व नोटिस अथवा नोटिस वेतन व छंटनी का मुआवजा प्रादि दिये जाने व अधिनियम की धारा 25-एफ का उल्लंघन किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः प्रार्थी श्रमिक का क्लेम अस्वीकार कर निरस्त किया जावे।

4. प्रार्थी श्रमिक पारसनाथ ने साक्ष्य में स्वयं का अपक्ष-पत्र प्रस्तुत किया है जिस पर प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से प्रतिपरीक्षा दी गयी है। प्रलेखीय साक्ष्य में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

5. प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से साक्षी एच.के. काठपाल, प्रशासनिक अधिकारी का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर प्रार्थी श्रमिक की ओर से प्रतिपरीक्षा दी गयी है। प्रलेखीय साक्ष्य से कोई प्रलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

6. मैंने दोनों पक्षों की बहस सुनी।

7. विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी श्रमिक की यह बहस रही है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य से तथा प्रतिपक्षी नियोजक की स्वीकारोक्तियों से यह पूर्णतया प्रमाणित किया गया है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा अपने नियोजन काल दिनांक 3-12-90

से दिनांक 27-5-93 तक निरन्तर कार्य कर उक्त नियोजन काल में हर बारह कलेण्डर माह में 240 दिवस से अधिक कार्य करा निरन्तर वर्ष पूर्ण कार्य किया गया है तब प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक की अधिनियम की धारा 25 एफ व जी की अवहेलना करते हुए अनूचित एवं अवैध प्रकार से सेवा से पृथक् किया गया है। प्रार्थी श्रमिक द्वारा कथित नियोजन काल व कार्य दिवसों के प्रतिवाद में प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक को कार्य मस्ट्रोल व कार्य भुगतान सम्बन्धी लेखा प्रलेख न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तथा प्रार्थी श्रमिक द्वारा कथित उक्त नियोजन काल व कार्य दिवस ही मान्य रहते हैं। प्रतिपक्षी नियोजक की माध्य से यह कतई प्रमाणित नहीं हुआ है कि प्रार्थी श्रमिक को निश्चित कार्य हेतु निश्चित समयवधि के लिए नियोजित किया गया था और वह कार्य समाप्त हो गया था। प्रार्थी श्रमिक को सेवा से पृथक् किया गया है और न प्रार्थी द्वारा स्वतः सेवा त्याग किया गया है। प्रतिपक्षी विभाग अधिनियम में परिभाषित 'उद्योग' की परिभाषा में आता है तथा इसका कर्मचारी प्रार्थी 'कर्मकार' की परिभाषा के अंतर्गत है। प्रार्थी श्रमिक सेवा समाप्ति के पश्चात् से ही बेरोजगार रहा है। अतः प्रार्थी श्रमिक द्वारा प्रस्तुत इस क्लेम को पूर्णतः स्वीकार किया जावे।

8. विद्वान प्रतिनिधि प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से उक्त बहस का खण्डन करते हुए यह बहस की गयी है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा किसी भी बारह कलेण्डर माह में निरन्तर 240 दिन तक कार्य नहीं किया गया है। प्रार्थी श्रमिक को यदाकदा आवश्यकता होने पर मस्ट्रोल पर पूर्णतया अस्थायी तौर पर स्मारकों की मरम्मत तथा आकस्मिक साफ सफाई जैसे कार्यों पर लगाया जाता रहा है जिसे पर्याप्त बजट के अभाव में वार्षिक मरम्मत प्राकलन स्वीकृत न होने के कारण कार्य से हटा दिया गया था। प्रार्थी का मामला सेवा से छंटनी का नहीं रहा है तब प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा भी अधिनियम के प्रावधानों की पालना किये जाने का कोई औचित्य नहीं रहा है। प्रतिपक्षी विभाग अधिनियम में परिभाषित "उद्योग" की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं है तथा प्रार्थी कर्मचारी भी परिभाषित "कर्मकार" की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं है तब उक्त मामले पर अधिनियम के प्रावधान प्रभावी नहीं होते हैं और इस न्यायाधिकरण को भी उक्त मामले पर सुनवाई का अधिकार उपलब्ध नहीं रहता है। प्रार्थी श्रमिक अपनी सेवा मुक्ति के पश्चात् से ही अन्यत्र लाभकारी नियोजित रहा है जो उसके द्वारा प्रतिपरीक्षा पर स्वीकार भी किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत क्लेम अस्वीकार किया जावे। विद्वान प्रतिनिधि द्वारा अपनी उक्त बहस समर्थन में "प्राचीन स्मारक तथा परातत्तीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1988 (जिने तदपुरान्त अधिनियम, 1988 से सम्बोधित" किया जायेगा) "व माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांत" 1997 एस सी सी (एल एंड एम) 1079 हिमांशु कुमार बनाम बिहार राज्य" भी उद्धरित किये हैं।

9. मैंने दोनों पक्षों की बहस पर विचार किया तथा पत्रावली व अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

10. प्रार्थी श्रमिक की क्लेम समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र पर अपने नियोजन काल व कार्य दिवसों के संबंध में मुख्यतः यह सुसंगत साक्ष्य रहा है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा प्रतिपक्षी नियोजक के यहां नियोजन में दिनांक 8-12-90 से रिक्त स्थायी बेलदार के पद पर नियोजित होकर दिनांक 27-5-93 तक निरन्तर कार्य कर उक्त नियोजन काल के हर बारह कलेण्डर माह में 240 दिवस से अधिक समय तक कार्य कर निरन्तर ढाई वर्ष से अधिक का सेवा कार्य पूर्ण किया गया है। शपथ पत्र पर प्रतिपरीक्षा पर यह साक्ष्य भी रहा है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा एक बार गांव जाने पर 8-10 दिन का अवकाश लिया है अन्यथा निरन्तर कार्य किया गया है। प्रार्थी श्रमिक को उक्त नियोजन काल में आठ घंटे ड्यूटी देनी पड़ती थी। प्रार्थी श्रमिक की हाजरी मस्ट्रोल पर होती थी और हाजरी अनुसार ही भुगतान भी मस्ट्रोल पर होता था। इसके विपरीत प्रतिपक्षी साक्षी श्री एच. के. काठपाल, प्रशासनिक अधिकारी की शपथ पत्र पर यह साक्ष्य रही है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा अपने उक्त नियोजन काल में भी निरन्तर 240 दिवस तक कार्य नहीं किया गया है। प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक को आवश्यकता अनुसार कार्य पर लगाया जाता रहा था। शपथ पत्र पर प्रतिपरीक्षा पर यह साक्ष्य भी रही है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा हमारे यहां 8-12-90 से 27-5-93 तक कार्य किया गया है तब उसके द्वारा वित्तीय वर्ष 90-91 में कुल 88 दिवस, वर्ष 91-92 में 289 दिवस, वर्ष 92-93 में 291 दिवस, व वर्ष 93-94 में 22 दिवस, कार्य किया गया था जो प्रार्थी श्रमिक के वास्तविक कार्य दिवस है जिनमें माप्ताहिक अवकाशों के दिवसों को नहीं जोड़ा हुआ है। आगे यह साक्ष्य भी रही है कि हमारे यहां दैनिक वेतन भोगी श्रमिक को मस्ट्रोल पर रखते समय कोई नियुक्ति पत्र, मस्ट्रोल पर कार्यरत रहते समय कोई जोब कार्ड वेज स्लिप व ऐसा कोई पत्र जिसमें दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के नियोजन काल व कार्य दिवसों का विवरण उल्लेखित होता है व सेवा से पृथक् करने पर कोई सेवा मुक्ति आदेश नहीं किया जाता है। प्रार्थी श्रमिक स्वीकार्य रूप में मस्ट्रोल पर दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के रूप में उक्त नियोजन काल में नियोजन में कार्यरत रहा है तब प्रार्थी श्रमिक के पास अपने नियोजन काल में कार्य दिवसों के प्रणाम में अपनी मौखिक साक्ष्य के अनिवार्य कोई प्रालेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहती है जबकि प्रतिपक्षी नियोजक के पास प्रार्थी श्रमिक का कार्य मस्ट्रोल व कार्य भुगतान संबंधी लेखा प्रलेख जो उक्त संदर्भ में सर्वातम एवं निर्णायक प्रालेखीय साक्ष्य रहते हैं, आधिपत्य में रहने पर सदैव उपलब्ध रहते हैं। प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक के उक्त स्वीकार्य नियोजन काल को कार्य मस्ट्रोल व कार्य भुगतान संबंधी लेखा प्रलेखीय बिना कोई कारण दर्शाये, न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। तब प्रार्थी श्रमिक द्वारा कथित उक्त नियोजन काल व कार्य दिवस ही मान्य रहते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत "1985 (4) एस. सी. सी 201-एच. डी. सिंह बनाम रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया" के मामले में उपस्थिति रजिटर अथवा भुगतान रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने पर व माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत 1996 (2)

एल.एल. जे. 122- चीफ इंजीनियर सिचाई विभाग बनाम कमलेश व अन्य" के मामले में कार्य मस्ट्रोल्स प्रस्तुत न किये जाने पर, श्रमिक द्वारा कथित नियोजनकाल व का दिवस को ही माने जाने का निष्कर्ष निकाले जाने का अभिमत ही प्रकट किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी श्रमिक द्वारा प्रतिपक्षी नियोजक के यहां नियोजन में दि. 8-12-90 से नियोजित होकर दि. 27-5-93 तक निरन्तर कार्यकर, उक्त नियोजनकाल के हर बारह कलेण्डर मास में 240 दिवस पूर्ण कार्य कर, निरन्तर ढाई वर्ष से अधिक सेवा कार्य किया गया है, पूर्णतः प्रमाणित हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रतिपक्षी साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य से यह भी स्वीकार किया हुआ है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा 8-12-90 से कार्य पर नियोजित होकर 31-3-91 तक कुल 88 दिवस, दि. 1-4-91 से 31-3-93 तक के एक वित्तीय वर्ष में 289 दिवस दि. 1-4-92 से 31-3-92 तक के एक वित्तीय वर्ष में 291 दिवस, दि. 1-4-93 से 27-5-93 तक 22 दिवस कार्य किया गया है जो वास्तविक कार्य दिवस है जिनमें साप्ताहिक अवकाश के दिवस नहीं जुड़े हुए हैं। प्रतिपक्षी नियोजक की प्रार्थी श्रमिक के उक्त स्वीकार्य कार्य दिवसों के सन्दर्भ मात्र यह आपत्ति रही है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा उक्त नियोजनकाल में कभी भी 240 दिवस तक निरन्तर कार्य नहीं किया गया तथा ब्रेक के साथ किया गया है जो ब्रेक अथवा कार्य विच्छेद व अनुपस्थिति की अवधि को जवाब क्लेम के पद सं. 4 में दर्शाया भी गया है। प्रतिपक्षी साक्षी की शपथ-पत्र पर यह साक्ष्य तो रही है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा लगातार कार्य नहीं किया गया है तथा उसे कार्य आवश्यकतानुसार कार्य पर लगाया जाता रहा है। परन्तु प्रतिपक्षी साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य में कार्य विच्छेद व अनुपस्थिति की कोई अवधि जवाब क्लेम के उक्त पैरा सं. 4 अनुसार नहीं बतलायी गयी है। प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा उक्त कथित कार्य विच्छेद व अनुपस्थिति के प्रमाण में प्रार्थी श्रमिक के नियोजनकाल की कोई कार्य मस्ट्रोल व अन्य प्रलेखीय साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गयी है तब प्रतिपक्षी नियोजक की साक्ष्य से ही यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि प्रार्थी श्रमिक का उक्त नियोजन काल ब्रेक अथवा कार्य विच्छेद के साथ रहा है और उक्त नियोजन काल में प्रार्थी श्रमिक भी स्वतः कार्य से अनुपस्थित रहा है। वैसे भी मेरे मत में जब अधिनियम की "धारा 25 एफ में प्रकट हुई निरन्तर एक वर्ष सेवा" को अधिनियम की धारा 25 बी (2) में परिभाषित करते हुए, ऐसे परिभाषित किया गया है कि बारह कलेण्डर मास में 240 दिवस कार्य पूर्ण कर लेने पर "निरन्तर एक वर्ष सेवा" पूर्ण कर लिया जाना जायेगा तब बारह कलेण्डर मास में ब्रेक अथवा कार्य विच्छेद व एक वर्ष से अल्पावधि के नियोजन काल में भी 240 दिवस सेवा कार्य पूर्ण कर लिया गया है जब भी "निरन्तर एक वर्ष सेवा" पूर्ण कर लिया जाना जायेगा तब बारह कलेण्डर मास में ब्रेक अथवा कार्य विच्छेद व एक वर्ष से अल्पावधि के नियोजन काल में भी 240 दिवस सेवा कार्य पूर्ण कर लिया गया है जब भी "निरन्तर एक वर्ष सेवा" पूर्ण कर लिया जाना माना जायेगा। मैं अपने उक्त मत का समर्थन माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय

दृष्टांत "1981 (1) एल.एल. जे. 366-सुरेन्द्र कुमार वर्मा बनाम औद्योगिक न्यायधिकरण, केन्द्रीय दिल्ली व अन्य" में तिपादित निम्न न्याय सिद्धान्त से भी पाता हूँ :—

"Even if a workman has not been in 'continuous service' under an employer for a period of one year, he shall be deemed to have been in such 'continuous service' for a period of one year if he has actually worked under the employer for 240 days in the preceding period of twelve months. There is no stipulation that he should have been in employment or service under the employer for a whole period of twelve months. In fact, the thrust of the provision is that he need not be. That appears to be the plain meaning without gloss from any source."

इस प्रकार प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से भी स्वीकार्य मामला रहा है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा प्रतिपक्षी नियोजक के यहां नियोजन में दिनांक 8-12-90 से नियोजित होकर 27-5-93 तक कार्यकर निरन्तर ढाई वर्ष सेवा कार्य पूर्ण किया है। अतः प्रार्थी श्रमिक की साक्ष्य से तथा प्रतिपक्षी नियोजक की उक्त स्वीकारोक्तियों से यह पूर्णतः प्रमाणित हुआ कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा प्रतिपक्षी नियोजक के यहां नियोजन में दिनांक 8-2-90 से नियोजित होकर दिनांक 27-5-93 तक कार्य कर निरन्तर ढाई वर्ष सेवा कार्य पूर्ण किया है।

11. प्रार्थी श्रमिक की शपथ-पत्र पर अपनी सेवा मुक्ति के सम्बन्ध में यह साक्ष्य रही है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा प्रतिपक्षी नियोजक के यहां नियोजन में जब दि. 27-5-93 तक कार्य कर लिया गया था तब प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक को दि. 27-5-93 से अकारण ही "पहले आये बाद जाये" सिद्धान्त की अवहेलना करते हुए, बिना एक माह का नोटिस अथवा नोटिस वेतन व छंटनी का मुआवजा दिये अथवा प्रस्तावित किये, अधिनियम की धारा 25-एफ व जी के विधि प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, अनुचित एवं अवैध प्रकार से सेवा से पृथक कर दिया गया। प्रार्थी श्रमिक अपनी उक्त साक्ष्य में यह बतलाने में असमर्थ रहा है कि प्रार्थी श्रमिक को सेवा से पृथक करते समय प्रार्थी श्रमिक ने सेवा में कनिष्ठ कितने श्रमिक व किस नाम के श्रमिक यथावत कार्य पर अथवा प्रतिपक्षी नियोजक के यहां सेवा में नियोजित रहे। प्रार्थी श्रमिक द्वारा इस सन्दर्भ में कोई प्रलेखीय साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गयी है और ना ही ऐसा कोई प्रलेखीय साक्ष्य ही प्रतिपक्षी नियोजक से प्रस्तुत करवाये जाने का प्रयास ही किया गया है।

प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से प्रार्थी श्रमिक से किसी कनिष्ठ श्रमिक को यथावत् नियोजित रखने को स्वीकार भी नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी श्रमिक साक्ष्य के अभाव में यह प्रमाणित करने में कतई सफल नहीं हुआ है कि प्रार्थी श्रमिक की सेवा से पृथक् करते समय, प्रार्थी श्रमिक से कनिष्ठ यथावत् सेवा पर नियोजित रहे। प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से जबाब वलेम प्रस्तुत कर अभिकथनों पर व प्रतिपक्षी साक्षी द्वारा शपथ-पत्र पर साक्ष्य पर यह स्पष्ट स्वीकारोक्ति भी रही है कि प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक को दि० 27-5-93 को सेवा से पृथक् किया गया था। प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से किसी भी स्तर पर ऐसा मामला भी नहीं रहा है कि उनके द्वारा प्रार्थी श्रमिक को सेवा से पृथक् करते समय अधिनियम की धारा 25-एफ के आज्ञात्मक प्रावधानों की पालना में कोई एक माह का नोटिस अथवा नोटिस बेतन व छंटनी का मुआवजा दिया गया अथवा प्रस्तावित किया गया। प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से जबाब वलेम प्रस्तुत कर यह अभिकथन व प्रतिपक्षी साक्षी द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत कर यह साक्ष्य कथन अवश्य रहे हैं कि प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक को केन्द्रीय सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक के लिए स्वीकृत वार्षिक मरम्मत प्राक्कलन के समक्ष दि० 8-12-90 को साफ-सफाई जैसे पूर्णतया अस्थायी प्रकृति के कार्य हेतु दैनिक बेतन भोगी बेलदार के रूप में मस्टील पर लगाया गया था जिसे वित्तीय वर्ष के स्वीकृत प्राक्कलन की समाप्ति पर अथवा कार्य समाप्ति पर सेवा से पृथक् कर दिया गया। प्रतिपक्षी विभाग में "बेलदार" पदनाम से कोई नियमित अथवा अस्थायी पद भी स्वीकृत नहीं है। प्रार्थी श्रमिक को जब स्वीकृत वार्षिक मरम्मत प्राक्कलन के समक्ष ही कार्य पर लगाया जाता रहा था तब प्राक्कलन स्वीकृत न होने पर अथवा प्राक्कलन में स्वीकृत कार्य के समापन पर, प्रार्थी श्रमिक को सेवा मुक्त किया जाना उसकी किसी भी प्रकार से अधिनियम के अधीन सेवा से छंटनी नहीं है। इसी सन्दर्भ में प्रतिपक्षी साक्षी की शपथ-पत्र पर यह साक्ष्य भी रही है कि प्रार्थी श्रमिक का उक्त नियोजनकाल प्रतिपक्षी साक्षी के पदस्थापना काल से पूर्व का रहा है और प्रार्थी श्रमिक द्वारा प्रतिपक्षी साक्षी के अधीन कोई कार्य नहीं किया गया है इसलिए प्रतिपक्षी साक्षी को प्रार्थी श्रमिक के कार्य की व्यक्तिगत जानकारी नहीं रही है तथा जो भी जानकारी रही है वह अभिलेख के आधार पर ही रही है। इस प्रकार प्रतिपक्षी साक्षी की वही साक्ष्य स्वीकार्य रहनी हैं जिस साक्ष्य का समर्थन किसी अभिलेखीय व प्रलेखीय साक्ष्य से होता हो। प्रतिपक्षी साक्षी की शपथ-पत्र पर भी प्रतिपरीक्षा पर आगे यह साक्ष्य रही है कि हमारे यहां काम का ऐस्टीमेट बनता है और ऐसे ऐस्टीमेट के आधार पर काम होता है जो ऐस्टीमेट खत्म हो जाने पर स्वतः खत्म हो जाता है। हमारे द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई प्रलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमें यह प्रकट होता हो कि प्रार्थी श्रमिक को किस ऐस्टीमेट के तहत कार्य पर नियोजित किया गया था तथा उक्त ऐस्टीमेट के तहत कौन सा कार्य हुआ

था और ऐस्टीमेट का कितना बजट था और उक्त ऐस्टीमेट का कार्य कब शुरू और कब खत्म हुआ। प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से इस सन्दर्भ में कोई प्रलेख न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया तब प्रतिपक्षी साक्षी की उक्त साक्ष्य का भी किसी अभिलेखीय साक्ष्य से समर्थन नहीं हुआ है तब प्रतिपक्षी साक्षी की यह साक्ष्य कि प्रार्थी श्रमिक को स्वीकृत कार्यों पर स्वीकृत प्राक्कलनों के समक्ष कार्य पर नियोजित किया गया था और जो नियोजन स्वीकृत प्राक्कलनों की समाप्ति पर अथवा स्वीकृत कार्य के समापन पर स्वतः समाप्त हो गया, समर्थित अभिलेखीय साक्ष्य के अभाव में स्वीकार्य नहीं रहती है। इस प्रकार प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा अपनी मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से यह कतई प्रमाणित नहीं किया गया है कि प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन के समक्ष स्वीकृत कार्यों पर नियोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रतिपक्षी नियोजक का ऐसा भी किसी स्तर पर मामला नहीं रहा है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बेरोजगारों के लिए कोई विशेष रोजगार योजना के अधीन कोई प्राक्कलन व कार्य स्वीकृत किये गये हों और उक्त विशेष रोजगार योजना के अधीन ही प्रार्थी श्रमिक द्वारा उक्त नियोजन काल में कार्य किया गया हो। प्रतिपक्षी नियोजक का किसी भी स्तर पर ऐसा मामला भी नहीं रहा है कि समुचित सरकार द्वारा उनके विभाग को स्वीकृत प्राक्कलनों के समक्ष स्वीकृत कार्यों को अधिनियम की धारा 36-बी के अधीन अधिसूचना जारी कर अधिनियम के प्रावधानों से छूट प्रदान की हुई हो। स्वीकार्य रूप में, प्रतिपक्षी विभाग केन्द्र सरकार का एक विभाग है तब उक्त विभाग के सम्पूर्ण कार्य-कलाप व खर्च का बजट केन्द्र सरकार द्वारा ही स्वीकृत किया जाता है तब मात्र केन्द्र सरकार द्वारा प्राक्कलन व कार्य स्वीकृत किये जाने से प्रतिपक्षी विभाग के समस्त कार्य स्वतः ही अधिनियम के प्रावधानों से छूट प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रतिपक्षी साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य की प्रतिपरीक्षा पर यह भी स्वीकार किया गया है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा प्रतिपक्षी नियोजक के यहां नियोजन में बिसलपुर में सिलदेव मन्दिर पर बेलदार के पद पर कार्य किया गया था जो बिसलपुर मन्दिर स्मारक अभी भी है। स्वीकार्य रूप में प्रार्थी श्रमिक का बेलदारी के रूप में कार्य उक्त बिसलपुर मन्दिर स्मारक की साफ-सफाई, देख-रेख व चौकीदारी का रहा है जो उसके द्वारा आठ घंटे की ड्यूटी देकर पूरी किया जाता था। बिसलपुर मन्दिर आज भी प्रतिपक्षी का संरक्षित स्मारक है और उस पर उक्त कार्य आज भी यथावत् किया जा रहा है तब प्रतिपक्षी नियोजक का यह मामला कि प्रार्थी श्रमिक को स्वीकृत प्राक्कलन के समक्ष स्वीकृत कार्यों पर नियोजित किया जाता रहा और उसे स्वीकृत प्राक्कलन की समाप्ति पर व स्वीकृत कार्यों के समापन पर, सेवा से पृथक् किया गया, स्वतः असत्य प्रकट होता है। मेरे मत में वैसे भी, स्वीकृत प्राक्कलन के समक्ष स्वीकृत कार्यों पर नियोजित वर्कचार्ज श्रमिक भी यदि अधिनियम में परिभाषित एक

“कर्मकार” है तब स्वीकृत प्राक्कलन के समक्ष स्वीकृत कार्यों के समापन पर भी, अधिनियम के अधीन समस्त लाभ प्राप्त करने का अधिकारी रहता है। मैं अपने उक्त मत का समर्थन माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायद्वयों “ए०आई०आर० 1980 एस०सी० 115—जसवन्त सिंह बनाम यूनियन आफ इण्डिया” में प्रतिपादित निम्न न्याय-सिद्धांत व अभिमत से भी पाता हूँ:—

“The entire strength of labour employed for the purposes of the Beas Project was work-charged. The work-charged employees are engaged on a temporary basis as their appointments are made for the execution of a specific work. From the very nature of their employment, their services automatically come to an end on the completion of the works for the sole purpose of which they are employed. They do not get any relief under the Payment of Gratuity Act nor do they receive any retrenchment benefits or any benefits under the Employees' State Insurance Schemes.

But though the work-charged employees are denied these benefits, they are industrial workers and are entitled to the benefits of the provisions contained in the Industrial Disputes Act. Their rights flow from that special enactment under which even contracts of employment are open to adjustment and modification. The work-charged employees, therefore, are in a better position than temporary servants like the other petitioners who are liable to be thrown out of employment without any kind of compensatory benefits.”

12. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, उक्त न्यायद्वयों में प्रतिपादित उक्त न्यायसिद्धांत व अभिमत को, अपने नवीनतम न्यायद्वयों “जे०टी० 1992(5) एस०सी० 179—हरियाणा राज्य बनाम पियारा सिंह” में भी उक्त सुसंगत ग्रंथों को उल्लेखित करते हुए प्रतिपादित न्यायसिद्धांत व अभिमत से पूर्ण सहमति व्यक्त की गयी है। इस प्रकार, विवेचनोपरान्त, प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक को दि० 27-5-93 से सेवा से पृथक् किया जाना, अधिनियम की धारा 2(ग्रोओ) के अधीन, प्रार्थी श्रमिक की सेवा से छंटनी ही है। इस प्रकार प्रार्थी श्रमिक द्वारा अपनी साक्ष्य से यह पूर्णतया प्रमाणित किया गया है कि उसे प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा दि० 27-5-93 से सेवा से पृथक् किया गया है। प्रतिपक्षी साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि प्रतिपक्षी विभाग द्वारा प्रार्थी श्रमिक को कभी

भी नोटिस अथवा नोटिस बेटन व छंटनी का मुआवजा सेवा से पृथक् करने से पूर्व नहीं दिया गया और न प्रस्तावित किया गया। इस तरह प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा अधिनियम की धारा 25-एफ की पालना नहीं की गयी है।

13. प्रार्थी श्रमिक के क्लेम स्टेटमेन्ट प्रस्तुत कर वह अभिकथन भी रहे हैं कि प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक को 27-5-93 से, प्रार्थी से कनिष्ठ श्रमिकों को यथावत सेवा में नियोजित रखते हुए बिना “पहले आगे बाद जाये” सिद्धांत की पालना किये, अधिनियम की धारा 25-जी के विधि प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सेवा से पृथक् किया गया है। प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा जवाब क्लेम प्रस्तुत कर उक्त तथ्यों को स्वीकार नहीं किया गया है। प्रार्थी श्रमिक ने अपने क्लेम स्टेटमेन्ट में मात्र अपने से कनिष्ठ श्रमिकों को नियोजित रखना बतलाया है परन्तु उसने क्लेम अथवा शपथ-पत्र में यह कहीं स्पष्ट नहीं किया है कि उससे कनिष्ठ कौन-कौन से श्रमिक प्रतिपक्षी नियोजक ने अपने यहां कार्यरत रखे हैं। प्रार्थी श्रमिक द्वारा उक्त अभिकथन के समर्थन में कोई प्रलेखीय साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गयी है और न ही प्रतिपक्षी नियोजक से ही कोई प्रलेख प्रस्तुत करवाये जाने का प्रयास ही किया गया है तब साक्ष्य अभाव में प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में उक्त सिद्धांत व अधिनियम की धारा 25-जी के विधि प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित नहीं होता है।

14. प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से जवाब क्लेम प्रस्तुत कर यह अभिकथन भी रहे हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ना तो किसी उद्योग की श्रेणी में आता है एवं ना ही अधिनियम की परिधि में आता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, केन्द्रीय सरकार द्वारा संरक्षित स्थल, स्मारक, पुरावशेषों और प्राचीन अमूल्य धरोहर तथा संस्कृति को जीवित रखने के उद्देश्य से उनका रख-रखाव का कार्य करता है। इस विभाग का कदापि यह उद्देश्य नहीं रहा है कि इन स्मारकों का रख-रखाव किसी प्रकार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अर्थ लाभ प्राप्त करने के लिए किया जावे तब भारतीय सर्वेक्षण विभाग उद्योग की परिभाषा में नहीं आता है। प्रतिपक्षी साक्षी एच०के० काठपाल, प्रशासनिक अधिकारी के भी शपथ-पत्र पर उक्त प्रकार से ही कथन रहे हैं। उसकी आगे शपथ-पत्र पर यह साक्ष्य भी रही है कि प्रार्थी श्रमिक को केन्द्रीय सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक की साफ-सफाई व स्वीकृत वार्षिक भरम्मत प्राक्कलन के समक्ष बेलदार के पद पर मस्ट्रोल पर लगाया गया था। विद्वान प्रतिनिधि प्रतिपक्षी की भी उक्त कथनों के आधार पर यह बहस रही है कि प्रतिपक्षी विभाग अधिनियम में परिभाषित “उद्योग” की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं है तथा प्रार्थी श्रमिक भी परिभाषित “कर्मकार” की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं है तब उक्त मामले पर अधिनियम के प्रावधान प्रभावी नहीं होने हैं और इस औद्योगिक न्यायाधिकरण को भी उक्त मामले पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार उपलब्ध

नहीं रहता है। विद्वान प्रतिनिधि प्रतिपक्षी की ओर से उक्त अभिकथनों के समर्थन में प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 भी उद्धरित किया है तथा अपनी उक्त बहस समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत "1997 एस०सी०सी० (एल० एण्ड एस०) 1079—हिमांशु कुमार बनाम बिहार राज्य" को उद्धृत किया गया है। उद्धृत उक्त न्यायदृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामला बिहार राज्य के को-ऑपरेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी, सहायक चालकों व चपरासियों के सेवा से निष्कासन पर पुनः सेवा में नियोजित करने का रहा है तब माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में निम्न अभिमत प्रकट किया गया है:—

"Every Department of Government can not be treated to be Industry. Where the appointments are regulated by statutory rules, the concept of Industry to the extent stands excluded. The petitioners were not appointed to the posts in accordance with the rules but were engaged on the basis of need of the work. They are temporary employees working on daily wages. Their disengagement from service cannot be construed to be retrenchment under the Industrial Disputes Act. The concept of retrenchment therefore cannot be stretched to such an extent as to cover these employees. Since the petitioners are only daily wage employees and have no right to be posts, their disengagement is not arbitrary."

15. उद्धृत उक्त न्यायदृष्टांत में बिहार राज्य के को-ऑपरेटिव इंस्टीट्यूट के स्थापना के क्या उद्देश्य रहे हैं तथा उक्त संस्थान द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, यह उक्त निर्णय में उल्लेखित नहीं है। इस न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत इस प्रकरण में प्रतिपक्षी नियोजक का यह मामला होना भी प्रकट नहीं हुआ है कि उनके नियोजन में कार्यरत श्रमिकों की सेवायें कानूनी नियमों से शासित होती हैं। प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से उद्धृत "प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958" (जिसे तदुपरान्त संक्षेप में "अधिनियम, 1958" से सम्बोधित किया जाएगा) में अथवा उक्त अधिनियम की धारा 38 जिसके अधीन नियम बनाये जाने के प्रावधान है, में भी सेवारत श्रमिकों की सेवायें शासित करने के लिए कोई सेवा नियम बनाए जाने का प्रावधान नहीं है। प्रतिपक्षी साक्षी की शपथ-पत्र पर प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकारोदित भी रही है कि हमारे यहां काम का ऐस्टीमेट बनता है और उस ऐस्टीमेट के आधार पर काम होता है परन्तु साथ ही वे यह बताने में असमर्थ रहे कि प्रार्थी श्रमिक को किस ऐस्टीमेट के तहत नियोजित किया गया तथा उक्त ऐस्टीमेट के तहत

कौन सा कार्य होना था तब प्रतिपक्षी नियोजक को उद्धृत उक्त न्यायदृष्टांत में प्रकट हुए अभिमत से प्रस्तुत प्रकरण में कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

16. प्रतिपक्षी विभाग, अधिनियम की धारा 2(जे) में परिभाषित "उद्योग" की परिभाषा में आता है अथवा नहीं, इस सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत "1978(1) एल०एल०जे० 349—बंगलौर वाटर सप्लाय एण्ड सीवेज बोर्ड बनाम ए० राजप्पा" के पैरा 133 में निम्न जांच सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:—

"IV. The dominant nature test :

- (a) Where a complex of activities, some of which equally for exertion others not involves employees on the total undertaking, some of whom are not 'workmen' as in the University of Delhi case or some departments are not productive of goods and services if isolated, even then, the predominant nature of the services and the integrated nature of the departments as explained in the Corporation of Nagpur, will be the true test. The whole undertaking will be 'industry' although those who are not 'workmen' by definition may not benefit by the Status.
- (b) Notwithstanding the previous clauses, sovereign functions, strictly understood, alone qualify for exemption, not the welfare activities or economic adventures undertaken by Government or statutory bodies.
- (c) Even in departments discharging sovereign functions, if there are units which are industries and they are substantially severable, then they can be considered to come within S. 2(j).
- (d) Constitutional and competently enacted legislative provisions may well remove from the scope of the Act."

17. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त जांच सिद्धांतों को अपने नवीनतम न्यायदृष्टांत (1) "ए०आई०आर० 1998 एस०सी० 656—जी०एम० टेलीकॉम बनाम एस० श्रीनिवास राय व (2) 1996(1) एल०एल०जे० 1223—चीफ कंजरक्टर ऑफ फॉरेस्ट बनाम जगन्नाथ मूर्ति कंधारे" में पुनः मान्यताप्राप्त की गयी है तथा उक्त जांच सिद्धांतों के विपरीत रहे माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत "(1996) 8 एस०सी०सी० 489—सब डिवि० आफ पोस्ट व जलम बनाम थिय्यम जोसेफ तथा ए०आई०आर० 1997 एस०सी० 2817—बॉम्बे टेलीफोन

कैन्टीन एम्प्लोज़ एमो० बनाम यनियन ऑफ इण्डिया” में प्रकट किए गये अभिमतों को निरस्त किया गया है और प्रथम न्यायदृष्टांत में टेलीफोन विभाग को व द्वितीय न्याय-दृष्टांत में वन विभाग को “उद्योग” की परिभाषा के अन्तर्गत होना माना गया है। द्वितीय न्याय-दृष्टांत वन विभाग वाले प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त उद्धृत बंगलौर वाटर सप्लाई वाले प्रकरण पर विचार करते हुए निर्णय के पैरा 13, 16 व 17 में निम्न प्रकार अभिमत प्रकट किये गये हैं :—

“(13) The aforesaid shows that if we were to extend the concept of sovereign function to include at welfare activities as contended on behalf of the appellants, the ratio in Bangalore Water Supply case (supra) would get eroded, and substantially. We would demur to do so on the face what was stated in the aforesaid case according to which except the strictly understood sovereign function, welfare activities of the State would come within the purview of the definition of industry; and not only this, even within the wider circle of sovereign function, there may be an inner circle encompassing some units which could be considered as industry if substantially severable.

(16) The aforesaid being the crux of the scheme to implement which some of the respondents were employed, we are of the view that the same cannot be regarded as a part of inalienable or inescapable function of the State for the reason that the scheme was intended even to fulfil the people. We are in no doubt that such a work could well be undertaken by an agency which is not required to be even an instrumentality of the State.

(17) This being the position, we hold that the aforesaid scheme undertaken by the Forest Department cannot be regarded as a part of sovereign function of the State and so, it was open to the respondents to invoke the provisions of the State Act. We would say the same qua the social foresting work undertaken in Ahmednagar district. There was, therefore, no threshold bar in knocking the door of the Industrial Courts by the respondents making a grievance about adoption of unfair labour practice by the appellants.”

18. अधिनियम, 1958 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत संरक्षित संस्मारक अनुरक्षण को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि “अनुरक्षण” के अन्तर्गत है किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसे पुनर्स्थापित करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधापूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है। इसी अधिनियम, 1958 के शीर्षक में “राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेषों, नक्काशी और अन्य ऐसी वस्तुओं के संरक्षण का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम” अंकित हुआ है। अधिनियम, 1958 की धारा 18 के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्याधीन रहने हुए, जनता को किसी भी संरक्षित संस्मारक तक पहुंच का अधिकार दिया गया है। इसी अधिनियम, 1958 की धारा 6 के अधीन संरक्षित संस्मारक के अनुरक्षण के लिए उनके स्वामियों से संधि करने का भी अधिकार कलेक्टर को दिया हुआ है। इसी अधिनियम, 1958 की धारा 15 के अधीन महानिदेशक को संरक्षित संस्मारक के अनुरक्षण खर्च के निमित्त चन्दा आदि दिये जाने पर स्वीकार करने का भी अधिकार है। इसी अधिनियम, 1958 की धारा 21 के अधीन पुरातत्वीय उत्खनन के लिए लाईसेंस भी जारी किये जाने का प्रावधान है। इसी अधिनियम की धारा 38(2)(सी) में संरक्षित प्राचीन संस्मारकों पर जनता की पहुंच व पहुंच के लिए शुल्क निर्धारित करने का भी प्रावधान है। इस प्रकार उक्त अधिनियम, 1958 के अवलोकन पर ऐसा प्रकट नहीं हुआ है कि प्रतिपक्षी विभाग द्वारा सरकार के प्रभुत्वसम्पन्न कार्यों का निष्पादन किया जाता है। प्रतिपक्षी विभाग द्वारा जो उक्त प्राचीन संस्मारकों, तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेषों के परीक्षण, पुरातत्वीय उत्खननों के विनियमन, रूप कृतियों, नक्काशी व ऐसी अन्य वस्तुओं के संरक्षण का कार्य किया जाता है वो जनता तथा देशी-विदेशी पर्यटकों को आमोद-प्रमोद व शैक्षणिक लाभ मुलभ कराने के उद्देश्य से ही किया जाता है जिससे प्रत्यक्षतः शुल्क लगाकर व अप्रत्यक्षतः विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर विदेशी मुद्रा का कुछ सीमा तक लाभ भी अर्जित किया जाता है। प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय अवशेषों के परीक्षण पर और संरक्षण पर कार्य किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा भी करवाया जा सकता है तब प्रतिपक्षी विभाग द्वारा किया गया उक्त कार्य किसी भी प्रकार से सरकार का प्रभुत्व सम्पन्न कार्य नहीं है। प्रार्थी श्रमिक द्वारा स्वीकार्य रूप में उक्त प्रतिपक्षी विभाग में दैनिक वेतन भोगी श्रमिक रूप में मस्ट्रोल पर बिसलपुर में मिलदेव मन्दिर स्मारक पर चौकीदारी, साफ-सफाई व मरम्मत आदि का कार्य किया गया है जो आज भी संरक्षित स्मारक है तब प्रतिपक्षी नियोजक संस्थान अधिनियम की धारा 2(जे) के अधीन परिभाषित “उद्योग” होना तथा प्रार्थी श्रमिक इसी अधिनियम की धारा 2(एस) में परिभाषित “कर्मकार” होना पाया जाता है।

18. अतः उक्त विवेचनोपरान्त निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रार्थी श्रमिक ने प्रतिपक्षी नियोजक के यहां दि० 8-12-90 से नियोजित होकर दि० 27-5-93 तक निरन्तर कार्य कर उक्त नियोजनकाल में निरन्तर हाई वर्प से अधिक समय तक सेवा कार्य पूर्ण किया है तब प्रतिपक्षी नियोजक द्वारा प्रार्थी श्रमिक को दि० 27-5-93 से अधिनियम की धारा 25-एफ के प्रावधानों के अन्तर्गत रखने हुए जो सेवा में पृथक किया गया है वो किसी भी प्रकार से उचित एवं वैध नहीं है, तब प्रार्थी श्रमिक प्रतिपक्षी नियोजक के यहां सेवा की निरन्तरता सहित पुनः सेवा में आने का अधिकारी घोषित होने योग्य रहता है।

19. जहां तक प्रार्थी श्रमिक के पिछले वेतन प्राप्त करने के अधिकारी होने का प्रश्न है, प्रार्थी की अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकारोक्ति रही है कि मैं आजकल दैनिक मजदूरी पर ठेकेदारों के यहां काम पर जाता हूं, महीने में मुझे 15-20 दिन मजदूरी मिल जाती है और प्रतिदिन के 32 रु० मिल जाते हैं। इस प्रकार प्रार्थी

श्रमिक स्वयं की माह्यानुसार सेवा में पृथक किये जाने के पश्चात् से आंशिक रूप से अन्यत्र लाभकारी नियोजित रहा है और इन तथ्यों व ममस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी श्रमिक पिछला 50% वेतन ही प्राप्त करने का अधिकारी रहता है।

20. अतः उक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा सम्प्रेषित निर्देश को इस प्रकार उत्तरित किया जाता है कि अधीक्षण पुरा-तत्वीय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर मण्डल, जयपुर द्वारा प्रार्थी श्रमिक पारसनाथ यादव की सेवार्थ दि० 27-5-93 से समाप्त करने की कार्यवाही उचित एवं न्यायसंगत नहीं है, फलस्वरूप प्रकरण की परिस्थितियों में प्रार्थी श्रमिक पिछले 50% वेतन व सेवा की निरन्तरता सहित पुनः सेवा में लिये जाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

इस अधिनियम को समुचित सरकार ही नियमानुसार प्रकाशनार्थ भिजवाया जावे।

जगदीश प्रसाद शर्मा, न्यायाधीश